राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 5] बारहवीं विधान सभा के पांचवें सत्र का पांचवां दिवस [संख्या : 5

शनिवार

04 मार्च, 2006

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे आपको सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

(1) श्री रणवीर सिंह गुढा एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से जोधपुर के एडवोकेट श्री सुरेश शर्मा हत्याकाण्ड में शामिल प्रभावशील लोगों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री जुबेर खान, सदस्य की ओर से जयपुर स्थित ऐतिहासिक धार्मिक स्थल गलताजी के चल रहे विवाद के सम्बन्ध में।

(3) श्री बाबूलाल नागर, सदस्य की ओर से दूदू में सरसों समर्थन मूल्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में।

यद्यपि उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य को अपनी बात कहने के लिए दो मिनट का समय दूंगी, दो मिनट में अपनी बात कहने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

मुझे प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं :-

(1) श्री हरिमोहन शर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र हिण्डोली में औसत से कम वर्षा होने के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री हरीश चन्द्र कुमावत, सदस्य की ओर से नगरपालिका मेड़ता के अधिशासी अधिकारी एवं अध्यक्ष द्वारा पद का दुरूपयोग करने के सम्बन्ध में।

(3) श्री ज्ञानचन्द पारख, सदस्य की ओर से पाली के कपड़े की रंगाई-छपाई के उद्योग से किसानों की भूमि प्रदूषित होने के सम्बन्ध में।

(4) श्री प्रभुलाल वर्मा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिपल्दा का इन्द्रगढ़ से ढीपरी राज्य मार्ग क्षतिग्रस्त होने के सम्बन्ध में।

(5) श्री महीपाल सिंह यादव, सदस्य की ओर से कस्बा बानसूर से गुजर रहे स्टेट हाइवे 52 के दोनों ओर की जमीन पर अतिक्रमण होने के सम्बन्ध में।

(6) श्री बंशीलाल खटीक, सदस्य की ओर से राजसमन्द के आर. के. चिकित्सालय को 200 बैड का करने के सम्बन्ध में।

(7) श्री अर्जुन सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र दानपुर में पुलिया का निर्माण करने के सम्बन्ध में।

(8) श्री बनवारी लाल शर्मा, सदस्य की ओर से धौलपुर शहर में ड्रेनेज स्कीम की क्रियान्विति के सम्बन्ध में।

(9) श्री रणधीर सिंह भीण्डर, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बल्लभनगर में यातायात के साधनों की समुचित व्ययवस्था नहीं होने के सम्बन्ध में।

(10) श्री संयम लोढ़ा, सदस्य की ओर से शिवगंज नगरपालिका द्वारा सीमा क्षेत्र (पैराफैरी) में भूमि रूपान्तरण की राशि बंडगांव व केसरपुरा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(11) श्री खुशवीर सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र खारची में राहत कार्य आरम्भ करने के सम्बन्ध में।

(12) श्री मांगीलाल गरासिया, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा की कतिपय सड़कों को पक्का करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगी कि इन्हें पढ़ा हुआ मान लिया जाए क्योंकि अब हमारे पास वाद-विवाद के लिए केवल साढ़े पांच घण्टे का समय है।

(नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री सुरेश मीणा (करौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इससे पहले कोई ऐसा मामला है जो सदन में रखना चाहता हूं, मेरे क्षेत्र में...

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं, तो आपका पढ़ा हुआ मान लेंगे ना।

श्री सुरेश मीणा : मेरे क्षेत्र में इस पानी को जनता पी रही है, इस पानी को, माननीय अध्यक्ष महोदय, इस चीज के बारे में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पढ़ा हुआ मान रहे हैं इसका मतलब कार्यवाही होगी ना। गुढा से आने वाले माननीय सदस्य, आप क्यों खड़े हो गए, मैं बैठी थोड़े ही हूं।

श्री सुरेश मीणा : इस पानी को जनता पीती है और हम बिसलरी का पानी पीते हैं, इसको हमारी जनता पीती है, इसको देखा जाए, इस पानी को, यह अख़बार में छपा मामला है, सारा मामला है। इस तरह की पांच स्कीम चल रही हैं राज्य सरकार की लेकिन आज तक स्कीम पूरी नहीं हुई और यह पानी पीया जा रहा है माननीय मंत्रीजी।

श्री अध्यक्ष : आपका तो कोई प्रस्ताव है नहीं, केवल पानी को लेकर खड़े हो गए आप। देखिये, मौका आयेगा बजट भाषण पर बोलियेगा, पानी दिखा दीजियेगा।

श्री सुरेश मीणा : बजट भाषण, पानी पीने का मामला है अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : तो पानी दिखा दीजियेगा ना, मैं कब ना कर रही हूं, मैं आपको बोलने का..(व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : इस पानी से लोग मर रहे हैं साहब।

श्री अध्यक्ष : बोलने का मौका दूंगी।

श्री सुरेश मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर जो अधिकारी लगे हुये हैं, दस-दस साल से वह वही टिके हुये हैं, मनमानी कर रहे हैं, उनको हटाया जाए वरना यहां धरने पर बैठूंगा, तब तक बैठूंगा जब तक मांग पूरी नहीं होगी। मैं धरने पर बैठता हूं।

(माननीय सदस्य सुरेश मीणा द्वारा सदन कूप में आकर भाषणबाजी)

श्री अध्यक्ष : आपको बोलने का मौका देंगे तब आप..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आश्वासन किसका चाहिये, स्थानान्तरण का चाहिये या पानी की समस्या का? अधिकारियों के तबादले का आश्वासन चाहिये या पानी की समस्या के समाधान का, पानी की समस्या का चाहिये, ट्रान्सफर का?

श्री अमराराम (धोद) : लोगों को इतना गंदा पानी पिला रहे हो।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप पहले....

श्री अमराराम (धोद) : ऐसे अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप पहले वहां जाइये, आप अपने स्थान पर जाइये, वहां से बात करिये, आप अपने स्थान पर जाइये, वैल में आकर बोलने का आपको कोई अधिकार नहीं है।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : करौली से आने वाले ..

श्री अध्यक्ष : एक सैकण्ड, मुझे कहने दीजिये, आपने यदि पहले माननीय मंत्रीजी का ध्यान पानी के सम्बन्ध में आकर्षित किया है और उन्होंने सुना नहीं है, कार्यवाही नहीं हुई है तब तो आपका यहां सब कहना उचित है। और यदि आपने, नहीं तो पहले ही आकर आप बोतल लेकर खड़े हो गए और दिखाने लग गए। मैं समझती हूं यह परम्परा ठीक नहीं है। अब आप मंत्रीजी बोलिये।

श्री रामनारायण मीणा : मंत्रीजी, मैं एक लाइन में अर्ज करूं यह सवाल करौली का नहीं है, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह मेरे करवर में बूंदी जिले में चार दिन से धरने प्रदर्शन चल रहे हैं, पीने के पानी की...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह आप क्या बता रहे हो बूंदी की? आप उपनेता हो,क्या कर रहे हो, क्या कह रहे हो इस समय ?

श्री सांवर लाल जाट (सिंचाई मंत्री) : आप उपनेता हैं माननीय सदस्य,

(श्री सांवर लाल जाट)

आपको इस तरह से बीच में नहीं बोलना चाहिये। पानी के ऊपर पूरे दिन बहस होगी, जो भी समस्या है आप उसमें उठाइये। माननीय सदस्य अख़बार की कतरन और बोतल भरकर लाए हैं माननीय अध्यक्ष महोदय..(व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : हकीकत बात है। कमेटी बनाकर भेज दीजिये इसमें गलती हो तो, हकीकत बात बता रहा हूं, हकीकत बात बता रहा हूं, इसमें कोई डर..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप सुनो तो सही। आप मंत्रीजी को सुनें तो सही।

श्री सांवर लाल जाट : हकीकत है, क्या है थोड़ा बहुत सुनो तो सही। बात आ गई आपकी। आपने अपनी बोतल रख दी इससे ज्यादा और क्या कहना है आपको? अध्यक्ष महोदय, पीने के पानी की व्यवस्था करवाना और शुद्ध पानी उपलब्ध कराना राजस्थान सरकार की जिम्मेदारी है और जिस प्रकार की भौगोलिक स्थिति राजस्थान की है सारे सदस्य और जनता भी वाकिफ है। राजस्थान में 10 प्रतिशत हिस्सा पूरे हिन्दुस्तान का है और 1.16 सरफेस वाटर है, जो भी बरसात के ऊपर निर्भर करता है। अण्डरग्राउण्ड वाटर का लगातार डिप्लीसन हो रहा है। धरती के अन्दर जो पानी है वह खारा है या फ्लोराइड का है, वही है, बाकी सब जगह हालात बड़े गम्भीर हैं। फिर भी सरकार की तरफ से अब हमने जल अभियान भी शुरू किया है जिसमें जो उपलब्ध जल है उसका ओप्टीमम यूटिलाइजेशन करें, इस प्रकार की चेतना पैदा करें और इसके साथ ही बरसात का पानी अगर गिरता है तो उसको रोकने के लिए सरकार व्यवस्था करे जिससे भूजल ऊपर आये।

श्री अध्यक्ष : आप तो इनके प्रश्न का जवाब दे दीजिये।

श्री सांवर लाल जाट : थोड़ा बैकग्राउण्ड तो बता दूं, मान्यवर।

श्री अध्यक्ष : बैकग्राउण्ड की आवश्यकता नहीं है।

श्री सांवर लाल जाट : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य की बात से सहमति और असहमति व्यक्त नहीं कर सकता। माननीय सदस्य ने इस विधान सभा में, इस बोतल के अलावा मुझे कभी नहीं कहा कि मेरे एरिया में इतना गंदा पानी पी रहे हैं आप व्यवस्था कीजिए। अब विधान सभा चल रही है और बोतल दिखाने के लिये लाये हो तो इसमें मुझे कुछ नहीं कहना। बाकी माननीय सदस्य की जिम्मेदारी बनती है...(व्यवधान)

श्री सुरेश मीणा : मैं आपको दिखाने के लिए (व्यवधान) हकीकत बात है यह।

श्री सांवर लाल जाट : आप बैठिये, आप सुनो पूरी, आपकी जिम्मेदारी यह भी बनती है कि अगर आपकी जनता को शुद्व पानी नहीं मिलता है तो हमारे को पत्र लिखते, हमारे पास आकर बताते कि ऐसी हालत है। बाकी मैं आपको यह विश्वास दिला सकता हूं अगर इस पानी में दोष होगा और ऐसा पानी जनता पी रही होगी तो हम अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री सुरेश मीणा : मंत्री महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं एक कमेटी गठित करके आज ही वहां पर जाया जाये और इस चीज को देखा जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बोल दिया ना उन्होंने।

श्री सांवर लाल जाट : कभी आपने कहा नहीं कि हमारी जनता ऐसा पानी पी रही है, आपने आज विधान सभा में कहा तो हमें जानकारी लेने दीजिये उसके बाद अगर वास्तव में आपकी बात ठीक होगी तो हम कार्यवाही करेंगे।

श्री सुरेश मीणा : मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री ओम बिरला (कोटा) : मंत्रीजी ने जवाब दे दिया कि जांच करेंगे, ऐसा पानी जनता पी रही है तो कार्यवाही करेंगे।

श्री सुरेश मीणा : जवाब कुछ नहीं है।

श्री सांवर लाल जाट : आपके इसी विधान सभा सत्र में यह रिपोर्ट लाकर आपको बता देंगे अगर गड़बड़ी होगी तो एक्शन करके बता देंगे।

श्री सुरेश मीणा : माननीय मंत्री महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं जो अधिकारी...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्री रणवीर सिंह गुढा।

श्री सुरेश मीणा : जो अधिकारी वहां पर दस साल से बैठे हुए हैं, पाइप लाइन का जो पाइप आता है उसको बेच दिया जाता है आज तक पाइप नहीं बिछवाई गई जबकि वहां पर बोरिंग है, वहां पर जीएलआर बने हुए हैं, लेकिन पाइप लाइन नहीं बिछाई। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल जाट : अधिकारी तो 60 साल की नौकरी करते हैं जो तो कह देंगे राजस्थान से बाहर भेज दो।

श्री सुरेश मीणा : पांच-पांच साल से, दस साल से अधिकारी वहां पर बैठे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष : करौली से आने वाले माननीय सदस्य, आपने सब बता दिया उसके बाद भी आप उत्तेजित हो रहे हैं।

श्री सुरेश मीणा : नहीं अध्यक्ष महोदय, हमको चुनकर भेजा है और हम इस पानी को पिलाते हैं जनता को, हम सरकार से यह कह सकते हैं इस बात को।

श्री अध्यक्ष : तो उन्होंने आपको यह आश्वासन दिया है (व्यवधान) आपको यह आश्वासन दिया है (व्यवधान) राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री बंशीलाल खटीक : यह प्रमाणित है क्या? यह प्रमाणित करके यहां लाए हैं क्या कि यह वहां का ही पानी है? यह सरकार को बदनाम करने की साजिश है। यह सरकार को बदनाम करने की साजिश है। यह प्रमाणित है क्या कि वहां का पानी है? यह झूठा करके लेकर आये हैं। (व्यवधान) इतने दिन क्या आपकी आंख फूट गयी (व्यवधान) इतने दिन आपकी आंखें फूट गयी थी क्या, ऐसा पानी पिला रहे थे। यह प्रमाणित है क्या वहां का पानी है ? यह जांच करवा लें यह वहां का प्रमाणित पानी है क्या, यह सरकार को बदनाम करने की साजिश है। यह वहां का पानी नहीं है। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उस इलाके का पानी है ही नहीं। यह कौनसा तरीका हुआ।

श्री अध्यक्ष : राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें, स्थान ग्रहण करें।

(श्री सुरेश मीणा, सदस्य द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री जीतमल खांट : पूरे राजस्थान का ठेका ले रखा है क्या ?

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। आप कृपया स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री रामनारायण चौधरी : स्थान ग्रहण करेंगे तो वहां इनकी पिटाई हो जाएगी। फिर पिटेंगे वहां पर।

श्री मुरारी लाल मीणा : मैं आपको बताना चाहूंगा..(व्यवधान)..करौली जिला ऐसा जिला है जहां से चम्बल नदी गुजरती है।

श्री अध्यक्ष : मैंने आपका नाम तो नहीं पुकारा, मैंने बोलने के लिये आपका नाम नहीं पुकारा है। माननीय सदस्य, मैंने नाम नहीं पुकारा है।

(श्री अध्यक्ष)

(व्यवधान) करौली से आने वाले माननीय सदस्य, आपको जब यह आश्वासन दे दिया कि यदि यह पानी, आप सही होंगे तो निश्चित तौर से उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। अब आप और क्या चाहते हैं। अब आप क्या चाहते हैं।

श्री रणवीर सिंह गुढा।

(श्री मुरारी लाल मीणा, सदस्य भी धरने पर बैठे)

(दोनों माननीय सदस्यों द्वारा धरना समाप्त)

श्री सुरेश मीणा : देखो मंत्रीजी, ऐसे +++ को बीच में क्यों बोलने देते हैं। +++ को बीच में नहीं बोलने दिया कीजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह कौनसी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं आप।

श्री अध्यक्ष : राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, आप मुझे मजबूर न करें, नाम लेकर पुकारने के लिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इस भाषा का उपयोग मत कीजिए आप। इस भाषा का उपयोग मत कीजिए।

श्री बंशीलाल खटीक : सरकार को बदनाम करने पर तुले हुए हैं। आपका काम ही सरकार को बदनाम करने का है। आपका काम क्या है, सरकार को बदनाम करने पर तुले हुए हो आप लोग।

श्री अध्यक्ष : राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपको चेतावनी दे रही हूं, राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य मैं आपको चेतावनी दे रही हूं। मंत्रीजी जवाब देते हैं, आप बीच में क्यों खड़े होते हैं ? आपकी जिम्मेदारी नहीं है जवाब देने की। (व्यवधान) अब आप खामखा में उत्तेजित हो रहे हैं, अब आप भी शांत होइये। अब आप भी शांत होइये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मेरी एक प्रार्थना है, माननीय सदस्य ने उत्तेजना में राजसमन्द से आने वाले माननीय सदस्य के लिये +++ और दूसरे शब्दों का उपयोग किया, इन्हें कार्यवाही से निकलवा दीजिये।

श्री अध्यक्ष : क्या कहा ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : +++ और दूसरे शब्दों का, इन +++ का बीच में बोलना बन्द कराओ। असंसदीय शब्द जो भी हैं इनको कार्यवाही से निकलवायें।

श्री अध्यक्ष : +++ ?

श्री सुरेश मीणा : मंत्रीजी, यह हमारा पानी का मामला है, इसमें बीच में बोलने की जरुरत क्या थी, मेरे कहने का मतलब यह था बस। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : करौली से आने वाले माननीय सदस्य, करौली से आने वाले माननीय सदस्य, आपको भी ऐसी भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। मैं +++ शब्द को एक्सपंज कर रही हूं।

श्री रामनारायण मीणा : यह असंसदीय नहीं है।

श्री सुरेश मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, रोजाना पता नहीं क्या ... (व्यवधान) सबको डिस्टर्ब करते हैं ये।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, +++ असंसदीय नहीं है। +++ शब्द अनपार्लियामेंट्री नहीं है। यह असंसदीय शब्द नहीं है। +++ शब्द अनपार्लियामेंट्री नहीं है।

श्री ओ.पी. महेन्द्रा : +++ शब्द यहां पर अनपार्लियामेंट्री है। (व्यवधान) +++ शब्द यहां पर अनपार्लियामेंट्री है। असंसदीय है यहां इस सम्बन्ध में। (व्यवधान) +++ शब्द कभी भी संसदीय नहीं हो सकता है।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, +++ शब्द कोई अनपार्लियामेंट्री नहीं है। (व्यवधान) +++ शब्द अनपार्लियामेंट्री नहीं है। +++ शब्द कोई अनपार्लियामेंट्री नहीं है। आपको सदस्य को रोकना चाहिए था, वह काम तो कर नहीं रहे हैं आप।

श्री जोगाराम पटेल : जिस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है, उस परिप्रेक्ष्य में असंसदीय है। +++ शब्द हो सकता है संसदीय हो पर उसका सेंस असंसदीय हो रहा है।

श्री सांवर लाल जाट : माननीय सदस्य के लिये +++ बोलना उचित मानते हो क्या ?

श्री बंशीलाल खटीक : +++ शब्द एक अभिशाप है, +++ शब्द एक अभिशाप है, +++ शब्द कभी भी संसदीय नहीं हो सकता है।

श्री अध्यक्ष : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, मैं आपको सूचित करना चाहूंगी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगी कि यदि कोई शब्द अनपार्लियामेंट्री नहीं भी हो तो भी यह आसन उसे एक्सपंज कर सकता है।

डा. सी.पी. जोशी : मानते हैं, आपकी बात से सहमत हैं, पर

(डा. सी. पी. जोश)

अनपार्लियामेंट्री के नाम पर आप नहीं कर सकते हैं। आपको यह अधिकार है पूरी की पूरी प्रोसीडिंग को बाहर निकाल दें ना आप। यह आपको अधिकार है परन्तु अनपार्लियामेंट्री के नाम पर नहीं निकाल सकते हैं। यह आपको अधिकार है, आप पूरी प्रोसीडिंग को बाहर निकाल दें, आपको अधिकार है। लेकिन अनपार्लियामेंट्री के नाम पर नहीं निकाल सकते हैं आप।

श्री जोगाराम पटेल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस परिप्रेक्ष्य में इस शब्द का प्रयोग किया गया था...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, जिस रूप में आप इस शब्द को पढ़ रहे हो नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य, यदि हर सदस्य के लिये +++ शब्द का इस्तेमाल होगा तो मत कहना आप।

श्री जोगाराम पटेल : जिस भावना से कहा गया है इसलिये वह असंसदीय शब्द बन जाता है (व्यवधान) सभी माननीय सदस्य स्वतंत्र हैं।

श्री सुरेश मीणा : मंत्रीजी, हमें इतना सा आश्वासन दे दें 10 साल से जो भ्रष्टाचारी अधिकारी वहां लगे हुए हैं उनको तुरन्त प्रभाव से हटाया जाए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये तो ट्रांसफर का तय करके आये हैं।

श्री जोगाराम पटेल : ट्रांसफर करवाने की साजिश है और कुछ नहीं है।

श्री सांवर लाल जाट : आप विराजो तो सही, मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने इतना आश्वासन दे दिया उसके बावजूद आप अभी के अभी सस्पेंड करवाना चाह रहे हो क्या, मैं कह रहा हूं कि जांच हो जायेगी इसी सत्र के अन्दर आपको सारी स्थिति से अवगत करा देंगे। इतना स्पष्ट कहने के बावजूद भी अगर आप संतुष्ट नहीं हो तो क्या इलाज है।

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहें। आप बोलिये।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

श्री रणवीर सिंह गुढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने एक संगीन विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री अध्यक्ष : बात कह दो अपनी, धन्यवाद तो कर दो, बात कह दें।

श्री रणवीर सिंह गुढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मंत्रीजी से यह पूछना चाहता हूं कि क्या जोधपुर के एडवोकेट सुरेश शर्मा हत्याकाण्ड के अन्दर एफ.आई.आर. के अन्दर दर्ज व्यक्तियों से

(श्री रणवीर सिंह गुढा)

पूछताछ की गयी, छानबीन की गयी। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो एडवोकेट सुरेश शर्मा जोधपुर के एडवोकेट, जिनकी हत्या हुई थी उनकी जमीन थी 102 बीघा, उस जमीन के ऊपर शुरू से लेकर आज तक मालिकाना हक कब्जा और नाम एडवोकेट सुरेश शर्मा का था और उसके विश्वास पात्र रिश्तेदार पृथ्वीराज पुत्र सूरजमल जो कि हरियाणा में रहता है वह सुरेश शर्मा के पिताजी के काम करते थे, उनके नाम कुछ जमीन थी । मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, उसमें हमारे मंत्री महोदय, नाम नहीं लेना चाहूंगा, उन्होंने 50 बीघा जमीन अपने नाम नामान्तरण करवाकर...

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी का नाम लेने के लिये 273 में नोटिस देना पड़ेगा।

श्री रणवीर सिंह गुढा : मैं नाम नहीं ले रहा हूं। हमारे मंत्रीजी हैं, उन्होंने अपने नाम से, अपनी दो बेटियों के नाम से हिमानी और चांदनी पूनिया के नाम से 50 बीघा जमीन अपने नाम करवाई।

श्री अध्यक्ष : अब आपने पूनिया कहकर बात तो स्पष्ट कर ही दी। अब देखिये, पूनिया कहकर बात आपने स्पष्ट कर दी। 273 का नोटिस दिया हुआ नहीं है। बात गलत है आपकी एक तरह से। आप 273 का नोटिस देकर उठाते।

श्री रणवीर सिंह गुढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, 2004 में...(व्यवधान) अपराध जगत से जुड़ा हुआ मामला है, हत्या का मामला है और 2 साल पहले 2004 में एडवोकेट सुरेश शर्मा ने अपनी निजी डायरी में लिखा है कि उनको उनकी जान को खतरा है। उनके पास में, यह निजी डायरी की फोटो कापी मेरे पास में है। उनके पास में फोन आया कि यू.पी. के शूटरों को बुलाकर उनकी हत्या करवाई जा सकती है, अगर वह जमीन के रास्ते में से, मंत्री के बीच में से नहीं हटेंगे तो। 23 तारीख को सुरेश शर्मा को बुलाया। 23 तारीख को सुरेश शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट उनके पुत्र ने दर्ज करवाई नवनीत शर्मा ने। माननीय अध्यक्ष महोदय, नवनीत शर्मा ने साफ-साफ लिखा है कि मेरे पापा को जो बुलाया गया है मुझे पूरी शंका है कि मेरे पापा की हत्या कर दी गयी है या उनके साथ में कोई अनहोनी घटना घट सकती है। और रिपोर्ट में साफ-साफ विजय पूनिया का नाम लिखा गया है, अध्यक्ष महोदय, जो एक मंत्री के पुत्र हैं। शाम को उनकी हत्या हो गयी। (व्यवधान) शाम को उनकी हत्या हो

(श्री रणवीर सिंह गुढा)

गयी और 24 तारीख को, अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, संगीन मामला है, इतना संगीन मामला है।

एक माननीय सदस्य : ये गम्भीर आरोप लगा रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या बात हुई, कोई नियम नहीं है। कोई भी आरोप लगा दे, यह क्या बात हुई अध्यक्ष महोदय ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। अंकित नहीं हो। (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा : x x x

श्री राजेन्द्र राठौड़ : x x x

श्रीमती उषा पूनिया : x x x

श्री ओम बिड़ला : x x x

श्री अध्यक्ष : अब आपका स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) अब अरन गृह मंत्रीजी को दे दें जो कुछ देना है। आपको जो कुछ देना है, गृह मंत्रीजी को दे दें आप। अब आपका समय खतम हुआ, अब आपका समय समाप्त हुआ।

श्री रणवीर सिंह गुढा : x x x

श्रीमती उषा पूनिया : यह बातें आप बाहर करिये, आप पर मानहानि का दावा मैं करूंगी।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो, अंकित नहीं हो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : x x x

श्री रणवीर सिंह गुढा : x x x

श्री अध्यक्ष : अब आप गृह मंत्री की बात सुनें। आपका तो अंकित नहीं हो रहा है। आपका अंकित नहीं हो रहा है। आप गृह मंत्रीजी को सुनिये। आपका समय समाप्त हुआ। मैंने केवल दो मिनट का समय दिया था आपको। आप ऊटपटांग बात बोल रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : अध्यक्ष महोदय यह सही है कि 22 तारीख की रात को सुरेश शर्मा की हत्या हुई। 23 तारीख को सवेरे एफ.आई.आर. लिखायी गयी और 27 तारीख को हमने तीन मुल्जिम जो इस घटना में, क्योंकि उनके घर के पास खून के छींटे देखे और उसके आधार पर पहुंचे कि उसमें एक हेमलता सोनी जो उसमें मुल्जिम थी, उसको हमने पकड़

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लिया। उसके बाद उसके पति और एक और नरपत सिंह को और भंवर सिंह को, उनको तीन को तो हमने 27 तारीख को ही गिरफ्तार कर लिया जो अभी भी जे.सी. में है। और उनसे पूछताछ से यह चार लोगों के नाम और निकल कर आये जो हेमलता के पीहर पक्ष के भाई और उनके लड़के हैं। जिसमें धनेश, बादल, जावेद और सतीश है। यह चार लोग आये। उनको भी जिस होटल में यह रुके इसके पहले भी एक अटेम्पट किया था और यह लोग उस होटल में रुके उसका रिकार्ड पहले का भी मिला और उस समय यह काम नहीं कर पाये। उसके बाद दूसरी तारीख को जब यह घटना हुई तो उनको आइडेंटिफाई किया और उस होटल में यह चार लोग भी रुके। यह सात लोग उसमें मुल्जिम हैं। एफ.आई.आर. में किसी का नाम नहीं था। यह तो ढूंढते-ढूंढते इस घटना से ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पहले बैठिये आप। सुनिये आप कि क्या कह रहे हैं यह। रोज बोल देते हो मर्जी आये सो ... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : तफ्तीश जैसे-जैसे आगे बढ़ी उसके आधार पर इसमें नाम निकलकर आये हैं। आप जो आरोप लगा रहे हैं, अभी तक कि मेरी जांच से इस प्रकार की कोई बात नहीं निकली है। मैं आपको यह यकीन दिलाता हूं कि इसमें किसी को भी संदेह नहीं रहना चाहिए कि हमने किसी भी प्रकार, अगर और मुल्जिम हो उसको छोड़ने की मंशा हो, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। और इसलिए इसके बाद भी जब वहां के लोगों ने कहा कि हमें तफ्तीश में संदेह है तो मैंने सी.आई.डी. को कल ही फाईल ट्रांसफर की है। कहीं पर भी आपको संदेह करने का कोई कारण नहीं होगा अगर मुल्जिम होगा तो ही मैं मुल्जिम बनाऊंगा। जबरदस्ती कोई प्रेशर से किसी को मुल्जिम बनाना चाहे तो यह मेरा धर्म नहीं कहता है कि मैं उसको कोई जबरदस्ती मुल्जिम बनाऊं।

मैं सदन को आश्वस्त कर रहा हूं कि सही जांच करके कहीं पर भी कोई संदेह का कोई कारण नहीं होगा। अगर किसी प्रकार की घटना में से निकल कर आये। अभी जैसे चार लोगों को हमें जो फरार हैं, उनको पकड़ने के बाद और कोई नयी बात उसमें से निकलेगी तो उसके बाद ही आगे बढ़ा जा सकता है। इतना मैं कहना चाहता हूं। ... (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा : x x x

श्रीमती उषा पूनिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष : प्रश्न पूछने की इजाजत नहीं है। नहीं-नहीं, नो-नो बिलकुल इजाजत नहीं है। कतई नहीं है। नो-नो। अंकित नहीं हो, कुछ नहीं। आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रणवीर सिंह गुढा : x x x

श्री राजेन्द्र राठौड़ : x x x

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री सांवर लाल जाट : x x x

श्री अध्यक्ष : आपके पास कोई कागज है तो दे दीजिए ... (व्यवधान) आपके पास कोई कागज है तो गृह मंत्री को दे दीजिए। आप गृह मंत्री को कागज दे दीजिए। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री रणवीर सिंह गुढा : x x x

श्री अध्यक्ष : मुझे आप मजबूर नहीं करें। गुढा से आने वाले माननीय सदस्य, आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। मैं निवेदन कर रही हूं कि आप मुझे मजबूर नहीं करें। मैं आपसे कह रही हूं कि अंकित नहीं हो रहा है। मैं आपसे कह रही हूं कि आप सदन छोड़कर चले जाएं। ... (व्यवधान)

श्री रणवीर सिंह गुढा : x x x

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। ... (व्यवधान)

श्रीमती उषा पूनिया : I am on an explanation.

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप स्थान ग्रहण करें, नहीं तो सदन छोड़कर चले जाएं। मुझे आप मजबूर कर रहे हैं। आप मुझे मजबूर कर रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री रणवीर सिंह गुढा : x x x

श्री अध्यक्ष : आप मुझे मजबूर कर रहे हैं। सार्जेण्ट एट आर्म्स। अंकित कुछ नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है। आप धींगामस्ती नहीं

(श्री अध्यक्ष)

करें। ... (व्यवधान) सार्जेण्ट एट आर्म्स, इनको बाहर करो। नहीं, करो-करो। ऐसे नहीं मानेंगे यह।

(श्री रणवीर सिंह गुढा, माननीय सदस्य को मार्शल द्वारा सदन से बाहर ले जाया गया)

श्री बहादुर सिंह गोदारा (नोहर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे से गलत दस्तखत करवाये गये हैं। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपके लिए तो मैंने कब कहा ? दो ही तो सदस्यों का नाम लिया है मैंने। आपका तो लिया नहीं मैंने।

श्रीमती उषा पूनिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो आरोप लगा रहे हैं, यह निराधार है। इनमें कोई लेना-देना नहीं है। उसकी कार्यवाही हो रही है और जो सारा केस है वह सामने आ जाएगा। दोषी पाये जाएंगे तब मैं देखती हूं। मैं तो चाहूंगी, फिर मैं देखती हूं कि इन पर क्या लिया जाएगा? यह झूठा है बिलकुल केस। इसका कोई आधार ही नहीं है। इसके बारे में हमारे को न कोई जानकारी है, न इसका कोई आधार है। यह बिलकुल झूठा साबित होगा जब मैं देखूंगी कि अपने माननीय सदस्य को क्या सज़ा दी जाती है ?

श्री अध्यक्ष : ठीक है। श्री जुबेर खान।

श्री जुबेर खान (रामगढ़) : सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से बड़ी शालीनता से निवेदन करना चाहूंगा कि जयपुर में स्थित... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दो मिनट में।

श्री जुबेर खान : हां। गलता पीठ जयपुर में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण भारत के लोगों के लिए प्रमुख तीर्थ स्थल है। इस गलता पीठ की स्थापना सन् 1960 में श्री कृष्णदास पयोहारीजी महाराज द्वारा की गयी थी जो इसके सबसे पहले महंत बने, और इसको तत्कालीन महाराजा सवाई मानसिंहजी ने और उसके बाद राज्य सरकार ने मान्यता दी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि 15 फरवरी, 2006 को महंत आदरणीय रामोदाराचार्यजी ब्रह्मलीन हो गये और उनके अन्तिम संस्कार के बाद जो कार्यक्रम होते हैं, नवें दिन, सुबह साढ़े पांच बजे के लगभग प्रातः, जब नवें दिन के कार्यक्रम उनके परिवार द्वारा वहां निवास स्थान पर कर रहे थे, तो कुछ साधु-संत के वेश में जो लोग गये, उनके साथ

(श्री जुबेर खान)

में कुछ ऐसे कार्यकर्ता गये जिन्होंने पुलिस के संरक्षण में जहां वहां पर अन्तिम कार्यक्रम की रश्में पूरी की जा रही थीं, सुबह साढ़े पांच बजे ही जाकर जिस तरह से हमला किया और पुलिस के संरक्षण में किया, यह अत्यन्त दु:ख की बात है।

एक निवेदन मैं और करना चाहूंगा कि चूंकि 2004 में माननीय उच्च न्यायालय ने उसमें स्थगन आदेश दिये हुए हैं कि जब तक न्यायालय कोई फैसला नहीं कर देगा, गलता पीठ में यथास्थिति रहेगी। जो महंत साहब थे वह रहेंगे और उनके क्रियाकर्म के बाद उनके ज्येष्ठ पुत्र महंत अवधेश कुमारजी को उनकी जगह गद्दीनसीन होना था। उसके पहले ही जिस तरह से वहां पर कुछ लोगों द्वारा आतंक फैलाया गया। मेरा आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी सत्ता के लोगों द्वारा जुड़े हुए, जिस तरह गलता महाराज की पीठ को हथियाने की कोशिश की जा रही है, असंवैधानिक तरीके से, गैर-कानूनी तरीके से, गैर-धार्मिक तरीके से, यह सरासर अन्याय है। मैं आपके माध्यम से यह चाहता हूं कि सरकार इसको स्पष्ट करे कि सरकार इसके ऊपर, आज वातावरण क्या है, माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां पर पुलिस की छावनी बनी हुई है। ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप क्या चाहते हैं ? आप चाहते क्या हैं ?

श्री जुबेर खान : श्रद्धालु जो नहीं जा पा रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह सब तो आपने कह दिया।

श्री जुबेर खान : मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि सरकार इसके ऊपर, सरकार इस गलता पीठ को बचाना चाहती है या अपने बलबूते पर कब्जा करना चाहती है ? मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने केवल आपको ... (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत : आपसी विवाद को इस पवित्र सदन में नहीं उठाया जाना चाहिए। यह पवित्र सदन है।

श्री अध्यक्ष : श्री बाबूलाल नागर। केवल दो मिनट में ही अपनी बात कहेंगे, मैं तीसरी मिनट नहीं दूंगी आपको।

श्री मोहन लाल गुप्ता : जो भी विवाद है सरकार ने उसके बारे में पूर्णतया न्यायिक दृष्टिकोण अपनाकर ही काम किया है। माननीय सदस्य, यहां

(श्री मोहन लाल गुप्ता)

तथ्यों को गलत रूप से प्रस्तुत कर रहे हैं। अभी वर्तमान में जो पीठ है वह उसको पब्लिक ट्रस्ट नहीं कर रही है, वह फैमिली ट्रस्ट बना रखा है, उसको आप इजाजत देंगे कि गलता को फैमिली ट्रस्ट बना दिया जाए ? फैमिली ट्रस्ट कर रखा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैंने परमिशन ली है, दो मिनट में अपनी बात कह दूंगा।

श्री अध्यक्ष : आपने पर्ची थोड़े ही दी है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : बहुत पब्लिक इंटरेस्ट का इश्यू है।

श्री अध्यक्ष : आप जब भाषण दें तो उसमें इसका भी जिक्र कर दीजियेगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ठीक है।

श्री अध्यक्ष : बाबूलाल नागर।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू) : अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सहकारिता मंत्रीजी का मैं ध्यान आकर्षित करना चाह रहा हूं। दूदू विधान सभा क्षेत्र में हमेशा वर्षा का अभाव रहता है। वहां की मुख्य फसल सरसों है और क्रय-विक्रय सहकारी समिति...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : अब आप भूमिका बांध रहे हो, इस पर आ जाओ आप। आप भूमिका मत बांधो। हां, बस आ जाओ अपनी बात पर।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि सरसों समर्थन मूल्य खरीद केन्द्र सरकार वहां पर खोलती है जहां पर सरसों की पैदावार हो और कृषि उपज मण्डी यार्ड हो, वहां गोदाम हो।

श्री अध्यक्ष : आप सीधी अपनी बात कहो कि दूदू में भी खोल दिया जाये, बस खतम बात। यह कह दें आप बस। हां, यही कह दें।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन करना चाह रहा हूं आप सही फरमा रही हैं कि दूदू में खोल दिया जाये। एक चीज आपके ध्यान में लाना चाहता हूं। अध्यक्ष महोदय, अभी 2005-06 में सांभर हमारे पास में सरसों खरीद केन्द्र है उसमें 60 हजार....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सीधी सी बात है कि आपने लिखकर दिया दूदू में सरसों समर्थन मूल्य खरीद केन्द्र खोलना, इतनी-सी बात है।

श्री बाबूलाल नागर : अध्यक्ष महोदय, मैं तो नहीं बोलूंगा, चलो मेरा काम हो जाना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : बस ठीक है, हो जायेगा।

श्री बाबूलाल नागर : बिलकुल मेरा काम हो जाना चाहिये। मंत्रीजी बोल तो दो।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी ने सुन लिया, ध्यान रखेंगे। मंत्रीजी ध्यान रखियेगा। मंत्रीजी ध्यान रखिये। अब बिराजिये। अब पर्ची पर बोलेंगे। श्री कालीचरण जी। कालीचरण जी, केवल चार मिनट का समय है। आप तो बोल चुके हैं लेकिन और माननीय सदस्यों को वाद-विवाद में अपना हिस्सा लेना है इसलिये आप चार मिनट में अपनी बात कह दें।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट में एक बात कहना चाहूंगा, माननीय मंत्रीजी सरसों की खरीद नहीं हो रही है। किसान परेशान है। मैं आसन से आग्रह करूंगा कि इस बारे में सरकार नोटिस ले और सरसों एक क्विंटल भी नहीं खरीदी जा रही है। मोइश्चर के नाम पर किसानों को वापस भेजा जा रहा है। किसान इतने परेशान हैं कि बिचौलियों को सरसों बेचनी पड़ रही है। सरकार इस बारे में ध्यान दे और किसानों का हित साधन करे।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

श्री अध्यक्ष : न पर्ची है, न बात, आप खड़े हो गये यूं ही। बोलिये कालीचरणजी।

राजस्थान में अकाल की स्थिति विषयक

श्री कालीचरण सराफ (जौहरी बाजार) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से राजस्थान में जो अकाल की स्थिति है और उसमें केन्द्रीय सरकार सहायता करने में जो कोताही बरती जा रही है। राजनीतिक भेदभाव के आधार पर पर्याप्त सहायता नहीं कर रही है उसके बारे में आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय राजस्थान की भौगोलिक स्थिति इस प्रकार की है कि यहां हर वर्ष कहीं न कहीं अकाल की स्थिति रहती है। कभी पूरे राजस्थान प्रदेश में अकाल की स्थिति रहती है, कभी कई जिलों में अकाल की स्थिति रहती है। इस वर्ष भी गिरदावरी की रिपोर्ट के आधार पर 22 जिलों में 15,778 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया है। राजस्थान सरकार

(श्री कालीचरण सराफ)

ने 1 जनवरी, 2006 से अकाल राहत के काम अभावग्रस्त क्षेत्रों में प्रारम्भ कर दिये हैं। चारा डिपो भी लगभग 265 स्थानों पर खोल दिये हैं। 50 हजार रुपये की राशि चारा डिपो को ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रदान भी कर दी गयी है। भारत सरकार को 26 दिसम्बर को ज्ञापन भी प्रस्तुत कर दिया गया। 1464.25 करोड़ रुपये का 15.86 लाख मीट्रिक टन गेहूं की मांग भी उसमें शामिल की गयी है। भारत सरकार का अध्ययन दल आ गया। उसने विस्तृत रिपोर्ट भी दे दी परन्तु मुझे कहते हुए अफसोस है कि अकाल की इतनी भीषण विकरालता को देखते हुए अभी तक भारत सरकार ने केवल 146.5 करोड़ रुपये की राशि आबंटित की है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि जब यहां कांग्रेस की सरकार थी और केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, बिना किसी राजनैतिक भेदभाव के केन्द्र की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब यहां भीषण अकाल की स्थिति थी तो खुले हाथों से यहां पर सहायता दी थी। मैं बताना चाहूंगा कि बीजेपी सरकार ने 946.82 करोड़ रुपये राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक निधि और 32.5 लाख मीट्रिक टन गेहूं की मदद उस समय की थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा इस सदन के माध्यम से केन्द्रीय सरकार को कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति को देखे और यहां जिस प्रकार की अकाल की स्थिति बनती जा रही है। और अभी जब यह स्थिति है तो आने वाले दिनों में- अप्रैल, मई और जून में और ज्यादा यहां स्थिति बिगड़ने वाली है। तो केन्द्रीय सरकार इसमें उदारता के साथ बिना किसी भेदभाव के अकाल राहत के कामों के बारे में राशि आबंटित करे और गेहूं भी आबंटित करे। मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहता हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : पहले राजस्थान सरकार तो न्याय करे। कई तहसीलें और कई जिले, जहां अकाल की स्थिति है, राजस्थान सरकार जान-बूझकर, पक्षपात कर वहां अकाल घोषित नहीं करती और यह केन्द्र की बात करते हैं। पहले अपना अन्याय तो सुधारो जो आपने हमारे साथ किया है।

श्री कालीचरण सराफ : कोई जगह ऐसी नहीं है जहां अकाल राहत कार्य प्रारम्भ नहीं किया हो। परन्तु केन्द्रीय सरकार राजनैतिक भेदभाव के आधार पर गेहूं और राशि आबंटित नहीं कर रही है।

श्री श्रवण कुमार : झुन्झुनूं जिला अकाल से पीड़ित है। माननीय अध्यक्ष महोदय झुन्झुनूं जिले में जाकर आईं, इनसे पूछो। माननीय अध्यक्ष महोदय दौरा करके आई हैं, लोग पानी के लिये तरस रहे हैं, भूख से तड़प रहे हैं और कह रहे हैं कि कोई पीड़ित नहीं है।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री श्रवण कुमार : x x x

श्री अध्यक्ष : जो मेरी बिना अनुमति के बोलते हों, उनका बिलकुल अंकित नहीं किया जाये।

श्री श्रवण कुमार : x x x

श्री अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : आप अवसर दें, दो शब्द कह दूं।

श्री अध्यक्ष : हां, आप दो शब्द कह दें।

श्री प्रद्युम्न सिंह : राज्य सरकार के पास 540 करोड़ रुपया अकाल के पेटे बचा हुआ है एन.सी.सी.एफ. के तहत, पहले उस पैसे को तो खर्च कर लें और उसके उपरान्त ट्वेल्थ फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट के बाद एक अप्रैल से राज्य सरकार 313 करोड़ रुपया नैक्स्ट फाइनेंशन ईयर में मिलेगा, उसके अन्दर 25 प्रतिशत राज्य सरकार का बजट का हिस्सा होगा।

श्री अध्यक्ष : आप बजट पर बोल लेना। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर नहीं बोला क्या ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुझे कह लेने दीजिये क्योंकि अनर्गल बात सदन के अन्दर आई है। रिकार्ड सही हो जाये, 373 करोड़ रुपये वह और 540 करोड़ रुपये वह इनको मिलाकर 920 के करीब होता है उस पैसे को राज्य सरकार खर्च नहीं कर रही है और यहां पर अनर्गल आरोप केन्द्रीय सरकार के ऊपर लगाये जा रहे हैं। यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य मंत्री) : अकाल के बारे में प्रद्युम्न सिंहजी ने जो बात कही उसके बारे में सदन में स्थिति स्पष्ट करना चाहूंगा। राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य ने जो कहा है इतनी राशि राज्य सरकार के पास नहीं है। हमको दिसम्बर में 146 करोड़ रुपये जो सीआरएफ का देना था वह पैसा आपकी केन्द्र सरकार ने नहीं दिया है। आप चाहो तो मैं सदन के पटल पर रख दूं। हमने मांग रख दी है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपके पास 540 करोड़ बचा है या नहीं पुराने अकेले के पेटे और सालों का, वह आप बता दीजिये।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : हमारे पास 540 करोड़ रूपया नहीं बचा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह आप गलत कह रहे हैं। आपके पास 540 करोड़ बचा है। आप बार-बार केन्द्र सरकार से कह रहे हैं कि उस 540 करोड़ रुपये को जो बचा हुआ है उसको प्लेन्ड एक्सपेंडिचर में काउंट किया जाये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह काम आपने नहीं किया था क्या?

डा. सी.पी. जोशी : हमने किया था।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री अध्यक्ष : अब अंकित हो।

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे 860 करोड़, 500...

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री अध्यक्ष : आप बिना आसन की अनुमति के बोलने लग जाते हैं, सी.पी. जोशी साहब।

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री महीपाल यादव (बानसूर): x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन: x x x

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री अध्यक्ष : आप इस तरह का आरोप लगाते हैं आसन के ऊपर, मैंने जब राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य खड़े हुए, मैंने उनको अनुमति दी बोलने के लिए। ...(व्यवधान) आप रोज ही आक्षेप...(व्यवधान)

(श्री अध्यक्ष ने इशारे से अंकित नहीं करने के निर्देश दिये)

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

डा. बुलाकीदास कल्ला : x x x...(भारी व्यवधान)...

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' : x x x

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : x x x

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' : x x x

डा. किरोड़ी लाल मीणा : माननीय सदस्य, आप विराजो।

श्री श्रवण कुमार : x x x

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' : x x x

श्री रामनारायण मीणा : x x x

श्री श्रवण कुमार : x x x

श्री ओम बिरला : x x x

श्री हरिमोहन शर्मा : x x x

श्री कन्हैया लाल मीणा (बस्सी) : x x x

श्री श्रवण कुमार : x x x

श्री अध्यक्ष : जो भी माननीय सदस्य मेरी बिना अनुमति के बोलते हैं वह अंकित तो हो नहीं रहा है इसलिए, माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें तो उचित रहेगा। मोहम्मद माहिर आजाद।

श्री श्रवण कुमार : x x x

श्री रामचन्द्र जारोड़ा (मेड़ता) : x x x

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद, बोलना प्रारम्भ करें, यह तो यों ही बोलते रहेंगे। बोलना प्रारम्भ करें। ...(व्यवधान)...

श्री बाबूलाल नागर : x x x

श्री कन्हैया लाल मीणा : x x x

श्री रामचन्द्र जारोड़ा : x x x

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपस में तर्क-वितर्क नहीं करें, आपस में सवाल-जवाब नहीं करें। मैं जिसका नाम पुकारूंगी केवल उसी का अंकित होगा इसलिए आप खामखा में खड़े होकर के अपनी शक्ति को यों ही व्यर्थ गंवा रहे हैं।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा : x x x

श्री अध्यक्ष : मैंने नाम नहीं पुकारा आपका, आपका कोई विषय भी नहीं है।

श्री रामचन्द्र जारोड़ा : x x x

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन कर रहा हूं...

डा. किरोड़ी लाल मीणा : मैं मेरा उत्तर तो पूरा कर लूं।

श्री अध्यक्ष : आप क्या कहना चाहते हैं? बात तो हो गयी।

मोहम्मद माहिर आजाद : अब क्या करें, साहब, जब मंत्री ही नहीं आपके आदेश की पालना करते हैं...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा : मेरे पर चार्जेज लगा दिये ...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, मंत्री ही आपके आदेश की पालना नहीं करें, मैं बोलने के लिए खड़ा हो गया फिर यह खड़े हो जाते हैं। अब इनका अंकित कराओगे आप ...(व्यवधान)

अब अंकित तो मेरा होगा, माननीय खाद्य मंत्रीजी।

श्री महीपाल यादव : x x x

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें।

यदि कोई विधान सभा में इस तरह का प्रश्न उठाया गया है जिसकी तरफ से सरकार को जवाब देना आवश्यक हो तो मंत्री उठ कर के अपनी सूचना दे सकते हैं। ...(भारी व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : जब सहकारिता मंत्रीजी खड़े हुए थे श्रीबाबूलाल नागर का जवाब देने के लिए तब आपने उनको बैठा दिया। जब बाबूलालजी नागर का जवाब देना चाहते थे माननीय मदन दिलावरजी... (व्यवधान)... मदन दिलावरजी खड़े हुए थे बाबूलालजी नागर का जवाब देने तब उनको बैठा दिया था और इनको खड़ा कर दिया। ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : x x x

श्री महीपाल यादव : x x x

श्री बाबूलाल नागर : x x x

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' : x x x

डा. किरोड़ी लाल मीणा : अब हमारी बात सुन लो। मेरी बात सुन लो।

श्री बाबूलाल नागर : x x x

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री बाबूलाल नागर : x x x

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' : x x x

श्री महीपाल यादव : x x x

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण कर लें तो उचित रहेगा। स्थान ग्रहण करें। आप स्थान ग्रहण कर लें।

श्री हेमाराम चौधरी (गुढामालानी) : x x x

श्री अध्यक्ष : यह अकाल पर चर्चा नहीं हो रही थी यह चर्चा भारत सरकार से जो अनाज मिलना चाहिए उसकी चर्चा हो रही है। ..(व्यवधान)... इस पर जवाब दे रहे हैं।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय।

श्री हेमाराम चौधरी : x x x

श्री अध्यक्ष : वह आपको मौका मिलेगा धन्यवाद प्रस्ताव पर जब आप बोलें, तब यह सब बातें कहियेगा आप। आपको मौका जब मिले धन्यवाद प्रस्ताव पर उस समय बात कहियेगा आप यह सब।

श्री हेमाराम चौधरी : x x x

डा. किरोड़ी लाल मीणा : गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य 2059 के अकाल में...

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी, आपको कुछ कहना है तो कहिए वरना मैंने नाम लिया है

श्री श्रवण कुमार : x x x

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : x x x

श्री श्रवण कुमार : x x x

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य, कोई इस समय पाइंट आफ आर्डर नहीं होता है। यह जीरो आवर है इस समय कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं होता। आप स्थान ग्रहण करें..(व्यवधान) आप प्लीज स्थान ग्रहण करें।

श्री हेमाराम चौधरी : x x x

श्री महीपाल यादव : x x x

डा. किरोड़ी लाल मीणा : मैं जवाब तो दूंगा ही।

श्री महीपाल यादव : x x x

श्री अध्यक्ष : आप हर समय इर्रेलेवेण्ट बात करते हैं।

श्री श्रवण कुमार : x x x

श्री महीपाल यादव : x x x

श्री अध्यक्ष : आपको जवाब देना हो तो दीजिए वरना मैं दूसरा नाम पुकार रही हूं।

श्री महीपाल यादव : x x x

श्री हेमाराम चौधरी : x x x

श्री अध्यक्ष : बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें (व्यवधान) आपको बहुत नम्र शब्दों में कह रही हूं स्थान ग्रहण कर लीजिए। बानसूर से आने वाले माननीय सदस्य कुछ अंकित नहीं हो रहा है आप ख्वाम ख्वाह में खड़े हैं।

श्री महीपाल यादव : x x x

श्री नन्दलाल बंशीवाल : x x x

डा. किरोड़ी लाल मीणा : आप विराज जाओ थोड़ी देर। अध्यक्ष महोदय, मैं शार्ट में दो मिनट में निपटाऊंगा। हमने भारत सरकार को...

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : x x x

श्री अध्यक्ष : खारची से आने वाले माननीय सदस्य...(व्यवधान) गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य...

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : x x x

श्री हेमाराम चौधरी : x x x

श्री अध्यक्ष : मेरे बात समझ में नहीं आ रही है गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य को क्या हो गया।

श्री हेमाराम चौधरी : x x x

श्री श्रवण कुमार : x x x

श्री राजेन्द्र राठौड़ : x x x

श्री श्रवण कुमार : x x x

श्री बाबूलाल नागर : x x x

श्री हेमाराम चौधरी : x x x

श्री राजेन्द्र राठौड़ : x x x

श्री श्रवण कुमार : x x x

श्री रामचन्द्र जारोड़ा : x x x

श्री अध्यक्ष : मैं नेता प्रतिपक्ष से निवेदन करना चाहूंगी कि वह अपनी पार्टी के इन सदस्यों को थोड़ा नियंत्रण में रखें। मैं देख रही हूं जब यह कहा जा रहा है कि अंकित नहीं हो रहा है उसके बावजूद भी दो-दो, तीन-तीन खड़े होकर ऐसे बोलने लग जाते हैं। यह कहने के बावजूद कि अंकित नहीं हो रहा है। आप क्या चाहते हो, सदन को चलाना चाहते हो कि नहीं चलाना चाहते हो ?

श्री श्रवण कुमार : x x x

श्री अध्यक्ष : मैंने कहा आप बैठ जाइये, स्थान ग्रहण करें...(व्यवधान) स्थान ग्रहण कर लें। आपका भी इरादा मुझे आज बाहर जाने का दिखता है।

श्री हेमाराम चौधरी : x x x

श्री अध्यक्ष : गुढामालानी से आने वाले माननीय सदस्य...

डा. किरोड़ी लाल मीणा : एक भी पशु नहीं मरा। एक भी पशु मर जाए तो मैं इस्तीफा दे दूं। एक भी पशु नहीं मरा। कोई पलायन नहीं हो रहा, गलत बोल रहे हैं एक पैसा नहीं दिया केन्द्र ने।

डा. बुलाकीदास कल्ला : x x x

डा. किरोड़ी लाल मीणा : गलत बोल रहे हो एक पशु नहीं मरा ..(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : x x x

श्री मदन राठौड़ : x x x

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल : x x x

श्री अशोक : x x x

डा. किरोड़ी लाल मीणा : आप जवाब दो मेरे इस सवाल का, हमने स्टेट प्लान में पचास करोड़ का प्रावधान रखा, कांग्रेस ने आज तक ऐसा प्रावधान नहीं रखा...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : x x x

श्री हेमाराम चौधरी : x x x

डा. किरोड़ी लाल मीणा : 16.86 लाख मीट्रिक टन गेहूं मांगा है जो दो लाख मीट्रिक टन गेहूं मिला है जो ऊंट के मुंह में जीरा डाला है आपने।

डा. बुलाकीदास कल्ला : x x x

डा. किरोड़ी लाल मीणा : साढ़े चार लाख मजदूर चयनित कर रखे हैं। मैं काम खोलना बताऊं..

डा. बुलाकीदास कल्ला : x x x

डा. किरोड़ी लाल मीणा : साढ़े चार लाख मजदूर दे रखे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : x x x

श्री मदन राठौड़ : x x x

श्री अशोक : x x x

श्री श्रवण कुमार : x x x

श्री बाबूलाल नागर : x x x

श्रीमती राजकुमारी शर्मा : x x x

डा. एन.एस. गुर्जर : x x x

डा. किरोड़ी लाल मीणा : हम तो पीड़ित हैं नहीं, हम तो किसान के बेटे हैं नहीं, हम तो पशु पालते नहीं हम तो किसान के बेटे हैं नहीं, आपने ही किसान का ठेका ले रखा है। मैं गाय पालता नहीं, मेरे भैंस है नहीं, मेरे बकरी है नहीं, तुम्हारे ही बकरी है, तुम्हारे ही पशु हैं मैं पशु रखता नहीं हूं, मैं पशु भी नहीं रखता, मैं चारा भी नहीं डालता, बकवास कर रहे हो।

श्री श्रवण कुमार : x x x

श्री बाबूलाल नागर : x x x

श्री नन्दलाल बंशीवाल : x x x

श्री अशोक : x x x

डा. किरोड़ी लाल मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस का एक भी सदस्य अगर एक भी पशु मरा, मरने का यहां लिखकर दे दे तो मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, लिखकर दे दे कांग्रेस पशु मरा हो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : x x x

श्री ओम बिड़ला : x x x

श्री हेमाराम चौधरी : x x x

श्री बाबूलाल नागर : x x x

श्री भवानी सिंह राजावत : x x x

श्री अमराराम : x x x

डा. किरोड़ी लाल मीणा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के नेता से पूछना चाहूंगा कि पहली बार भारतीय जनता पार्टी से...

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : x x x

श्री अध्यक्ष : आप बीच में ही खड़े हो गये।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : x x x

डा. किरोड़ी लाल मीणा : मैं जवाब दे रहा हूं मिर्धाजी, कोई सुन ही नहीं रहा। मैं जवाब दे रहा हूं कोई जवाब सुनना नहीं चाहता।

(समय : 12.00 बजे)

श्री अमराराम (धोद) : x x x

श्री रामचन्द्र जारोड़ा : x x x

श्री मदन राठौड़ : x x x

श्री नन्दलाल बंशीवाल : x x x

श्री बाबूलाल नागर : x x x

श्री राजेन्द्र राठौड़ : x x x

श्री अमराराम (धोद) : x x x

डा. किरोड़ी लाल मीणा : अभी दे देता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप स्थान ग्रहण करें। मैंने कहा स्थान ग्रहण करें।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये प्रश्न के ऊपर यदि आप लोग इस प्रकार से प्रश्न दर प्रश्न उठाते चले जायेंगे तो आगे फिर कैसे होगा। अब मैंने आपसे निवेदन किया ना यह तो पर्ची के माध्यम से उठाया गया था, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। मंत्रीजी का जवाब सुन लो, आप संतुष्ट नहीं हो आपको मिलेगा मौका वाद-विवाद में भाग लेने का। उस समय आप अपनी बात कह सकते हैं कि यह मंत्रीजी ने गलत कहा है। आप कह सकते हैं। अब आप फिर.. (व्यवधान) The Chair is on the legs.

श्री हेमाराम चौधरी : x x x

डा. किरोड़ी लाल मीणा (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, एक बात उभरकर सामने आयी है हमने यह राजनैतिक भेदभाव

(डा. किरोड़ी लाल मीणा)

किया। मेरे खुद के इलाके में अगर भेदभाव किया होता तो मुख्य मंत्रीजी के इलाके के गांव को भी हम अभावग्रस्त घोषित करें और फेमिन कोड में यह बना रखा है...(व्यवधान)

श्री मंगलाराम गोदारा : x x x

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं बोलें। डूंगरगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलें...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : x x x

श्रीमती राजकुमारी : x x x

श्री अध्यक्ष : सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य भी बीच में नहीं बोलें। जवाब देने दें।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : मैंने अगर, राजनीतिक भेदभाव की बात कर रहे हैं, राजनीतिक भेदभाव अगर किया होता...

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष) : हुआ है ना।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : नहीं हुआ। हमारे आम तौर पर गिरदावरी होती है। अध्यक्ष महोदय, जो 50 प्रतिशत से ऊपर का जो खराबा होता है उसी को फेमिन कोड में लेते हैं और उसी का ज्ञापन हम भारत सरकार को देते हैं जिसके आधार पर कि हमको मदद मिलती है। अब 50 परसेंट का खराबा जहां भी है...

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री अध्यक्ष : बैठे-बैठे माननीय मुख्य सचेतक, आप भी न बोलें।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : उसको अभावग्रस्त घोषित कर दिया गया और 15778 गांव 22 जिलों के नोटिफाई हो गये। भारत सरकार की टीम आ गयी। केन्द्रीय नेतृत्व टोली उसको देखकर चली गयी और हमने टोली को ज्ञापन दे दिया। ज्ञापन में हमने लेबर के लिये क्वांटिटी मांगी है गेहूं की 16.56 लाख मीट्रिक टन और 749.34 लाख कैश। मेटेरियल कम्पोनेंट के लिये 377.7 लाख कैश मांगा है। फोडर ट्रांसपोर्टेशन सब्सिडी के लिये 37.50 करोड़ मांगा है। कैटल कैम्प सब्सिडी के लिये 61.65 मांगा है...

श्री अध्यक्ष : पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य, यह क्या कर रहे हैं ? आपको सदन के नियमों की जानकारी नहीं है? हाथ ऐसे कैसे कर रहे

(श्री अध्यक्ष)

है ? कंघा लेकर बाल बना रहे हैं आप। यह क्या तरीका है यहां पर ? कमाल करते हो आप भी। हद हो गयी किसी चीज की, आपको यह भी ध्यान नहीं है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : गौशाला सब्सिडी के लिये 61.65 कैटल फीड सब्सिडी के लिये 6.75, मिनरल मिक्सचर्स के लिये 50, ड्रिंकिंग वाटर के लिये भी हमने 120 करोड़ मांगा। इस ढंग से 1544.73 करोड़ रुपये मांगा और बीज की कोस्ट होती है 775, टोटल 2320 करोड़ रुपये का हमने भारत सरकार को ज्ञापन दिया है।

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री जोगाराम पटेल : x x x

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : x x x

श्री जोगेश्वर गर्ग : x x x

श्री जालम सिंह रावलोत : x x x

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष) : अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में आपके विचारार्थ एक बात प्रस्तुत कर रहा हूं। आपका जन्म हुआ किसारी में, आप शादी होकर गयी पातोसरी में...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मेरी समझ में नहीं आ रहा है आपको हो क्या गया है ? आपको हो क्या गया है ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : लेना देना है, पूरी बात तो सुनो। कोई बात हुई क्या ? दया करो मेरे ऊपर। मैं आपसे हाथ जोड़ता हूं दया करो।

श्री अध्यक्ष : What has happened to you ? प्रतिपक्ष के नेता What has happened to you I could not understand.

श्री रामनारायण चौधरी : मैं कोई गलत बात नहीं करूंगा।

श्री अध्यक्ष : क्यों आप इन्हें चढ़ाकर फालतू की बात करवा रहे हैं ? आप इन्हें चढ़ाकर फालतू की बात यहां करवा रहे हैं, अपने प्रतिपक्ष के नेता से। यह क्या बात हुई ? मैं कहां जन्मी, कहां शादी होकर गयी ? क्या है यह ? यह बयान करने की क्या आवश्यकता है यहां ? क्या आवश्यकता पड़ गयी माननीय प्रतिपक्ष के नेता ?

श्री रामनारायण चौधरी : भैंरोसिंहजी शेखावत खाचरियावास के हैं हमारे महामहिम उप राष्ट्रपति महोदय। महाराजा जयसिंह ने ही इस जयपुर को बसाया था। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : x x x

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : x x x

श्री रामनारायण चौधरी : इसमें अपराध क्या हो गया ? मुझे बताओ, आप किस बात का विरोध कर रहे हो ? मैं अगर गलत बोलता हूं तो आप मेरा गला पकड़ लेना। आप बात तो सुनो मेरी।

श्री अध्यक्ष : आप लोग चढ़ा रहे हो इनको ख्वामखाह में। मैं आपके हाथ जोड़ती हूं आप मेरा बखान न करें। मेरा बखान न करें। आप बैठ जाएं।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं नहीं बोलूंगा गलत कुछ भी। मैं गलत कुछ नहीं बोलूंगा, मेरी सारी कार्यवाही निकाल देना, मैं कह दूंगा सब निकाल दो।

श्री अध्यक्ष : मैं आपसे कह रही हूं, आप बैठ जाएं। मैं आपसे निवेदन कर रही हूं कृपापूर्वक आप बिराज जाएं, मेरा बखान, मैं कहां जन्मी, कहां शादी हुई, यह न करें तो अच्छा है। मैं जो कुछ हूं यही...

श्री रामनारायण चौधरी : इस राजस्थान का और झुंझुनूं जिले का इसमें फायदा होगा।

श्री अध्यक्ष : क्या कर रहे हो ? आप भी क्यों बावली बात करवा रहे हो ? क्या मतलब है ? I would not allow you.

श्री जोगेश्वर गर्ग : x x x

श्री रामनारायण चौधरी : मैं आपका बखान नहीं कर रहा हूं। मैं आपका बखान नहीं करूंगा, मैं वादा करता हूं मैं आपका बखान नहीं करूंगा। मेरे जिले के हित के लिये मैंने आपका श्रीमती सुमित्रा सिंहजी का जिक्र किया है, अध्यक्षजी का नहीं किया है। श्रीमती सुमित्रा सिंहजी का जन्म स्थान एक जगह है, ससुराल दूसरी जगह है। मान्यवर, आप हमें यह कह दीजिये आपके दोनों गांवों के अन्दर फसल अच्छी है क्या ?

श्री अध्यक्ष : क्या है ?

श्री रामनारायण चौधरी : फसल पिछले रबी और खरीफ की अच्छी है और गिरदावरी ठीक हुई है आपके क्षेत्र की तो मैं सब बात विदड्रा करता हू।

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री राजेन्द्र राठौड़ : x x x

डा. किरोड़ी लाल मीणा : 16.86 लाख मीट्रिक टन जो हमने गेहूं

(श्री किरोड़ी लाल मीणा)

मांगा उसमें मात्र हमको 2 लाख मीट्रिक टन गेहूं मिला है। एक और जानकारी मैं सदन को देना चाहता हूं कि राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य और नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने हमसे हिसाब पूछा था।

पहली बार राजस्थान सरकार ने स्टेट प्लान के अन्दर उस पेटे 50 करोड़ का फण्ड रखा था।

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री अध्यक्ष : खड़े हो गये (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : x x x

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष) : भारत सरकार द्वारा भेजा हुआ फण्ड करोड़ों रूपया पड़ा हुआ है। इस साल का आपके पास और आ रहा है इसके बावजूद भी माननीय मंत्री महोदय आपने किसी भी गांव में, किसी भी जिले में कोई काम चालू नहीं किये हैं फेमिन के अन्दर। यह आपने महा अन्याय किया है देश के साथ में। आपने राजस्थान को धोखा दिया है। यह सरकार इस लायक ही नहीं है कि इस जगह पर यह रहे। हम इसकी भर्त्सना करते हैं और इसके विरोध में कि आपने कोई काम चालू नहीं किये हैं, सारा रूपया लेकर बैठे हैं और उसका दूसरे कामों में दुरूपयोग कर रहे हैं और फालतू में कह रहे हैं कि भारत सरकार हमें पैसे नहीं दे रही है। ऐसा आडम्बर आप क्यों रचते हैं ? हम इसके खिलाफ बहिर्गमन करते हैं।

(कांग्रेस के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

डा. किरोडी लाल मीणा : सुन तो लें...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : x x x

डा. बुलाकीदास कल्ला : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : x x x

श्री अध्यक्ष : बैठ जायें अब माननीय मंत्रीजी...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा : 32.5 लाख मीट्रिक टन तत्कालीन सरकार को दिया था जिससे बेशुमार काम खुले थे और अब यह कह रहे हैं कि अकाल के काम नहीं चालू...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, माननीय मंत्रीजी।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : जनवरी, 2006 में जो सीलिंग हैं 25 हजार उसमें 2 लाख 23 हजार काम कर रहे हैं। फरवरी में 3 लाख 50 हजार की सीलिंग हैं जिसमें 2 लाख 18 हजार हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, पर्ची के माध्यम से जो प्रश्न जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने उठाया था उसके बारे में आपको कोई जवाब देना नहीं है तो आप किसे जवाब दे रहे हैं ? क्या मतलब है ...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल मीणा : उसी का तो दे रहा हूं। भारत सरकार कोई मदद नहीं कर रही है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कह दिया ना उन्होंने, देखिये, माननीय सदस्य ने वह बात कह दी (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इन्होंने कह दिया कि मार्च में चार लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह अकाल राहत की बात कर रहे हैं और अकाल ग्रस्त होने की बात कर रहे हैं। जब यह सुनना ही नहीं चाह रहे हैं तो आप क्या बोल रहे हैं, क्या मतलब है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, एक वह समय था इस राजस्थान में अकाल पड़ा था और 246 करोड़ रूपये अटल बिहारी वाजपेयी ने दिये थे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : पर्ची के माध्यम से माननीय सदस्य ने पूरा दिया है ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : अध्यक्ष महोदय, सदन को चलाना है तो एक चीज की व्यवस्था कर दें कि जो माननीय सदस्य हो-हल्ला करे उसका प्रेस में, मीडिया में जिक्र नहीं हो तो हाउस में बहुत शांति रहेगी, यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष : मोहम्मद माहिर आजाद।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी और शिक्षा राज्य मंत्री का ध्यान राजस्थान में (व्यवधान) यह क्या हो रहा है, यह मेरा सोच है, मेरी पार्टी पूछेगी कि आप पूछेंगे ? Who are you to ask me ?

श्री अध्यक्ष : आप इनसे बात नहीं करें मुझसे बात करें।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, यह मुझसे पूछ रहे हैं कि आप बाहर क्यों नहीं गये। यह इनका काम है क्या ?

श्री अध्यक्ष : वह कुछ भी कहें लेकिन आप इधर संबोधित करें। उन्हें कहने दीजिये अगर कुछ कहते हैं वो। आप दरगुजर करें उन्हें।

बेरोजगार प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति

मोहम्मद माहिर आजाद : हां, बकने दूंगा, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय शिक्षा मंत्रीजी और शिक्षा राज्य मंत्री का ध्यान राजस्थान में बेरोजगार प्रशिक्षित शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति के संबंध में दिलाना चाहता हूं। इन बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाये। माननीय शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी जी ने अजमेर में, पढ़ रहा हूं मांग पत्र है, अध्यक्ष महोदय, यह क्या है, कुछ लोगों के तो बीमारी हो गयी है क्या ? मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आपको पढ़ने की आवश्यकता होनी ही नहीं चाहिए... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं पढ़ रहा हूं कि कौनसी तारीख का है यह भी नहीं पढ़ूंगा, मुझे पढ़ना सिखा रहे हैं। आपसे तीन डिग्री ज्यादा पढ़ा हुआ हूं (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपको पढ़ने की कहां आवश्यकता है (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : मैं अनपढ़ आदमी हूं इसलिए पढ़ रहा हूं। महावीरजी, मैं अनपढ़ आदमी हूं इसलिए पढ़ रहा हूं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप क्या हो...(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : आपके जैसे बिना नापे एक मीटर कपड़े को चारों तरफ से नाप कर और दलितों और आदिवासियों के पैसे नहीं लिये हैं मैंने।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसा है, मैं कोई जमीन नहीं नापता हूं जो सरकारी जमीन हो और उस पर कब्जा कर लूं। मैं ऐसा नहीं करता हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : ठीक है, हिम्मत चाहिए हिम्मत।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हिम्मत चाहिए, वह हिम्मत आपमें हैं, आपको मुबारक हो।

श्री अध्यक्ष : क्या कह रहे हो ? क्या कह रहे हो आप ? क्या बोल रहे हो आप ?

मोहम्मद माहिर आजाद : कह रहे हैं कब्जा कर रखा है। मेरे ऊपर कब्जा करने का आरोप लगा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : सरकारी जमीन कब्जा करने में हिम्मत चाहिए, क्या बोल रहे हो आप ?

मोहम्मद माहिर आजाद : इन्होंने करी होगी ...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की जाये। माननीय शिक्षा राज्य मंत्री वासुदेव देवनानी ने अजमेर में यह घोषणा की थी कि स्थानीय निकाय के चुनाव सम्पन्न होने के बाद हम शारीरिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया प्रारम्भ करवा देंगे। अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान में लगभग 8563 शारीरिक शिक्षकों की वेकेन्सी है। राजस्थान में आठ कालेज हैं, जोधपुर, बारां, उदयपुर, केकड़ी, जामडौली, सूरोठ, बीकानेर और अजमेर और इसके अलावा चारों विश्वविद्यालयों में भी शारीरिक शिक्षकों की ट्रेनिंग की जाती है। सन् 2000 में जब पिछली कांग्रेस की सरकार थी माननीय बी.डी. कल्लाजी शिक्षा मंत्री थे तब लगभग 1100 शारीरिक शिक्षकों की भर्ती हुई थी। उसके बाद 5-6 वर्ष निकल गये आज तक शारीरिक शिक्षकों की कोई भर्ती नहीं की गयी है। लगभग 50 हजार शारीरिक शिक्षक राजस्थान में बेरोजगार हैं। उन्होंने दो महीने तक स्टेच्यु सर्किल पर धरना भी दिया और आमरण अनशन भी किया। जब आमरण अनशन किया तो माननीय शिक्षा मंत्रीजी घनश्यामजी तिवाड़ी और शिक्षा राज्य मंत्रीजी ने आश्वासन देकर धरना समाप्त करवाया कि हम बहुत जल्दी शारीरिक शिक्षकों की भर्ती कर देंगे।

अध्यक्ष महोदय, यह बात सही है कि भारत और राजस्थान जैसे राज्य में जहां पर श्रम का बहुत जोर था। श्रम किया जाता था। आज एक तरह तो बाबा रामदेवजी के प्रयासों से हम योग और शारीरिक शिक्षा की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ आज इतनी बड़ी संख्या में शारीरिक शिक्षकों के पद रिक्त पड़े हैं। हमने कम्पलसरी कर दिया कि आठवीं तक की हर स्कूल में एक शारीरिक शिक्षक होगा। स्वयं खेल मंत्रीजी ने भी घोषणा की है कि राजस्थान में खेलों को बढ़ावा देने के लिए ग्राम स्तर पर शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति होनी चाहिए इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यहां पर दोनों शिक्षा मंत्री और शिक्षा राज्य मंत्रीजी बैठे हैं, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप स्वयं, माननीय घनश्यामजी यह कहते हैं कि कर्म वाणी और आचरण में समरूपता होनी चाहिए। जब आपने घोषणा की थी और आपने विश्वास दिलाया

(मोहम्मद माहिर आजाद)

था कि बहुत जल्दी शारीरिक शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया चालू की जायेगी। आपने कल कहा कि 7200 शिक्षकों की आप नियुक्ति करने जा रहे हैं। उसके साथ ही मेरा निवेदन है कि आप शारीरिक शिक्षकों की भी नियुक्ति करें और ग्रामीण क्षेत्र के विद्यार्थियों को भी उनकी प्रतिभा निखरने का और शारीरिक शिक्षक जो 50 हजार के करीब बेरोजगार हैं उनमें से कई ओवर एज होने जा रहे हैं उनकी भी नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ करें। आपने कहा था, कहा था कि नहीं। कहा था अजमेर में।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : सरकार इस समस्या से अवगत है।

श्री अध्यक्ष : श्री मांगीलाल गरासिया।

बेकरिया पंचायत (गोगुन्दा) के कृषक पर वन विभाग कर्मियों द्वारा कथित अन्याय

श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से वन मंत्री एवं गृह मंत्रीजी का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगा कि पंचायत बेकरिया में गांव पीलका में उदा पिता नंगा गरासिया का मामला है और गांव पीलका में उदा के नाम पांच बीघा कृषि भूमि है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस भूमि के माध्यम से उदा पुत्र नंगा गरासिया अपने 9 सदस्यीय परिवार का भरण पोषण कर रहा था, उस पर जब उसने अपनी फसल बोई और फसल बोने के साथ में राजस्व मिसल संख्या 110/1962 से उक्त भूमि का नियमन प्रार्थी के नाम करने का आदेश भी प्रदान हुआ, 1962 में। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि इस भूमि पर जब फसल हुई और फसल होते ही 17.02.2006 को उस भूमि पर वन विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंचे। और फोरेस्टर जय सिंह, गार्ड मन्नाराम करके उन्होंने इस पर जो फसल थी उस फसल को उखाड़लने की बात की। उखाड़ने के लिए जब उस परिवार के लोगों ने मना किया तो वह फोरेस्टर माना नहीं और जबरन उनको लताड़ देने का काम किया, गाली गलौच देने का काम किया। माननीय अध्यक्ष महोदय वहां पर सरसों भी थी, उसमें आग लगा दी और आग लगाने से उसका पूरा मकान जल गया और वहां पर जो अनाज और बाकी सामान था वह पूरा जलकर राख हो गया, उसमें कुछ रुपये भी थे वे भी जल गए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मामला गम्भीर है।

(श्री मांगीलाल गरासिया)

माननीय अध्यक्ष महोदय, उदा अपने नौ सदस्यीय परिवार को लेकर असहाय हो गया और इस स्थिति में अब तकलीफें सह रहा है और दर-दर की ठोकरें खा रहा है। जब थाने में गया तो थानाधिकारी ने उसकी नहीं सुनी। इस तरह के गम्भीर मसले में उन्हें करीबन 1 लाख रुपये तक का नुकसान हो गया और वह परिवार बेघर की तरह घूम रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय वन मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा क्योंकि आपका हृदय उदारवादी है इसलिए आप इसको देखकर पूरी तहकीकात करवाने का काम करें। वास्तव में एक तरह का अकमर्ण्यता का काम हुआ है और उसके साथ ज्यादती हुई है। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से भी अनुरोध करूंगा क्योंकि वे भी उदयपुर ज़िले के हैं और उदयपुर ज़िले का मामला होने के नाते गरीब असहाय आदिवासी भाई को मुआवजे के रूप में एक तरह से पूरी सहायता मिले।

अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से वन मंत्रीजी से अनुरोध है कि आप इसकी पूरी तहकीकात कराएं। वन अधिकारियों ने एक तरह से उस असहाय व्यक्ति के साथ ज्यादती की है।

श्री अध्यक्ष : वन भूमि पर अतिक्रमण तो नहीं कर रखा था, वन भूमि पर काश्त तो नहीं कर रहा था?

श्री मांगीलाल गरासिया : वन भूमि पर नहीं था, वन भूमि पर काश्त नहीं कर रहा था। इसलिए मैं अनुरोध कर रहा हूं कि इस भूमि पर जिस तरह से फसल उगा कर पूरे परिवार का भरण पोषण कर रहा था उसके साथ बहुत ज्यादती और अन्याय हुआ है, इस अन्याय से उसे राहत दिलाने की माननीय वन मंत्रीजी से अनुरोध करूंगा।

श्री अध्यक्ष : श्री बहादुर सिंह गोदारा। वन मंत्रीजी क्या कह रहे हैं?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे (वन और पर्यावरण मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो सूचना दी है, अगस्त माह में इस उदा ने दूसरी बार इस जमीन पर अतिक्रमण किया। वहां की वन सुरक्षा समिति और वन विभाग के कर्मचारियों ने 17-18 फरवरी को इन का अतिक्रमण हटाया, जब अतिक्रमण हटाया तो उदा ने खुद की अपनी जो घास की झोपड़ी बनी हुई थी, उसको आग लगा दी और यह दिखाने की कोशिश की कि यह आग वन विभाग के कर्मचारियों द्वारा लगाई गई है और वन सुरक्षा समिति के सदस्यों के

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

साथ मारपीट की। बेकरिया थाने के अन्दर वन विभाग के कर्मचारियों ने सी आर नम्बर 20/06, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। माननीय सदस्य अगर यह बताते कि 1962 के अन्दर इनके रेगूलराइजेशन का कोई मामला है तो मैं इस मामले की जांच करवा दूंगा। बाकी अतिक्रमण जिस हिसाब से लगातार वन भूमि पर हो रहे हैं, इन अतिक्रमणों को रोकने के लिए सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी।

श्री मांगीलाल गरासिया : अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह सरनोट की जमीन का मामला था, वह इस भूमि पर गैर खातेदार के रूप में काश्त कर रहा था। मैं मानता हूं कि यह जमीन विभाग की नहीं थी और जिस तरह से उसके साथ अन्याय हुआ उसको देखने का काम करें।

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। पर्ची पर उन्होंने जवाब दे दिया है। श्री बहादुर सिंह गोदारा।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : अध्यक्ष महोदय, एक मिनट केवल। अध्यक्ष महोदय, उदयपुर सम्भाग में वन विभाग द्वारा यह आम बात हो गई है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि किसी अतिक्रमी ने जंगलात की जमीन पर कब्जा किया है तो उसका झोपड़ा जलाना, उसकी चल और अचल सम्पत्ति को नष्ट करना आपके फोरस्ट कानून में आता है ? प्रतापगढ़ से लेकर कोटड़ा तक इस तरह से आदिवासियों के झोपड़े जलाने में जंगलात विभाग के कर्मचारी माहिर हो गए हैं। इसलिए मंत्री महोदय, आप इसकी व्यवस्था करें कि कम से कम अगर अतिक्रमी है 1980 के पहले के, मैं यह कहना चाहता हूं कि 1980 के पहले के जो अतिक्रमी थी उन अतिक्रमियों के विरुद्ध जो छानबीन कमेटी बनी थी। उसमें वन विभाग की मनमानी हुई है, वह लोग आज बच गए हैं जिनके 1980 के पहले भी कब्जे थे। इस बारे में आप एक कमेटी जिसमें जनप्रतिनिधि भी हों, पुनः मूल्यांकन कराएं ताकि आदिवासियों के सामने जो अहम सवाल है जंगलात की जमीन पर कब्जे का उसको किस तरह से सुलझाया जा सकता है उसके बारे में व्यवस्था करें। गरीबों के झोपड़े जलाने वाली बात, उनको प्रताड़ित करने वाली बात हो रही है यह हमारे लिए निन्दनीय है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : माननीय अध्यक्ष महोदय, 1980 के पहले के राजस्थान में 5466 ऐसे प्रकरण हैं उनको राज्य सरकार ने नियमित करने के

(श्री लक्ष्मीनारायण दवे)

लिए भारत सरकार को भेजा है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के कारण यह मामले पेडिंग पड़े हैं। और जहां तक यह प्रकरण है, इस प्रकरण में अतिक्रमी ने लगातार दूसरी बार एन्क्रोचमेण्ट किया है। और इस एन्क्रोचमेण्ट को रोकने के लिए जब उस अतिक्रमी के खिलाफ बेगरिया थाने में मुकदमा दर्ज किया तो रिएक्शन के तौर पर उसने अपना झोपड़ा जलाया। अगर वन विभाग के किसी अधिकारी और कर्मचारी ने यह कृत्य किया है, इसमें अगर कोई सत्यता है तो इसकी जांच करवा दूंगा। अगर वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी किसी के साथ इस तरह का कोई कृत्य करते हैं तो आप मुझे इसकी जानकारी दें और जांच करने पर अगर वास्तव में वह दोषी पाया जाएगा तो निश्चित रूप से उसे पनिश किया जाएगा। बाकी कोई नया एन्क्रोचमेण्ट वन विभाग के अन्दर राजस्थान में होगा तो उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। श्री बहादुर सिंह गोदारा।

नोहर विधान सभा क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था सुधारने विषयक

श्री बहादुर सिंह गोदारा : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र में अकाल की भयंकर समस्या की ओर दिलाना चाहता हूं। मेरा नोहर विधान सभा क्षेत्र ज्यादातर बारानी है। बहुत ही थोड़े क्षेत्र में सिंचाई की व्यवस्था है लेकिन उसमें भी पूरा पानी नहीं मिलता। बुवाई के बाद लोगों को रेगूलर पानी नहीं मिला इसलिए भी फसल अच्छी नहीं हुई।

डा. एन.एस. गुर्जर (टोडारायसिंह) : आन ए पाइण्ट आफ आर्डर।

डा. बुलाकीदास कल्ला (बीकानेर) : जीरो आवर में पाइण्ट आफ आर्डर नहीं होता।

डा. एन.एस. गुर्जर : हां, हां, कल्लाजी, आप बैठिए। मैं बता रहा हूं। सुनो एक मिनट।

डा. बुलाकीदास कल्ला : पाइण्ट आफ आर्डर जीरो आवर में नहीं होता।

डा. एन.एस. गुर्जर : हां, पाइण्ट आफ आर्डर, जीरो आवर में, आप सुनिए तो सही, क्यों नहीं हो सकता ? पचासों बार उठा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : इस पर व्यवस्था दी हुई है अध्यक्ष महोदय की।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं बताऊं आपको, पाइण्ट आफ आर्डर जीरो आवर में कितनी बार उठा है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : इस पर अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था दी हुई है।

डा. एन.एस. गुर्जर : मैं बताऊ, पाइण्ट आफ आर्डर जीरो आवर में कितनी बार उठा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : जीरो आवर में पाइण्ट आफ आर्डर नहीं होता। दो मिनट का समय है, उसके बाद उठा लीजिए।

डा. एन.एस. गुर्जर : इसी से सम्बन्धित है, एक मिनट आप विराजिए।

श्री अध्यक्ष : No, I will not allow.

डा. बुलाकीदास कल्ला : फिर हम भी उठाएंगे।

डा. एन.एस. गुर्जर : आप बोल लीजिए, इसके बाद बोल लूंगा।

श्री बहादुर सिंह गोदारा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में रेगूलर पानी नहीं मिलने की वजह से सिंचित फसलें भी बरबाद हो गई और पानी के अभाव में लोगों ने अरण्ड और सरसों की फसल बोई थी वह सर्दी की वजह से बिलकुल बरबाद हो गई। सिंचित एरिये में भी भयंकर अकाल है, बारानी क्षेत्र में न साढ़िया बीजी गई और न सावणिया बीजी गई और यह हालत मेरे क्षेत्र की लगातार सात साल से होती आ रही है। लेकिन अभी तक वहां किसी किस्म की कोई भी अकाल सहायता नहीं खोली गई है।

श्री अध्यक्ष : यहां अकाल राहत मंत्रीजी भी नहीं हैं।

श्री बहादुर सिंह गोदारा : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि इस तरह के क्षेत्र में जहां पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो गई हो या बुवाई नहीं हुई हो ऐसे क्षेत्र के अन्दर शीघ्र अकाल सहायता कार्य खोले जाएं और लोगों को राहत दी जाए। अकाल सहायता कार्य खोलने के लिए मेरा एक निवेदन है कि उस क्षेत्र के अन्दर खेतों के अन्दर जो कुण्ड या डिग्गियां बनवायी जाएं, जहां नहरों का सर्वे नहीं हुआ है, वहां नहरों का सर्वे कराकर खाले, नाले बनाये जाएं और लोगों को राहत दी जाए। (समय समाप्ति सूचक घण्टी) एक मिनट में मैं मेरी बात पूरी करता हूं। मेरे क्षेत्र के किसान 6.2.2006 से लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, आन्दोलन कर रखा है। कल नोहर बन्द था और उसके बाद किसानों ने आमरण अनशन का आह्वान किया है। आज तक किसी भी सरकारी कर्मचारी ने जाकर किसानों की बातें नहीं सुनी, किसानों को राहत देने की कोशिश नहीं की। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि उन धरने पर बैठे हुए काश्तकारों की बात नहीं सुनी गयी तो वे

(श्री बहादुर सिंह गोदारा)

आमरण अनशन पर बैठेंगे। उसकी सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। अतः मेरा निवेदन है...

श्री अध्यक्ष : हो गई आपकी बात।

श्री बहादुर सिंह गोदारा : उस क्षेत्र के अन्दर शीघ्रातिशीघ्र सहायता कार्य खोले जाएं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, मुझे आपको यह सूचित करना है कि अब जो साढ़े पांच घंटे की बहस होगी...

श्री महावीर प्रसाद जैन : एक मिनट मैं बोल सकता हूं, आपकी इजाजत हो तो?

श्री अध्यक्ष : क्या बोलेंगे आप?

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप जो समय का आबंटन कर रहे हैं उसके बारे में आपका आदेश शिरोधार्य है, किसी को एतराज का सवाल ही नहीं है। मैं कल यह निवेदन करना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों को बहुत कम समय मिला है..

श्री अध्यक्ष : मैं वही बता दूंगी, जितना आपकी पार्टी का समय है वह सब दूंगी आपको। मुझे आपको यह सूचित करना है कि अब हमारे पास केवल साढ़े पांच घंटे हैं जिसमें वाद-विवाद को समाप्त करना है, फिर मुख्य मंत्रीजी का जवाब होगा। वैसे तो पांच बजे की सीमा तय की गई थी बी.ए.सी. में, लेकिन मैंने इसे आधा घंटा बढ़ाकर साढ़े पांच कर दिया। तो साढ़े पांच घंटे बचे हैं, अब छह बजे तक कर दिया, छह बजे उनका रिप्लाई आएगा। अब जो समय है उसमें भारतीय जनता पार्टी का समय है 3 घंटे 19 मिनट। इण्डियन नेशनल कांग्रेस का समय है एक घंटा 31 मिनट। इण्डियन नेशनल लोकदल का समय है 7 मिनट। जनता दल (यूनाइटेड) का है 3 मिनट। बहुजन समाज पार्टी का है 3 मिनट। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी का है 2 मिनट। लोक जनशक्ति पार्टी का है 2 मिनट। राजस्थान सामाजिक न्याय मंच का है 2 मिनट और निर्दलीय का है 21 मिनट। अब इस हिसाब से आप अपनी-अपनी बात कह सकते हैं।

श्री फतेह सिंह : अध्यक्ष महोदय, जनता दल तो कभी बोला ही नहीं है। 15 मिनट आपने दिये थे उसके बाद में आपने 3 मिनट बताए। हमारा सदस्य तो कोई बोला ही नहीं। आपके सदस्य ज्यादा संख्या में हैं यह बात तो सही है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप मेरी बात सुनें। इसलिए कि कल पूरे समय यदि चर्चा होती तो जो समय आपको मिलना चाहिए था 15 मिनट मिलते, लेकिन चूंकि अब सदन का समय वाद-विवाद के लिए साढ़े पांच घंटे ही रह गया तो साढ़े पांच घंटे के हिसाब से संख्या से हिसाब से नम्बर आता है और संख्या के हिसाब से यही समय आया है। अब मैं इस पर क्या कर सकती हूं ?

डा. सी.पी. जोशी : आप टाइम बढ़ा दो।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, सवाल यह है कि दो दिन तक पहले बहस हुई है जिसमें सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी और प्रमुख प्रतिपक्ष कांग्रेस के सदस्य बोले हैं। जो छोटे दल हैं उसमें एकाध साथी ने भाग लिया है। तो निश्चित रूप से जिन्होंने भाग लिया है दो दिन तक कल नहीं हुई किसी भी कारण से डेढ़ घंटे ही चर्चा हुई है, लेकिन उससे पहले दो दिन तक पूरे टाइम सात बजे तक के लिए चर्चा हुई है। इसलिए हमारा निवेदन है कि आपका आदेश तो शिरोधार्य है..

श्री अध्यक्ष : आप समय मांग लें बहुजन समाज पार्टी, लोक जनशक्ति से मांग लें तो आपका समय हो सकता है।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, जिन्होंने व्यवधान किया है उनको सज़ा मिलनी चाहिए। जिन्होंने व्यवधान नहीं किया, जिन्होंने समय नष्ट नहीं किया उनका समय क्यों काटा जाए? समय तो उनका काटा जाना चाहिए। कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी), जनता दल ने, इण्डियन नेशनल लोकदल ने तो समय बर्बाद नहीं किया है। जिन्होंने समय बर्बाद किया है उनका समय काटा जाए। जो तीन दिन में नहीं बोले उनका समय तो वही रहना चाहिए। हमारा आपसे निवेदन है जिन्होंने कल बहस नहीं की उसके कारण उनका समय काटा जाना चाहिए। जिसने अपराध किया उसको सज़ा मिलनी चाहिए। मैं समझता हूं इससे बेहतर होगा (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उषा पूनिया।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, ये पार्लियामेंट्री मिनिस्टर पान खा रहे हैं हाउस के अन्दर।

श्री अध्यक्ष : अब कोई नहीं। मैंने नाम पुकार लिया उषा पूनिया।

श्री संयम लोढ़ा : हाउस के अन्दर पार्लियामेंट्री मिनिस्टर पान खा रहे हैं या सुपारी खा रहे हैं। हाउस के अन्दर यह सुपारी खा रहे हैं। आप हाउस के अन्दर सुपारी खा रहे हो यह गलत बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बिना कारण से आरोप लगा दिये।

श्री संयम लोढ़ा : यह आप जैसे वरिष्ठ सदस्यों से अपेक्षा नहीं है। आप पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर हैं और आप ऐसा करें। अभी मुंह चला रहे थे हाउस के अन्दर।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, यहां तो बिना कोई कारण से आरोप लगा दिया।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय पार्लियामेंट्री मिनिस्टर साहब क्या खाते और क्या पीते हैं आप ही क्यों देखते हो इनको।

श्री अध्यक्ष : इतने गम्भीर विषय पर बात हो रही थी और आप कहां पान और गुटके पर आ गये फालतू में।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, जब आपने एक प्रयास किया था (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप मुझसे कोई बहस नहीं कर सकते, स्थान ग्रहण करें। मैंने उन्हें देखा और देखकर मुझे बड़ा अनुचित लगा कि कंघा लेकर बाल बना रहे हैं। तो मैंने उसके बारे में उनको टोका और यदि कोई चुपचाप दूर से किसी को बिना दिखाये यों करके कोई चीज खा लेता है तो उस पर कोई आपत्ति नहीं होती। सवाल यह है कि प्रदर्शन करके खाये यह होता है। उषा पूनिया।

डा. सी.पी. जोशी : इनको चैक करवाओ। ये निगल गये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये डाक्टर बैठे हैं, इनसे चैक करा दूं।

श्री अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण कर लें।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर डा. दिगम्बर सिंह जी से जांच नहीं हो सकती हो तो हमारे पास बैद और डाक्टर दोनों एक ही आदमी हैं।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

श्री अध्यक्ष : श्रीमती उषा पूनिया। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान टूरिज्म डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-03

श्रीमती उषा पूनिया (पर्यटन राज्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी

(श्रीमती ऊषा पूनिया)

अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 619 (ए) के अन्तर्गत राजस्थान टूरिज्म डवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड का 24वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 सदन की मेज पर रखती हूं।

श्री अध्यक्ष : डा. बुलाकीदास कल्ला।

श्री रामनारायण चौधरी : आपने हमारा टाइम बताया एक घंटा।

श्री अध्यक्ष : अब वे समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन कर रहे हैं वह तो कर लेने दें उन्हें आप। आपका समय मैंने बताया एक घंटा 31 मिनट।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। माननीय मंत्री महोदय ने जो प्रतिवेदन रखा है वह 2002 का रखा है। अब चल रहा है 2006 2007 । अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था है एक साल का ही डिले हो, लेकिन अपने पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर कारपोरेशन की रिपोर्ट को 4-4, 5-5 साल के प्रतिवेदन को आप रखेंगे तो हम असेम्बली में क्या डिबेट करेंगे? सरकार बदल गई, नई सरकार आ गई, पिछली सरकार के प्रतिवेदन को हम रख रहे हैं, कम से कम आप विभाग को यह डाइरेक्शन दें (व्यवधान) हमने तो रखा ही नहीं 25 साल तक, यह कोई आर्गुमेंट है क्या? उससे क्या तकलीफ है ? आप इम्प्रूव करना चाहते हो या हमने क्या किया वह बातें करना चाहते हो ? आप खड़े होकर बोलें यहां पर।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हम भी इम्प्रूव कर रहे हैं।

डा. सी.पी. जोशी : क्या इम्प्रूव कर रहे हैं ? Please don't protect the wrong thing. आप अध्यक्ष हैं या आप अध्यक्ष हैं ? मैं अध्यक्ष महोदय से अनुमति मांग रहा हूं. अध्यक्ष महोदय, आप निर्देश दें।

श्री अध्यक्ष : आपका सुझाव ठीक है, सरकार इस बारे में सचेत रहे कि भविष्य के अन्दर गत वर्ष का..

श्रीमती उषा पूनिया : आगे से इसका ध्यान रखेंगे।

श्री अध्यक्ष : यह 2005-06 चल रहा है। विगत वर्ष 2004-2005 तक का रख दिया करें, यह ध्यान रखें।

डा. सी.पी. जोशी : यह हर विभाग का है। I am not saying about this department only. हर विभाग के लिए विधान सभा से डाइरेक्शन जाना चाहिए कि कम से कम इसको एडहियर करें, एक साल का गैप तो समझ में आता है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपकी आज्ञा शिरौधार्य है, सब जगह इस चीज को लिखकर भी दे देंगे और भविष्य के अन्दर कोशिश करेंगे कि इसमें विलम्ब न हो।

श्री नरपत सिंह राजवी : अध्यक्ष महोदय, एक निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं कि जो आज एलिगेशन लगा रहे हैं कि यह लेट हुआ है यह एलिगेशन लगाने की जरूरत नहीं है। आप खुद ही कर लेते तो मेरे खयाल से जरूरत नहीं पड़ती।

डा. सी.पी. जोशी : हम करते तो इधर नहीं बैठते, उधर बैठते फिर।

श्री नरपत सिंह राजवी : आप निवेदन तो सुन लें।

डा. सी.पी. जोशी : माननीय राजवी साहब, आप बार-बार यह कहकर शेल्टर नहीं ले सकते कि हमने नहीं किया। जो नियम हैं, कानून है उसके हिसाब से आना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष : उद्योग मंत्रीजी, सवाल यह है कि जिसने गलती की, लेकिन सिस्टम को करेक्ट करने वाली बात है तो सही है, वह सिस्टम डवलप हो ऐसा प्रयत्न अपने को करना चाहिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिस्टम डवलप होगा।

श्री नरपत सिंह राजवी : आपका आदेश शिरोधार्य है। मैं तो इतना ही निवेदन करना चाह रहा था कि हमारे इस पीरियड में हो तो डेफिनेटली ठीक कर देंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : दो साल से आप सरकार में हो, सारी जिम्मेदारी आपकी है।

श्री अध्यक्ष : आपको क्या सारी गलतियां वही करनी हैं जो इन्होंने की थी ? वो ही सारी गलतियां करनी हैं क्या आपको ? (व्यवधान) बस तो फिर।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा आपने गत सत्र में भी डाइरेक्शन इसी संबंध में सरकार को दिये थे और सरकार आपके डाइरेक्शन को इतनी लाइटली ले रही है, यह बहुत गलत बात है, इनको दुबारा से सख्त निर्देश दीजिए कि आइंदा दुबारा से आपको रिपीट नहीं करना पड़े। हमको याद है आपने गत सत्र में भी इनको निर्देशित किया था।

श्री रामनारायण चौधरी : तो, अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि बी.डी. कल्ला साहब जो बोलेंगे हमारी तरफ से पी.सी.सी. प्रेसीडेंट तो हमारे पास टाइम बचा है आपके पास एक घंटा और 31 मिनट, एक घंटा आप इनको दे दीजिए, 31 मिनट में हमारे दो तीन और बोलना चाहते हैं, दस-दस पन्द्रह पन्द्रह मिनट उनको दे दीजिए, ऐसा बंटवारा कर दीजिए।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, हमको क्या एतराज है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पर प्रतिपक्ष के नेता, आपके विचार भी हम जानना चाहेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : पर अध्यक्ष महोदय, हमारा आग्रह यह भी है कि प्रतिपक्ष के नेता भी बोलें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह राजस्थान के इतिहास में पहली बार होगा कि प्रतिपक्ष के नेता नहीं बोलें। हम आपके भी विचार जानना चाहेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : प्रतिपक्ष के नेता भी बोलें, हमारा आग्रह है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके विचारों से लाभान्वित होना चाहते हैं, सरकार आपके विचारों से दिशा निर्देशित होना चाहती है, आप विचार व्यक्त करें, यह सी.पी. जोशी साहब चाहते हैं कि आप बोलें नहीं, हम चाहते हैं कि आप बोलें।

डा. सी.पी. जोशी : नहीं, नहीं, हमारे लीडर बोलेंगे, अभी अध्यक्षजी और इनका जो अपना है वह चाय पर बैठकर बात हो जाए फिर प्रतिपक्ष के नेता भी अपनी बात कहेंगे, जरूर बात कहेंगे, ऐसी बात थोड़े ही है।

श्री रामनारायण चौधरी : स्पीकर महोदया थोड़ी नाराज चल रही हैं (व्यवधान) हां, मैं कोशिश करूंगा (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर यह कह रहे हैं, बोलना खुद नहीं चाहते, सरकार के खिलाफ बोलने के लिए कोई इनके पास मैटेरियल ही नहीं है।

श्री जुबेर खान : माननीय मंत्री महोदय, सुन तो लीजिए, आप सुनिए।

डा. सी.पी. जोशी : 50 साल का मैटेरियल है इनके पास।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बुलाइए न आप, पर आप नहीं चाहते, आप नहीं चाहते कि इनके विचार आएं।

डा. सी.पी. जोशी : राजेन्द्रजी, जब आप पानी पी रहे हैं तब का मैटेरियल है, चिन्ता क्यों कर रहे हैं ? हर मैटेरियल इकट्ठा है इनके पास

(डा. सी. पी. जोशी)

चिन्ता क्यों कर रहे हैं। अभी तो खाली यह है कि माननीय अध्यक्ष महोदया, कल हुआ उसमें सौहार्दपूर्ण वातावरण हो जाए उसके बाद बोलेंगे।

श्री रामनारायण चौधरी : ठीक है, मैं इनकी बात से सहमत हूं।

श्री अध्यक्ष : लेकिन यह सदन सुनना चाहता हूं, नये प्रतिपक्ष के नेता को यह सदन सुनना चाहता है।

डा. सी.पी. जोशी : आपकी भावना को शिरोधार्य रखते हुए हमारे विपक्ष के नेता बोलेंगे। जब आपका मन, आपका हमारे प्रति, नेता के प्रति वह एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में बात हो जाए माननीय नेता बोलेंगे।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, तो अति प्रसन्न हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं....

श्री अध्यक्ष : किसी भी प्रकार की कोई घटना हो जाती है तो मैं उसका मेरे दिल पर कोई असर नहीं रखती।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, आपके बहुत आभारी हैं, आपने सह्रदयता बताकर यह कहां उसके अनुरूप हम आचरण करेंगे।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ : पी.डब्ल्यू.डी. मंत्री जब आप पानी को बू कहते थे वे आए थे, यह दूसरी बात है कि वह ब्रेक डांस करते हुए आए हैं और आप भंगड़ा डालते हुए चौथी बार पहुंच गये।

श्री रामनारायण चौधरी : देखिए, हर चीज का एक असर होता है, चोट शरीर पर लगती है, ह्रदय पर लगती है, मेरे सिर पर यह चोट लगी हुई है उसका निशान बना हुआ है, यह मिट नहीं सकता। अध्यक्ष महोदय की भावनाओं को कहीं ठेस लगी है उनको मैं नार्मलाइज करना चाहता हूं। उसके बाद, और मैं नैक्स्ट टाइम जब बजट सेशन आएगा, अभी उसमें मेरे जैसी है, भाव व्यक्त करने की कोशिश करूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हम तो अब सुनना चाहते हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बात का दुःख है कि कल सदन के नेता को मुख्य मंत्रीजी को खेद व्यक्त करना पड़ा उनकी भावनाओं को और उनके दिल को ठेस पहुंची, आपको भी पहुंची। मैंने कोई ऐसी बात नहीं कही थी, वह चेप्टर वहीं क्लाज हो गया। और मैं आज नहीं बोलूंगा, अगर आप अनुमति देंगी तो बजट पर बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। Have you begun your speech ? (व्यवधान) अच्छा, अच्छा, अभी तो वह रख रहे हैं, यस, यस, आप रख रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ये व्यवधान मंत्री बैठे तब न।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अध्यक्ष महोदय, आपके कक्ष में माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय को चाय पर, मिठाई पर आमंत्रित करता हूं, इसके तत्काल बाद।

श्री रामनारायण चौधरी : आप ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : हां, मैं, सच में।

श्री रामनारायण चौधरी : आप तो पानी में आग मत लगाओ और सब ठीक है। किसी को पता नहीं चलता आप पानी में आग लगा देते हो।

श्री अध्यक्ष : पानी में आग लगती ही नहीं है।

समिति का प्रतिवेदन

जन लेखा समिति, 2005-06 के 33 प्रतिवेदन

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार जन लेखा समिति, 2005-06 के निम्न 33 प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं :-

1. जनलेखा समिति, 2002-2003 के 161वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक) समिति का 101वां प्रतिवेदन।
2. जनलेखा समिति, 2003-2004 के 201वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक्) समिति का 102वां प्रतिवेदन।
3. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1999-2000 अनुच्छेद संख्या-6.4 उच्च शिक्षा तथा वर्ष 1999-2000 अनुच्छेद संख्या-3.8 शिक्षा विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 103वां प्रतिवेदन।
4. जनलेखा समिति, 2000-2001 के 67वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक्) समिति का 104वां प्रतिवेदन।

(डा. बुलाकीदास कल्ला))

5. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1999-2000 का अनुच्छेद संख्या 4.1 (आर.) वन विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 105वां प्रतिवेदन।
6. जनलेखा समिति, 2002-2003 के 151वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक्) समिति का 106वां प्रतिवेदन।
7. जनलेखा समिति, 2002-2003 के 152वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक्) समिति का 107वां प्रतिवेदन।
8. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) में समाविष्ट वित्त विभाग से संबंधित अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2000-2001 का अनुच्छेद संख्या 6.2 से संबंधित मामलों पर समिति का 108वां प्रतिवेदन।
9. जनलेखा समिति, 2001-2002 के 110वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक्) समिति का 109वां प्रतिवेदन।
10. जनलेखा समिति, 2000-2001 के 78वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक्) समिति का 110वां प्रतिवेदन।
11. जनलेखा समिति, 2004-2005 के 52वें प्रतिवेदन (12वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक्) समिति का 111वां प्रतिवेदन।
12. जनलेखा समिति, 2002-2003 के 181वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक्) समिति का 112वां प्रतिवेदन।
13. जनलेखा समिति, 2003-2004 के 213वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक्) समिति का 113वां प्रतिवेदन।
14. जनलेखा समिति, 2003-2004 के 215वें प्रतिवेदन (11वीं विधान

सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक्) समिति का 114वां प्रतिवेदन।

15. भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2000-2001 के पैरा संख्या 3.10 में समाविष्ट राजस्व, शिक्षा, सार्वजनिक निर्माण, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य व अन्य विभागों से संबंधित राजकीय धन/सम्पत्ति के दुर्विनियोजन, गबन एवं चोरी इत्यादि प्रकरणों पर समिति का 115वां प्रतिवेदन।

16. वर्ष 2000-2001 तथा 2001-2002 के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट भूमि एवं भवन कर विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 116वां प्रतिवेदन।

17. विनियोग लेखे वर्ष 2000-2001 के बताये गये दत्तमत अनुदानों तथा प्रभृत्त विनियोगों में अतिरेक के मामलों पर समिति का 117वां प्रतिवेदन।

18. जनलेखा समिति, 2000-2001 (11वीं विधान सभा) के 74वें, जनलेखा समिति 2002-2003 (11वीं विधान सभा) के 132वें एवं 175वें प्रतिवेदनों में समाविष्ट क्रमशः वित्त, राज्य आबकारी एवं वाणिज्यिक कर विभागों से संबंधित सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक्) समिति का 118वां प्रतिवेदन।

19. वर्ष 2000-2001 के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट परिवहन विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 119वां प्रतिवेदन।

20. जनलेखा समिति, 2000-2001 के 71वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक्) समिति का 120वां प्रतिवेदन।

21. जनलेखा समिति, 2002-2003 के 139वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक्) समिति का 121वां प्रतिवेदन।

22. जनलेखा समिति, 2004-2005 के 53वें प्रतिवेदन (12वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक्) समिति का 122वां प्रतिवेदन।

(डा. बुलाकीदास कल्ला))

23. जनलेखा समिति, 2002-2003 के 149वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक्) समिति का 123वां प्रतिवेदन।

24. जनलेखा समिति, 2002-2003 के 172वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक्) समिति का 124वां प्रतिवेदन।

25. जनलेखा समिति, 2003-2004 के 204वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक्) समिति का 125वां प्रतिवेदन।

26. जनलेखा समिति, 2002-2003 के 136वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक्) समिति का 126वां प्रतिवेदन।

27. जनलेखा समिति, 2004-2005 के 28वें प्रतिवेदन (12वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक्) समिति का 127वां प्रतिवेदन।

28. जनलेखा समिति, 2001-2002 के 124वें प्रतिवेदन (11वीं विधान सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक्) समिति का 128वां प्रतिवेदन।

29. भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2001-2002 में समाविष्ट ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित अनुच्छेद संख्या 6.5 अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 का अनुच्छेद संख्या 4.5.1 तथा पंचायती राज विभाग से संबंधित वर्ष 2002-2003 का अनुच्छेद संख्या 1.8.2, 4.6.2 तथा 5.1.3 से संबंधित मामलों पर समिति का 129वां प्रतिवेदन।

30. भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 2000 2001 का अनुच्छेद संख्या 4.17, 4.19 एवं 4.21, अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2002-2003 का अनुच्छेद संख्या 2.6, 4.4.4, 4.4.5, 4.4.6, 4.4.7 तथा 4.6.3 सार्वजनिक निर्माण विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 130वां प्रतिवेदन।

31. जनलेखा समिति, 2002-2003 के 144वें प्रतिवेदन (11वीं विधान

(डा. बुलाकीदास कल्ला))

सभा) में समाविष्ट सिफारिशों की परिपालना हेतु शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर (क्रियान्विति विषयक्) समिति का 131वां प्रतिवेदन।

32. वर्ष 2001-2002 के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट परिवहन विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 132वां प्रतिवेदन।

33. वर्ष 2002-2003 के लिये भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (राजस्व प्राप्तियां) में समाविष्ट परिवहन विभाग से संबंधित मामलों पर समिति का 133वां प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष : अच्छी बात है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर अग्रिम वाद विवाद। सर्वप्रथम श्री जोगाराम पटेल। हां, अब आप पाइंट आफ आर्डर पर फरमा दें।

डा. एन.एस. गुर्जर : हां, मैं आपसे परमिशन ले रहा हूं, with your permission. यह जब गवर्नर एड्रेस होता है या बजट होता है तो जो चीजें उसमें बोली जा सकती हैं। हमारे नियमों में प्रावधान है। अध्यक्ष महोदय, आप अच्छी तरह जानते हैं, बहुत सीनियर सदस्य रहे हैं, जो एक बार विषय जो सदन में अभी उस पर दुबारा चर्चा नहीं कराई जा सकती। यह नियमों में प्रावधान है। (व्यवधान) नहीं, नियमों में तो यही प्रावधान है, अब एक्स्ट्रा कहीं हो तो आप मुझे बता दें, मैं सीख लूं।

डा. सी.पी. जोशी : नहीं, यह प्रावधान है कि desirable is not essential. दूसरा, क्योंकि जनरल नैचर के मैटर्स पर माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर यहां सदन में उठाये जा सकते हैं और स्पेसिफिक नैचर के मैटर्स हैं उनको हम दूसरे 295, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव या पर्ची के माध्यम से ही सदन में उठा सकते हैं, जो उसमें नहीं बोल सकते।

श्री अध्यक्ष : क्या पाइंट आफ आर्डर है आपका ? पाइंट आफ आर्डर क्या है वह तो बताएं ?

डा. एन.एस. गुर्जर : सुनिए तो सही, मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है, मैं यह देख रहा हूं 2-3 दिन से कि जब राज्यपाल महोदय का अभिभाषण हो रहा है तब भी ऐसे मामले सदन में आ रहे हैं जिनका अभिभाषण के ऊपर हम बोल सकते हैं। लेकिन उन्हीं मामलों को यहां उठाकर आइदर किसी भी रूप में और आधे घंटे तक एक-एक घंटे तक उस इश्यू पर हंगामा होता रहता है हाउस

(डा. एन. एस. गुर्जर)

के अन्दर। और सदन का कितना पैसा वैस्ट होता है, इस पर अगर उसके बजाय अभिभाषण पर चर्चा हम लोग करें, उसका जवाब आए, तो एक स्वस्थ परम्परा होगी और नियमों की पालना होगी। धीरे-धीरे हम नियमों में कट करते जा रहे हैं। नियमों के बाहर चीजें हैं उसमें एंटर होते जा रहे हैं। मेरा आपसे पाइंट आफ आर्डर यही है कि इस चीज को आप बन्द करिए, ताकि सदन का समय बचे और अनावश्यक जो हो-हुल्लड़ होता है सदन के अन्दर जिससे सदन की इमेज बाहर खराब होती है, बन्द हो। मैं आपसे यही अनुरोध करना चाहता हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह माननीय सदस्य ने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया अभी कोई ऐसी व्यवस्था चल भी नहीं रही थी, उन्होंने इर्रेलेवेंट व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

डा. सी.पी. जोशी : वेरी गुड, आज तो कल्ला साहब सिक्सर हैं, आन सिक्सर मारा है आपने।

डा. एन.एस. गुर्जर : अभिभाषण पर क्या-क्या हो रहा है ? (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसी कोई व्यवस्था चल ही नहीं रही थी।

डा. एन.एस. गुर्जर : क्या इर्रेलेवेंट है ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : इस वक्त इस तरह का मामला जिसका उन्होंने जिक्र किया है व्यवस्था का प्रश्न उठाते तब तो कोई बात बनती। लेकिन इन्होंने अभी जैसे समितियों के प्रतिवेदन रखे गये हैं, यहां पर कहीं कोई व्यवस्था भी वैसी नहीं हुई है जिससे यह व्यवस्था का प्रश्न उठाते।

डा. एन.एस. गुर्जर : ऐसी व्यवस्था तो पर्ची के टाइम पर मैं उठाने लगा तो आपने रोका, आपने ही टोका मुझे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : पर्ची के वक्त व्यवस्था का प्रश्न कभी नहीं उठ सकता। अध्यक्ष महोदय, इस बारे में आप निर्णय ले चुके हैं।

डा. एन.एस. गुर्जर : यह व्यवस्था का प्रश्न कब उठता है, यह बता दीजिए, पचासों बार आपने भी उठाया है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : तो हमारा यही कहना है कि बोलते वक्त पालनीय नियमों का ध्यान रखना चाहिए।

डा. एन.एस. गुर्जर : पचासों बार कल्ला साहब पक्ष और विपक्ष को....

श्री अध्यक्ष : बिजनैस शुरू हो गया था सदन की मेज पर रखे जाने वाले रख रहे थे उसके बाद उठाया है उन्होंने। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : उसके बारे में अलग से रख सकते हैं।

मोहम्मद माहिर आजाद : बहादुरसिंहजी गोदारा जब बोलने खड़े हुए थे तब उठाया था इन्होंने, इतना तो पता है कि जब हाउस में कोई बिजनैस हो तब उठा सकते हैं। बहादुर सिंह गोदारा बोल रहे थे।

डा. एन.एस. गुर्जर : आपको मालूम है जीरो आवर में कितनी बार मैं रेकार्ड दिखाऊं आपको ? जीरो आवर में कितनी बार उठाया गया पाइंट आफ आर्डर, मैं रेकार्ड दिखाऊं ? क्या बात करते हो ?

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री जोगाराम पटेल (लूणी) : माननीय अध्यक्ष महोदया, माननीय राज्यपाल महोदया द्वारा इस सदन में इस गरिमामय आदरणीय सदन में, जो अभिभाषण प्रस्तुत किया, जिसके संबंध में माननीय सदस्य ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा, उसके समर्थन में मैं तथ्यों पर नम्रतापूर्वक इस सदन में अपनी बात रखना चाहता हूं। आदरणीय अध्यक्ष महोदया, राजस्थान की पांच करोड़ जनता के सामने हमें यह एक दस्तावेज के रूप में पूर्व में हुई सरकार की कार्यवाहियों, सरकार के कृत्यों, सरकार के कार्यों, आने वाले भविष्य के लिए सरकार की योजनाओं, सरकार के कार्य का एक दस्तावेज है। और इस दस्तावेज के रूप में मौजूदा सरकार ने जो कार्य किये, आने वाले भविष्य में जो किये जाएंगे, उनका एक प्रकार का लेखा-जोखा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पिछले दो दिन की चर्चा में सार्वजनिक हित के अनेक मुद्दे डिस्कश हुए, माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बात कही। सड़क से सम्बन्धित हो, शिक्षा से सम्बन्धित हो या और कोई विषय हो, मैं उन विषयों में नहीं जाऊंगा, जिनका काफी डिस्कशन यहां हो चुका परन्तु वो विषय जो जनमानस के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, वो विषय जो हर पशुधन, हर मनुष्य और धरती पर जीवित हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है उसके सम्बन्ध में और कुछ ऐसे विषय कानून से सम्बन्धित हैं, माननीय सदस्यों ने उठाये, उनसे सम्बन्धित निवेदन करने का प्रयास करूंगा।

(श्री जोगाराम पटेल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, भौगोलिक दृष्टि से 3 लाख 42 हजार वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ यह राजस्थान, देश का करीब 10.40 प्रतिशत भौगोलिक क्षेत्रफल वाला यह राजस्थान, आबादी के हिसाब से 5.75 प्रतिशत वाला यह प्रदेश, 18.70 प्रतिशत पशुधन वाला यह प्रदेश, सतही जल के हिसाब से मात्र 1.16 प्रतिशत सतही जल रखता है। राज्य में 94 प्रतिशत जो पेयजल योजनाएं हैं वो सतही जल से चल रही हैं। मैं इस सम्बन्ध में आपके मार्फत निवेदन करना चाहूंगा कि भू-जल से सम्बन्धित जो योजनाएं हैं वो 10 प्रतिशत हैं और 10 प्रतिशत पेयजल के काम आती हैं और 90 प्रतिशत पानी खेती के काम में आता है। वर्तमान में पश्चिमी राजस्थान ही नहीं, जोधपुर जिला ही नहीं, मेरा विधान सभा क्षेत्र लूणी ही नहीं, पूरा भारत और मैं यहां तक कहूं तो विश्व पेयजल समस्या से जूझ रहा है। कई भविष्य वक्ताओं ने, कई विद्वानों ने यह घोषणा भी की है कि आने वाला अगर युद्ध होगा, तो वह पानी के लिए होगा। मैं इस सम्बन्ध में आपके समक्ष निवेदन करना चाहूंगा, यह विषय कोई किसी राजनैतिक विचारधारा वाले दल का नहीं, यह विषय किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, यह विषय सार्वजनिक हित का है और सभी को इस पर बहुत गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता भी है। हमारी सरकार ने जितना हो सके, उतना प्रयास किया और वो सब आपके सामने है। पूर्ववर्ती सरकार ने भी प्रयास किये होंगे, वह भी आपके सामने हैं। आने वाले भविष्य की सरकारें भी इस सम्बन्ध में कार्यवाही करेंगी परन्तु इस विषय पर पेयजल, जिसको अंग्रेजी में ड्रिंकिंग वाटर कहते हैं, उसका पूरा का पूरा किस तरह से उपयोग किया जाए, जो जल बहकर चला जाता है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है, जो जल फालतू चला जाता है जिसको रोक नहीं पा रहे हैं, जो नदियों का इधर से उधर पानी बह जाता है उसको रोक नहीं पा रहे हैं। इस विषय पर गम्भीरतापूर्वक माननीय सदस्यों को और इस गरिमामय सदन को विचार करना चाहिए। और एक ऐसा अभियान चलाना चाहिए जैसा अभी राजस्थान सरकार ने, आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने जल अभियान चलाया, जल चेतना जाग्रत की उससे सम्बन्धित निवेदन करूंगा। दलगत भावना से ऊपर उठकर इस विषय पर इस सदन में एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया जाए जिससे कि आने वाला भविष्य सुरक्षित हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले 44 बार अकाल पड़ा और उस अकाल में अधिक भू-जल के दोहन की वजह से प्रदेश के 237 ब्लाक ऐसे हैं जो क्रिटिकल स्टेज में हैं, 46 तो विशेष क्रिटिकल स्टेज में हैं और मात्र

(श्री जोगाराम पटेल)

30 सुरक्षित रह गये हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि सरकारों की इस96 सम्बन्ध में मंशा क्या है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 1999 से 2004 तक के जो बजट आये वो शहरी क्षेत्र में 132 करोड़ के औसतन आये और पूर्ववर्ती सरकारों ने मात्र 132 करोड़ औसतन बजट दिया। इसी तरह से ग्रामीण क्षेत्र में 165 करोड़ का बजट दिया। मौजूदा सरकार आने के बाद माननीय मुख्य मंत्रीजी की इस विषय में गहनता की वजह से, इस महत्वपूर्ण विषय की जानकारी की वजह से आते ही 2004-05 के बजट में इसका बजट बढ़ाकर शहरी क्षेत्र में 196.88 करोड़ किया गया। और ग्रामीण क्षेत्र में 259 करोड़ किया गया तथा 2005-06 में 211 करोड़ शहरी क्षेत्र में और 341 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में किया गया। जो 165 करोड़ ग्रामीण क्षेत्र में थे, उसका 341 करोड़ किया गया। यह हमारी सरकार की उपलब्धि थी और उपलब्धि के मार्फत् पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई। इतना ही नहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में अकाल के दौरान, ग्रीष्म अवधि के दौरान करीब एक लाख गांव-ढाणियों को विभिन्न टैंकरों के मार्फत, विभिन्न पेयजल योजनाओं के मार्फत पेयजल उपलब्ध कराया गया। राज्य में अनेक योजनाएं पेयजल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में प्रारम्भ की गई जिसमें मुख्य रूप से....

श्री अध्यक्ष : यह आवाज कहां से आ रही है ? बन्द करवाइये इसको।

श्री जोगाराम पटेल : 11 हजार करोड़ की बीसलपुर-जयपुर की पेयजल योजना, जिसके सम्बन्ध में यहां बताया गया। अम्ब्रेला परियोजना, बीसलपुर देवली-उनियारा परियोजना, चम्बल-धौलपुर परियोजना, नागौर लिफ्ट परियोजना, जवाई बांध से पाइप लाइन लाने की परियोजना, नर्बदा नहर परियोजना, ये सारी परियोजनाएं मौजूदा सरकार ने प्रारम्भ की और एक मैसेज दिया। इतना ऐतिहासिक कार्य किया जिसके लिए मौजूदा सरकार को बधाई दूंगा। इसके अलावा 4758 करोड़ की नई पेयजल योजनाएं प्रारम्भ की गईं। ये सारी योजनाएं बनाकर सरकार ने आम जनता को, पशुधन को पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु अति महत्वपूर्ण ऐतिहासिक कदम उठाया जिसके लिए मौजूदा सरकार धन्यवाद की पात्र है।

अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा राज्य के सीमित जल संसाधनों के समुचित उपयोग हेतु प्रोफेसर वी. एस. व्यास की अध्यक्षता में एक कमेटी

(श्री जोगाराम पटेल)

गठित की गई। और वह कमेटी यह कार्यवाही कर रही है कि सतही जल का अधिक से अधिक उपयोग किस तरह हो सके, जो पानी बहकर के जा रहा है उसका उपयोग कैसे हो सके, जो अण्डरग्राउंड वाटर है उसका कैसे उपयोग हो सके। 29 जिलों में 23297 गांवों में फ्लोराइड मात्रा में अधिक है जिसमें 34.68 करोड़ की लागत से एकीकृत फ्लोरोसिस उन्मूलन परियोजना स्वीकार की गई और जो यह पानी पीने के लिए उपयोगी नहीं है उसको उपयोगी बनाने का प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, करीब 6 हजार करोड़ की 12 अम्ब्रेला परियोजनाएं, जिनका मैंने ऊपर जिक्र किया, उनकी क्रियान्विति की जा रही है। जल अभियान मुख्य रूप से चलाया जा रहा है, सम्पूर्ण पानी शुद्ध हो उसकी परियोजना चलाई जा रही है। और ऐसी करीब 7 हजार करोड़ की 22 योजनाएं अलग-अलग स्तर पर स्वीकृत की गई हैं और यह सभी कार्य शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु किये जा रहे हैं। मैं इसके लिए विशेष रूप से माननीय मुख्य मंत्रीजी को, जलदाय मंत्रीजी को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र में हिन्दुस्तान आजाद होने के बाद एक भी ऐसी जल प्रदाय योजना प्रारम्भ नहीं की जिसे सतही जल प्रदाय योजना कह सकें। परन्तु मौजूदा सरकार ने, माननीय मुख्य मंत्रीजी, वसुन्धरा राजेजी ने, जलदाय मंत्रीजी ने 57 करोड़ की योजना प्रारम्भ की और उसका काम चल रहा है। दो योजनाएं विचाराधीन हैं जिनसे लूणी क्षेत्र में शुद्ध पेयजल मिल सकेगा। जिसके लिए मैं अलग से विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा।

इसके अलावा दो विषय माननीय सदस्यों ने कल उठाये थे कि यह लैण्ड बैंक बन रहा है इस लैण्ड बैंक में पंचायतों की जमीन ली जा रही है और यह कांस्टीट्यूशनल अवहेलना है और उन्होंने इसका जिक्र आर्टिकल 243 (जी) के सम्बन्ध में किया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आर्टिकल 243 (जी) इस सम्बन्ध में है ही नहीं और आर्टिकल 243 (जी) पावर अथोरिटी एण्ड रेस्पोन्सिबिलिटी आफ पंचायत है उसमें किसी लैण्ड का डिस्पोजल उस लैण्ड का मैनेजमेंट, इनसे कहीं सम्बन्धित नहीं है। किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में अगर

(समय: 13.00 बजे)

कोई नजूल लैण्ड है, वह राज्य सरकार की है, उसका मैनेजमेंट राज्य सरकार के खाते में है और पंचायत के पास धारा 50 का एकमात्र अधिकार है और उस अधिकार के तहत फंक्शन एण्ड पावर आफ द पंचायत, पंचायती राज

(श्री जोगाराम पटेल)

अधिनियम 1994 के तहत है और उसमें किसी भी जमीन की व्यवस्था से सम्बन्धित जो पंचायत के खाते में नहीं है। पंचायत के खाते में एकमात्र आबादी भूमि होती है। और जो बकाया भूमि होती है, वह एज ए ट्रस्टी पंचायत उसका फैसला करती है। और जो शिड्यूल दिया गया है उस शिड्यूल में भी जो नजूल लैण्ड है उसका पंचायत से कोई सम्बन्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में यह जो एतराज किया गया था, यह जो बात बताई गई थी, वह पूर्ण रूप से गलत है। जे.डी.ए. एक्ट की धारा 54 के तहत जो शिड्यूल एक और दो में जितने भी रेवेन्यु विलेज आये हुए हैं करीब 374, वह सारे के सारे रेवेन्यु विलेज की जमीन जे.डी.ए. के कंट्रोल, पावर और अथोरिटी में है और जे.डी.ए. उसके सम्बन्ध में लैण्ड बैंक बनाता है तो कानून की कोई अवहेलना नहीं हो रही है।

दूसरी बात यह उठाई गई थी कि पंचायत की भूमि को बिना पंचायत के पूछे, बिना पंचायत की सहमति लिये लोकतंत्र के विरुद्ध उस जमीन को लैण्ड बैंक बनाया गया है। मेरी प्रार्थना है, मेरा निवेदन है, मेरा अनुरोध है कि यह जो बात कही गई है, वह पूर्ण रूप से गलत है क्योंकि लैण्ड बैंक की भूमि राज्य सरकार के खाते की होती है धारा 92 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट के तहत, उसको सैट-अपार्ट करने का कानूनन अधिकार मात्र राज्य सरकार को है और इसके तहत अगर राज्य सरकार किसी भूमि को व्यवस्थित या सुरक्षित करती है तो यह कहना कि आर्टिकल 243(जी) की अवहेलना हो रही है, यह पूर्ण रूप से गलत है।

इसके अलावा मैं सरकार की महत्वपूर्ण उपलब्धियों की ओर ध्यान दिलाना चाहूंगा, जिसमें महिला सशक्तीकरण के बहुत विशेष प्रयास मौजूदा सरकार के द्वारा किये गये हैं जिसके लिए मैं सरकार को बधाई दूंगा। महिला स्वास्थ्य एण्ड समूह आन्दोलन के तहत विशेष प्रयास कर महिलाओं का आर्थिक सशक्तीकरण वृहद स्तर पर सहायता स्वयं समूह कार्यक्रम शुरू किये गये। एक लाख से अधिक समूहों का गठन किया गया। 38138 महिलाओं को विभिन्न वित्तीय संसाधनों से 72 करोड़ के ऋण उपलब्ध करवाये गये ताकि उनको रोजगार मिल सके। महिलाओं को किस तरह से अधिक से अधिक रोजगार मिल सके, उसकी पूरी की पूरी व्यवस्था की गई है। चार करोड़ की राशि का रिवाल्विंग फण्ड स्थापित किया गया ताकि उनको रोजगार दिलाने में सहायता मिल सके। महिला समिति समूहों को सरकारी बैंकों से 25 करोड़

(श्री जोगाराम पटेल)

रुपये उपलब्ध करवाये गये ताकि जो भी महिला है वह स्वयं अपने पैरों पर खड़ी होकर अपना रोजगार कर सके। 5000 आंगनबाड़ी केन्द्रों में गरम पौष्टिक भोजन, 500 आदिवासी महिलाओं व समूहों को 10000 रुपये प्रत्येक को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई गई ताकि महिलाएं स्वयं सशक्त बनकर अपना जीवन यापन अपने स्तर पर कर सकें।

इतना ही नहीं, आजादी के पहले और आजादी के बाद यह सुनते आये थे कि भूमि में महिला का कोई अधिकार नहीं है। हालांकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में महिला चार प्रकार हक प्राप्त करती है, बेटी के रूप में, पत्नी के रूप में, मां के रूप में और बहिन के रूप में परन्तु राजस्थान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं थी जिसके तहत यह अधिकार मिल सके। यह मौजूदा सरकार ने महिलाओं को अधिक सशक्त करने, महिलाओं को अधिकार देने, महिलाओं को संरक्षण देने के लिए जो स्टाम्प ड्यूटी के सम्बन्ध में पांच प्रतिशत कम जो किया गया, जिसका जिक्र तक आपके सामने बार-बार हुआ है। परन्तु उसके अलावा जो विशेष एक बात की गई, वह यह है कि जब कभी भी लैण्ड अलाटमेंट होगा तो उसमें पति और पत्नी का नाम साथ लिखा जायेगा। यह एक विशेष बात थी और मौजूदा सरकार ने पहली बार राजस्थान में यह व्यवस्था की है। इतना ही नहीं, जो कामकाजी महिलाएं हैं, जिनके लिए 500 आंगनबाड़ी केन्द्र, शिशु पालन गृह की व्यवस्था की गई और उसमें से 434 आंगनबाड़ी केन्द्र और शिशु पालन गृह प्रारम्भ हो गये हैं और 13 कामकाजी महिलाओं के होस्टल स्थापित किये गये हैं। 10 अल्प आवास गृह यानी शोर्ट पीरियड होस्टल की व्यवस्था के रूप में किया गया है।

इतना ही नहीं माननीय अध्यक्ष महोदय, 315 जो विधवाएं हैं, जो परित्यक्ताएं हैं, उनको रोजगार उपलब्ध करवाने हेतु 63 लघु उद्योगों के माध्यम से उनको व्यवस्था उपलब्ध करवाई गई है। 3606 ट्रेनिंग कैम्प खोले गये हैं जहां कि जो महिला है, इसमें से लघु उद्योग का, काश्तकारी का, दस्तकारी का प्रशिक्षण ले सके। 655 खादी ग्रामोद्योग के तहत लाभान्वित किया गया है। 22500 आदिवासी महिलाओं को भी आधुनिक खेती कैसे की जा सकती है, खेती के नये-नये तरीके क्या हैं, उसके सम्बन्ध में प्रशिक्षण दिया गया है। और यह व्यवस्था पहली बार राजस्थान में की गई है जिसके लिए मैं मौजूदा राजस्थान सरकार को बहुत-बहुत बधाई देता हूं। 1040 दुग्ध

(श्री जोगाराम पटेल)

सहकारी समितियां बनाई गईं जिसके तहत 2228 महिला समितियां बनाई गई हैं और विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त करने का प्रयास किया जा रहा है। इतना ही नहीं, श्रेष्ठ पुरस्कार, शिक्षा मित्र इत्यादि के नाम से अनेक योजनाएं चलाकर सरकार यह पूरा प्रयास कर रही है कि महिलाएं सशक्त हों। परन्तु पूर्ववर्ती सरकार ने ऐसी एक भी योजना नहीं चलाकर महिलाओं को रोजगार देने, महिलाओं को अपना रोजगार स्वयं पैदा करने, अपने पैरों पर खड़ा होने के सम्बन्ध में एक भी ऐसी योजना नहीं चलाई। जबकि मौजूदा सरकार ने अपने दो साल के कार्यकाल में इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं। यह सब मौजूदा सरकार के महिलाओं के प्रति, कमजोर वर्गों के प्रति जो परिदृश्य है, जो इच्छा शक्ति है, उसको दर्शाता है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा मैं आपके समक्ष जो महत्वपूर्ण विषय है जिसकी बार-बार यहां चर्चा हो रही है कानून और व्यवस्था, उसके सम्बन्ध में भी आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा और यह निवेदन करना चाहूंगा हमारे प्रतिपक्ष के साथियों से कि बार-बार यह विषय उठाया है कि राजस्थान में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। परन्तु जब आंकड़े देखेंगे, वास्तविकता देखेंगे तो इस नतीजे पर पहुंचेंगे कि राजस्थान में जो कानून व्यवस्था है वह भारत के अन्य राज्यों से बहुत बेहतर है। जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया, 342 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है राजस्थान, कहीं पहाड़ तो कहीं रेगिस्तान और कहीं और तरह की स्थिति है। 1040 किलोमीटर लम्बी अन्तरराष्ट्रीय सीमा है, इस हिसाब से अगर दृष्टि डाली जाये तो सन् 1971 में जो आफेंस थे और वर्तमान में जो आफेंस है, अगर उनका कम्पेरिजन किया जाये, अगर उनका तुलनात्मक विवरण देखा जाये तो मौजूदा सरकार और पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान अगर अपराधों की संख्या के आधार पर देखा जाये तो यह पाया जायेगा कि दिनों दिन अपराधों में कमी हुई है। कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ है और राजस्थान में अमन-चैन है। 1971 की जनसंख्या के अनुसार दो करोड़ 50 लाख जनसंख्या थी राजस्थान में और उस समय 36343 अपराध घटित हुए थे और उसमें पुलिस बल की संख्या थी, नफरी थी वह 38800 थी। मौजूदा 2004 में जब करीब साढ़े पांच करोड़ की आबादी हुई है तो अपराध 154859 हुए हैं, करीब पांच गुना बढ़े हैं। जबकि पुलिस की नफरी है वह मात्र दो गुना बढ़ी है। पुलिस की नफरी नहीं बढ़ी। पूर्ववर्ती सरकार का कोई प्रयास नहीं रहा, कभी कोई भर्ती नहीं की, किसी को

(श्री जोगाराम पटेल)

रोजगार नहीं दिया और इसकी वजह से पुलिस बल में दिनों दिन कमी होती गई। 1974 में 710 व्यक्तियों पर एक पुलिसकर्मी था और 2004-2005 में 950 व्यक्तियों पर एक पुलिसकर्मी है। और यह जो रेशो घटता गया, इसका भी एक कारण बना। साथ ही साथ जो अन्तरराष्ट्रीय सीमा है, जो प्रदेशों की सीमा है, आवागमन के साधन, कम्युनिकेशन के साधन, इनकी वजह से जो अपराध हुए परन्तु उसके बावजूद भी राजस्थान में अपराध घंटे और अपराध भविष्य में नहीं हो, अपराध कम से कम हो, आम जनता शान्ति से रहे, इसके लिए विशेष प्रयास किया गया। जबकि पूर्ववर्ती सरकार में ऐसा कोई प्रयास नहीं किया। पुलिस बल का पुनर्गठन किया गया, समितियों का गठन किया गया और जिसकी रिपोर्ट अभी शीघ्र आने वाली है और समितियों की रिपोर्ट आने के बाद पुलिस का पुनर्गठन होने वाला है, उसके सम्बन्ध में प्रयास किया जा रहा है। 2004-2005 में शान्ति सुरक्षा, आन्तरिक सुरक्षा, अपराध नियंत्रण की स्थिति संतोषजनक रही। मात्र सराडा, मांडल के अलावा कहीं भी छोटी-मोटी घटना भी नहीं हुई और ये घटनाएं भी सर्वदलीय प्रयासों से तुरन्त नियंत्रण में कर ली गई। पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान जो साम्प्रदायिक दंगे हुए अनेक स्थानों पर, ऐसा एक भी कोई दंगा नहीं हुआ। आतंककारी घटना भी घटित नहीं हुई। कोई बोर्डर क्रोसिंग बहुत अधिक कम हुए और विशेष रूप से जो 110 बांग्लादेशी नागरिक हैं, उनको आइडेंटिफाई किया गया, बाहर निकाला गया। इसी तरह अनेक जो तस्कर लोग थे उनको आइडेंटिफाई किया गया और बाहर निकाला गया। यह सारे प्रयास शांति-व्यवस्था के लिए किये गये।

कम्प्यूटर, साइबर कैफे, तीन जिलों में विज्ञान प्रयोगशाला, यह सभी कार्य इसीलिए किये गये कि शांति-व्यवस्था में सहायता मिले। बजट का प्रावधान जो 2004-05 में 878 करोड़ था वह 2005-06 में 918 करोड़ बढ़ाया गया जबकि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान अत्यन्त ही कम था। ऐसी स्थिति में, माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार के प्रयास हैं जिससे शांति व्यवस्था कायम हुई है जबकि पूर्ववर्ती सरकारों के दौरान ऐसी कोई व्यवस्था नहीं की गई। पुलिस के आधुनिकीकरण के लिए अनेक कार्यक्रम बनाये गये। प्रारम्भ में जो पुलिस की नफरी कम है उसके सम्बन्ध में प्रयास किये गये। 2004-05 के प्रारम्भ में 2333.12 लाख के आस-पास जो थी, उनको बढ़ाकर मोटर साइकिलें दी गईं, 344 मोटर साइकिल्स, 238 लाइट मोटर्स, 8 वीडियो मोटर व्हीकल्स, 13 हैवी मोटर व्हीकल्स, 224 बोटल कापियर्स, 242

(श्री जोगाराम पटेल)

हार्डली मैटल डिटेक्टर, 50 दरवाजे, 350 वायरलैस सेट, यह आधुनिक व्यवस्था हेतु पुलिस को उपलब्ध कराये गये जिनकी वजह से, जिनकी सहायता से, जिनके आधार पर पुलिस अपराध को नियंत्रण कर सके। यह सारे कार्य मौजूदा सरकार में किये गये जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने ऐसे कोई प्रयास नहीं किये। पुलिस और आम जनता में सामंजस्य बैठाने हेतु जन समुदाय का सामंजस्य कार्यक्रम रखवाया गया, पुलिस कल्याण कार्यक्रम भी किये गये और यह सारे काम इसी वजह से किये गये कि जनता में यह मैसेज जाये कि पुलिस पूरी व्यवस्था कर रही है, पुलिस सतर्क है और आम जनता सुरक्षित है।

मैं आपके सामने आंकड़ों के आधार पर यह भी बताना चाहूंगा कि 2003 में 1 लाख 45 हजार अपराध घटित हुए, 2005 में 1 लाख 40 हजार 917 अपराध घटित हुए, अपराध निरन्तर घटते जा रहे हैं, हर वर्ष अपराधों का जो आंकड़ा है, वह घटता जा रहा है। इतना ही नहीं, दर्ज अपराधों का निस्तारण भी मौजूदा सरकार के कार्यकाल के दौरान बहुत अधिक हुआ। वर्ष 2005 में 82.21 प्रतिशत चालान हुए और मात्र 2.46 प्रतिशत अपराध पेण्डिंग हैं जबकि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल के दौरान 50 प्रतिशत, 45 प्रतिशत, 55 प्रतिशत अपराधों में चालान नहीं होते थे, पेण्डिंग रहते थे। इसी हिसाब से मौजूदा जो रिक्त पद हैं उनकी भर्ती की भी कार्यवाही चल रही है, छह हजार कांस्टेबल्स की भर्ती, 1418 ए.एस.आई. के पद स्वीकृति, दो महिला थाने गंगानगर और जयपुर, 24 नये बिजली की चोरी की रोकथाम हेतु थाने, 90 थानों में 180 महिला डेस्कों की स्वीकृति, 10 नई पुलिस चौकियां जो गौवंश को रोकने हेतु मेवात क्षेत्र में, अलवर में पांच, भरतपुर में पांच, स्थापित की गई, छह सम्भागीय मुख्यालयों पर पुलिस परामर्श सहायता केन्द्र स्वीकृत किये गये जिसके लिए 48 पद स्वीकृत किये गये। सात नई पुलिस चौकियां जिसके लिए 48 पद स्वीकृत किये गये, सात पुलिस रेंजों में 42 पद स्वीकृत, उनकी भर्ती की कार्यवाही चल रही है, 117 पुलिस प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित किये गये। यह सब इसीलिए किया गया है कि पुलिस शांति-व्यवस्था स्थापित कर सके, आम जनता को शांति मिल सके। (व्यवधान) यह इसमें बहुत कुछ लिखा हुआ है पर पढ़ने वाला ही पढ़ सकता है और आपकी नजर में वह आ नहीं सकता, आपके चश्मा दूसरा लगा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : आप बैठे हुए की बात का जवाब नहीं दें, आप तो अपना भाषण रखें जारी।

श्री जोगाराम पटेल : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सारे आंकड़े शो कर रहे हैं कि मौजूदा सरकार कानून-व्यवस्था बनाने में पूर्ण रूप से सक्षम रही है और गहनता से, गम्भीरता से हर स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास किया है। और इतना प्रयास किया है जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने कोई प्रयास नहीं किया। इसके अलावा विशेष रूप से नर्बदा नहर परियोजना जो पश्चिमी राजस्थान के लिए एक जीवन रेखा के रूप में साबित होगी, चाहे बाड़मेर हो, चाहे जालौर हो, चाहे वह पीने के पानी की व्यवस्था हो, चाहे खेती की व्यवस्था हो, 1450 करोड़ की लागत की यह योजना जिसके संबंध में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने विशेष प्रयास कर इस योजना को स्वीकृत करवाया। और जो पुरानी बकाया राशि थी राजस्थान सरकार के हिस्से की, वह गुजरात सरकार को जमा करवाई। कल ही गुजरात विधान सभा के एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने राजस्थान सरकार के कमिटमेंट की तरह, जून, 2006 तक इसका पानी गुजरात के बोर्डर को क्रास कर राजस्थान में आयेगा, ऐसा एक प्रश्न के लिखित उत्तर में जवाब दिया। राजस्थान सरकार भी इसके लिए कमिटेड है, इससे 2.46 लाख हैक्टेयर में खेती होगी, जो जालौर और बाड़मेर के गांव हैं, 1107 गांवों और 2 कस्बों में पेयजल की सुविधा है, आम जनता को पीने का मीठा पानी मिलेगा। बेहतर वित्तीय प्रबंधन कर गुजरात की पांच वर्ष से लम्बित राजस्थान की हिस्सा राशि 375 करोड़ का भुगतान किया गया जबकि पूर्ववर्ती सरकार ने ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं बनाया, ऐसा भुगतान नहीं किया और पानी मिल सके जनता को, ऐसा कोई प्रयास नहीं किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसके अलावा जो महत्वपूर्ण कार्य मौजूदा सरकार में हुए, शिक्षा से संबंधित, जिसकी जानकारी आपको माननीय सदस्यों ने दी, सड़क से संबंधित जो कार्य हुए जिसकी जानकारी माननीय सदस्यों ने आपको दी। हिन्दुस्तान के इतिहास में पहली बार शिक्षा में इतने अधिक कार्य हुए, चाहे स्कूलें क्रमोन्नत करने का काम हो, चाहे राजीव गांधी स्कूलों को क्रमोन्नत करने का काम हो, चाहे नई प्राइमरी स्कूल खोलने का काम हो, चाहे पांचवीं से आठवीं क्रमोन्नत करने का काम हो, चाहे आठवीं से दसवीं क्रमोन्नत करने का काम हो या दसवीं से ग्यारहवीं क्रमोन्नत करने का हो, हिन्दुस्तान के इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में पहली बार इतनी स्कूलें क्रमोन्नत की गईं। यह सरकार की मंशा स्पष्ट करता है। शिक्षा का स्तर सुधरेगा तो

(श्री जोगाराम पटेल)

राज्य का विकास होगा। शिक्षा हर नागरिक के लिए अत्यन्त जरूरी है और जो शिक्षकों की भर्ती, शिक्षकों का प्रमोशन और जितनी सुविधाएं विद्यालय को देनी चाहिए, जितना ऐतिहासिक काम मौजूदा सरकार ने किया है उतना कभी पूर्ववर्ती सरकार ने प्रयास भी नहीं किया। मैं इसके लिए आदरणीय मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी को धन्यवाद और बधाई देता हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मैंने आंकड़ों सहित मेरे एक साल के कार्यकाल के उपरान्त बताया था...

श्री अध्यक्ष : शिक्षा मंत्रीजी, आपको बधाई दे रहे हैं, आप तो बातें कर रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल : उन्होंने जो 57 साल में नहीं किया, वह मौजूदा सरकार ने एक साल में कर दिया। स्कूलों का क्रमोन्नत करना हो...

श्री अध्यक्ष : आपको बधाई दे रहे हैं, आप बातें कर रहे हैं। वह आपको बधाई दे रहे हैं।

श्री जोगाराम पटेल : मैं विशेष रूप से इस बात के लिए भी बधाई दूंगा कि इस साल एक सीनियर हायर सैकण्डरी गर्ल्स, दो सैकण्डरी स्कूल गर्ल्स, दो स्कूलें बायज की क्रमोन्नत कीं सैकण्डरी और हायर सैकण्डरी। इसके अलावा 22 राजीव गांधी पाठशालाओं को प्राइमरी में क्रमोन्नत और 9 प्राइमरी नई और पांच मिडल स्कूलें खोलीं। यह इतनी कभी भी राजस्थान के इतिहास में, लूणी विधान सभा क्षेत्र में नहीं खुलीं, जितनी इस शैक्षणिक सत्र में खोली गई हैं, जिसके लिए मैं विशेष धन्यवाद आदरणीय मुख्य मंत्रीजी और शिक्षा मंत्रीजी को दूंगा।

इतना ही नहीं, सड़क के क्षेत्र में प्रधान मंत्री रोजगार योजना के तहत व अन्य योजनाओं के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र में करीब एक अरब रूपये की सड़क योजनाओं का काम हुआ है जबकि हिन्दुस्तान के इतिहास में, राजस्थान के इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ। पूर्ववर्ती सरकार के माननीय विधायक या माननीय मंत्री रहे होंगे परन्तु उन्होंने भी इतने प्रयास नहीं किये। कोई पेयजल योजना नहीं लाये, कोई सड़क के संबंधित योजना नहीं लाये, कोई स्कूल क्रमोन्नत नहीं किया। उनके कार्यकाल में, हिन्दुस्तान आजाद होने के बाद मात्र 11 हायर सैकण्डरी स्कूलें हैं और एक साल में एक हायर सैकण्डरी स्कूल, उनके इतिहास में कुल 25 सैकण्डरी स्कूल हैं जबकि इस साल

(श्री जोगाराम पटेल)

चार सैकण्डरी स्कूल, उनके इतिहास में 140 प्राइमरी स्कूल हैं और हमने 32 स्कूलें एक साथ दे दीं, तो यह सारा शो करता है कि मौजूदा सरकार काम करना चाहती है, काम किया है और भविष्य में भी काम करना चाहती है। सड़क के मामले में 250 की जनसंख्या वाले, 500 की जनसंख्या वाले सारे गांव सड़क से जुड़ गये हैं और दो-चार योजनाएं अभी भी चल रही हैं और 250 की जनसंख्या वाले जो गांव हैं उनका सर्वे का काम चल रहा है। जोधपुर जिला मरूस्थलीय क्षेत्र के अन्दर आता है और उस योजना के तहत 250 की जनसंख्या के जितने भी रेवेन्यू विलेज हैं उनको जोड़ने का काम चल रहा है और साथ ही साथ एक हमारी सरकार और हमने जो प्रयास किया। जो रेवेन्यू विलेज डिक्लेयर नहीं हैं 2001 की जनगणना के अनुसार विलेज की श्रेणी में नहीं आते हैं परन्तु उसमें एक हेबिटेशन वर्ड है, जो रेवेन्यू विलेज नहीं है परन्तु हेबिटेशंस हैं, 250 की जनसंख्या से ऊपर हैं, उनको हेबिटेशंस का प्रमाणित करवा कर जुड़वाने का प्रयास किया जा रहा है। जिसके लिए मैं आदरणीय राजेन्द्र सिंहजी, सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का विशेष रूप से आभारी हूं कि उन्होंने इसमें हमारा पूरा सहयोग किया है। इतना ही नहीं, मिसिंग लेन, डब्लू.बी.एम. से बीटी और जो विशेष योजनाओं के तहत सड़के हैं, उसके लिए भी विशेष प्रयास किया। कई ऐसी सड़कें थीं जो 20-20, 30-30 सालों से ऐसे ही पड़ी थी उन सड़कों को जोड़ा है और आम जनता में यह अमन स्थापित हुआ है कि यह सरकार विकास के काम कर रही है। विकास के काम करने की इसकी मंशा है और इसी मंशा, कर्मणा और वाचना के साथ यह सरकार काम कर रही है। इसलिए हमारे राजस्थान की जनता पश्चिमी राजस्थान में लूणी विधान सभा क्षेत्र की जनता इस सरकार के काम काज से अति प्रसन्न है। इसके लिए मौजूदा सरकार बधाई की पात्र है। इतना ही नहीं आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके समक्ष कुछ विशेष उल्लेख के तहत यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि सड़क, पानी के अलावा बिजली के मामले में भी पूर्ववर्ती सरकार ने कोई कार्यवाही नहीं की। पिछले 57 साल के कार्यकाल के दौरान 12 करोड़ रुपये की रेवेन्यु बिजली के मामले में बकाया रखी। करीब 26 हजार के कंज्यूमर होने के बावजूद भी 161 रेवेन्यु विलेज होने के बावजूद भी एक ही सब डिवीजन रखा 150 किलोमीटर की दूरी, 26 हजार कंज्यूमर, 161 रेवेन्यु विलेज और इन सबके बावजूद भी कभी भी उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया। लम्बे-लम्बे तारों की लहरें झूलती हुई अगर एक जगह कंप्लेंड

(श्री जोगाराम पटेल)

मिले तो तीन दिन बाद दूसरी जगह पहुंचेंगे। परन्तु मौजूदा सरकार ने इस एक डिवीजन को दो डिवीजन बनाने के संबंध में प्रयास शुरू किये जिसके लिए मैं आदरणीय बिजली मंत्रीजी का बहुत-बहुत तहेदिल से आभार व्यक्त करता हूं।

मैं विशेष रूप से राजस्थान की ओजस्वी मुख्यमंत्री वसुन्धराजी का अभिनन्दन करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा, धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जैसा कहा वैसा करके बताया। वहां इलेक्शन के बाद तुरन्त ही उन्होंने जो सबसे महत्वपूर्ण योजना थी पेयजल योजना उस पेयजल योजना का शिलान्यास किया और 57 करोड़ रुपये स्वीकृत किये। और 57 करोड़ रुपये स्वीकृत ही नहीं किये जो तीन साल का टारगेट था उस योजना को पूरा करने का उसको घटा करके दो साल किया और यह कहा कि योजना दो साल के अन्दर-अन्दर पूरी होनी चाहिए। यह मंशा, वाचा और कर्मणा है सरकार की। जबकि पूर्ववर्ती सरकार के पूर्ववर्ती मंत्री चाहे जलदाय मंत्री रहे हों परन्तु उन्होंने ऐसी कोई योजना नहीं बनायी इसलिए मे विशेष रूप से बधाई देना चाहूंगा मेरे विधान सभा क्षेत्र में जो पेयजल योजना स्वीकृत की स्वीकृत ही नहीं की फण्ड अलाट किया, सैंक्शन किया, काम शुरू किया और काम चल रहा है। इतना ही नहीं जो 74 विलेज मेरे बकाया रह गये थे उनके लिए करीब 35 करोड़ रुपये की योजना बनवाकर सरकार के समक्ष विचाराधीन है और यथाशीघ्र वो भी स्वीकृत हो जाएगी ऐसी मुझे पूरी आशा है और इसलिए पूरा लूणी विधान सभा क्षेत्र जो पश्चिमी राजस्थान का एक भाग है वो पूरा का पूरा पेयजल समस्या से हमेशा-हमेशा के लिए सुरक्षित रह जाएगा ऐसा प्रयास कभी भी नहीं किया गया जबकि मौजूदा सरकार ने किया।

अध्यक्ष महोदय, राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान को ध्यान में रखते हुए पश्चिमी राजस्थान में चाहे वो बाड़मेर हो चाहे जालौर हो चाहे इधर का बैल्ट हो सबसे अधिक जीरा पैदा होता है। हमारी लम्बे समय से यह मांग थी कि हमारा सारा जीरा बिकने के लिए ऊंझा मंडी जाता था। परन्तु जोधपुर में मंडी की घोषणा करके एक अति महत्वपूर्ण कदम उठाया गया और इस कदम से जो फायदा ऊंझा मंडी को मिलने वाला था वो फायदा अब राजस्थान में पश्चिमी राजस्थान में और जोधपुर में काश्तकारों को और व्यापारियों को मिलेगा जबकि ऐसा पूर्व में कभी भी नहीं किया गया। इतना ही नहीं जो एम्स का मामला लम्बे समय से राजनीतिक कारणों से अटका रही थी पूर्ववर्ती सरकार और मेरे प्रतिपक्ष के साथी। इसके लिए सरकार ने विशेष प्रयास किया

(श्री जोगाराम पटेल)

मुख्य मंत्रीजी ने विशेष प्रयास किया और एम्स का अति महत्वपूर्ण जो प्रोजेक्ट है उसके जितने भी विवाद उत्पन्न किये गये वो राजनीतिक भेदभाव से केन्द्र की सरकार ने जो भी रोड़े लगाये। उन रोड़ों को खतम करके इसकी बाधाएं दूर की गई और एम्स का प्रोजेक्ट जोधपुर में प्रारम्भ हुआ। यह सारा कार्य राजनीतिक भेदभाव की वजह से राजनीति द्वेषता की वजह से मेरे प्रतिपक्ष के साथी केन्द्र में बैठे उनके साथी जानबूझकर इसलिए कर रहे थे कि प्रोजेक्ट यहां स्टार्ट नहीं होना चाहिए। परन्तु माननीय अध्यक्ष महोदय, आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने अति विशेष प्रयास कर इसको प्रारम्भ किया और प्रारम्भ कर सारी बाधाएं दूर की इसके लिए मैं धन्यवाद दूंगा।

इसके अलावा एक विषय हमारे प्रतिपक्ष के साथियों ने उठाया था शिक्षा संकुल का नाम राजीव गांधी से डा. राधाकृष्णन किया जा रहा है। इस संबंध में मैं इतना निवेदन अवश्य करना चाहूंगा कि राधाकृष्णन वो हस्ती हैं वो शिक्षाविद् हैं जिनका नाम इतिहास में नहीं हर व्यक्ति को फक्र के साथ लेने में आनन्द आता है और उनके नाम का अगर कोई संकुल स्थापित हो उसके संबंध में भी राजनीतिक भेदभाव की वजह से आरोप लगाया जाए, मेरा यह निवेदन है कि यह गलत है। इतना ही नहीं कई सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि कृषि कार्यों पर ध्यान नहीं दिया गया जबकि मौजूदा सरकार ने सबसे अधिक कृषि कार्यों पर ध्यान दिया है। पेयजल योजनाओं पर ध्यान दिया है, ऊर्जा क्षेत्र में ध्यान दिया है, शिक्षा के क्षेत्र में ध्यान दिया है। इतना ही नहीं जो भी समाज के कमजोर वर्ग हैं उनकी उन्नति कैसे हो सकती है चाहे आदिवासी क्षेत्र हो चाहे और कोई क्षेत्र हो उनके संबंध में पूरे प्रयास किये गये उनको सशक्त बनाने का पूरा प्रयास किया गया। और ये सब इसीलिए किया गया कि राजस्थान का सर्वांगीण विकास हो। इसलिए मैं मौजूदा सरकार को तहेदिल से बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा और आपको भी धन्यवाद दूंगा कि आपने बोलने का समय दिया। धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री अध्यक्ष : श्री ज्ञानचन्द पारख।

(समय : 13.27 बजे)

(डा. एन.एस. गुर्जर, सभापति, पदासीन)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली) : माननीय सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल द्वारा इस पवित्र सदन में जो अभिभाषण दिया गया और उसके ऊपर माननीय डा. एन.एस. गुर्जर ने जो धन्यवाद प्रस्ताव पर अपने समर्थन का

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

वक्तव्य दिया, मैं भी उसका समर्थन करता हूं। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण हमारी सरकार की सवा दो साल की उपलब्धियों का ब्यौरा था, हमारी सरकार ने राजस्थान के चहुंमुखी विकास के लिए जो कार्य किये उसका लेखा जोखा इस अभिभाषण में दर्ज था। हमारी सरकार के कार्यकाल में समाज के हर वर्ग के उत्थान और कल्याण के लिए जो भी काम किये गये उसका ब्यौरा भी बताया गया। कौन-कौन सी उपलब्धियां जो हम हासिल करने जा रहे हैं उसके लिए सरकार क्या प्रयास कर रही है क्या कदम उठा रही है उसकी जानकारी भी सदन को दी। ये दो साल हमारी सरकार के ऐतिहासिक वर्ष रहे। हमने जो काम किया मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि हम और हमारा प्रदेश राजस्थान सुनहरे कल की ओर बढ़ रहा है और आने वाले कुछ सालों में हम देश के विकसित प्रदेशों में से पहले नम्बर पर होंगे।

माननीय सभापति महोदय, हमें जो जनादेश मिला, हमने विश्वास से यह जनादेश प्राप्त किया और जनादेश के बाद में हमारी नीति और नीयत दोनों ठीक होने के कारण हमें लगातार सफलता मिलती रही। हमारी जो माननीय मुख्य मंत्रीजी हैं चुनाव के पहले परिवर्तन यात्रा के दौरान राजस्थान के गांव-गांव में घूमी। किस गांव में क्या समस्या है, उस समस्या का समाधान क्या है, उस गांव में विकास की सम्भावनाएं कैसे बन सकती हैं, समाज के कौनसे वर्ग की आर्थिक स्थिति कैसी है, शैक्षणिक स्थिति कैसी है, उसकी सामाजिक स्थिति कैसी है, इन सारी बातों की जानकारी उन्होंने उस समय प्राप्त की। और उस समय से ही उन्होंने जनता को विश्वास दिला दिया था कि यदि हमें जनादेश दिया, हमें अवसर दिया तो हम आपके विश्वास पर खरा उतरेंगे। हमने जनादेश कोई असत्य बोलकर या झांसे से नहीं लिया। सवा सात साल पहले आपको भी जनादेश मिला था। आपने कैसे लिया आपको पता है। साढ़े आठ साल तक आप सत्ता से बाहर थे और आपको सत्ता में आने की कुलबुलाहट थी। समाज का कौनसा तबका किस कारण से सरकार से नाराज है आपने वह चीजे ढूंढी, वह बातें ढूंढी और आपने सत्ता हासिल करने के लिये प्रदेश की जनता के साथ धोखा किया, नये-नये तरीके के आपने हथकंडे अपनाये। उस समय कर्मचारियों से वादा किया, आपको पता था कर्मचारी सरकार से नाराज हैं और आपने वादा किया, आपने विश्वास दिलाया कि आपकी जितनी भी सुविधाएं हैं, आपकी जितनी भी मांगे हैं हमारी सरकार मानेगी। उनको अपनी ओर खींचने का गलत तरीके से प्रयास किया। बेरोज़गारों

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

को आपने झांसा दिया। प्रदेश में बहुत बड़ी मात्रा में बेरोजगारी फैली हुई है। आपने उसकी नब्ज को देखा कि यह रोजगार चाहते हैं आपने उनके साथ भी दगा किया। आपने चुनाव में यह भरोसा दिलाया, विश्वास दिलाया कि आपकी सरकार अगर आई, अगर आपको जनादेश मिला तो आप रोजगार के अवसर दोगे। लेकिन चुनाव के बाद क्या हुआ, आपने एक भी नौकरी अपने पांच साल के कार्यकाल में किसी बेरोजगार को नहीं दी और इतना ही नहीं आपने तो रोजगार के अवसर भी सदा सदा के लिये खतम करने का काम किया। 50 हजार से ज्यादा पद आपने खतम कर दिये। चाहे कोई वर्ग हो, किसानों को भी झांसा दिया आपने कि पर्याप्त मात्रा में बिजली देंगे। आपके हित भी हित हैं उनकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन आपके राज में किसानों की स्थिति बहुत ज्यादा दयनीय हो गई। लेकिन हमने ऐसा प्रयास नहीं किया। हमने जो कहा एक-एक कर उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास इन सवा दो साल के शासनकाल में लगातार कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे और इसके परिणाम आप खुद देखेंगे।

कल नगर से आने वाले माननीय सदस्य गेहूं को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित थे कि राजस्थान में गेहूं की हालत बहुत ज्यादा खराब है। गेहूं बहुत ज्यादा महंगा हो गया। बीपीएल वालों को राशन का गेहूं मिल नहीं रहा और यह भी चर्चा कर रहे थे कि उनके कांग्रेस काल में अकाल के दौरान इतना गेहूं दिया गया कि उनके घरों में, जब अच्छी वर्षा हुई, तब भी इतना गेहूं नहीं आया। मैं उनको बताना चाहूंगा आपको शायद याद नहीं होगा कांग्रेस काल में पहली बार राजस्थान में भूख से बहुत बड़ी संख्या में मौतें हुई थीं। राजस्थान की धरती को यह बहुत बड़ा कलंक आपकी सरकार के काल में लगा। एक नहीं पांच सौ के करीब भूख से मौते हुईं। हाई कोर्ट ने भी इस बात को माना था कि इसमें आपकी सरकार जिम्मेदार है और हाई कोर्ट ने इस बात को लेकर आपको लताड़ भी लगाई थी।

श्री श्रवण कुमार : भूख से एक भी नहीं हुई होगी।

श्री सभापति : वह बोल रहे हैं आप बाद में जवाब दे देना। प्लीज नो इन्ट्रप्शन।

श्री ज्ञानचन्द पारख : माननीय माहिर आजाद साहब जब यह निर्दलीय सदस्य थे तब यह मुद्दा उन्होंने खुद ने उठाया था। सभापति महोदय, हाई कोर्ट ने इस बात को माना था और इनकी सरकार को लताड लगाई थी।

मोहम्मद माहिर आजाद : हाई कोर्ट ने या सुप्रीम कोर्ट ने? यह तो जरा करेक्ट करें आप।

श्री ज्ञानचन्द पारख : सुप्रीम कोर्ट ने लताड़ लगाई थी आपको।

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, गत वर्ष बारां में जो हुई सहरिया आदिवासी क्षेत्र में वह बता रहे हो या पहले की बता रहे हो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री ज्ञानचन्द पारख : मैं कांग्रेस काल की बात कर रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : 500 कहां-कहां हुई जरा उसकी डिटेल भी आप दे देंगे तो मैं आपका अहसानमंद रहूंगा।

श्री सभापति : माननीय सदस्य आप विराजिए, आप एक मिनट विराजिये। देखिये यह वाद विवाद हो रहा है जब इधर से बोले तो इधर से टोकना शुरू कर देते हैं, इधर से बोले तो इधर से टोकना शुरू कर देते हैं। चूंकि वाद विवाद है दोनों तरफ के माननीय सदस्य बोल रहे हैं। आप पाइंट नोट कर लीजिए। जब उसका जवाब देना है तो खड़े होकर जब बोलते हैं तो उसका जवाब दे दीजिए। बीच-बीच में बहस करने से वह भी डिस्टर्ब होते हैं आप भी डिस्टर्ब होते हैं। इसलिए जब माननीय सदस्य बोले आप पाइंट नोट कीजिए, कोई बहुत आपत्तिजनक बात बोले तब अलग बात है, लेकिन हर बात पर ही एक-एक इश्यू पर बहस करना शुरू कर दें that is not desirable. Please carry on.

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, मैं तो कल बोल चुका अब मैं तो जवाब देने वाला नहीं हूं।

श्री सभापति : आपकी पार्टी से कहिये, अभी माननीय बीडी कल्ला साहब, संयमजी लोढा बोलेंगे।

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा नाम लेकर कोई बात कही जाये तो उसको तो करेक्ट करना पड़ेगा।

श्री सभापति : आपका नाम लेकर कही गई है तो आप पहले परमिशन सीक कीजिए for personal explanation. Thereafter you can speak on that.

मोहम्मद माहिर आजाद : आपसे इजाजत लेकर ही तो कह रहा हूं, आपसे इजाजत लिये बिना नहीं कहूंगा।

श्री सभापति : थैंक्यू, बैठ जाइये।

श्री ज्ञानचन्द पारख : सभापति महोदय, जब राजस्थान में भुखमरी के हालात हो गये थे। तो उस समय केन्द्र की सरकार जो हमारी पार्टी की थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधान मंत्री थे, कोई व्यक्ति भूख से नहीं मरे, इसलिए गेहूं के गोदाम खोल दिये। और राजस्थान सरकार को बहुत बड़ी मात्रा में गेहूं का आबंटन किया। और माननीय सदस्य कह रहे हैं कि उनके काल में अकाल में इतना गेहूं घरों में आ गया जितना सुकाल में भी नहीं आया। यह गेहूं भी हमारा दिया गया था और अगर हम गेहूं नहीं देते तो शायद हालात कुछ और होते और मैं यह कह दूं कि इस गेहूं ने तो आपकी पार्टी की लाज और साख बचा दी। आपने चुनाव मे खास मुद्दा यही बनाया, चुनाव में भी मुख्य मुद्दा यही था। हमने अकाल में इतना गेहूं दिया और आप हमको वोट दो और कोई मुद्दा इनके पास चुनाव में नहीं था। कोई काम का मुद्दा नहीं था। अकाल में गेहूं जो घरों में पहुंचा हमारी सरकार का दिया हुआ, हमारी पार्टी का दिया हुआ। अगर उस समय अटलजी की सरकार गेहूं नहीं देती तो जितनी संख्या में आज यह आये हैं ना आज 54 हैं शायद 4-5 तक सीमित रह जाते, खाता खुल जाता कहीं से भी। आप तो धन्यवाद दो माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी की सरकार को, राजग की सरकार को जिन्होंने आपकी लाज रख दी और आज आप गेहूं के ऊपर राजनीति कर रहे हो। कल आपने आरोप लगाया कि हमारी सरकार गेहूं नहीं उठा रही है। वहां आप मना करवा रहे हो कि उनको गेहूं मत दो। पहले भी आपने गेहूं के ऊपर राजनीति की और आज भी वही पासा आप वापस चलाना चाहते हो ताकि यह जनता झांसे में आ जाये, धोखे में आ जाये, हमारी सरकार को बदनाम कर दें। मैं आपको स्पष्ट कर दूं आज तक आप गेहूं खाते आये हो अगर गेहूं के ऊपर ज्यादा राजनीति की तो यह गेहूं कल आपकी पार्टी को पूरा का पूरा निगल जायेगा यह मानकर चलना आप।

सभापति महोदय, नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इस अभिभाषण पर चर्चा के दौरान इस बात पर सहमति जताई कि हमारी सरकार ने बहुत विकास किया, हमारी सरकार ने बहुत काम किया। पर यह कहकर कि हमने लोकतांत्रिक परम्पराओं को, व्यवस्थाओं को कमजोर किया हमारे काम में पारदर्शिता नहीं, यह कह कर उन्होंने अभिभाषण का समर्थन करने में अपनी ओर से असमर्थता जताई। हमने कभी लोकतंत्र को कमजोर नहीं किया। लोकतंत्र को इस देश में किसी ने कमजोर किया है तो उसके लिये भी आप

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

स्वयं जिम्मेदार हो। हमारी पार्टी में पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था है, सारे निर्णय सामूहिक आधार पर लिये जाते हैं, सब मिलकर करते हैं। ऊपर से कोई निर्णय आ गया और वह मानना, ऐसा हमारी पार्टी में हम आपस में बैठकर निर्णय करते हैं। मैं आपसे यह भी कह दूं कि किसी भी बड़े व्यक्ति ने भी कोई निर्णय ले लिया....

श्री सभापति : समाप्त प्लीज (व्यवधान) नम्बर भी बहुत है, 15 मिनट हो गए।

श्री ज्ञानचन्द पारख : नहीं पांच मिनट हुए हैं, मुश्किल से पांच मिनट। मैं अभी बात पर तो आया ही नहीं हूं।

श्री सभापति : जल्दी बोलिये, 15 मिनट ले चुके। मैं ध्यान दिला रहा हूं।

श्री ज्ञानचन्द पारख : हमारी पार्टी का आंतरिक लोकतंत्र बहुत मजबूत है। सारे निर्णय होते हैं वह मिल बैठकर होते हैं। सबको अपनी बात कहने और रखने का अधिकार भी है हमारी पार्टी में, चाहे किसी निर्णय पर असहमति हो। हमारा कार्यकर्ता हो चाहे हमारा मंत्री हो बड़ी दबंगता से पूरे साहस से अपनी बात रखता है। आपकी पार्टी में आपको ऐसा अवसर कभी नहीं मिला होगा। आपके नेता ने ऊपर से जो कह दिया....

श्री श्रवण कुमार : आप शहरों के आदमी हो, गांव के मामले में क्या मालूम।

श्री सभापति : प्लीज आप बैठिये, नो इन्ट्रप्शन, नो इन्ट्रप्शन। (व्यवधान) आप सदन को थोड़ा ढंग से चलाये। आप अपनी बात बोलिये, इधर देखकर बोलिये आप उनसे सीधे बात मत कीजिए, बिराजिए।

श्री श्रवण कुमार : हमें मालूम है गांव में बिजली नहीं....(व्यवधान)

श्री सभापति : आप इधर देखकर बोलिये, उधर नहीं।

श्री ज्ञानचन्द पारख : माननीय सभापति महोदय, यह पंक्तियां इनको बता दूं।

श्री सभापति : आप उनसे उलझिये मत, आप अपनी बात कहिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख : यह सुनी होगी इन्होंने 'जिनके अपने घर की दीवारें शीशे की होती हैं वह दूसरो के ऊपर पत्थर नहीं उछाला करते।' आप ध्यान रखा करें इस बात का।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

माननीय सभापति महोदय, ऐसा नहीं है कि विकास की जो जानकारी है यह कोई अभिभाषण के माध्यम से ही माननीय सदस्य को मिली हो या छपी छपाई सामग्री हमने दे दी और उससे हम यह साबित करना चाहते हैं कि हमने बहुत विकास कर दिया, प्रत्यक्ष रूप में किसी भी गांव में चले जाइये, ढाणी में चले जाइये हमारे विकास की गवाही वह गांव-ढाणी दोनों आज तत्पर बैठे हैं। बिलकुल तत्पर बैठे हैं। आज आप हंस रहे हो ना, जनता कल आपके ऊपर हंसेगी देखना। 50 साल आपने शासन किया।

श्री सभापति : माननीय सदस्य Please don't comment upon him.

श्री श्रवण कुमार : 'शीशे की दीवार। फानूस बनकर जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे'।

श्री सभापति : प्लीज आप बैठिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख : अब आपकी शमा कोई ज्यादा चलने वाली नहीं है।

श्री सभापति : प्लीज अब आप समाप्त कीजिए।

श्री ज्ञानचन्द पारख : यह अपनी शमा की बात कर रहे हैं।

श्री सभापति : आप समाप्त कीजिए।

श्री ज्ञानचन्द पारख : यह अपने खुदा की बात कर रहे हैं, मैं स्पष्ट कह दूं आपको मात्र एक सहारे से आप बहुत लम्बे समय तक जीवित नहीं रह सकते। गांधी परिवार के नाम का सहारा लेकर आप आज तक राजनीति करते आये हो, जब तक काम नहीं करोंगे तो यह नाम भी ज्यादा लम्बे समय तक चलने वाला नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति : आपका समय जाया हो रहा है इसलिऐ आप टाइम इधर उधर खराब मत करिये, आप बोलिये।

श्री ज्ञानचन्द पारख : आज हर गांव में ढाणी में विकास की गंगा वहां तक पहुंच गई। चाहे कोई भी क्षेत्र ले लीजिए आप, कोई बताने की आवश्यकता नहीं है, आप खुद महसूस करते होंगे। चाहे सड़क का क्षेत्र ले लीजिए, चाहे मेगा हाइवे हो, राजस्थान का नाम पूरे हिन्दुस्तान में वह कर जायेगा। चाहे गांवों को सड़क से जोड़ने की योजना हो राजस्थान पहले नम्बर पर है, पहले नम्बर पर राजस्थान को हम ले आये। मैं बिलकुल कह सकता हूं कि जितनी सड़कें आजादी के बाद मेरे विधान सभा क्षेत्र में नहीं बनी, मैं

राजेन्द्र राठौड़जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि इन सवा दो साल में उससे ज्यादा सड़कें बनाकर उन्होंने गांव-गांव में सड़क पहुंचा दी। यही नहीं डब्ल्यू.बी.एम. सड़कों के बारे में तो आपको भी पता है कि आपने पिछली बार भी डब्ल्यू.बी.एम. को बीटी करने के लिए अपनी बात कही थी सदन में और आपके मंत्रीजी ने कभी इसके ऊपर गम्भीरता से नहीं लिया। आपके कई माननीय सदस्यों ने जो हमारी क्षतिग्रस्त सड़के हैं डब्ल्यू.बी.एम. की, अपना दुखड़ा रोया था, अपनी पीड़ा बताई थी कि सड़के क्षतिग्रस्त हैं इनका डामरीकरण किया जाना बहुत आवश्यक है। लेकिन एक भी डब्ल्यू.बी. एम. सड़क को उस समय डामरीकरण में नहीं बदला गया। और हमारी सरकार ने आते ही, हमारे मंत्रीजी ने आते ही इन सवा दो साल में राजस्थान की जितनी भी डब्ल्यू.बी.एम. सड़के हैं एक आदेश में ही कि उन सारी सड़कों का डामरीकरण करने की स्वीकृति दी जाती है, आज वह सड़के लगभग बनकर तैयार हैं। और इतना ही नहीं....

श्री सभापति : प्लीज।

श्री ज्ञानचन्द पारख : जो भी एमडीआर सड़के हैं जिसमें शहरी और गांव क्षेत्र आता है, आबादी क्षेत्र आता है और वह पानी की वजह से, कीचड़ की वजह से, नाली नहीं होने की वजह से (व्यवधान) मात्र पांच मिनट....

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप 20 मिनट ले चुके हैं।

श्री ज्ञानचन्द पारख : मात्र 10 मिनट लिये हैं मैंने।

श्री सभापति : रेकार्ड है यहां पर मेरे पास।

श्री ज्ञानचन्द पारख : दस इन्होंने ले लिये वापस मेरे तो, इनके काट देना आप। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : हमारे तो कटे ही सवा दो साल हो गए।

श्री सभापति : दो-तीन मिनट में समाप्त कीजिए1

श्री ज्ञानचन्द पारख : जितनी भी आबदी क्षेत्र की जो सड़के हैं पीडब्ल्यूडी की, उनको सीमेंट का बनाने की जो स्वीकृति जारी की यह भी आजादी के बाद पहली बार हुआ है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में पीडब्ल्यूडी की मुख्य सड़क मंडिया रोड़ 91 लाख की सीमेंट कंकरीट रोड़ की स्वीकृति देकर पाली वालों के ऊपर बहुत बड़ा अहसान किया है उसके लिए मैं ह्रदय से माननीय सार्वजनिक मंत्रीजी का आभार प्रकट करता हूं।

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

चाहे शिक्षा का क्षेत्र ले लें सारी जनता जानती है, सारा प्रदेश जानता है इतनी प्राथमिक शालाएं आज तक नहीं खुली। हर एक किलोमीटर के एरिया में प्राथमिक शाला। कोई बच्चा पढ़ना चाहे उसके घर के पास स्कूल मौजूद। बहुत बड़ी संख्या में प्राइमरी स्कूलों को अपर प्राइमरी में क्रमोन्नत किया, इतनी बड़ी संख्या में जितना हमने भी चुनाव में वादा नहीं किया उससे भी बढ़कर। आपके काल में एक भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं हुई, किसी को नौकरी नहीं दी। हमारी सरकार ने स्कूल भी खोले और स्कूलों को अच्छी तरह से चलाने के लिए ताकि बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, योग्य अध्यापकों की 54000 अध्यापकों की भर्ती करके पूरे हिन्दुस्तान में एक रेकार्ड कायम किया। ऐसा नहीं है कि हमने कोरे विद्यालय क्रमोन्नत कर दिये, जिस विद्यालय में जो-जो आवश्यकता, चाहे पूरे विद्यालय भवन की आवश्यकता तो उसकी मंजूरी भी साथ में, चाहे कमरों की आवश्यकता तो वह मंजूरी भी साथ में, चाहे विद्यालय में पानी के टांके की आवश्यकता तो उसकी मंजूरी भी और चाहे शौचालय की तो उसकी स्वीकृति, चाहे किचन सैट बनाना हो तो उसकी भी स्वीकृति, कोई कसर शिक्षा के क्षेत्र में बाकी नहीं है। पहले पढ़ना चाहते थे लेकिन गांवों में स्कूल मौजूद नहीं, आज जो भी पढ़ना चाहता है वहीं पास में विद्या का मंदिर इन्होंने स्थापित करके एक कीर्तिमान स्थापित किया है।

कानून व्यवस्था की बात करें, आज ऐसा ठीक कर दिया राजस्थान को हमने। पुलिस पहले सत्तापक्ष की गुलाम थी। सत्तापक्ष जैसा चाहता था पुलिस को मजबूरन वैसी ही जांच करनी पड़ती थी। आज हमारे शासन काल में हमने उसे ठीक करके वह कानून की रखवाली बने, रक्षक बने उसके लिऐ चाहे हमारे कार्यकर्ताओं को भी नाराज करना पड़ा। हमारे गृह मंत्रीजी ने बिलकुल ईमानदारी से सच्चाई से, पुलिस अपना काम भी ईमानदारी से सच्चाई से करें उसी नीति से उन्होंने पुलिस अधिकारियों को इस आशय का संदेश भी दिया, हवाला भी दिया कि कानून के ऊपर कोई नहीं चाहे सत्तारूढ पार्टी का कार्यकर्ता हो चाहे कोई भी व्यक्ति, कोई बहुत बड़ा प्रभावशाली व्यक्ति हो।

श्री जुबेर खान : माननीय सदस्य, आपके घर से आपकी जीप ही चोरी चली गई। (व्यवधान) सत्तापक्ष के विधायक के बावजूद भी आपकी जीप चोरी हो गई आपके यहां से, यह कह रहा हूं।

श्री ज्ञानचन्द पारख : मैं यह नहीं कह रहा कि उन्होंने पूरे अपराध खतम कर दिये, मैं बिलकुल नहीं कह रहा, अपराधों पर जिस प्रभावी तरीके से अंकुश लगाया है....

श्री जुबेर खान : यह सही है पक्षपात नहीं हुआ, यह तो हम कह रहे हैं पक्षपात नहीं हुआ।

श्री ज्ञानचन्द पारख : जिस तरीके से अंकुश लगाया वाकई में काबिले तारीफ है।

श्री संयम लोढ़ा : आपकी क्वालिस मिली कि नहीं ?

श्री ज्ञानचन्द पारख : मेरी नई क्वालिस आ गई, आप चिन्ता नहीं करें मेरी गाड़ी की। मेरे पास अपनी गाड़ी है।

श्री संयम लोढ़ा : चोरी गई वह आई कि नहीं ?

श्री ज्ञानचन्द पारख : चोरी गई वह तो नहीं आई।

श्री संयम लोढ़ा : इतना ही पूछना था।

श्री ज्ञानचन्द पारख : और मान्यवर, पेयजल के मुद्दे पर, पेयजल जैसी गम्भीर समस्या के मुद्दे पर भी आपकी सरकार कभी गम्भीर नहीं रही। चाहे व्यक्ति पानी (व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : अब तो गाड़ी दे दो इनको। (व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख : नहीं नहीं, कोई आपकी पार्टी से सम्बन्धित रहा होगा वह चोर।

श्री संयम लोढ़ा : यह वसुन्धराजी से पूछकर बताएंगे कि गाड़ी कहां भेजी है।

एक माननीय सदस्य : आपको मालूम होगा, पड़ौसी आप हैं ना।

श्री ज्ञानचन्द पारख : माननीय सभापति महोदय, मैं अन्तिम, अन्तिम जो पानी का विषय है मेरे इलाके का प्रमुख विषय है।

श्री सभापति : प्लीज, माननीय सदस्य, 25 मिनट आप ले चुके हैं।

श्री ज्ञानचन्द पारख : पानी का जो अन्तिम विषय है, पानी की समस्या जैसे गम्भीर मुद्दों पर भी आपकी सरकार की सरकार कभी गम्भीर नहीं रही, आप याद करो।

श्री सभापति : अब आप 2 मिनट में कन्क्लुड करिये। 2 मिनट में कन्क्लुड करिये 25 मिनट आप ले चुके हैं।

श्री ज्ञानचन्द पारख : बस, पानी वाला मैटर है, 2 मिनट में, हां। पानी का आप याद करो, अकाल के दौरान जिस समय टैंकरों के माध्यम से गांवों में पानी की गाड़ी जाती थी आपकी सरकार के कार्यकाल में प्रति व्यक्ति

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

मात्र 10 लीटर पानी की मंजूरी थी, मात्र 10 लीटर पानी की और उसमें चाहे गांव का पशु भी है तो वह व्यक्ति अपना पानी काटकर उस पशु को पिलाये। और ज्योंहि यह जानकारी हमारी सरकार आने के बाद में हमने हमारे पेयजल मंत्रीजी को दी तो पिछली बार के अकाल में प्रति व्यक्ति 10 लीटर के बजाय 30 लीटर पानी कम से कम दिये जाने की स्वीकृति, बहुत बड़ी स्वीकृति है यह और जहां पशु संख्या अधिक है वह इस बात की भी अधिकारियों को छूट दे दी कि जिस गांव में पानी की जितनी आवश्यकता हो, पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध करवाया जाए। और पानी की बड़ी-बड़ी योजनाओं के बारे में, आपको खुद को जानकारी है और मेरे खुद के विधान सभा क्षेत्र में बताऊं हमने 17 करोड़ की पाइप लाइन के लिये जब पाली पूरा प्यासा था बहुत बड़ा धरना प्रदर्शन किया था। 50 हजार लोग इक्ट्ठा हुए थे। पाली पानी के लिये तरस रहा था। एक बार नहीं, कई बार प्रदर्शन हुए, धरना हुए, आन्दोलन हुए, बन्द हुए, लाठी चार्ज हुए, आपकी सरकार ने उस मामले को भी गम्भीरता से नहीं लिया, 17 करोड़ की योजना को भी ठुकरा दिया और हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री ने पहली ही बार में 354 करोड़ की योजना पाली और पाली के आसपास के गांवों की जनता को पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने के लिये पिछले बजट में मंजूर कर दिये। कहीं हम पीछे नहीं हैं काम के मामले में।

श्री सभापति : नो कमेण्ट्स, बैठे-बैठे, प्लीज।

श्री ज्ञानचन्द पारख : कहीं हम पीछे नहीं हैं और मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं, हमारी सरकार ने जो वादे किये, एक-एक करके उनको पूरा कर रही है। हम जनता की नजरों में खरा उतर रहे हैं। आज जो मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं माननीय सभापतिजी का बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा, धन्यवाद।

श्री सभापति : श्री रामप्रताप कासनिया।

सूचना

दानपुर (बांसवाड़ा) क्षेत्र में ओलावृष्टि

श्री रघुवीर सिंह मीणा : सभापति महोदय, एक सूचना है। सभापति महोदय, खबर यह है कि बांसवाड़ा जिले के दानपुर क्षेत्र में एक घंटे तक ओलावृष्टि हुई है। चूंकि अभी फसल पक गयी है, कटने को है, इसलिये हम यह चाहेंगे कि सरकार को इस बारे में जितनी जानकारी है वह सदन को भी बताने

(श्री रघुवीर सिंह मीण)

की कृपा करे। चित्तौड़ जिले में दलोड़ क्षेत्र में भी ओलावृष्टि हुई है इसलिये कृपा करके जितनी जानकारी हो उतनी सदन को बता दें।

श्री सभापति : श्री रामप्रताप कासनिया।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद

श्री रामप्रताप कासनिया (पीलीबंगा) **:** सभापति महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदया ने इस सदन में जो अभिभाषण दिया है मैं उसका समर्थन करता हूं। समर्थन इसलिये करता हूं कि उस अभिभाषण में राजस्थान की आन-बान-शान और बेहबूदी का ध्यान रखा गया है। इसलिये मैं इस अभिभाषण का समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, सबसे पहले तो राजस्थान सरकार का जो वित्तीय प्रबन्धन है वह बहुत ही सराहनीय है। और यह बात, सभापति महोदय, केन्द्र सरकार ने भी वित्तीय प्रबन्धन के मामले में राजस्थान सरकार की पीठ थपथपाई है और पीठ थपथपाने के साथ 60 करोड़ रुपये प्रोत्साहन राशि के रूप में राज्य सरकार को दिये हैं। इससे राज्य सरकार का वित्तीय प्रबन्ध जो है उसका स्वतः ही पता लगता है। सभापति महोदय, राज्य सरकार के अच्छे वित्तीय प्रबन्ध के कारण पिछले 6 माह में भारतीय रिजर्व बैंक के अन्दर एक दिन भी ओवर ड्राफ्ट नहीं लेना पड़ा। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। पूर्ववर्ती सरकार के आये दिन बैंकों के अन्दर खाता सफा मिलता था। और इस सरकार के आने के बाद में कभी भी हमारी माननीय मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने यह नहीं कहा कि राजस्थान सरकार का खजाना खाली है। जब भी कभी किसी बात को लेकर गये, जनता की कोई बात हुई, कोई मांग हुई तो यह कभी नहीं कहा कि खजाना खाली है। खजाना हमेशा भरा रहा है और भरा रहेगा। सभापति महोदय, कुल मिलाकर के राज्य सरकार ने 2 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित माननीय मुख्य मंत्रीजी की जन सम्पर्क यात्राओं में भारी जन समूह उमड़ पडा, उससे सरकार की लोकप्रियता का अपने आप ही पता लगता है कि जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्रीजी की जन सभाओं में जो भीड़ जुटी, लोग अपने आप चलकर आये उससे राज्य सरकार के क्रियाकलापों का स्वतः ही पता लग जाता है। राजस्थान उद्योगों में भी प्रगति की ओर बढ़ रहा है, निवेशकों की बढ़ती संख्या और रुचि इस बात की प्रतीक है कि प्रदेश के

श्री रामप्रताप कासनिया)

विकास की मंजिल पाने के लिये निरन्तर आगे बढ़ रहा है यह प्रदेश। कुल मिलाकर के पिछले 2 वर्ष के अन्दर हर मामले में राज्य सरकार ने उपलब्धि हासिल की है। सभापति महोदय, शिक्षा के मामले में पिछले 2 वर्षों में 1350 प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमौन्नत किये गये हैं यह अपने आप में एक रेकार्ड है। पीछे का आप बजट उठाकर देख लें कि इतने विद्यालय एक साथ कभी भी क्रमौन्नत नहीं हुए। सभापति महोदय, ग्राम पंचायतों पर 500 महात्मा गांधी सार्वजनिक पुस्तकालय खोले गये हैं। यह भी कोई कम बात नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में आधारभूत सुविधाओं के अन्तर्गत 4886 स्कूलों में पेयजल सुविधा और 5499 विद्यालयों में शौचालय कुल मिलाकर के अतिरिक्त कक्षा तथा 3331 भवन निर्माण के कार्य किये गये हैं। यह ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को शिक्षा देने के लिये बहुत ही अच्छा कार्यक्रम राज्य सरकार ने प्रस्तुत किया है। इसमें कोई सन्देह नहीं है। विकास की सोच और महत्वपूर्ण निर्णय, सभापति महोदय, वर्ष 2005-06 में कक्षा एक से 12वीं तक के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क पाठ्य पुस्तक उपलब्ध करवाना बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी भी गांव की तरफ शहरों की तरफ से कोई मांग नहीं की थी, ग्रामीण क्षेत्रों में, शहरी क्षेत्रों में बच्चों को निःशुल्क पुस्तकें उपलब्ध करवायी जाएं। यह भारतीय जनता पार्टी की सोच है कि बिना मांगे, बिना किसी के कहे गरीबों को शिक्षा देने के लिये सरकार ने इस तरह के महत्वपूर्ण निर्णय लेकर के गरीब बच्चों को शिक्षा देने का जो काम किया है यह बहुत ही पुण्य का काम है। इससे राजस्थान शिक्षित होगा, राजस्थान का हर बच्चा पढ़-लिखकर कामयाब होगा। सभापति महोदय, पहली कक्षा से अंग्रेजी की शुरूआत करना, यह भी बहुत अच्छी सोच है। यह सरकार की सोच किसी के कहने से नहीं, अपनी सूझबूझ से यह पहली कक्षा से अंग्रेजी लागू की है। सभापति महोदय, विकलांग व मंद-बुद्धि बालकों हेतु विशेष छात्रवृत्ति प्रारम्भ करना और ग्रामीण क्षेत्रों की बालिकाओं को माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययन करने के लिये घर से स्कूल और स्कूल से घर तक आने-जाने के लिये निःशुल्क पास जो राज्य सरकार ने दिया है बस यात्रा का, यह भी बहुत सराहनीय कदम है।

(समय : 14.00 बजे)

सभापति महोदय, किराये के अभाव में ग्रामीण क्षेत्र की बच्चियों को कोई दो-चार-पांच-दस किलोमीटर दूर पढ़ने के लिए उन्हें जाना पड़े तो उनके

(श्री रामप्रताप कासनिया)

पास किराये की कमी थी, इस कारण से बच्चियां अनपढ़ रह जाती थीं परन्तु अब राज्य सरकार ने नि:शुल्क पास उपलब्ध कराकर गरीब बच्चों, बच्चियों को शिक्षा देने के लिए बहुत ही बड़ी उपलब्धि की है।

सभापति महोदय, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र में 12255 बालिकाओं को नि:शुल्क साइकिल उपलब्ध कराना, यह भी एक शिक्षा को बढ़ाना देने वाला कार्यक्रम है। बहुत ही पुण्य का काम है कि गरीब की बच्चियों को साइकिल मुहैया कराना, नि:शुल्क, तो उसको स्कूल जाने में, पढ़ने में वह साइकिल बहुत ही अच्छी साबित होगी।

सभापति महोदय, सभी सरकारी एवं गैर-सरकारी विद्यालयों में योग शिक्षा प्रारम्भ करना, यह भी बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत अच्छा कार्यक्रम है। सभापति महोदय, इससे एक तो बच्चे का स्वास्थ्य बहुत ही सही रहेगा। डाक्टर के पास जाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। बच्चा बड़ा हृष्ट-पुष्ट होगा। जिन-जिन स्कूलों में सब जगह राजस्थान सरकार ने यह फैसला कर लिया कि योग हर विद्यालय में जरूरी है तो इससे बच्चे स्वस्थ और निरोग होंगे, यह भी बहुत अच्छा कदम है।

सभापति महोदय, सरकारी विद्यालयों में विद्यार्थियों का कम्प्यूटर शुल्क का 50 परसेंट अब राजस्थान सरकार वहन करेगी। यह भी शिक्षा को बढ़ावा देने वाला कार्यक्रम है।

सभापति महोदय, सभी 4117 पात्र विधवा आवेदकों को स्कूलों के अन्दर नियुक्तियां दी गयीं हैं। उसमें से 2155 को तो नियुक्तियां दी जा चुकी हैं और शेष नियुक्तियां शीघ्र ही होंगी। विधवाओं को अध्यापिका लगाने में सरकार ने बहुत अच्छा पुण्य का कार्य किया है, यह ऐसी सोच पहली बार सरकार की है। सभापति महोदय, इसके अलावा बालिकाओं को नि:शुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने का यह भी कोई कम बात नहीं है।

सभापति महोदय, 6473 राजीव गांधी पाठशालाओं को प्राथमिक पाठशाला में परिवर्तित करके सरकार ने एक रेकार्ड कायम किया है। इसके साथ-साथ 4162 नवीन प्राथमिक शालाएं भी खोली गयी हैं। 5170 प्राथमिक पाठशालाओं को उच्च प्राथमिक पाठशालाओं में क्रमोन्नत किया गया है। कुल अब 13528 विद्यालय खोले गये हैं एवं क्रमोन्नत करने के आदेश जारी किये गये हैं, जो अपने आप में एक कीर्तिमान रेकार्ड है।

(श्री रामप्रताप कासनिया)

सभापति महोदय, इतना ही नहीं कृषि के क्षेत्र में सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए कृषि के बजट में छह गुणा वृद्धि करके काश्तकारों को राहत प्रदान की है। वर्ष 2004-05 में सरसों का रिकार्ड उत्पादन हुआ है। वर्ष 2004 05 में मूंगफली का रेकार्ड उत्पादन हुआ है। सभापति महोदय, 2005-06 में कपास का भी बहुत रेकार्ड उत्पादन हुआ था। कुल मिलाकर सरकार की सोच, सूझबूझ के कारण यह लक्ष्य अर्जित किये गये हैं।

सभापति महोदय, किसानों को कृषि जलवायु के अनुकूल तकनीकी उपलब्ध कराने के लिए तीन नये खण्ड कार्यालय सीकर, बीकानेर, जालौर एवं गृह परीक्षण केन्द्रों की स्थापना का निर्णय करके काश्तकारों के हित का काम किया है। दो नये बीज परीक्षण प्रयोगशाला अलवर व जोधपुर, तीन नयी उर्वरक परीक्षण जोधपुर, कोटा व दो टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला झालावाड़ एवं गंगानगर में। सभापति महोदय, नयी मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला बारां, धौलपुर, करौली, चूरू, झुन्झुनूं, जालौर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, बाड़मेर, राजसमन्द, दौसा, बूंदी जिलों में स्थापित की जा रही हैं। किसानों को इससे बहुत ही लाभ मिलेगा।

श्री सभापति : समाप्त करिये प्लीज। आपका 21 मिनट में है, जिसमें आपके एक सदस्य और बोलेंगे। ...(व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, पेट तो ऊंट का दुखे और ...(व्यवधान) गधा को दो। सभापति महोदय, टाइम खराब तो करे मेरे दाईं और बाईं और वाले और काट रहे हैं मेरा, यह न्यायसंगत बात नहीं है।

श्री सभापति : नहीं-नहीं, 21 मिनट हैं, उसमें आप और दूसरे मैम्बर भी बोलेंगे। थोड़ा जल्दी करिये आप।

श्री रामप्रताप कासनिया : सभापति महोदय, किसानों को फव्वारा सैट, बूंद-बूंद सिंचाई के लिए व पाइप-लाइन के लिए 13 करोड़ रुपये का अनुदान, सहायता व्यवस्था करके सरकार ने बहुत बड़ी राहत प्रदान की है। गत पांच वर्षों के फव्वारा वितरण 11700 की तुलना में चालू वित्तीय वर्ष में दो हजार, 27000 फव्वारा सैट एवं 3500 हैक्टेयर में बूंद-बूंद सिंचाई सैट हेतु अनुदान का प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, गत वर्षों में 225 डिग्गियों का निर्माण प्रतिवर्ष में हुआ है, उसके मुकाबले में चालू वित्तीय वर्ष में नौ हजार, 956 डिग्गियों के निर्माण का प्रावधान है जो किसानों को बहुत ही लाभ देगा।

(श्री रामप्रताप कासनिया)

बूंद-बूंद सिंचाई के लिए अनुदान बदलकर 50 परसेंट करके काश्तकारों को बहुत ही अच्छी राहत प्रदान की गयी है। सभापति महोदय, इतना ही नहीं, उद्यान के अन्दर गत वर्षों में योजनाओं के लिए उपलब्ध धनराशि 7.20 करोड़ रुपये के बजट को बढ़ाकर इस वर्ष 20 करोड़ रुपये किये हैं जो बहुत ही अच्छा कार्य है।

सभापति महोदय, 2005 में.... (व्यवधान) किसानों को नुकसान नहीं हो इसके लिए अलग-अलग शहरों के अन्दर अलग-अलग जिन्सों के हिसाब से सरकार ने जो मण्डी खोलने का निर्णय लिया है, वह काश्तकारों के हित का काम है। इसी तरह से जैविक खेती की तरफ भी ध्यान दिया गया है।

सभापति महोदय, नहरों का पिछले 20-25 वर्षों के अन्दर किसी भी सरकार ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद पहली बार सरकार ने यह सोचा कि वर्षों से नहर के अन्दर सिल्ट जमा है, जगह-जगह टूटी-फूटी हैं, उनकी मरम्मत करने के लिए, सिल्ट निकालने के लिए राज्य सरकार ने जो बजट दिया है, इससे किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिला है। अन्तिम छोर के काश्तकारों को पिछले 15-15, 20-20 वर्षों के अन्दर पानी नहीं मिला जो अब की बार उपलब्ध हुआ है। सभापति महोदय, इस सरकार ने हर क्षेत्र के अन्दर, चाहे पी.डब्ल्यू.डी. हो, चाहे पी.एच.ई.डी.हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, ऐसा कोई भी विभाग नहीं है जिसमें किसी न किसी रूप में छूट नहीं दी गयी हो। ... (व्यवधान)

श्री सभापति : कन्क्लूड प्लीज।

श्री रामप्रताप कासनिया : राज्य सरकार ने राजस्थान को आगे बढ़ाने का जो कार्य किया है, उसके लिए सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का बहुत ही धन्यवाद प्रगट करना चाहता हूं। मैं इसके साथ-साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि अगर राजस्थान को खुशहाल देखना है, इस राज्य को विकसित करना है तो पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर एक बात सुन लें कि इस प्रदेश का अगर भला करना है तो जब तक प्रदेश ही नहीं, सभापति महोदय, इस पूरे देश के अन्दर एक बच्चा पैदा करने की जब तक हम पाबन्दी नहीं लगाएंगे तब तक चाहे हम कितने ही विकास क्यों नहीं कर लें, यह राज्य खुशहाल होने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, दूसरा, खेती आज घाटे का सौदा हो गयी है। जब

(श्री रामप्रताप कासनिया)

तक काश्तकारों को लाभकारी मूल्य नहीं मिलेगा, चाहे मेरी दाईं साइड वाले चिल्लाते रहे, चाहे कुछ भी करते रहे, इस तरफ तो इन्होंने 50 वर्ष तक राज कर लिया, कभी भी किसान को लाभकारी मूल्य देने की बात नहीं सोची। अगर इस देश को, इस राज्य को खुशहाल करना है तो काश्तकारों को लाभकारी मूल्य देना होगा तभी यह प्रान्त और देश आगे बढ़ सकता है। सभापति महोदय, आपने समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति : धन्यवाद। श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय सभापति महोदय, इस सरकार ने महामहिम राज्यपाल महोदय से जो लम्बा, उबाऊ और नीरस किस्म का जो अभिभाषण पढ़वाया, इस सर्वोच्च सदन में सत्तारूढ़ पार्टी के सदस्यों के आचरण से ही यह साबित हो गया था। जब महामहिम राज्यपाल महोदय अपना अभिभाषण पढ़ रही थीं तो उसकी नीरसता की वजह से कई सदस्य बाहर जा रहे थे और आ रहे थे। राजस्थान की मुख्य मंत्री ने, जब पहली बार भारतीय जनता पार्टी को राजस्थान में पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ और राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन के माध्यम से पहले अभिभाषण के दौरान अपना मशहूर शेर पढ़ा था कि-

आंधियों को कह दें कि अपनी औकात में रहे।

हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं।।

तो उन हौंसलों के उन दो वर्ष की यात्रा हौसलों के नीचे खिसककर माननीय सभापति महोदय हवाई जहाज तक आ गयी है। इन दो सालों में एक काम राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री ने किया 200 से ज्यादा हवाई यात्राएं करने का एक कीर्तिमान कायम किया। और इन 700 दिनों में 250 घंटे हवाई जहाज के अन्दर बिताने का काम किया और सरकारी विमान होने के बावजूद 2005 के अन्दर निजी विमानों से 30 लाख रूपये की यात्राएं करने का काम किया। और आज उनके हौंसलों को लेकर, एक जो मशहूर फिल्मी गीत हुआ है, लोग उन्हें वसु मैडम हवा-हवाई के नाम से पुकारने लग गये।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार पूरी तरह से दिशाहीन है, यह अभिभाषण खुद अपने आप जाहिर करता है। एक तरफ राजस्थान की मुख्य मंत्रीजी की दाओस यात्रा की आर्थिक दुनिया, दाओस के माध्यम से राजस्थान की प्रजा को दिखाये गये आर्थिक सपने और दूसरी तरफ राजस्थान

(श्री संयम लोढ़ा)

सरकार की इस कैबीनेट की दिलावरी दुनिया। कितने फासले और अन्तरद्वंद्व दोनों के बीच है। इस अभिभाषण के माध्यम से मुख्य मंत्रीजी की खूब पीठ ठोकी है। लेकिन राजस्थान के एक प्रमुख अख़बार ने आपकी सरकार के दो वर्ष पूरे होने पर राजस्थान के अन्दर जो सर्वेक्षण करवाया। उस सर्वेक्षण से आप अपनी सरकार का आत्मलोचन करने की कोशिश कीजिये। उसमें राजस्थान की जनता ने क्या मत व्यक्त किया? जब राजस्थान की जनता को यह पूछा गया कि आप क्या पहले से अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं, 78 फीसदी लोगों ने हां नहीं कहा। जब उनसे यह पूछा गया कि क्या इस दो वर्ष के शासन में भ्रष्टाचार घटा है 82 प्रतिशत लोगों ने हां नहीं कहा और जब उनसे यह पूछा गया कि क्या सरकारी दफ्तरों में जनता की सुनवाई कैसी हो रही है, अच्छी हो रही है, तो 77 फीसदी लोगों ने अच्छी नहीं कहा। और माननीय सभापति महोदय, यह पूछा गया कि क्या आप राज्य सरकार के काम-काज से सन्तुष्ट हैं तो 61 फीसदी लोगों ने हां नहीं कहा। इससे ज्यादा शर्म की बात माननीय सभापति महोदय, यह है कि जब राजस्थान की जनता से सर्वेक्षण में उस प्रमुख अख़बार ने यह पूछा कि क्या सरकारी अधिकारी ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो माननीय सभापति महोदय, 90 फीसदी लोगों ने हां नहीं कहा।

श्री जोगाराम पटेल : हाउस में अख़बार की कटिंग नहीं बताई जा सकती।

श्री सभापति : बिराज जाइये।

श्री संयम लोढ़ा : राजस्थान के प्रमुख अख़बार, और आपकी पार्टी के प्रिय अख़बार 'राजस्थान पत्रिका' के सर्वेक्षण को कोट कर रहा हूं मैं।

श्री ओम बिरला : वह अख़बार भारतीय जनता पार्टी का अख़बार है, यह कहना चाहते हैं।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह आत्मालोचन का अवसर है। सत्ता के मद में, अहंकार के मद में डूबने का समय नहीं है। इस अख़बार ने सर्वेक्षण के माध्यम से अगर कुछ जानकारी राजस्थान की जनता के माध्यम से आपके सामने लाने का प्रयास किया है तो इसको सकारात्मक रूप से लेना चाहिये। राजस्थान की माननीय मुख्य मंत्री के बारे में भी सर्वेक्षण पूछा कि क्या मुख्य मंत्री की लोकप्रियता बढ़ी है तो 60 प्रतिशत लोगों ने हां नहीं कहा। इससे

(श्री संयम लोढ़ा)

ज्यादा आप क्या जानना चाहते हैं? माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं....(व्यवधान)

श्री सभापति : नो-नो, इंटरप्शन प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, लूणी से आने वाले माननीय सदस्य का 56 मिनट का भाषण मैंने यहां बैठकर पूरी शांति से सुना। जितनी गौरव गाथा गानी थी, उन्होंने बहुत आराम से गायी। मैं आपका सरंक्षण चाहते हुए यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो बात मैं कह रहा हूं आपके हित में कह रहा हूं। तीन साल आपके पास और हैं। हम यह जो बातें निवेदन कर रहे हैं वह इसलिए कह रहे हैं कि आप अपनी सरकार की परफोर्मेन्स और बेहतर कर सकें। हमें मालूम है कि हमारे बोलने से आपका राज जाने वाला नहीं है। राजस्थान की जनता ने जो पांच साल के लिये आपको जनादेश दिया है, आपकी हुकूमत रहेगी इसलिए मेहरबानी करके उसको उसी रूप में लें। माननीय सभापति महोदय, जब सरकार थी कांग्रेस पार्टी की, बहुत भूख को लेकर बवाल मचाया था और यह कहा था कि राजस्थान के लोग भूख से मर रहे हैं, कुपोषण से मर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन ने और एक एन.जी.ओ. हे सैंटर फार एनवायरनमेंट फूड सिक्योरिटी द्वारा मार्च से जून, 2005 के बीच में राजस्थान के 40 आदिवासी गांवों का जो सर्वेक्षण किया, उसकी रिपोर्ट क्या कहती है? 99 फीसदी आदिवासी भूख से पीड़ित हैं और 30.30 फीसदी आदिवासी अल्प भुखमरी से पीड़ित हैं। यह मैं निवेदन कर रहा हूं और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस दिशा में उपाय सुझाया है और यह आपकी सरकार के वक्त में राजस्थान के 40 आदिवासी गांवों का एक चित्र वगैरह पेश करने की कोशिश की है।

माननीय सभापति महोदय, इस सरकार का तीसरा बजट आने वाला है। तीसरा अभिभाषण पढ़वा दिया। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, इसके बावजूद सत्ता पक्ष के सदस्यों की यात्रा वही, अशोक गहलोत सरकार जो 2003 में चली गयी, उससे शुरू होती है, उसके काम पर शुरू होती है उससे आगे की यात्रा नहीं करना चाहते हैं। लेकिन उस सरकार और इस सरकार, दोनों के चेहरों को देखने की कोशिश कीजिए। क्या था अशोक गहलोत की सरकार का चेहरा और आप भूल गये 'मुख्य मंत्रीजीवन रक्षा कोष' समाज का वह सबसे वंचित आदमी, जिसके इलाज के लिये ...(व्यवधान)..

श्री धर्मपाल चौधरी : 156 से 56 पर उस चेहरे से ही आये आप।

श्री सभापति : धर्मपालजी, आप बोलेंगे। माननीय सदस्य, आपका नम्बर है, जब आपका नम्बर आये तो बोलिये। आपका नाम है अभी बोलेंगे आप।

श्री संयम लोढ़ा : मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि जो 2003 में राजस्थान की जनता ने कांग्रेस पार्टी को जनादेश दिया, हमने उसको शिरोधार्य किया। और अब कांग्रेस पार्टी का यह जनादेश है कि हम आपकी सरकार से काम करवाने के लिये राजस्थान की जनता से किये हुए वायदों को पूरे करवाने के लिये एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका हम अदा करें। हम उसी कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि 'मुख्य मंत्रीजीवन रक्षा कोष' के माध्यम से तत्कालीन अशोक गहलोत की सरकार ने समाज के सबसे अन्तिम छोर पर बैठे हुए आदमी की पीड़ा को बांटने का प्रयास किया था। आप भूल गये वृद्वावस्था पेंशन के अन्दर कहां 96 करोड़ का प्रावधान था और कहां तत्कालीन अशोक गहलोत सरकार ने उसको 200 करोड़ रूपये करने का काम किया था। कोई पाप कर दिया था, लेकिन नहीं, मानवीय सरोकार से ताल्लुक रखने वाले उन तमाम प्रावधानों की आपके दिल में कोई जगह नहीं है और इस सरकार की प्राथमिकता में वह किसी भी रूप में नहीं है। मैं इसको पूरी तरह साबित करूंगा और मैं चाहता हूं कि राजस्थान की मुख्य मंत्री जब इस सदन में अपना जवाब दें तो बतायें कि क्या 2005 के अन्दर शिवगंज ब्लाक में चार महीने तक आपने विधवाओं की पेंशन नहीं बांटने का काम किया और वह इस बात का जवाब दें कि सिरोही ब्लाक के अन्दर 2004 के शुरूआत में वह गरीब बीपीएल परिवार का मुखिया, जो गुजर गया, उसके पीड़ितों को सहायता देने का काम आपने दो साल तक नहीं किया। और आप इस बात का भी जवाब दें कि विधवाओं की पुत्रियों के लिये जो सहायता राशि का प्रावधान है, आज राजस्थान के अन्दर कितने फार्म बिके हुए हैं ? शादियां हुए कई महीने हो गये, विधवाओं की पुत्रियों के 1000 फार्म पेण्डिंग पड़े हुए हैं और अलवर जिले के अन्दर नौ महीने से विधवाओं की पुत्रियों की, जिनकी शादियां हो चुकी हैं, आपने पैसे नहीं देने का काम किया है। और आपके माध्यम से, सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं राजस्थान में जो सरकार आई है, यह परिवर्तन हुआ सबसे बड़ी भूमिका किसकी थी, राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लाने के पीछे, भारतीय जनता पार्टी को पहली बार ऐतिहासिक बहुमत देने के पीछे अगर

(श्री संयम लोढ़ा)

किसी आदमी, किसी वर्ग की भूमिका थी तो वह राजस्थान का दलित और राजस्थान का आदिवासी था, जिसने भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक यहां जिताकर भेजे हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सरकार ने उन दलितों और आदिवासियों के साथ क्या किया? 29 सितम्बर, 2000 का आदेश है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्ति की अगर सामान्य वर्ग के व्यक्ति द्वारा हत्या हो तो बोडी का पोस्टमार्टम होने के बाद 50 प्रतिशत पैसा तुरन्त उसको मुहैया कराया जायेगा और दोष सिद्ध होने के बाद बाकी का पैसा दिया जायेगा। राजस्थान में जो हत्यायें हुई, 2005 के आंकड़े मैं सुना रहा हूं। एक-एक आंकड़ा मेरे पास है। मैं आपके माध्यम से शुरूआत यहां से करता हूं सीकर से – श्री रामकुमार पुत्र प्रहलाद बियाना बिहारीपुरा 26 मार्च, 2005 को उसकी हत्या हुई सीकर में, आपने आज तक उसके परिवार को फूटी कौड़ी दी ? ताराचन्द बाजीगर, गंगानगर के अन्दर 16 जनवरी, 2005 को उसकी हत्या हुई, आज तक आपने उसको फूटी कौड़ी दी ? राजू जाति नायक भादूवाला रायसिंहनगर थाना 16 मार्च, 2005 को उसकी हत्या हुई, आपने आज तक उसको फूटी कौडी दी ? जसपाल कौर जाति मजहबी सिंह, धौलावालाचक थाना सार्दुलशहर, दो मार्च, 2005 को उसकी हत्या हुई, आपने फूटी कौड़ी दी? मांगीलाल जाति मेघवाल निवासी 59 एलएमपी थाना घमंडवाली, 11 जून, 2005 को उसकी हत्या हुई, आज तक आपने उसको फूटी कौड़ी दी ?

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा (रानीवाड़ा) : आपने कितनी दी थी? पहले वाली सरकार ने कितने दिये, कुल बता दो कि कांग्रेस सरकार ने इतनी दी।

श्री संयम लोढ़ा : हमारे तो करम फूटे हुए थे, हम विपक्ष में आकर बैठ गये, आप सत्ता में बैठे हो, आपको एक-एक बात पर जवाब देना पड़ेगा और राजस्थान की जनता की ओर से यह सारे पैसे हम दिलाकर रहेंगे आप से।

श्री सभापति : प्लीज सिट डाउन।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : पहली वाली सरकार ने कितना दिया, वह भी बता दो ताकि सही चीज आ जाए।

श्री सभापति : नो इन्ट्रप्शन प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा : एक गरीब आदमी की हत्या हो गयी, आपका यह कमेंट है ?

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : मैं यह पूछ रहा हूं कि पहले वाली सरकार ने कितना दिया ? मैं मेरी जानकारी के लिए आपसे पूछ रहा हूं।

श्री सभापति : नो इन्ट्रप्शन।

डा. सी.पी. जोशी : इधर आ जाओ जब पूछ लेना आप। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष) : सभापति महोदय, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि माननीय सदस्य बोल रहे हैं वक्ता वे अपने भाषण की शैली भी ऐसे रखें, यद्यपि मेरी पार्टी के हैं, उनका समर्थन करता हूं लेकिन सीधा उनको आह्वान नहीं करें कि इसी वक्त खड़े होकर वो जवाब दें।

श्री अर्जुन सिंह देवड़ा : मैंने जानकारी चाही है, साहब।

श्री रामनारायण चौधरी : आप बाद में दे सकते हैं लेकिन हाथ की हाथ देंगे, उनको भी समझना चाहिए कि उनका टाइम कन्जूम हो जायेगा। लेकिन वह तो नहीं सम्भलते हैं, टाइम लिमिट इनको दे रखी है उसमें इनकी बात पूरी नहीं होगी तो, साहब, हमारी बात पूरी नहीं हुंई। पूरी नहीं हुई तो दोष किसका है ? आप बोलते हैं, सामने वाले को इन्वाइट करते हैं वो खड़े हो जाएं।

आप भाषण, हमारे सदस्य से मेरा अनुरोध है कि भाषण की शैली ऐसी रखें कि वह भाषण सेल होता चला जाए यह नहीं हो कि सीधा उसको छाती में मारो। छाती में मत मारो, सेल होता जाए और उसका बाद में जवाब आ जायेगा...(व्यवधान)

श्री सभापति : नो इन्ट्रप्शन बैठे-बैठे, बैठे-बैठे नहीं बोलें प्लीज।

श्री रामनारायण चौधरी : आप बैठे-बैठे बोल रहे हैं। आपसे यह भी अनुरोध है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर नीति सम्बन्धी प्रश्नों को ही आप यहां रखें, इंडीविजुअल केस में रखें उसका उत्तर कैसे आयेगा ? उत्तर नहीं आ सकेगा तो फिर आपको निराशा होगी जब यह डिमाण्ड आये, तो माननीय सदस्यों से, मेरे पक्ष वालों से निवेदन है कि उन पर डिमाण्ड पर जवाब आयेगा, उस पर बोलिये आप, हम बुलवायेंगे। राज्यपाल का भाषण तो नीति-नीति पर, क्या हुआ पहले उसके ऊपर आप बोलेंगे, अब आप यह मांग लेंगे मेरे जवाजा के अन्दर क्या हुआ, जवाजा का जवाब कैसे आयेगा ?

माफ करना लेकिन आप भी इतने भड़कें नहीं। पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर साहब, आपसे मेरा अनुरोध है कि आप अपने सदस्यों को संयमित

(श्री रामनारायण चौधरी)

रखते हुए, मंत्रियों को संयमित रखें कि वह भड़कते क्यों हैं? आप राज कर रहे हैं, राज करने वालों पर तो आक्षेप लगेगा। राज करने वाला आक्षेप से, एक भी आक्षेप से डरते हैं आप तो आपका जीना कैसे होगा?

आप सुनिये, हमारी बात तो सुनिये और आप शांति से सुनिये, आप भभकें नहीं और हम भी कोशिश करेंगे आपको हम भभकायें नहीं।

श्री सभापति : नो इन्ट्रप्शन प्लीज।

श्री रामनारायण मीणा : यह इसलिए तकलीफ आ रही है कि मुझे ऐसा लगता है कि यह सारे के सारे, जिनका नाम यह ले रहे हैं वह शिड्यूल्ड कास्ट के लोग हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : नेता के बाद उप नेता का बोलना जरूरी है क्या ? यह नेता ही नहीं मानते आपको।

श्री रामनारायण मीणा : और आदिवासी लोगों को आप पैसे नहीं दे रहे हो...(व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिये, वो बोल रहे हैं, आपकी ही पार्टी के सदस्य हैं।

श्री संयम लोढ़ा : सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान की लिस्ट मेरे पास हैं, मैं पूरी लिस्ट नहीं पढ़ करके सिर्फ यह ध्यान में लाना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान का कोई जिला ऐसा नहीं है...

श्री सभापति : समय का ध्यान रखें प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा : कोई जिला ऐसा नहीं है कि जहां शिड्यूल्ड कास्ट एण्ड ट्राइब के आदमी का मर्डर हुआ हो और वहां उसको सहायता उपलब्ध करायी गयी हो। 75 फीसदी मामले ऐसे हैं शिड्यूल्ड कास्ट एण्ड ट्राइब के मर्डर के कि जहां फूटी कौड़ी इस सरकार ने उन लोगों को नहीं दी है।

सभापति महोदय, बड़े गीत गाते हो यह महिला मुख्यमंत्री के राज में यह शिड्यूल्ड कास्ट की महिलाओं से बलात्कार जो राजस्थान के अन्दर हुए हैं उनको, जिसको चिकित्सा जांच के तुरन्त बाद 50 फीसदी सहायता देने का प्रावधान है, 79 महिलाएं राजस्थान के हर जिले में हैं और 70 फीसदी शिड्यूल्ड कास्ट एण्ड ट्राइब की महिलाएं हैं जिनको आपने फूटी कौड़ी नहीं दी है। क्या महिला सशक्तीकरण को लेकर अब आप भाषण देते हो और कौनसी

(श्री संयम लोढ़ा)

महिला के उत्थान की बात आप कर रहे हो ? और अगर मैं गलत कह रहा हूं, यह समाज कल्याण मंत्री यहां पर विराजमान हैं, आप चाहें तो पूरी एक-एक लिस्ट मैं सुना सकता हूं... एक-एक नाम मैं सुना सकता हूं। पूरे राजस्थान के हर जिले के अन्दर जिस शिड्यूल्ड कास्ट एण्ड ट्राइब की लेडी से बलात्कार हुआ है उसको फूटी कौड़ी की सहायता नहीं दी आपने।

सभापति महोदय, इसी सदन में पिछले सत्र में यह बात हुई थी कि जो संवैधानिक प्रावधान है, राजस्थान के आदिवासी इलाके के अन्दर उसमें शराब के ठेकेदार नहीं जायेंगे, अंग्रेजी शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। और इसी सदन में राजस्थान की माननीय मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया था कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। एक कमेटी बनायी गयी थी, उस कमेटी की इसके बाद में मीटिंग हुई लेकिन पूरा साल निकाल दिया और राजस्थान के आदिवासी लोगों के हक के साथ, उनकी परम्परा के साथ खिलवाड़ करने का काम राजस्थान की इस वसुन्धरा सरकार ने किया है। आज पूरे आदिवासी इलाके के अन्दर शराब के ठेकेदारों के साथ मिलकर पुलिस उनके खिलाफ झूठे मुकदमें दर्ज करने का काम कर रही है। डूंगरपुर में बड़े-बड़े आन्दोलन हुए लेकिन इस सरकार के कान पर कोई जूं नहीं रेंगी, सभापति महोदय।

अब, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से राजस्थान सरकार का ध्यान अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

श्री सभापति : समाप्त करें प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा : शुरू किया है मैंने अभी, समाप्त की बात मत करो।

श्री सभापति : You have taken 17 minutes.

श्री संयम लोढ़ा : 17 minutes taken by the ruling party Members.

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान के माननीय शिक्षा मंत्रीजी ने एक वक्तव्य दिया अपने घर पर किसानों को संबोधित करते हुए कि सेज नाम की कोई योजना नहीं है। और वह राजस्थान के तमाम अखबारों में छपा कि सेज नाम की कोई योजना नहीं है। और उसके बाद, सभापति महोदय, माननीय मुख्यमंत्री के नाम से जयपुर विकास प्राधिकरण के आयुक्त के यहां से एक फैक्स हुआ, मुख्यमंत्री का स्टेटमेंट कि सेज की योजना है और उसके बाद में मुख्य मंत्रीजी का यह

(श्री संयम लोढ़ा)

खण्डन कि इस तरह की कोई योजना के विषय में जो कार्यवाही की गयी, बजाय जिन लोगों ने वह फैक्सक बनाया, जिन लोगों ने वह भेजा उसके खिलाफ कार्यवाही करने के बजाय मामूली से, छोटे अधिकारियों को हटाने का या सस्पैंड करने का काम इन्होंने किया। और आज तक यह सरकार यह पता नहीं लगा पायी और यह जवाब नहीं दे पायी कि वह कौन लोग थे जिन्होंने आयुक्त के यहां से यह फैक्स किया है।

सभापति महोदय, यह नौबत क्यों आयी ? राजस्थान की सरकार ने अघोषित रूप से जयपुर के आस-पास के पूरे कृषि क्षेत्र की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध लगा दिया। और जब यहां के जनप्रतिनिधियों ने और यहां के जिला कलक्टर को पूछा कि आपने किसानों की रजिस्ट्री पर प्रतिबंध क्यों लगा रखा है, उस कलक्टर ने यहां के जनप्रतिनिधियों को जवाब दिया कि मुख्य मंत्री के मौखिक निर्देश पर हमने यह प्रतिबंध लगा रखा है। लोग, यहां के जयपुर के किसान हाई कोर्ट में गये और हाई कोर्ट के अन्दर, सभापति महोदय, मुझे बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि राजस्थान सरकार के...

श्री धर्मपाल चौधरी : मुख्य मंत्रीजी पर आरोप लगा रहे हो, क्या आप वहां बैठे थे?

श्री सभापति : आपका नम्बर आयेगा, धर्मपालजी, तब बोलियेगा आप।

श्री धर्मपाल चौधरी : नहीं, समय आयेगा, यह कह रहे हैं मुख्य मंत्रीजी का नाम लेकर। किसने कहा, कौनसे ने कहा? नाम बताएं, ऐसे ही मुख्य मंत्रीजी पर चार्ज लगाने लग रहे हैं।

श्री सभापति : आपका नम्बर आयेगा तब बोलिये प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा : जयपुर के जिला कलक्टर ने कहा है यह।

श्री धर्मपाल चौधरी : जयपुर के जिला कलक्टर से कहलवा दो। दिलाओ एफिडेविट जयपुर के जिला कलक्टर से।

श्री सभापति : प्लीज, प्लीज।

श्री रामलाल शर्मा : आपके पास सबूत है क्या?

श्री धर्मपाल चौधरी : जयपुर के जिला कलक्टर ने कहा, अख़बार ने कहा और उस दम पर यहां बोलते हो।

श्री सभापति : आपका नम्बर आये तब बोलियेगा आप।

श्री धर्मपाल चौधरी : नहीं, नम्बर आयेगा लेकिन झूठी बात को कैसे सुन लेंगे यहां पर।

श्री सभापति : आपका नम्बर आयेगा तो आप खण्डन करियेगा इसका, बैठ जाइये।

श्री संयम लोढ़ा : खण्डन करने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी बहुत सक्षम हैं।

माननीय सभापति महोदय, जयपुर का किसान हाई कोर्ट में गया कि यह क्या मामला है, हमारी रजिस्ट्री रोकी जा रही है। और तब नगरीय विकास मंत्री ने जयपुर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में हाई कोर्ट में यह शपथ पत्र दिया कि सेज नाम की कोई योजना नहीं है। राजस्थान सरकार का एक कैबीनेट मंत्री किसानों को भाषण में कहता है कि सेज नाम की कोई योजना नहीं है, राजस्थान सरकार का दूसरा मंत्री हाई कोर्ट में जाकर एफिडेविट देता है कि सेज नाम की कोई योजना नहीं है और जयपुर विकास प्राधिकरण उससे बहुत पहले, सभापति महोदय, इस सम्बन्ध में सारे प्रस्ताव जमीन के एक्विजिशन को लेकर भेज चुका था। एक झूंठा शपथ पत्र राजस्थान के नगरीय विकास मंत्री ने उच्च न्यायालय में दिया। 3936 बीघा तो जयपुर विकास प्राधिकरण की बिखरी हुई लैण्ड थी और 15240 बीघा जो प्राइवेट लैण्ड थी उन सब के सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण ने जयपुर के बीस गांवों की जमीन का यह प्रस्ताव भेजा।

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आज किस तरह का वातावरण इस सरकार को लेकर जयपुर में बन रहा है और यह जयपुर विकास प्राधिकरण क्या-क्या कारनामें कर रहा है। सभापति महोदय, आप देखिए अगर आपके मुख्यमंत्री के अन्दर सच्चाई है और इस सरकार के अन्दर सच्चाई है, मैं कोई आरोप नहीं लगाता तो आप इस बात का जवाब दीजिए कि आपने यह 90-बी की कार्यवाही कहां-कहां बन्द की और क्यों बन्द की और कब खोली ? इस बात का भी जवाब दो कि पिक एण्ड चूज, यह 90-बी की कार्यवाही में पिक एण्ड चूज की कार्यवाही क्यों की ? कितने ऐसे मामले हैं जो महीनों से जे.डी.ए में पड़े हुए हैं जिनके ऊपर कोई एक अंट खींचने को तैयार नहीं है और उसके बाद में आए हुए कितने ऐसे मामले हैं जिनके मामले में आपने त्वरित रूप से कार्यवाही की। और यह भी जानकारी दो उस प्राधिकरण

(श्री संयम लोढ़ा)

में कितनी ऐसी सड़कें हैं जिनकी आपने सौ फीट चौड़ाई घटाकर अस्सी फीट कर दी और बीस फीट की रोड पर आपने दुकानें काट दीं। कितनी ऐसी सड़कें हैं जिनकी 120 फीट से चौड़ाई घटाकर 100 फीट कर दी और उस बीस फीट के अन्दर उन लोगों को लाभान्वित करने का काम किया दुकानों के माध्यम से। आपमें अगर सच्चाई है तो आप इस बात की भी जानकारी दो कि सुविधा क्षेत्र के अन्दर से कितनी जमीनें आपने निकाली हैं और कितने सुविधा क्षेत्र के प्लाट को भूखण्ड बनाकर जयपुर के भू-माफिया को लाभान्वित करने का काम आपने किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो आप योजना लाए हो रोहिणी नगर की फस्ट और सैकिण्ड, आपने इसके फार्म इकट्ठे करने का काम किसको दिया, कितने कमीशन पर दिया? जयपुर विकास प्राधिकरण का इतना बड़ा आपका लवाजमा है। लेकिन आपने पन्द्रह रुपए प्रति फार्म के कमीशन पर राजस्थान बैंक को जो एक प्राइवेट बैंक है और सात आठ रुपए प्रति फार्म पर एक लोकमित्र नाम की संस्था को आपने दिया और बारह लाख रुपए कमाने का उनको मौका दिया। और जो पचास करोड़ रुपया आपने रोहिणी नगर योजना के फार्म के माध्यम से इकट्ठा किया वह पचास करोड़ रुपया दूसरे बैंकों से प्रस्ताव मंगाने के बजाए उसी बैंक में आपने जमा कराने का काम किया। और आपका जो आयुक्त है जे.डी.ए का, क्या आप इस बात का जवाब दोगे कि कितने ऐसे आदमी जे.डी.ए में उसके आने के बाद आ गये हैं जो उससे पहले मार्केटिंग बोर्ड में था तब भी उसके साथ थे, उसके बाद वह डेयरी में गया उसके साथ थे, अब यह जे.डी.ए में आ गया है तब उसके साथ है? यह कोई संस्थागत, जे.डी.ए को आपने लूट का अड्डा बना दिया। आज इस जे.डी.ए की जयपुर में क्या पहचान बन गयी है। लोग क्या कहते हैं जयपुर में जे.डी.ए और जंगल में भेड़िए । यह आपके जे.डी.ए. की एक छवि बन चुकी है। मैं आपके माध्यम से सभापति महोदय,...

श्री सभापति : सम अप प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा : इस सरकार को राजस्थान की जनता को उन बातों का जवाब देना पड़ेगा, इस सरकार का अगर दामन साफ है तो आप मुझे एक एक बात कहने का अवसर दीजिए।

श्री सभापति : You have taken 22 minutes.

श्री संयम लोढ़ा : जिससे यह सरकार अपनी असली स्थिति को राजस्थान की जनता के सामने रख सके। मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि जिस रिंग रोड का अलाइनमेंट आपने तय किया है आपने उस पर क्यों ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी ? और मंत्रीजी क्या यह सही है कि रीको से जिस अधिकारी को उठाकर रिंग रोड के प्रोजक्ट में लाए हो उस संजय गुप्ता के दोस्तों ने इसके आसपास की सारी जमीन को बेनामी रूप से खरीदा है ? आप जवाब देना इस बात का और मैं आपसे यह भी पूछना चाहता हूं यह जो भी....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कहां से लाए हैं ?

श्री संयम लोढ़ा : रीको से, रीको का एक्स.ई.एन है वह। और मैं आपसे, यह भी मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि यह जो विज्ञापन और होर्डिंग का आपने बिना टेण्डर किए काम दिया है और साल का, महीने का डेढ़ करोड़ रुपया एडवरटाइजमेंट जो प्रिंट मीडिया का और इस सब पर हो रहा है, एक खास आदमी को लाभान्वित करने के लिए किया है जो आप टेण्डर प्रोसेस में नहीं गए। और आप इस बात का जवाब देना कि विद्याधर नगर के पास ग्राम बीड पापड़ में आरक्षित वन की भूमि 90-बी की कार्यवाही कर रहे हो, साठ बीघा की 90-बी आपने कर दी है और 700 बीघा की 90-बी आप करने जा रहे हो। इसके अलावा माननीय सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं...

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : मेरा आपसे निवेदन है कि समय की सीमा आसन ने तय की हुई है।

अनेक माननीय सदस्य : बढ़ा दो, बढ़ा दो।

डा. सी.पी. जोशी : आपसे निवेदन कर रहे हैं कि आप प्रस्ताव रखें कि सदन की कार्यवाही रात दस बजे तक चले।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यह तो सर्वदलीय बैठक में तय हुआ है और प्रतिपक्ष के नेता महोदय इसके साक्षी हैं। और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि उन्होंने प्रस्ताव किया है कि एक घंटा बी.डी. कल्ला साहब बोलेंगे और एक घंटा तीस मिनट कुल मिलाकर टाइम है तो हमको कोई एतराज नहीं है। आप बी.डी. कल्ला साहब का समय काट दें। समय सीमा का ध्यान रखें।

श्री हरिमोहन शर्मा : समय की सीमा आप बढ़ा दो ..(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : मुख्य मंत्रीजी के भाषण तक, रात के बारह बजे तक...(व्यवधान) बारह बजे तक समय बढ़ाया जाए ...(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : कांग्रेस ने डबल समय बोलने में लिया है तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों को टाइम मिलना चाहिए। हमने केवल इस मंशा के आधार पर कि सदन में प्रतिपक्ष को बोलने का मौका मिलना चाहिए अपना समय काटकर, आप समय देख लीजिए। हमको बारह घंटे का समय आबंटन हुआ था, अभी तक हमारे पास छह घंटे मौजूद हैं लेकिन उसके बाद हमारा समय काटा...

श्री हरिमोहन शर्मा : आप तो राज चलाओ।

श्री श्रवण कुमार : आप तो राज कर रहे हो, बोलने की जरूरत कहां है, बोलना तो हमें चाहिए...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : यह अत्यन्त खेद की बात है कि सच्चाई सुनने के लिये सरकार के पास टाइम नहीं है।

श्री सभापति : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय आपकी पार्टी के एक घंटा इक्कतीस मिनट थे उसमें से ...

श्री संयम लोढ़ा : यह ध्यान रखना, मुझे बोलने नहीं दिया, एक-एक बात बोलूंगा।

श्री सभापति : आप तय कर लें..(व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : पहले तो अपनी सीट से बोलें।

श्री सभापति : प्लीज, प्लीज, माननीय नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य आप अपनी सीट से नहीं बोल रहे हैं ...(व्यवधान) मैं माननीय प्रतिपक्ष के नेता से निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी ही पार्टी का समय जाया हो रहा है। माननीय बी.डी. कल्ला साहब बोलेंगे, चार नाम दे रखे हैं। संयम लोढ़ाजी, श्रीमान हरिमोहन शर्मा, श्रीमान श्रवण कुमारजी उसके बाद बी. डी. कल्लाजी। अब यह इनको कितना समय बाद में दिया जाएगा, इस पर सोच लें क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अभी तीन घंटा उन्नीस मिनट में से केवल दो सदस्य बोल पाए हैं और अभी दूसरे दलों के माननीय सदस्य हैं। एक ही दल के माननीय सदस्य बोल पाए हैं, निर्दलीय उनका भी समय है तो आप उस हिसाब से अपने सदस्यों को नियंत्रित करिए कि वह जो समय सीमा तय है उसमें बोलें । आप कह देते हैं कि नहीं, हमारी पार्टी का समय है, बोलने दीजिए फिर मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री संयम लोढ़ा : मुझे बहुत खेद है कि सत्तारूढ पार्टी के इतने लोग 55-55 मिनट तक बोले तब आपने एक बार टोकने का प्रयास नहीं किया और मैं राजस्थान की जनता की ओर से कोई सच्चाई रख रहा हूं तो बार-बार भारतीय जनता पार्टी टोक रही है कभी आप टोक रहे हैं,। मैं सरकार की सच्चाई बता रहा हूं।

श्री सभापति : टोक रहा हूं मैं, उनको भी टोका है, उनका समय है... (व्यवधान) आप विराजो।

श्री रामनारायण चौधरी (नेता, प्रतिपक्ष) : आपकी व्यवस्था सभापति महोदय शिरोधार्य है समय का..(व्यवधान)

श्री सभापति : प्रतिपक्ष के नेता बोल रहे हैं माननीय सदस्य बैठे-बैठे बात नहीं करें।

श्री रामनारायण चौधरी : सभापति जी, आपकी व्यवस्था शिरोधार्य है। यह समय का नियमन करना आपका काम है, आसन का काम है, आप व्यवस्था जो देंगे उसका हम पालन करवायेंगे। लेकिन व्यवस्था में आप ही ढील करें आसन से उसका क्या करें ? यह आसन पर आक्षेप नहीं है लेकिन प्रतिपक्ष का चीफ व्हिप प्रतिपक्ष का नेता ही कोप भाजक हो जाए अपने आदमियों का, ऐसा नहीं होगा। आसन को डरने की जरूरत नहीं होती है। इनको सबको पालन कराओ, नियमित समय पर बुलवाओ, नियमित समय के बाद रिक्वेस्ट कर दो। अब मेरे से क्यों कहलवाते हो सब बात। ऐसा नहीं, सभापति ऐसा कमजोर नहीं चाहिए, आसन ऐसा कमजोर नहीं चाहिए।

श्री सभापति : आपकी पार्टी से जब यह बात आती है कि हमारी पार्टी का समय है बोलने दीजिए तब आसन की मजबूरी हो जाती है।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं पार्टी का विनम्र सेवक हूं और सेवा में मैं कोई फर्क नहीं पड़ने देना चाहता उसके बाद पालन करवाने का काम आसन का है। मैं आपको सहयोग करूंगा।

श्री सभापति : धन्यवाद। Please sum up your speech now.

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं और आपको यह लग रहा है कि मैं कोई अनर्गल बात कर रहा हूं तो आप कह दें मैं बैठ जाता हूं।

श्री सभापति : यह नहीं है, समय का सवाल है।

श्री संयम लोढ़ा : क्या बात हुई, माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं..

श्री सभापति : समअप।

श्री संयम लोढ़ा : मुख्य मंत्रीजी इस बात का भी जवाब दें कि जे.डी.ए ने बिना टेण्डर के जो एक करोड़ दस लाख के जो ....

श्री महावीर प्रसाद जैन : सभापति महोदय, मेरा पाइंट आफ आर्डर यह है कि अपने कुछ 269-270 में, यह नियम है कि कोई भी माननीय सदस्य ऐसा कोई भाषण नहीं देगा जिससे उत्तेजना फैले।

दूसरी बात यह है कि जैसा प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने कहा कि राज्यपाल का अभिभाषण कुछ नीतियों और उसके ऊपर बोलने का है। अब हरेक में वह जवाब दो, जवाब दो। जवाब होना चाहिये तो क्वेश्चन के माध्यम से या और बहुत सारे माध्यम हैं। मैं यह नहीं कह रहा उनको नहीं बोलना चाहिये पर अपने इस प्रक्रिया और नियम में बहुत सारे ऐसे माध्यम हैं जिनके माध्यम से, 273 है, कोई आक्षेप आप लगाना चाहते हैं, आप कोई प्रस्ताव लेकर आएं। अब बिना प्रस्ताव लाये यहां पर अनावश्यक रूप से कोई भी बात कहेंगे और जवाब दो, हाथों हाथ क्या जवाब देंगे ? इसलिये मेरा आपसे निवेदन है कि जवाब तो समय पर दिया जायेगा...

श्री संयम लोढ़ा : मत देना जवाब हमारे क्या फर्क पड़ता है ?

डा. सी.पी. जोशी : मत दो जवाब।

श्री महावीर प्रसाद जैन : जवाब दिया जायेगा। क्यों नहीं देंगे ? लेकिन यह नहीं हो सकता वह सदन में बार-बार अनर्गल आरोप लगाये जायें। यह ठीक नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सभापति महोदय, जो पाइंट आफ आर्डर उन्होंने 269 और 270 में, 270 में तो कोई पाइंट आफ आर्डर आ ही नहीं सकता। 1 उसमें तो यह व्यवस्था है कि, 270 के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा पुकारे जाने पर सदस्य का बोलना। तो यह नियम तो इन्होंने गलत कोट किया है। 269 में बोलते समय पालनीय नियमों का उल्लेख किया गया है...

श्री महावीर प्रसाद जैन : तो उसको पढ़ो तो आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उसमें माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, बिलकुल नियमों के अन्तर्गत बोल रहे हैं। गवर्नर एड्रेस के ऊपर खुली डिबेट होती है और उसमें मुख्य मंत्रीजी आज जवाब देंगी, जो प्रश्न वह उठा रहे हैं

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

उनका जवाब दे देंगी। यह कोई प्रश्नों के माध्यम से उठाने वाले बिन्दु नहीं हैं, इस पर जनरल डिबेट हो रही है इसलिये जो यह मुद्दे उठा रहे हैं उनका प्रत्युत्तर जवाब दें, तब दे दें। कोई नियम के विरुद्ध नहीं बोले हैं।

श्री सभापति : समय का ध्यान रखें। प्लीज, समय, समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय सभापति महोदय, जिस 56,000 बीघा लैंड बैंक का ढिंढोरा पीट रहे हैं उसका टाइटल तो कितने बरसों से जे.डी.ए. के नाम पर है। मैं यह नहीं कहता कि यह सारी 56,000 बीघा भूमि पहले की है, आपने भी पहले कुछ महीने में जे.डी.ए. के नाम की है। लेकिन उस 56,000 बीघा में से बहुतायत में भूमि का टाइटल पहले से जे.डी.ए. के नाम पर है।

माननीय सभापति महोदय, आज जयपुर विकास प्राधिकरण में जिस तरह के काम हो रहे हैं, आप देखिये। शूटिंग रेंज, जगतपुरा, कंसलटेंट साढ़े तीन प्रतिशत, कोस्ट का साढ़े तीन प्रतिशत। स्मृति उद्यान-कंसलटेंट, कोस्ट का तीन प्रतिशत, खोले के हनुमानजी, भले ही वह मंदिर के लोग चाहते हों, नहीं चाहते हों, काम हो कि नहीं पर ओब्लाइज करना है तो तीन प्रतिशत कोस्ट का उनको दी। जयपुर विकास प्राधिकरण में 38 कम्प्यूटर और 3 लैपटाप हैं, इसके बावजूद एक-एक के ऊपर 118 कम्प्यूटर लेकर 60 लाख रुपये प्रतिवर्ष चूना लगाने का काम इस जयपुर विकास प्राधिकरण के अन्दर हो रहा है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं...

श्री सभापति : समाप्त प्लीज। आप अब बहुत समय ले चुके हैं, प्लीज समाप्त करिये वरना मैं दूसरे का नाम पुकारता हूं।

श्री संयम लोढ़ा : मैं अब आपकी आज्ञा का पालन करूंगा।

मैं आपके माध्यम से यह भी ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि जब अकाल को लेकर गिरदावरी हुई, हमारे अपने सिरोही जिले में चार पंचायत समितियों में रिजोल्यूशन लिया कि यह गिरदावरी गलत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के लोग उसमें बैठे हुए थे। जिला परिषद् ने जब रिजोल्यूशन लिया भारतीय जनता पार्टी के छह लोग इसमें बैठे हुए थे। सरकार को हमने रिप्रजेंटेशन दिया और जब जोधपुर में माननीय अकाल राहत मंत्रीजी ने बैठक ली हमने इस बात को रखा कि यह गिरदावरी गलत हुई है। भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने उस मीटिंग में यह कहा गिरदावरी के अन्दर धांधली हुई है।

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय सभापति महोदय, सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से राजस्थान के हजारों गांवों को गिरदावरी में अण्डर 50 परसेंट से कम खराबा में रख करके लोगों को आर्थिक नुकसान पहुंचाने का काम किया है।

श्री सभापति : समाप्त प्लीज।

श्री संयम लोढ़ा : और जिस चारा डिपो और अनुदान का जिक्र कर रहे हैं मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि शिवगंज की गौशाला...

श्री सभापति : श्री जीवाराम चौधरी।

श्री संयम लोढ़ा : पांच मिनट में वाइंड अप कर रहा हूं माननीय सभापति महोदय।

आज शिवगंज की गौशाला के अन्दर यह..(व्यवधान) लेकिन इसके बावजूद एक रुपये का अनुदान आपने नहीं दिया।

श्री सभापति : No. I can't allow you. You have taken more than 35 minutes. Sorry please.

श्री संयम लोढ़ा : मैं वाइंड अप कर रहा हूं। मैं दो मिनट में वाइंड अप कर रहा हूं। दो मिनट लूंगा मैं आपके। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज जिस..(व्यवधान) दो मिनट प्लीज। दो मिनट में वाइंडअप कर रहा हूं मैं..

श्री जीवाराम चौधरी : उनसे लो परमीशन।

श्री संयम लोढ़ा : मेरे दो इशु हैं, मैं दो मिनट में वाइंड अप कर रहा हूं। मैं आपको कह रहा हूं..

श्री सभापति : You have taken more than 35 minutes.

श्री संयम लोढ़ा : मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस आज इमानुअल मिशन की पांच संस्थाओं का रजिस्ट्रेशन रद्द किया सरकार ने। इमरजेंसी के अन्दर भी आर.एस.एस. से जुड़े हुए लोगों का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया था लेकिन माननीय सभापति महोदय, वह आज थामस बदमाश हो सकता है। थामस के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये। उस किताब के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिये लेकिन अगर सरकार किसी भी संस्था का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करती है तो पहले प्रशासक की व्यवस्था करती है, वह आपने व्यवस्था की नहीं। उन बच्चों का क्या होगा ? यह आपने व्यवस्था की नहीं और उससे पहले आप जो अनाथ बच्चों के साथ करने जा रहे हो वह किसी भी रूप में सर्वथा उचित नहीं है।

श्री सभापति : धन्यवाद। प्लीज, श्री जीवाराम चौधरी।

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री सभापति : जीवाराम चौधरी। Take your seat please. Nothing to record.

श्री बंशीलाल खटीक : x x x

श्री कन्हैया लाल मीणा : x x x

श्री महावीर प्रसाद जैन : पाइंट आफ आर्डर। मैंने पहले भी यह कहा था कि 269 के तहत पालनीय नियम है उसकी पालना सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य नहीं कर रहे हैं, यह बोलते जा रहे हैं।

श्री सभापति : आप सदन का ध्यान दिलाना चाहते हैं तो नियमों के तहत आइये। ऐसा नहीं है No. I would not allow it. Nothing is going on record. I would not allow it. You please come. नो, रिकार्ड में कुछ नहीं जायेगा।

श्री संयम लोढ़ा : x x x

श्री बंशीलाल खटीक : x x x

श्री सभापति : श्री जीवाराम चौधरी।

श्री जुबेर खान : सभापति महोदय, आन ए पाइंट आफ इन्फार्मेशन। नेता प्रतिपक्ष के पास एक तार आया है बसेड़ी से, और महिला ने किया है कि मेरे पति दीनदयाल पुत्र गोरे काछी निवासी झील बसेड़ी को जेरोली से पुलिस मार्शल जीप में पकड़ कर ले गयी और मुझे इसका पूरा अंदेशा है कि उनका एनकाउंटर करके उनको मार दिया जायेगा। मैं आपके माध्यम से गृह मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि एक महिला जो अपने पति के लिये इस तरह की गुहार कर रही है उनको सुरक्षा दिलायी जाये और इसकी पड़ताल की जाये कि कहीं पुलिस उसको एनकाउंटर में मार नहीं दे। मैं आपके माध्यम से यह पाइंट आफ इन्फोरमेशन माननीय गृह मंत्रीजी को देना चाहता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (गृह मंत्री) : तार इधर दे दो।

श्री सभापति : श्री जीवाराम चौधरी।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचौर) : आदरणीय सभापति महोदय, मैं महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के समर्थन में बोलने जा रहा हूं। मेरे से पूर्व सभी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने विचार प्रकट किये। मैं सभी माननीय सदस्यों से हाथ जोड़कर प्रार्थना करता हूं कि मैं इस विधान सभा में

(श्री जीवाराम चौधरी)

दो साल के कार्यकाल में दूसरी बार बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं इसलिये मैं आपका सब का समर्थन चाहूंगा कि मुझे बीच में व्यवधान पैदा नहीं करें।

माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचौर में विश्व की सबसे बड़ी गौशाला श्रीगोपाल गौवर्धन गौशाला के नाम से है जिसमें हम लाखों गायों की जनता के सहयोग से और हमारी लोकप्रिय सरकार के सहयोग से रक्षा करते हैं।

इनकी सरकार पिछले कितने साल रही उस गौ-शाला की 6 किलोमीटर सड़क इनके वहां के उस समय के विधायक, उस समय के माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोकजी और पूर्व सरकार के कई मंत्री जो उस गौ-शाला में जाकर के अपनी-अपनी तरफ से सड़क को बनाने के लिए घोषणा करके आये । मुझे खेद है कि इनके पांच साल के कार्यकाल में इतनी बड़ी गौ-शाला की 6 किलोमीटर की सड़क इनकी सरकार नहीं बना सकी। उस 6 किलोमीटर की सड़क की वजह से इतनी बड़ी गौ-शाला का प्रतिदिन चारा लाने के लिए ट्रकों का 15 हजार रुपए का किराया, सड़क ना होने के कारण से लग रहा था। मैं धन्यवाद देता हूं हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी और हमारे सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को जिन्होंने हमारी सरकार बनते ही 6 महीने के अन्दर वह 6 किलोमीटर सड़क बनाकर के हमारी गौ-शाला को गौरवान्वित किया और हमारी गौ-शाला को लाभ दिया।

सभापति महोदय, ठीक इसी प्रकार से मेरे विधान सभा क्षेत्र के हजार की जनसंख्या वाले गांव जुड़ गये हैं, पांच सौ की जनसंख्या के गांव सड़कों से वर्तमान में जुड़ चुके हैं और अभी 250 की जनसंख्या वाले गांवों के प्रस्ताव माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी ने मंगवा लिये हैं। उसके लिये भी मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूं। दूसरे माननीय सदस्यों ने पूरे प्रदेश के बारे में जो जिक्र किया है हमारी सरकार की लोकप्रियता की वह बातें मैं वापिस रिपीट नहीं करूंगा। मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचौर में इन दो-सवा दो साल की अल्पावधि में हमारी लोकप्रिय सरकार ने जो-जो कार्य किये, सिर्फ उन्हीं को आपके माध्यम से गिनाना चाहूंगा।

सभापति महोदय, जैसा कि सर्वविदित है कि पूरे प्रदेश में पानी की कमी है यह हम, आप और माननीय प्रतिपक्ष के सदस्य और राजस्थान की जनता जानती है। हमारे इस प्रदेश की भौगोलिक स्थिति ही कुछ ऐसी है

(श्री जीवाराम चौधरी)

जिसकी वजह से हम उस तकलीफ को सहन करते जा रहे हैं। लेकिन हमारी इस लोकप्रिय सरकार के आने के बाद मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचौर के गांवों में से 150 गांव ऐसे हैं, वहां का क्षेत्र ऐसा है जहां जमीन के अन्दर ही पानी उपलब्ध नहीं है और अगर है तो बिलकुल साल्टी वाटर है। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे पी.एच.ई.डी. मंत्रीजी को जिन्होने दो साल में 35 नये बोर जहां पानी की उपलब्धता है वहां स्वीकृत करवा कर हमारी जनता को पानी पहुंचाने का बहुत शुभ कार्य किया है। उसके साथ-साथ पौने तीन करोड़ रुपये की केरिया और अगड़ावा और तीन करोड़ की भादरणा और अरनाय यह दो स्कीमें हमारी सरकार से स्वीकृत करने की मांग हमने की है। बेडिया एक क्षेत्र है जो बाखासर बोर्डर पर पड़ता है। वहां से एक डायरेक्ट अप्रोच ना होने के कारण वहां की जनता को पीने के पानी की समस्या होती है, लाइट ना होने के कारण हमारे विभाग ने 31 लाख रुपये की स्कीम बनाकर के सरकार को भेजी है। मैं चाहूंगा कि वह भी तुरन्त स्वीकृत हो जाये । मैं धन्यवाद दूंगा आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को और सिंचाई मंत्रीजी को जिन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक नहर क्षेत्र है जहां लूणी नदी का पानी बारिश होने पर प्रवेश करता है। आज से चालीस साल पहले उस पानी को रोकने के लिए वहां पर डेढ़-डेढ़, दो-दो किलोमीटर के लम्बे अलग-अलग जगह पर बांध बने हुए थे और 25-30 साल पहले लूणी में खूब पानी आने के कारण वह सारे बांध बीच-बीच में से टूट गये थे। पिछली सरकारों ने उस बांध की तरफ कोई चिन्ता व्यक्त नहीं की। उन किसानों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उस बांध में पानी भरने के बाद उस क्षेत्र के खेत पानी से लबालब हो जाते हैं और पानी सूखने के बाद उस क्षेत्र में गेहूं को खूब बोया जाता है उसके बाद में उस फसल के लिए उन किसानों का कोई खर्चा नहीं होता है। ऐसी जगह पर हमारे माननीय सिंचाई मंत्रीजी जिन्होंने उन 19 बांधों को इन दो साल में 4 करोड़ 55 लाख रुपये स्वीकृत करके काम समय पर पूरा करवा लिया । मैं पुनः उनको और हमारी आदरणीय मुख्य मंत्रीजी को वहां के किसानों और मेरी ओर से धन्यवाद देता हूं। जिन्होंने नर्मदा नहर परियोजना जो कि साढ़े 74 किलोमीटर सिर्फ मेरे निर्वाचन क्षेत्र सांचौर से होकर के निकलती है। पिछली सरकार ने उनके कार्यकाल में 110 करोड़ नर्मदा नहर परियोजना के लिए नहीं दिये थे जिनकी वजह से यह कार्य डिले हुआ। अगर वह पिछली कांग्रेस सरकार समय पर उनका भुगतान गुजरात सरकार को कर देती तो आज नहीं आज से तीन साल

(श्री जीवाराम चौधरी)

पहले हमारी विधान सभा क्षेत्र सांचौर में नर्मदा का पानी आ चुका होता। लेकिन वह इतना महत्वपूर्ण कार्य हमारी सरकार ने महत्वपूर्ण समझा। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी को और हमारे सिंचाई मंत्रीजी को जिन्होंने हमारी सरकार बनने के तुरन्त बाद 344 करोड़ रुपये और उसके बाद 150 करोड़ रुपये कुल मिलाकर 644 करोड़ रुपये गुजरात सरकार को भुगतान कर चुके हैं। और नर्मदा का कार्य मेरे विधान सभा क्षेत्र में लगभग पूर्ण होने पर है और गुजरात का कार्य जो राजस्थान से जोड़ने का है वह तीन-चार महिनों में हो जाना चाहिए, ऐसी सम्भावना सरकार ने व्यक्त की है। जून-जुलाई तक नर्मदा का पानी सांचौर में आयेगा। मैं निवेदन करूंगा हमारे सिंचाई मंत्रीजी और हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी को कि जिस स्पीड से यह काम आपने हाथ में लिया, चालू रखा है इसी स्पीड से इसको कायम रखें ताकि जून-जुलाई तक हमारे जालौर जिले में, सिरोही जिले और बाड़मेर जिले के लोगों को नर्मदा से पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध हो सके।

(14.55 बजे)

(श्री रामनारायण विश्नोई, उपाध्यक्ष, पदासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे याद है 1998 में मैंने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांचौर से चुनाव लड़ा था और उसके पांच साल तक हम लोग विपक्ष में रहे और सामने बिराजे माननीय सदस्यों की कांग्रेस की सरकार रही। मुझे याद है एक-एक ट्रांसफार्मर लगाने के लिए, सीजन के टाइम पर किसान 15-15, 20-20 दिन तक तड़फता था और उसके बाद चार-पांच हजार रुपये रिश्वत लेने के बाद उस किसान को ट्रांसफार्मर मिलता था। मुझे यह कहने में बड़ा गौरव महसूस होता है, मैं धन्यवाद देता हूं हमारे बिजली मंत्रीजी को और हमारे मुख्य मंत्रीजी को कि आज की वर्तमान स्थिति सांचौर की ऐसी है वहां पर स्टोर में 450 ट्रांसफार्मर अभी वर्तमान में हाजिर हैं। और हमारी सरकार के कार्यकाल में (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : आपको जवाब देना पड़ेगा। आपने जो अन्याय किसानों के साथ किया है उसको किसान बर्दाश्त नहीं करेगा (व्यवधान) चार-चार घंटे बिजली नहीं आती, किसान की फसल जल गयी है (व्यवधान)

श्री जीवाराम चौधरी : हमने किसानों के साथ कोई अन्याय नहीं किया (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : यह अन्याय है।

श्री जीवाराम चौधरी : हमने किसानों के लिये जो फायदा किया है (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार : हम तो भुगत रहे हैं न।

श्री जीवाराम चौधरी : हमने किसानों के लिए जो फायदा किया है। हमारी सरकार ने किसानों के हितों के लिए जो कार्य किया वह मैं गिना रहा हूं और वह भी मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचौर का गिना रहा हूं। सांचौर में पहली बार विद्युत का स्टोर हमारी सरकार ने खोला और जिस सामान के लिए, एक-एक एंगल के लिए, एक-एक बोल्ट के लिए, एक-एक नट के लिये किसान जिसे नया कनेक्शन मिलता था उसके लिए महीने-महीने, डेढ़-डेढ़ महीने तड़फता था आज वहीं सांचौर में स्टाक 450 तक नये ट्रांसफार्मर अभी वर्तमान में स्टाक में हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आप चाहें तो हमारे जिला कलक्टर जालौर से उनके स्टाक की संख्या मंगा लें। हम भी असत्य नहीं बोलते और हमारी सरकार भी नहीं बोलती।

श्री श्रवण कुमार : वह साढ़े चार सौ झुंझुनूं मंगाओ आपका जिला है।

(15.00 बजे)

श्री जीवाराम चौधरी : दो साल के कार्यकाल में मेरे विधान सभा क्षेत्र में पांच 33 केवीए के नए जीएसएस हमारी सरकार ने खोले और 132 केवीए के दो जीएसएस, सांकड़ और भादरोना, उसमें भादरोना तो कम्पलीट हो चुका है और सांकड़ दो महीने में कम्पलीट होने जा रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे बिजली मंत्रीजी को कि दो साल में इतना बड़ा कार्य बिजली के विभाग का मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचौर में इन्होने कराया है।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे आदरणीय शिक्षा मंत्रीजी का जिन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचौर में सिर्फ दो साल में 51 नई प्राइमरी स्कूलें मिडल में क्रमोन्नत की और 64 नए प्राइमरी स्कूल खोले। वर्तमान में उन 64 प्राइमरी स्कूलों में दो-दो सौ, तीन-तीन सौ बच्चे शिक्षा का लाभ ले रहे हैं। 5 स्कूलें मिडल से सैकण्डरी में क्रमोन्नत की और एक को सीनियर सैकण्डरी में क्रमोन्नत करके मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचौर की जनता को लाभांवित किया।

(श्री जीवाराम चौधरी)

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी को जिनके सहयोग से नगरपालिका, सांचौर ने दो साल में 200 छोटी-मोटी सड़कें बनाकर एक कीर्तिमान स्थापित किया है। सांचौर नगरपालिका क्षेत्र में आज कोई भी ऐसी गली, जिसको गली कह सकते हैं, 40 फीट की है तो वहां सड़क निर्मित है और जहां रोलर नहीं जाता था वहां पर हमने सीसी रोड बनाई है।

सांचौर नगरपालिका बनने के बाद से आज दिन तक वहां फायर ब्रिगेड की गाड़ी नहीं थी और हमारे वहां पर इस प्रकार की कोई दुर्घटना हो जाती थी तो फायर ब्रिगेड की गाड़ी हमें जालौर जिला हैड क्वाटर या भीनमाल से मंगवानी पड़ती थी। और जब तक वह गाड़ी उस स्थान तक पहुंचती थी तब तक वहां सब कुछ जल कर राख हो जाता था। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे स्वायत्त शासन मंत्रीजी को जिन्होंने 19 लाख रुपए की एक नई फायर ब्रिगेड की गाड़ी नगरपालिका सांचौर को दी।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे समाज कल्याण मंत्रीजी को जिन्होंने दो साल में समाज कल्याण के क्षेत्र में मेरे विधान सभा क्षेत्र में आवासीय विद्यालय खोला जिसमें अभी वर्तमान में हमारे एससी और एसटी के बालक बालिकाएं शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं और रह रहे हैं।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय स्वास्थ्य मंत्रीजी को जिन्होंने विधान सभा क्षेत्र सांचौर में 14 नए उप स्वास्थ्य केन्द्र खोले और राजकीय अस्पताल, सांचौर को आदर्श अस्पताल का दर्जा दिया।

आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार बनने से पहले भी इस प्रदेश में कई बार अकाल पड़ा। पिछले अकाल में मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचौर में जितने भी इससे पूर्व के अकाल थे, इनकी सरकार के समय में 13 हजार से ज्यादा श्रमिक संख्या कभी भी पूरी तहसील में नहीं रही। मैं धन्यवाद देता हूं, हमारे अकाल राहत मंत्रीजी को जिन्होंने पिछले अकाल में अकेले विधान सभा क्षेत्र सांचौर में 26 हजार की श्रमिक संख्या देकर हमारे गरीबों को रोजगार दिया।

श्री उपाध्यक्ष : पूरे मंत्रियों को एक साथ ही धन्यवाद दे दो, बाकी मत छोड़ो।

श्री जीवाराम चौधरी : मुझे गर्व है कि हमारे हर विभाग ने मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही नहीं हमारे पूरे प्रदेश में अच्छा काम किया है। इसीलिए

(श्री जीवाराम चौधरी)

भी यह धन्यवाद के पात्र हैं। मैं झूठा धन्यवाद नहीं देता हूं, इन्होंने इतने काम किए हैं जिनका उद्घाटन मैं नहीं कर पाया हूं। शर्म आनी चाहिए आप लोगों को।

उपाध्यक्ष महोदय, अन्त में मैं राजस्थान की ओजस्वी, यशस्वी और तेजस्वी मुख्य मंत्री महोदया का हृदय से धन्यवाद देता हूं कि प्रदेश में इसी प्रकार की विकास की गंगा बहाती रहें। सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य को अभी पता नहीं, कहां से उलट-मुलट आंकड़े इकट्ठे करके प्रचार पाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : वह छोड़ो, उनकी चर्चा आप छोड़ो।

श्री जीवाराम चौधरी : हमारी लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी कुछ दिन पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र सांचौर में एक गौशाला में पधारी थीं। उनके साथ हमारे सदन की अध्यक्षा भी थीं। मुझे यह कहते हुए खुशी हो रही है कि सिर्फ एक दिन के शोर्ट नोटिस पर, आज तय हुआ कि कल आदरणीय मुख्य मंत्रीजी पधार रही हैं, दूसरे दिन जब मुख्य मंत्रीजी पधारीं तो उस समय सवा लाख से ज्यादा की संख्या में लोग उन्हें सुनने और देखने के लिए आए थे।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : गाड़ियां कितनी लाए थे ?

श्री जीवाराम चौधरी : एक सिंगल गाड़ी नहीं लगाई थी। गौशाला में धार्मिक फंक्शन था, सबको खुद को यह पता था कि आदरणीय मुख्य मंत्रीजी गौशाला पधार रही हैं। गाड़ियां लगाने का काम आप लोगों को सौंपा हुआ है।

श्री हरिमोहन शर्मा : सभी जानते हैं कि जहां पोलिटिकल फंक्शन करते हैं, सभी पार्टियां गाड़ी लगाती हैं। अभी उनियारा में प्रभुलालजी ने लगाई थी।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर) : वह आपकी परम्परा है, हमारी नहीं।

श्री जीवाराम चौधरी : आप मुझसे वरिष्ठ सदस्य हैं। मैंने शुरूआत में ही आपसे निवेदन कर दिया था लेकिन आदत से बाज बन्दर कितना ही बूढा हो जाए, गुंलाटी मारना नहीं भूलता। आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इन्हीं को कह रहा हूं, गड़बड़ कहीं और होती है और चिल्लाते कहीं और हैं ऐसे कांग्रेसी मित्रों को भी मेरा राम-राम, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग : धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान) तुलसीदासजी ने कहा है, 'दुर्जन पहले वन्दिए'।

उपाध्यक्ष महोदय, पिछले चार दिन से यह सदन एक दस्तावेज के बारे में चर्चा कर रहा है। महामहिम राज्यपाल महोदया ने कृपापूर्वक जो भाषण हम सबके सामने रखा, उसमें वर्णित बातों के बारे में यह सदन चर्चा कर रहा है। साल के 52 सप्ताह और 52 पृष्ठों का यह दस्तावेज। 52 सप्ताह के कामों को 52 पृष्ठों में समेटना और वह भी वसुन्धराजी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कामों को, बहुत मुश्किल काम था, मगर गागर में सागर भरने का प्रयास महामहिम राज्यपाल महोदया ने किया है। यह वास्तव में सराहनीय प्रयास है। इतनी सारी बातें इसमें आने के बाद भी बहुत सारी बातें ऐसी बच गई थी जो इसमें नहीं ले पाई, उन सबका वर्णन मेरे साथी माननीय सदस्यों ने अपने-अपने भाषण में किया है। इतनी सारी बातों का उल्लेख इस दस्तावेज में होने के बाद भी बहुत सारी बातें ऐसी हैं हमारे पास कहने को जो काम हुए हैं राजस्थान की धरती पर और हम गिना नहीं पा रहे। इतनी लम्बी सूची है। किसी भी विभाग में चले जाएं किसी भी विभाग को हाथ में ले लें, चाहे चिकित्सा हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे परिवहन हो, चाहे खेल, चाहे बिजली हो, चाहे अकाल राहत, चाहे समाज कल्याण हो चाहे महिला कल्याण, चाहे आदिवासी कल्याण, जिस तरफ भी हम देखेंगे उधर हमारे पास गिनाने के लिए इतने सारे काम हैं जो पिछले एक साल ही नहीं पिछले दो साल में हमने किए हैं इसलिए उन सबकी लम्बी सूची पढ़ने के बजाय मैं तुलसीदासजी की एक चौपाई पढ़ना चाहूंगा।

'हरि अनन्त, हरि कथा अनन्ता,
कहहि, सुनहि, बहु विधि सब सन्ता'

(व्यवधान)

इतने विशाल, इतने सारे जो उल्लेखनीय काम किए हैं, उसका प्रत्यक्ष असर राजस्थान में नजर आ रहा है, आंकड़े बोल रहे हैं। राज्य की वार्षिक योजना का आकार बढ़ा है, वर्ष 2003-2004 में जब ये लोग यहां विराज रहे थे तो कुल मिलाकर 4258 करोड़ रुपए की वार्षिक योजना थी। उसमें भी 75 प्रतिशत ही खर्च कर पाए थे बाकी की व्यवस्था नहीं कर पाए थे, वह भी हमने बाद में जाकर पूरी की थी। वर्ष 2005-2006 की वार्षिक योजना का आकार देखें, 8350 करोड़ रुपए हो गया है। दुगुने के आसपास तक पहुंच गया है और

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

उसका असर हुआ, कैपिटल आउट-ले भी बढ़ा जो इनके समय में 3181 करोड़ रुपए था वह अब 5161 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। ये सारे प्रत्यक्ष आंकड़े गवाह हैं। उसके बाद भी आलोचना हो रही है और आलोचना क्यों हो रही है इसके दो कारण हो सकते हैं या तो यह कि इनके चश्मे का नम्बर ठीक नहीं है या फिर इनकी नीयत ठीक नहीं। हरिमोहनजी, तुलसीदासजी ने आपके लिए एक चौपाई और कही है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। हमको विकास नजर आ रहा है, इनको नजर नहीं आ रहा है। या तो अपने चश्मे का नम्बर बदलिए या अपनी भावना बदलिए।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपकी भावना यह है और हमारी भावना यह है कि हम कमियों को देखें। आपकी भावना मंत्रिमण्डल में जाने के लिए बिलकुल ठीक है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि आप इसी तरह उधर बैठे हमारी कमियां देखते रहें। हम इधर बैठे इसी तरह विकास करते रहें, ईश्वर निश्चित रूप से आपकी तमन्ना पूरी करेगा।

श्री रामनारायण मीणा : क्या आप वाल्मीकि रामायण की चौपाई पढ़ सकते हैं?

श्री जोगेश्वर गर्ग : यह मेरे बस का रोग नहीं है।

श्री रामनारायण मीणा : भारतीय जनता पार्टी में जाने के बाद शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों की भावना बदल जाती है। वाल्मीकि की ओरिजनल रामायण है, तुलसीदासजी का नाम बाद में लें कृपा करके। आप तो ध्यान रखें वाल्मीकिजी का।

श्री जोगेश्वर गर्ग : अब वाल्मीकिजी तो आपके रिश्तेदार थे?

श्री रामनारायण मीणा : बिलकुल हमारे थे। आपके नहीं थे क्या? (व्यवधान) उनका नाम क्यों नहीं लेते हो? नाम वाल्मीकिजी का लो, उद्धार हो जाएगा। सारी सीटें हमसे छीनकर ले गये, फिर भी वाल्मीकिजी को याद नहीं कर रहे हो आप ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : फिलहाल तो आप अपने उद्धार की चिन्ता कीजिए, हमारा उद्धार तो हम कर लेंगे। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब से राजस्थान की स्थापना हुई है राजस्थान एक गरीब प्रदेश है, आय के साधन कम हैं, उसके कारण से हमेशा एक स्थिति यह बनी रही बार-बार अकाल पड़ता है, संसाधनों की आवश्यकता बहुत है, क्षेत्रफल बहुत है, जनसंख्या बहुत है, संसाधन कम हैं।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

मुझे एक शायर का शेर याद आ रहा है- और कुछ भी मुझे दरकार नहीं है, लेकिन जो राजस्थान पिछले 50-60 साल से कशमकश झेल रहा है वह यह है कि 'और कुछ भी मुझे दरकार नहीं है, लेकिन मेरी चादर मेरे पैरों के बराबर कर दें'। राजस्थान 50-60 साल से यह कोशिश कर रहा है सिर को ढकने की कोशिश करता है, पैर नंगे हो जाते हैं, पैरे को ढकने की कोशिश करता है सिर नंगा हो जाता है। चादर कभी हमारे शरीर के नाप की नहीं बन पायी, पर आज मैं खुशी के साथ कह सकता हूं, गर्व के साथ कह सकता हूं, पिछले दो वर्षों में माननीय वसुन्धराजी के नेतृत्व में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजस्थान में काम कर रही है उस चादर को हमारे शरीर के नाप के बराबर करने का उन्होंने प्रयास किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : वह साड़ी की वजह से लम्बाई बढ़ी है, ध्यान करें। चादर नहीं है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : आपको भी एक साड़ी भेट कर देंगे। उपाध्यक्ष महोदय, हमने इस सदन में वे दिन भी देखे हैं जब इधर बैठे हुए लोग, जिम्मेदार लोग जिन पर राजस्थान की जनता ने इतना भरोसा किया था कि 156 सीटें दी थीं, वो इधर बैठकर दीनता के साथ कहते थे हमारा खजाना खाली है, हमारे पास देने को कुछ नहीं है, न कम्रचारियों को देने को कुछ है, न किसानों को देने को कुछ है, न मजदूरों को देने को कुछ है, न युवाओं को देने को कुछ है, खजाना खाली, खजाना खाली। पिछले दो वर्षों में कोई माई का लाल यह कह दे, हमारी मुख्यमंत्री तो छोड़िए, सामान्य से आम कार्यकर्ता ने भी नहीं कहा कि हमारे पास इस चीज के लिए पैसे की कमी है। जनता हमसे काम मांगती है, हम बेधड़क, बिना मंत्रियों से पूछे, बिना मुख्य मंत्रीजी से पूछे हां भरकर आते हैं, हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे और आते हैं, व्यवस्था होती है, काम होता है। यह जो माहौल बदला है इसके लिए निश्चित रूप से हमारे यशस्वी मुख्य मंत्रीजी बधाई के पात्र हैं, हमारी सरकार के सारे मंत्री बधाई के पात्र हैं।

ये लोग जहां जाते हैं, जहां-जहां पांव पड़े संतन के तहां-तहां बंटाधार। अब साल भर से दिल्ली में इनकी सरकार है। दिल्ली में क्या हाल है ? माननीय अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, आज बहुत चर्चा हो रही थी गेहूं की। एफ.सी.आई. के गोदामों में रखने के लिए जगह नहीं थी, बाहर गेहूं रखते

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

थे और खराब न हो जाए उसके लिए तिरपालों से ढककर रखना पड़ता था। सरप्लस गेहूं पड़ा था। आज क्या स्थिति है ? भारत सरकार का बनाया हुआ नियम है एफ.सी.आई. के गोदाम में मिनिमम 87 मिलियन मैट्रिक टन रिजर्व स्टाक रहना चहिए। भारत सरकार का आंकड़ा बोल रहा है। आज की तारीख में 42 मिलियन मैट्रिक टन उपलब्ध है। हमारे पास 87 से ज्यादा सरप्लस था, आपके पास सिर्फ 42 मिलियन मैट्रिक टन गोदामों में पड़ा है, बाकी गोदाम खाली पड़े हैं, उनमें चूहे दौड़ रहे हैं। क्या देंगे आप जनता को? आप जनता को क्या खिलाएंगे ? कहां से आप ए.पी.एल. और बी.पी.एल. के गेहूं देंगे। आखिर बाजार में भाव नहीं बढ़ेंगे तो क्या होगा ? पर यह स्थिति किसने बनायी ? जैसे दिल्ली में कांग्रेस की सरकार आती है, खजाना खाली हो जाता है, उत्पादन कम हो जाता है, महंगाई बढ़ जाती है। इनका और महंगाई का तो चोली-दामन का साथ है। कांग्रेस जहां आयी महंगाई बढ़ी। इनकी भावना शुद्ध नहीं रहती है इसलिए भगवान भी इनका साथ नहीं देता। हमारी भावना शुद्ध है, हमारी सरकार की भावना शुद्ध है इसलिए भगवान भी हमारा साथ दे रहा है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य परसों जब बोल रहे थे तो एक जोरदार, धांसू आंकड़ा दिया समाज कल्याण विभाग में एस.सी., एस.टी. वेलफेयर मद में 19 परसेंट खर्चा हुआ। उनका भाषण पूरा होते ही मैं भागकर गया, उनसे पूछा, मान्यवर कौनसा हैड है बताइए। उस हैड में टोटल अमाउंट था 69 लाख। 69 लाख का कोई छोटा सा मद कहीं से उठाकर लाये, उसमें किसी कारण से खर्चा कम हुआ होगा, उसका उल्लेख करके सनसनी फैलाना चाहते हैं। मैंने समाज कल्याण विभाग से सम्पर्क किया, उनकी सारी मदों का यह प्रिंट आउट निकाला। यह आयोजना भिन्न, नान प्लान इसमें 43 मद हैं। 43 मदों की एक-एक की मैं चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन 43 मदों में कुल मिलाकर जितना खर्च हुआ है उसका ओवरआल परसेंटेज है 83.26 । यह जनवरी एण्ड तक के फीगर हैं। जो प्लान बजट है, जो प्लान का खर्चा हुआ है उसका भी एवरेज है 53.92 परसेंट जो जनवरी एण्ड तक है। दो महीने बाकी हैं और सारा संसार जानता है कि प्लान का ज्यादातर पैसा फरवरी और मार्च तक खर्च होता है। यह हम शत-प्रतिशत तक पहुंचाएंगे, आपको आलोचना का मौका हम नहीं देंगे। इसमें कई मद ऐसी हैं जिनमें 90 प्रतिशत से ऊपर तक खर्चा हो चुका है। इस तरह के भ्रामक आंकड़े देकर सनसनी फैलाना चाहते हैं। बोलते इधर हैं और नजर उधर होती

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

है, कोई प्रेस वाला नोट कर रहा है या नहीं कर रहा है, अख़बार में नाम आ रहा है या नहीं आ रहा है। इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है, बाकी हकीकत यह है कि बहुत काम हो रहे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य रूप से दो बातों पर अपना ध्यान केन्द्रित करना चाहूंगा। मैंने निवेदन किया कि कोई विभाग ऐसा नहीं है जिसके बारे में चर्चा करने के लिए एक-एक घण्टा बोलें तो भी कम पड़े, लेकिन दो बातों की ओर विशेष ध्यान दिलाना चाहूंगा जो हमने सुधार किये हैं। पिछली सरकार गयी उसमें बहुत बड़ा कारण था बिजली। बिजली नहीं मिलती थी और बिजली ये नहीं दे पाते थे, बिजली के साधन नहीं दे पाते थे। ट्रांसफार्मर नहीं दे पाते थे, लाइन नहीं दे पाते थे, जीएसएस नहीं दे पाते थे और उसका परिणाम यह होता था इनके कार्यकाल पांच वर्ष में जो तीन-चार महीने का काश्तकार का सीजन होता है, पांच साल में एक भी सीजन ऐसा नहीं गया जब राजस्थान की धरती पर 100 से 150 बार कहीं न कहीं काश्तकारों ने चक्का जाम नहीं किया हो, रोड जाम नहीं किया हो, धरने पर नहीं बैठे हों, और फिर भागकर सरकार को जाना पड़ता था, और दो-तीन दिन चक्का जाम रहने के बाद समझौता होता था और जैसे-तैसे उनको मनाकर उठाते थे। पिछले दो वर्षों में यह तीसरा सीजन जा रहा है, इनको चुनौती देकर मैं पूछना चाहता हूं कोई माई का लाल बता दे, पूरे राजस्थान में एक बार भी काश्तकार सड़क पर आया हो, धरने पर बैठा हो, हमारी सरकार के खिलाफ बिजली के कारण। एक जगह भी नहीं। यहां आकर चिल्लाना अलग बात है, यहां चिल्लाना आपका फर्ज है, आपको तनख्वाह मिलती है। इस बात के लिए आपकी पार्टी ने भेजा है आपको चिल्लाने के लिए, लेकिन राजस्थान की जनता आपके साथ नहीं है।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप चिल्ला रहे हो या बोल रहे हो?

श्री जोगेश्वर गर्ग : अब आंखों के साथ कानों का भी इलाज करवा लीजिए आप।

श्री खुशवीर सिंह जोजावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महापड़ाव हुआ था जयपुर में, 3 लाख लोग आये थे।

श्री हरिमोहन शर्मा : हमारा बोलना तो चिल्लाना है और आपका बोलना बोलना है, वाह भाई वाह।

श्री जोगेश्वर गर्ग : महापड़ाव हुआ था तो उसका इलाज भी हुआ, उनके साथ वार्ता भी हुई और उनको सन्तुष्ट करके यहां से भेजा गया था और वे सारे काम भी हुए।

डा. चन्द्रशेखर बैद : माननीय सदस्य, पावर की आप बात कर रहे हो, हंड्रेड परसेंट पावर कट चल रहा है। 50 हजार मजदूर बेरोजगार हो जाएंगे आने वाले सप्ताह के अन्दर। यह आपको जानकारी है या नहीं ? 50 हजार परिवार रोटी खाने से लाचार हो जाएंगे आने वाले सप्ताह के अन्दर।

श्री जोगेश्वर गर्ग : तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य, आप अपना भाषण दे चुके हैं परसों। (व्यवधान) बिजली का उत्पादन नहीं हो रहा था, बिजली का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमारी सरकार ने जो प्रयास किये हैं वे सब आपके सामने हैं, जितनी हमको बिजली चाहिए उतनी हमको नहीं मिल पा रही है।

श्री रामनारायण चौधरी : बिजली बढ़ाने का कुछ भी प्रयास आपने नहीं किया।

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय विपक्ष के नेता बहुत वरिष्ठ हैं, मैं उनसे कुछ नहीं कहना चाहता पर यदि यह पुस्तक आपने पढ़ी होगी तो एक-एक प्रयास का विस्तार से इसमें विवरण है, कौन सा कारखाना कब लग रहा है, कब उसका उत्पादन शुरू होगा, कब इसका निर्माण पूरा होगा, एक-एक इसमें वर्णन किया हुआ है।

श्री संयम लोढ़ा : आप तो थोड़ा यह बता दो कि जालौर सिरोही जनता ने 6 विधायक जिताकर भेजे, तीसरा बजट आ गया, एक मंत्री नहीं बनाया, जालौर सिरोही की जनता वोट नहीं देती क्या भाजपा को ?

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 45 सौ मेगावाट अतिरिक्त क्षमता वृद्धि का महत्वपूर्ण निर्णय हमारी सरकार ने लिया है, आगामी वर्षों में 1500 मेगावाट राज्य क्षेत्र में, 1500 मेगावाट केन्द्रीय क्षेत्र में (व्यवधान) और 1500 मेगावाट बिजली निजी क्षेत्र की परियोजनाओं से होगी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री जोगेश्वर गर्ग : बस मैं एक उदाहरण देता हूं, बाकी सारी लम्बी चौड़ी चर्चा नहीं करूंगा। बहुत सारी योजनाएं हैं। माननीय विपक्ष के नेता ने जो प्रश्न किया है उसका जवाब मैं दे सकता हूं पर समय मेरे पास इतना नहीं है।

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, जैसलमेर जिला सबसे अन्तिम जिला है इस राजस्थान का, सबसे पिछड़ा जिला है, सबसे कमजोर जिला है, बिजली को तरसता था 34 मेगावाट उस जैसलमेर जिला में दैनन्दिन आवश्यकता है, आज वह जैसलमेर जिला पावर ऊर्जा के बलबूते पर 203 मेगावाट का उत्पादन करके पड़ोसी जिलों को बिजली पहुंचा रहा है। यह परिवर्तन यह जादुई परिवर्तन हुआ है, वह जादुई परिवर्तन आप नहीं कर पाए वह हमारी वसुन्धराजी ने कर दिया और उसका परिणाम हमारे सामने है। और दूसरी बात बिजली होती थी हमारे पास वह हम नहीं दे पाते थे, एक तो हमारे जी.एस.एस. की कमी थी तो जी.एस.एस. की कमी दूर करने के लिए पिछले दो वर्षों में मैं कहना चाहता हूं 4 के.वी. के जी.एस.एस. राजस्थान की धरती पर गिने चुने 4-5 थे, इन दो वर्षों में हमने 200 बना लिए और आगामी वर्ष में दो और बनाने की तैयारी है 220 के 6 हमने बना लिए, दो वर्षों में और आगामी साल भर में 10 और बनाने की तैयारी है, 132 के 22 बनाये हैं 30 और बनाने की तैयारी है, 33 के.वी. के जी.एस.एस. तो गिन गिन के हमारी अंगुलियां घिस गई हैं, 326 जी.एस.एस. बनाये हैं राजस्थान की धरती पर 2 साल में और आने वाले साल में 300 और बिलकुल तैयारी में हैं उनकी स्वीकृति के आसपास है। यह जो स्थिति बनी, दूसरी बात जो छीजत होती थी, छीजत जी.एस.एस. के कारण भी होती थी, लाइनें कमजोर होने के कारण भी होती थी लेकिन बड़ी छीजत चोरियों के कारण होती थी। और वह उदाहरण भी राजस्थान की जनता को याद है जब अखबारों में बड़ी-बड़ी हैडलाइन छपी थी चोरी पकड़ने के लिए विद्युत विभाग के अधिकारी गये और विद्युत विभाग के मंत्री ने फोन किया कि वापस आपके माध्यम से जाओ, मौके पर से वापस आए थे। चोरियां नहीं रोक पा रहे थे। चोरियां करवा रहे थे आप लोग और उसका खामियाजा भुगत रहे थे राजस्थान के काश्तकार, आज हमने यह स्थिति पैदा कर दी है कि ऐसे ऐसे फीडर थे आपके कार्यकाल में जिनकी छीजत 62.5 परसेंट, वह फीडर आज 22 परसेंट पर आकर रूक गये हैं, 62.5 परसेंट छीजत वाले अनेक थे आपके कार्यकाल में, उनकी छीजत हमने चोरियां रोक दी, ट्रांसफार्मर बड़े लगा दिये, जी.एस.एस. बड़े लगा दिये, उसका परिणाम यह हुआ कि 22 परसेंट छीजत पर आकर हम रूक गये हैं और इसको कम करने का प्रयास सरकार कर रहीं है। फिर मैं कहना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कृषि कनेक्शन नीति जो सरकार ने घोषित की है उसके कारण

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

काश्तकारों को कितना फायदा हुआ ? अभी तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि काश्तकार रो रहे हैं। काश्तकार गुण गा रहे हैं राजस्थान सरकार को, वसुन्धरा सरकार के। मैटेरियल कास्ट जब आपके समय में आती थी, एक काश्तकार जब कनेक्शन लेने जाता था 30 परसेंट कास्ट काश्तकार को देनी पड़ती थी। और हजारों रुपये का उसका डिमाण्ड नोटिस आता था, आज उसकी जगह सिर्फ 10 परसेंट काश्तकार से मैटेरियल कास्ट ली जा रही है। और डिमाण्ड नोट केन्द्रीय सरकार राशि आधी से भी कम हो गई आपके कार्यकाल की तुलना में। और इसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगा घरेलू कनेक्शन में जो ढाणियां हैं, गांव से दूर रेगिस्तान इलाके के गांव से 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 9-9 किलोमीटर दूर ढाणियां होती हैं उन ढाणियों में विद्युतीकरण की बात आपके राज में जब भी आता था एक किलोमीटर का डेढ़ लाख रुपये पहले चार्ज करते थे। और यदि 5 किलोमीटर की ढाणी है तो उसके लिए उस ढाणी के निवासियों के बस में नहीं होता था कि वह कनेक्शन ले सकें। हमने नियमों का सरलीकरण करके यह नियम अभी लागू कर दिया, पिछले साल भी 15 कनेक्शन चाहिए, एक साथ यदि फाइल जमा हो जाए तो प्रति कनेक्शन मात्र 1500 रुपये लगेगा, बाकी सारा खर्चा सरकार देकर उस ढाणी का विद्युतीकरण कर रही है। हजारों की संख्या में रोजाना पिछले इस एक साल में विद्युतीकरण हुए हैं जो आपके कार्यकाल में नहीं हो पाए थे और उन 15 कनेक्शनों को मिलाकर हम केवल साढ़े 22 हजार रुपये लेते हैं। आपके समय में वह एस्टीमेट ढाई से तीन लाख पर था, यह जो परिवर्तन आया है उस सब का असर हमको दिख रहा है। शिफ्टिंग आफॅ कनेक्शन में आपके कार्यकाल में नियम बना था।

श्री उपाध्यक्ष : आप कन्क्लूड करें, बिजली पता है सब को छोड़ो। इसमें यह सब सुधार हो ही रहा है।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : सारे काम ठीक हुए हैं, एक भूल यह मुख्य मंत्रीजी से कैसे हुई, ऐसे विद्वान व्यक्ति को मंत्रिमण्डल में कैसे नहीं लिया, यह बड़ी भूल हुई है और सब ठीक है।

श्री जोगेश्वर गर्ग : जितनी बार आप सिफारिश करते हैं उतनी बार नम्बर कट जाता है, आप मेहरबानी रखिए।

एक बिजली के बारे में अन्तिम बात मैं कहकर अपनी बात पूरी

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

करूंगा। सैंट्रल सैक्टर की कई मशीनें इस सीजन में अचानक ब्रेक डाउन हुई हैं, जो कह रहे हैं श्रवण कुमारजी और चन्द्रशेखरजी बार बार कह रहे हैं कि इस साल काश्तकारों को तकलीफ क्यों आई, 6 घंटे पर ही हम क्यों अटक गये, उसका बड़ा कारण मैं इस सदन के सामने रखना चाहता हूं। सैंट्रल सैक्टर की कई मशीनें इस सीजन में अचानक ब्रेक डाउन हुआ और उसमें, जैसे उदाहरण के लिए कि रावतभाटा की यूनिट है, परमाणु बिजली घर की यूनिट 10 अक्टूबर, 2004 से बन्द पड़ी है। यह फर्स्ट यूनिट परमाणु बिजली यूनिट, जो केन्द्र सरकार की जिम्मेदारी है, अक्टूबर, 2004 से बन्द पड़ी है, इसी की थर्ड यूनिट 11 फरवरी से बन्द पड़ी है नाथपा-झांकड़ी हिमाचल प्रदेश की जो जिसमें हमारा हिस्सा है वह यूनिट एक हजार मेगावाट की यूनिट है पिछले कई महीनों से बन्द बड़ी है। नरोरा का परमाणु बिजली घर बन्द हुआ है और इसी प्रकार से और कई यूनिटें जिनका मेंटीनेंस करना भारत सरकार का दायित्व है सैंट्रल सैक्टर का दायित्व है वह समय-समय पर अचानक खराब होती गई और लम्बे समय तक ठीक नहीं हुई। उसके कारण नार्थ ग्रिड की फ्रीक्वेंसी कम पड़ गई और नार्थ ग्रिड की फ्रीक्वेंसी कम पड़ने के कारण हम बिजली को ओवरड्रा नहीं कर पाये और उसके कारण हम काश्तकारों को पूरी बिजली नहीं दे पाये। खपत बढ़ी है हमारी। 8 करोड़ यूनिट की जगह आज 9 करोड़ 80 लाख यूनिट प्रतिदिन की जो डिमाण्ड जो बनी है, खपत हमारी बढ़ी है वह हम पूरी कर सकते थे यदि यह नार्थ ग्रिड और सैंट्रल सैक्टर हमको ठीक-ठीक से सहयोग करता। पर सहयोग करवाना आपके बस में नहीं है, न आपकी भावना है, न आप सहयोग करवाना चाहते हैं।

आखिर में एक बात और निवेदन करना चाहूंगा, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दूसरी बात समस्या है राजस्थान में पीने के पानी की। पीने के पानी की बहुत बड़ी समस्या है। और इसलिए उस समस्या को पहचान कर हमारी सरकार ने आते ही पहला निर्णय किया सरफेस वाटर जितना अवेलेबल है उसमें प्रायोरिटी अब तक थी आपके राज में सिंचाई को प्राथमिकता हमारी सरकार ने कतई उस प्राथमिकता को बदलकर पहली प्राथमिकता इसलिए पेयजल को दी और उसका परिणाम यह आया कि अब इन्दिरा गांधी नहर से भी गांवों में पीने का पानी पहुंच रहा है। जोधपुर में पहुंचा, जोधपुर के आसपास के क्षेत्र में पहुंचने की तैयारी है। नागौर में पहूंचने की तैयारी है और कई जिलों में और इसी प्रकार से नर्मदा का पानी पूरे जालौर जिले और बाड़मेर

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

जिले को मिले वह योजना मन्जूर हुई है। और इधर जवाई का पानी पूरे पाली जिले के हर गांव को मिले वह भी पूरी तैयारी हो रही है। यह उस प्रायोरिटी को प्राथमिकता को बदलने के कारण हुई है और उसका कारण निश्चित रूप से हम सब को फायदा मिलेगा और नर्मदा में जो कुछ हो रहा है, 2006 में नर्मदा से नहर में पानी आपके माध्यम से जाएगा और उसके बाद पीने का पानी गांव गांव तक पहुंचेगा। इसमें मैं यहां निवेदन करना चाहूंगा जलदाय मंत्रीजी नहीं हैं, कोई बात नहीं है, पर वह सुन रहे होंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पेरेलल जो आपने व्यवस्था की है ऐसा सांचौर पहुंच गये हैं एक सरकलपुरा पहुंच गया, दो डिवीजन एक बाड़मेर और सांचौर में पहुंच गई हैं। वह लोग अपना सर्वे कर रहे हैं, डिटेल स्कीम बना रहे हैं। उसके साथ-साथ इस साल के बजट में इसमें प्रावधान भी हो जाए, लगभग 9 करोड़ रुपये कुल खर्चा आने वाला है। और मेरा निवेदन सरकार से कि ऐसी कुछ व्यवस्था कर दी जाए कि इधर नहर में पानी आए। और उधर पीने के लिए भी पानी लोगों को मिलना शुरू हो जाए। समानान्तर व्यवस्था दोनों चले, समानान्तर कार्यवाही दोनों की चले। बजट भी मिले, कार्यवाही भी हो, समय पर उनके टेण्डर हो जाए, समय पर वो काम शुरू हो जाए, यह सब करें तो हम 2007 की गर्मी तक यदि जालौर की जनता को और बाड़मेर की जनता को नर्बदा का पानी पीने के लिए दे सकें...

श्री उपाध्यक्ष : धन्यवाद। गर्ग साहब, धन्यवाद।

श्री जोगेश्वर गर्ग : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, और भी बहुत सारी बातें कहने को हैं लेकिन समय की सीमा है इसलिए मैं आखिर में मैंने दो दोहे लिखे हैं, मैं सदन की नजर करना चाहता हूं। जो हमारी सरकार की भावना है वह दो दोहों में मैंने समेटने की कोशिश की है। वह कह कर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा।

राजस्थान आगे बढ़े बस इतनी सी चाह
हमारी सरकार की और माननीय वसुन्धरा राजेजी की।
राजस्थान आगे बढ़े बस इतनी सी चाह
क्या-क्या हमने कर दिया, यह दस्तावेज गवाह।
प्रतिपक्षी कुछ भी कहे, हमको नहीं परवाह,
जनता तो बस यह कहे,

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

वाह वसुन्धरा वाह, वाह वसुन्धरा वाह।।

धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री उपाध्यक्ष : श्री विजय बंसल।

श्री विजय बंसल (भरतपुर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल के इस सदन में दिये गये अभिभाषण पर चर्चा में भाग लेता हुआ पुरजोर शब्दों में उसका समर्थन करता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सवा दो साल पहले जब कांग्रेस का शासन था, सदन की नेता ने परिवर्तन यात्रा के दौरान जिन समस्याओं को देखा, समझा और उनसे वायदे किये उन वायदों को लेकर के जब चुनाव में जनता के समक्ष आईं, जनता विश्वास कर सत्ता में लायी और जो वायदे पांच वर्ष के लिए किये गये थे, मैं धन्यवाद देता हूं सदन की नेता को, उनमें से 75 प्रतिशत से ज्यादा वायदे और समस्याओं का निराकरण इस दो साल में करके यह दिखा दिया कि हमारी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक साल पहले 10 साल से यह मांग उठती चली आ रही थी कि भरतपुर को एक सम्भाग बनाया जाए। माननीय वसुन्धरा जी ने एक भाषण में इसका जिक्र किया कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो निश्चित रूप से भरतपुर को सम्भाग बनायेंगे और भरतपुर को सम्भाग बनाकर के यह बता दिया कि उनकी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से जैसा कि अन्य वक्ताओं ने कहा कि कांग्रेस सरकार में खजाना खाली, खजाना खाली बार-बार कहा जाता था, दो वर्ष के शासन में कुशल मानीटरिंग और वित्तीय प्रबन्धन के द्वारा बगैर ओवर ड्राफ्ट किये, टैक्स रिकवरीज द्वारा इस सरकार को चलाकर, जनता के कामों को पूरा करना, यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरे भरतपुर को जो नया सम्भाग बनाया है इसके लिए सदन की नेता को मैं अपनी तरफ से और भरतपुर सम्भाग की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी प्रदेश के विकास के लिए शिक्षा का एक बहुत बड़ा महत्व है। आज हिन्दुस्तान में केरल में सर्वाधिक साक्षर लोग हैं। इसी को देखते हुए राजस्थान में भी शिक्षा के क्षेत्र में जो दो साल में उपलब्धि हुई है, जितने नये स्कूल खोले गये हैं, जितने उन स्कूलों में कुशल

(श्री विजय बंसल)

टीचर भर्ती किये गये हैं, जितने स्कूल क्रमोन्नत किये गये हैं, निश्चित रूप से आगामी वर्षों में राजस्थान साक्षरता के क्षेत्र में आगे बढ़कर के विकास की गति प्राप्त करेगा। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय घनश्यामजी तिवाड़ी को जिन्होंने मेरे विधान सभा क्षेत्र में, जैसा कि उन्होंने सदन में कहा था कि दो सैकण्डरी स्कूल और एक सीनियर सैकण्डरी स्कूल क्रमोन्नत किया जाएगा लेकिन मेरे क्षेत्र में चार मिडल से माध्यमिक और दो सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोलने पर उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर का डवलप होना परम आवश्यक है। कोई भी क्षेत्र औद्योगिक विकास और सड़कों का विकास जब तक नहीं हो तब तक वह क्षेत्र प्रगति के पथ पर आगे नहीं बढ़ सकता है। सवा दो साल के शासन में जयपुर से लेकर उदयपुर तक सिक्स लेन रोड और हाल ही में आगरा से जयपुर तक फोर लेन रोड का कार्य चालू हुआ है। इसके अलावा विभिन्न ग्रामों को प्रधान मंत्री सड़क रोजगार योजना के द्वारा 500 की आबादी के गांवों को सड़कों से जोड़ दिया गया है। सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी इसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान खनिज के मामले में हिन्दुस्तान में बहुत आगे है लेकिन पिछले 50 वर्षों से उन खनिजों का अवैध खनन होता चला आ रहा था। आप देख सकते हैं, रेवेन्यु के मामले में, मेरे विधान सभा क्षेत्र में अनेक खनिज की खानें हैं और मात्र 50 हजार रुपये सालाना उनसे रेवेन्यु वसूल हो पाती थी। पिछले वर्ष खनिज मंत्रीजी ने जब दौरा किया था, इनका ध्यान इस ओर आकृष्ट किया गया, आज इन्होंने अवैध खनन पर अंकुश लगाकर इस कदर का माहौल कर दिया कि उनसे वसूल होने वाली राशि 50 हजार रुपये से बढ़कर 15 लाख रुपये हो गई है। निश्चित रूप से इस महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में जो कहा है उसमें एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में एक विरोधाभास जरूर है। फोरेस्ट विभाग और खनिज विभाग, इनमें आपस में प्रतिस्पर्धा चलती है, एक-दूसरे की जमीन पर ये लोग अनधिकृत कब्जा करते हैं। मैं यह कहना चाहूंगा कि इनकी अलग तरह से सीमा निर्धारित कर दी जाए तो राजस्थान खनिज उत्पादन में निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा, फोरेस्ट वालों का उस पर कोई प्रभाव नहीं रह पायेगा।

(श्री विजय बंसल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान शुरू से ही पेयजल और सिंचाई के पानी के लिए पिछड़ा रहा है लेकिन पिछले समय में पेयजल के लिए अनेक योजनाएं बनाकर और उनकी क्रियान्विति हुई है। लेकिन तत्कालीन व्यवस्था के लिए निश्चित रूप से इतने डीप बोर लगाकर जन सुविधा के लिए पानी जो उपलब्ध कराया गया है इसके लिए वास्तव में माननीय पीएचईडी मिनिस्टर साहब धन्यवाद के पात्र हैं। मेरे भरतपुर विधान सभा क्षेत्र में जो कृषि भूमि थी, जहां पानी की पाइप लाइन नहीं डल सकती थी, पिछले दिनों ही सरकार ने 2 करोड़ 46 लाख रुपये की एक लाइन डलवाकर भरतपुर की जनता के साथ जो भला किया है इसके लिए मैं पीएचईडी मिनिस्टर साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि स्वायत्त शासन विभाग द्वारा चाहे वह घरौंदा योजना हो या कृषि भूमि का नियमन हो, जो काम दो साल में हुए हैं या जिन्होंने सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे किये हुए थे उनको हटाकर गरीब तबके को नियमन करके जमीन उपलब्ध कराई है यह बहुत बड़ा काम था। इसके लिए स्वायत्त शासन मंत्री महोदय, बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। साथ-साथ मैं इसमें यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि एक कंट्रोवर्सी इस डिपार्टमेंट में भी चल रही है कि जहां नगर पालिका और नगर परिषद हैं और यू.आई.टी. हैं, दोनों में अलग-अलग होड़ रहती है। मेरा सुझाव है कि नगर परिषद की भूमि में यू.आई.टी. का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए क्योंकि यू.आई.टी. का मतलब है जमीन एक्वायर कर अपनी कालोनी बनाकर, प्लाट काटकर विकसित होने पर नगर परिषद को हैण्ड-ओवर करे। माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी का मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इसके साथ-साथ कल जैसे गृह कर पर एक बहस चल रही थी, यह आमजन से जुड़ा हुआ मुद्दा है। मेरा एक सुझाव है, क्योंकि मैं नगर परिषद का सभापति रह चुका हूं, कि 182 नगरपालिकाओं, नगर परिषदों और नगर निगमों से आप यह जानकारी करायें कि हाउस टैक्स की वसूली के लिए लगे हुए अधिकारी और कर्मचारियों की तनख्वाह और गृह कर की वसूली में कौन ज्यादा है ? मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि उन अधिकारियों और कर्मचारियों की तनख्वाह ज्यादा है। जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने अभी दो दिन पहले कहा था कि हमारा पांच साल का कार्यक्रम है, मैं विश्वास करता हूं कि उनकी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है। यह हाउस टैक्स निश्चित रूप से समाप्त किया जाना चाहिए और समाप्त होगा।

(श्री विजय बंसल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केवलादेव नेशनल उद्यान के लिए पानी की व्यवस्था के लिए पिछले वर्ष भी यहां हंगामा हुआ था क्योंकि विश्व हैरिटेज के नाम से जाने वाला यह उद्यान पानी की कमी से जूझ रहा था। मैंने जब विधान सभा में यह बात उठाई थी तो माननीय मुख्य मंत्री महोदया ने पूरे कार्यक्रम को अपने हाथ में लेकर 100 करोड़ रुपये की योजना बनाकर केन्द्र सरकार को भेजी है। और मैं कांग्रेस के माननीय महानुभावों से कहना चाहूंगा कि विश्व हैरिटेज को बचाने के लिए आपकी सरकार केन्द्र में है, कम से कम इसकी क्रियान्विति करके इस सार्थक भरतपुर के केवलादेव नेशनल उद्यान को बचाने का प्रयत्न करें।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल नगर से आने वाले माननीय विधायक ने एक शेर पढ़ा था ''अंजाम-ए-गुलिस्तां क्या होगा, हर शाख पे उल्लू बैठा है''। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, 1975 में इमरजेंसी के बाद जब 1977 में चुनाव हो रहे थे, इमरजेंसी से पीड़ित विभिन्न दलों ने जनता पार्टी के नाम से सब मिलकर उस कुशासन से मुक्ति पाने के लिए चुनाव लड़ रहे थे। तब कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा पोस्टर बनाकर हिन्दुस्तान के शहरों में छपवाया था और उसमें एक पेड़ की विभिन्न शाखाओं पर जनता पार्टी के विभिन्न नेताओं को दर्शाकर उन्होंने एक शेर लिखा था ''अंजाम-ए-गुलिस्तां क्या होगा, हर डाल पर उल्लू बैठा है''। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमने भरतपुर में उसकी एवज में एक दूसरा पोस्टर लगाकर वैसा पोस्टर और एक पेड़ और उस डाल पर कांग्रेस के एक पदाधिकारी का फोटो लगाकर जिन्होंने इस इमरजेंसी को किया था, नीचे लिखा था, ''बरबाद-ए-गुलिस्तां करने को एक ही उल्लू काफी है''।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि 1999-2003 तक एक ही व्यक्ति ने पांच साल के अन्दर इस प्रदेश का विकास के नाम पर विनाश करके छोड़ दिया...(व्यवधान) माननीय उपाध्यक्ष महोदय, समय बहुत कम है, इसलिए मैं एक बार पुनः इस महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी जुबान को विराम देता हूं। आपने समय दिया, धन्यवाद।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी देना चाहता हूं कि रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने एक तार के माध्यम से एक विषय उठाया था कि इनकी पत्नी का तार आया है कि उनको एनकाउंटर में मार देंगे। मैंने पूरी जानकारी की है। दीनदयाल गोरेगाछी को तीन और चार

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

की रात को इसे गिरफ्तार किया है एक मुकदमे में 36/06 में। इसके पहले भी इस पर 12 मुकदमे हैं जिसमें से मर्डर के केस भी हैं, 307 के भी हैं और यह 2000 रुपये इनामी डाकू के रूप में इसकी पहले से ही सूचना दे रखी है कि जो भी पकड़ेगा उसे पुरस्कार मिलेगा। यही नहीं, जिस रात को हमने पकड़ा, यह लगभग नौ डकैतों का ग्रुप एक साथ था, उसमें से निहाल पर 25000 रुपये की इनामी घोषणा थी, राजकुमार पर 2000 रुपये की थी और गुड्डू गाछी पर 50000 रुपये का इनाम था। इनमें से केवल एक भारत जरूर अरेस्ट हुआ इसके साथ, बाकी सारे भाग गये तो मैं सोचता हूं कि एनकाउंटर करने का कोई सवाल नहीं। इस प्रकार समाजद्रोही लोग हैं जो लगातार समाज पर इस प्रकार का हमला करते हैं, उनको पकड़ने और अगर वह भागने की कोशिश करेंगे तो आवश्यकता पड़ेगी तो एनकाउंटर भी करेंगे, ऐसे लोगों को बख्शा नहीं जायेगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरिमोहन शर्मा।

श्री जुबेर खान : हम सन्तुष्ट हैं, हमारा तो धर्म था आपकी जानकारी में लाना। जो दोषी है, जो अपराधी है, आप सज़ा दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, वह सुरक्षित हो गये। उन्हीं की सुरक्षा की चिन्ता थी।

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : सम्माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर श्री नाथूसिंहजी गुर्जर द्वारा प्रस्तावित धन्यवाद प्रस्ताव पर विचार विमर्श के लिए मेरी पार्टी की ओर से बोल रहा हूं। जो वर्तमान स्थिति है इस सरकार की और इस राजस्थान की जनता की, जो विशेषता है उनकी मैं तारीफ करूंगा और जो कमजोरियां हैं उनका उल्लेख करूंगा। यह सही है कि राजस्थान की वर्तमान मुख्य मंत्री ने अखिल भारतीय स्तर पर हुए उनके अन्तर्विरोधों के बाद राजस्थान के उनके ही दल के विधायकों द्वारा अनेक प्रश्नचिन्ह लगाने के बाद भी निर्भीकता से, राजनैतिक दृष्टिकोण से उनको शिकस्त देकर उनको जिस ढंग से पानी पिलाया है, उसके लिए राजस्थान की मुख्य मंत्री बधाई की पात्र हैं। राजस्थान की मुख्य मंत्री ने उनके दल के लोगों को जिस ढंग से पानी पिलाया है, उसके लिए ही नहीं, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने महामहिम राज्यपाल महोदय को 179 पैरे और 52 पेजों का एक विशाल दस्तावेज सम्बोधन के रूप में देकर

(श्री हरिमोहन शर्मा)

महामहिम तक को भी तीन-चार बार पानी पीने के लिए बाध्य कर दिया, इसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्रीजी बधाई की पात्र हैं।

मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कुछ ऐसी परियोजनाएं हैं, कुछ ऐसे विचार हम सब राजनैतिक दलों को चाहे उस पक्ष में बैठने वाले हों चाहे इस पक्ष में बैठने वाले हों, राजनीति से अलग हटकर विचार करके कुछ ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिससे आगे आने वाले समय में इस राजस्थान को सभी दृष्टिकोण से हम नई दिशा दे सकें। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, चाहे शासन किसी का भी रहा हो और चाहे आज वर्तमान में माननीय मुख्य मंत्रीजी वसुन्धराजी का शासन हो, लेकिन जिस प्रकार से इस लोकतंत्र में यह राजशाही, यह सरकारी तंत्र, यह सरकारी अधिकारी हावी हैं, अनेक मंत्रियों को कानों में यह कहते सुना है कि अधिकारी उनकी बात नहीं मानते। चाहे राज किसी का भी हो, चाहे हमारे समय में भी यह धारणा बनी थी। आज सरकारी तंत्र निरंकुश है, निरंकुश था और आज भी मजबूती से मैं कह सकता हूं कि वह निरंकुश है और मंत्रियों और जन प्रतिनिधियों की बातों को कोई विशेष तवोज्जह नहीं देते हैं। आज वह बैठे हैं, कल हम बैठेंगे, हमको अलग हटकर इस वर्तमान शासनतंत्र में इन अधिकारियों के कार्यकलापों पर एक साथ बैठकर विचार करना चाहिए कि किस प्रकार से लोकतंत्र में चुने हुए जन प्रतिनिधियों को और लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को उनकी इच्छा, उनके निर्देशों को नियमित ढंग से नियमों के अन्तर्गत उनकी भावनाओं को अभिव्यक्त करके कारगर ढंग से उनकी बात को माने। इस बात के लिए आज विचार करने का अवसर है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अच्छा होता यह पहल पिछली बार अगर हमने नहीं की तो आपकी तरफ से आती और इस पहल पर विचार करते और आगे आने वाले समय के लिए हम कोई रास्ता निकालते। अनेक समस्याएं हैं चाहे वह पेयजल की हो, चाहे इन्टरस्टेट वाटर डिस्पुट की हो, चाहे अन्य कोई उद्योग की योजना की हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे कोई बड़े-बड़े मामले हो। अगर हम साथ बैठकर विचार करेंगे तो सेज जैसे महत्वपूर्ण जो विवादित मसला बन गया, अगर ट्रांसपेरेसी होती तो वह विवादित मसला नहीं बनता। मैं इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी को कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपना मंत्रिमण्डल बनाया तो यह सोचा, उनके मंत्रिमण्डल के गठन से मुझे ऐसा लगा कि वह चाहे उनके लिए यह प्रचार किया जाये कि वह शाही तरीके से शासन कर रही

(श्री हरिमोहन शर्मा)

हैं लेकिन मंत्रिमण्डल बनाते समय जो गरीबों से सम्बन्धित, जो अनुसूचित जाति से सम्बन्धित, जो विकलांगों से संबंधित, जो गरीब तबके को सहायता देने वाला विभाग था, वह एक गरीब तबके के व्यक्ति को, दिलावर साहब को उसका मंत्री बनाया। और हमने यह सोचा था कि मूल भावना मुख्य मंत्री की ठीक है लेकिन आज हम देखें कि क्या माननीय दिलावर साहब, माननीय समाज कल्याण मंत्री, क्या यह सरकार, क्या माननीय मुख्य मंत्रीजी, उनकी भावनाओं के अनुरूप गरीबों को लाभ पहुंचाने में कामयाब रहे या नहीं रहे। मुझे अफसोस है इस बात का कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट भाषण में यह घोषणा की थी कि वह विकलांग व्यक्तियों के लिए, विधवा महिलाओं के लिए दस किलोग्राम गेहूं प्रतिमाह उन लोगों को देंगी। और उन्होंने घोषणा की थी यह गत सत्र के बजट में, मुझे अफसोस है इस बात का कि राज्य सरकार ने उन विकलांगों को, उन विधवाओं को, इस मिनट तक भी, जो दो करोड़ रुपये का प्रावधान किया था, उसमें से एक पैसा भी खर्च नहीं किया, इससे ज्यादा शर्म की बात क्या हो सकती है। मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनको चाहिए था बजट का प्रोवीजन, इन्होंने किया था दो करोड़, उन्होंने संख्या बताई है आज की तारीख में, यह इनके द्वारा दी गई संख्या है। और उस संख्या के लिए तीस हजार क्विंटल हर महीने में उनको देने के लिए इनको चाहिए, उसकी कीमत होती है डेढ़ करोड़ रुपये। अगर इनकी नीयत साल भर तक उन विकलांगों को दस किलो गेहूं देने की होती तो 18 करोड़ का बजट प्रोवीजन होता, तब जाकर के यह उनको लाभ पहुंचा सकते थे। किया दो करोड़। माननीय मंत्रीजी, और उन दो करोड़ में से भी इस माह तक एक पैसा भी आपने उसमें खर्च नहीं किया। इनको यह भी पता नहीं है, एक इनका सरकारी दस्तावेज बताता है कि उनकी संख्या क्या है, तो दूसरा सरकारी जो दस्तावेज है वह अलग कहानी कहता है। वह यह कहता है, एक दस्तावेज बता रहा है इनका कि विभिन्न जिलों में 2 लाख 66 हजार 966 विधवा और विकलांग हैं और एक दूसरा जो स्टेटमेंट है इन्हीं का, वह विभिन्न जिलों में 2 लाख 99 हजार 400 बताता है। यह विधवा और विकलांगों की संख्या, इनके द्वारा दिया गया यह जवाब, जिसमें गर्व से कहते हैं कि हां, हमने दो करोड़ में से एक पैसा भी खर्च नहीं किया।

श्री मदन दिलावर : माननीय सदस्य, यह संख्या रोज बढ़ती है, आपको पता है कि नहीं। रोज पेंशन स्वीकृत होती है, रोज बढ़ती है संख्या।

श्री हरिमोहन शर्मा : मुझे आपकी बात से इत्तफाक है कि विधवाओं की संख्या भी रोज बढ़ती है लेकिन यह दोनों दस्तावेज एक ही तारीख को आपने मुझे दिये हैं। जब एक दस्तावेज में संख्या बढ़ गई तो उसके साथ यह कम संख्या वाला मुझको काहे को दे दिया आपने। तारीख एक ही है, दस्तखत एक ही है, आप ही का है, आप ही पढ़ लेते प्रश्न का जवाब देने से पहले, आपके पास से गुजरा होगा। आप कष्ट कर लेते तो मैं यह बात नहीं बोलता। इस प्रकार यह सही जवाब देने की स्थिति में नहीं हैं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, हमें उम्मीद थी इस बात की, हमें इस बात की उम्मीद थी कि इनके मंत्री बनने के बाद जिन विधवाओं की लड़कियों की शादी में जो इनको पैसा देना था, इसीलिए उनको सहायता दी जाती है कि वह अत्यन्त गरीब, निर्धन, असहाय हैं, वह तरस रही हैं दिलावर साहब, आपकी तरफ भीख का कटोरा लेकर के खड़ी हुई हैं हर जिले में कि हमने जिन बालिकाओं की शादी की है...

श्री मदन दिलावर : उनका अधिकार है। भीख नहीं है। उनका अधिकार है यह।

श्री हरिमोहन शर्मा : वह अधिकार है और अधिकार होते हुए भी वह याचना करती हुई आप जैसे विद्वान, न्यायिक और बहुत गरीबों के हिमायती मंत्री से कह रही हैं कि हमने उस टाइम हमारी पुत्री का विवाह किया था, आप हमारा पैसा दे दो। दे दिया आपने? दे दिया क्या आपने? आपने विकलांगों को नहीं दिया, आपने विधवाओं को नहीं दिया, आपने सामाजिक सहायता जो महत्वपूर्ण चीज है, उसका पैसा नहीं दिया। सड़क पर खड़े हैं। जिनका पति मर गया, गरीब है, पैसा मांगने जाती हैं...

श्री जोगेश्वर गर्ग : आपने तो यह योजना ही बन्द कर दी थी।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप विराज जाइये।

श्री मदन दिलावर : मैं आपको जानकारी दे दूं माननीय सदस्य... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : आपसे जानकारी मुझे मिल गई है।

श्री मदन दिलावर : माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 5 हजार को 10 हजार किया था विधवाओं की पुत्रियों की शादी के लिए और लगभग आज हम सब को दे चुके हैं यानि पैसा जारी हो गया कल की तारीख में, सब को।

श्री हरिमोहन शर्मा : कल की तारीख में हुआ होगा। आप परसों की तारीख में और कर दो।

श्री मदन दिलावर : सब को जारी हो गया है। मेरी बात तो सुन लें।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं आज की तारीख तक की बात कर रहा हूं।

श्री मदन दिलावर : सब को जारी हो गया पैसा और पहले पचास लाख का प्रावधान था, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने उसको दो करोड़ बढ़ा करके किया है। यह आपकी जानकारी के लिए बता रहा हूं।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह : आपके कार्यकाल में तो सब बन्द पड़ा था। कुछ था ही नहीं।

श्री मदन दिलावर : जहां कांग्रेस के राज में पचास लाख था वहां भारतीय जनता पार्टी के राज में दो करोड़ रुपये है।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह : यह पालन योजना, नई पेंशन पालिसी सब अभी लागू हुई हैं। यह पालन योजना अभी लागू हुई है, आपके टाइम में क्या था। नई पेंशन अभी लागू हुई है, आपके टाइम में थी ही नहीं।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय मुख्य मंत्रीजी विराज रही हैं, जवाब देंगी न। आप क्यों चिन्ता कर रहे हो। आपके मंत्रिमण्डल में आने का हो तो आप भले ही बोलो, मैं बैठ जाता हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपके बैठने से आ जायेंगे।

श्री हरिमोहन शर्मा : माननीय मंत्रीजी, माननीय दिलावर साहब, अच्छा होता...

श्री महावीर प्रसाद जैन : आसन को सम्बोधित करें आप।

श्री हरिमोहन शर्मा : अच्छा होता माननीय समाज कल्याण मंत्रीजी, अच्छा होता आप अपनी दिलावरी इन गरीबों की सहायता के लिए करते। अच्छा होता उन विधवाओं की मदद करने में करते। आपने दिलावरी किसमें दिखाई ? संविधान का उल्लंघन करके, जो शपथ ली है आपने, उस शपथ का उल्लंघन 26 जनवरी को करके आपने दिलावरी दिखाई। आपने विधान सभा में विपक्ष में बैठ करके अपने कपड़े फाड़ने में दिलावरी दिखाई। आपने अपनी आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने में अपनी दिलावरी दिखाई। आपने जिस प्रकार की व्यवस्था की है उससे गरीब का कोई लेना-देना नहीं है। माननीय मुख्य मंत्रीजी, जिन उम्मीदों के साथ आपने यह विभाग इनको सम्भलाया था, मैं विनम्र शब्दों में आपसे अनुरोध करता हूं और प्रार्थना करता हूं कि आप अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें, गरीब तड़पता मर जायेगा, इनको लड़ने से फुर्सत नहीं। यह अल्पसंख्यक गरीब लोगों के खिलाफ एक ऐसे

(श्री हरिमोहन शर्मा)

द्वेष का वातावरण बनाकर पूरी इस जगह का ऐसा वातावरण करते हैं कि जिसके कारण माननीय गृह मंत्री को कोटा जाकर अपनी ही पार्टी के लोगों से याचना, प्रार्थना, निवेदन करना पड़ता है कि भाइयों, यह तो वैसे ही भड़काते हैं, मेरे कहने से ही मानो, आन्दोलन मत करना। इसलिए (व्यवधान) मैं, माननीय, निवेदन करना चाहता हूं, इन सारी परिस्थितियों में यह निश्चित रूप से जो मैसेज जा रहा है, भले ही आप अपने मन में ठीक मानें, चाहे जालौर से आने वाले विधायक बहुत तारीफ करते हैं, तारीफ करनी चाहिए, मैं भी अगर उस जगह होता और मेरी सरकार होती तो वही करता जो आपने किया है, इसमें कोई विवाद की बात नहीं है लेकिन मैं इधर बैठा हूं तो जो मेरा फर्ज, जो मेरा कर्तव्य है वह मुझे करना चाहिए और मैं मेरे कर्तव्य का निर्वहन कर रहा हूं। माननीय गृह मंत्रीजी ने आंकड़े दिये विधान सभा में महामहिम राज्यपाल के उसमें, जहां तक माननीय गृह मंत्रीजी का सवाल है, विभाग में तो भ्रष्टाचार है, इससे इन्कार नहीं किया जा सकता, करप्शन है। जो आपने कहा था कि सड़क पर वेश्यावृत्ति नहीं होने दूंगा, मेन रोड नेशनल हाईवे पर सब काम चल रहा है। आपने फरमाया था कि सट्टा जिस थाने में चलेगा, उसके तत्काल सब के बोरिया-बिस्तर बांध दूंगा। यह राष्ट्रीय समस्या है, सट्टा आप बन्द नहीं कर पाये। मेरा आपसे विनम्र अनुरोध है कि आपकी शराफत में मुझे कोई शक नहीं है लेकिन मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप हमारे पूरे राजस्थान की पुलिस के, गृह विभाग के सेनापति हैं। और सेनापति अगर किसी के कहने में विवेक खो दे तो क्या नतीजा हो सकता है ? मेहरबानी करके आप हमारे सेनापति हैं, गृह मंत्रालय आपके पास है, हो सकता है कि डी.जी. तो कोई विवेक खो दे, एस.पी. विवेक खो दे, लेकिन गृह मंत्रीजी उत्तेजना में अगर विवेक खो दें तो क्या स्थिति राजस्थान की बनेगी। तो मेरा आपसे विनम्र अनुरोध और प्रार्थना है कि आप विवेक किसी भी परिस्थिति में नहीं खोयें, नहीं तो अगर किसी राष्ट्रपति ने विवेक खो दिया और उस एटामिक पावर प्रोजेक्ट की उसने अगर चाबी किसी को दे दी तो जो बंटाढार होने वाला है, वह उस आपके विवेक खोते समय हो सकता है। आपसे प्रार्थना है, या तो माननीय मुख्य मंत्रीजी इनको ऐसा कोई विभाग दें जिसमें कोई ऐसी दिक्कत या परेशानी की बात नहीं हो, बढ़िया से बढ़िया, या माननीय गृह मंत्रीजी विवेक का परिचय दें और उत्तेजना में अपनी बात को मजबूती से कहें लेकिन विवेक नहीं खोयें। विवेक खोने की जो धारणाएं बनती चली जा रही हैं, वह चिन्ता का

(श्री हरिमोहन शर्मा)

विषय है। माननीय गृह मंत्रीजी ने यह लिखा है, पैरा नम्बर 72, जिसमें आपने कहा है कि इतने प्रतिशत अपराध कम हो गये, गरीबों का यह हो गया, अनुसूचित जाति का यह हो गया, इतनी-इतनी बात हो गई, आप यह तो जानते हैं कि जब से अपन ने थानों में यह समितियां बनवाई हैं, काग्नीजेबल आफेंस जो हैं, उसको अपन दर्ज ही नहीं करते। रिपोर्ट ही दर्ज नहीं होती, फौरन समिति को बुलाते हैं, आपस में समझौता करो। तो जो अपराध, जिसमें राजीनामा नहीं हो सकता है जो काग्नीजेबल है नोट कंपाउंडेबल हैं लेकिन हम

(समय : 16.00 बजे)

उन समितियों के माध्यम से उनको दर्ज ही नहीं करते। एक तो आपका अपराध कम होने का कारण यह दर्ज है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं और एक आपने बहुत ऐतिहासिक काम किया है वो ऐतिहासिक काम जो आप करने जा रहे हैं आप कृपा करके उस ऐतिहासिक काम को जो इस राजस्थान की वर्तमान सरकार पर आगे जाकर कलंक साबित होगा वैसा कलंक जैसा आपने 1977 में इमरजेंसी के दौरान मीसा के माध्यम से जिसमें आप लोग गिरफ्तार किये गये थे और जिस प्रकार की यातनाएं और जिस प्रकार का मानस आपका बना था। आप इस राजस्थान की जनता को कलंकित कर एक ऐसा कानून लाने जा रहे हैं जिस कानून में आप किसी भी आदमी को एक साल तक बन्द कर सकते हैं अदालत में जाने का दरवाजा बन्द कर सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को अधिकार देना चाहते हैं कि आप उनको 12 दिन तक पकड़ करके रख दें। आप यह अधिकार देना चाहते हैं। और इसमें कौन हैं, इसमें जो आपकी परिभाषा है परिभाषा लैण्ड ग्रेबर्स की देख लें परिभाषा आप एक्साइज एक्ट वाली देख लो जो परिभाषाएं हैं वो परिभाषाएं आप देखें उन परिभाषाओं को आपने पढ़ा नहीं। यह केवल ये जो एक्ट है जो एंटी सोशल एक्टिविटी एक्ट है ये आपने 18 धाराएं संख्या में तो आपने नकल की हैं नेशनल सिक्योरिटी एक्ट की और जोड़ी है इसमें कोई दूसरी बात। चीजें सारी अक्षर-अक्षर उसकी उतारी हैं। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट है वो तो फारेनर्स के लिए नेशन के लिए है ...(व्यवधान) आप विराजिये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये तो आपकी बिना मंजूरी के थोड़े होगा बिल पास। ये तो आगे उस समय कर लेना। आप बहुत विद्वान हैं इसलिए मैं कह रहा हूं।

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं इसलिए चेतावनी दे रहा हूं कि आपकी अगर यह हिम्मत होती अपराधों की कमी के साथ-साथ आप बहादुरी के साथ-साथ आप इसको भी राज्यपाल के अभिभाषण में कहते कि हम ऐसे लोगों के लिए ऐसा कानून बनायेंगे जिसमें हम... आप फरमायेंगी ? आप कुछ बोल तो रही हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : मुझ से बातचीत कर रही हैं।

श्री हरिमोहन शर्मा : अच्छा तो आप बातचीत करने की बजाय मेरी बात को सुन लें। ये एक्ट ऐसा है जिसमें साल भर तक आप उसको बन्द कर दो कोई कानूनी बात नहीं। आप ऐसा कमीशन बना दें जिस बात को माननीय कटारिया साहब सन् 1977 में आपका नेतृत्व वर्ग पूरे देश में करता रहा है वो काम आप करने जा रहे है। आप उन लोगों को कानून देखिये हो सकता है कि आपके जो जगन्नाथजी वर्मा हैं मान लो वो कोई काम करते हैं शराब का आपने उसमें कानून लगा दिया एक्साइज एक्ट का। जो भी काम करेगा उसमें जो कंट्रावेंशन करेगा उसको हम उठा करके इसमें धर देंगे। अगर कोई किसी को फाइनेंशियल एड देगा, आपने पढ़ा उसको ? आपने यह कह दिया कि अगर एक्साइज के काम करने वाले ठेकेदार को अगर कोई फाइनेंशियली मदद करेगा और आपको पता लग गया तो इधर उधर का कानून एक्साइज एक्ट धरा रहेगा आप उठा करके उस जगन्नाथजी वर्मा को या दूसरे साहब को जिसको आपको साफ करना हो उसको या हमको जिनको भी आपको साफ करना हो उनको आप ले जायेंगे। आपने जो लैंड ग्रेबर्स का जो उसमें बनाया है, आप देखिये सरकारी जमीन पर जो कब्जा कर लेगा आप उसको उठा करके धर देंगे। सरकारी जमीन पर कब्जा कितने किसानों ने कर रखा है ? 91 की कार्यवाहियां पेण्डिंग हैं, सारा का सारा आपने एन्क्रोचमेंट को उसको इस में लेकर के और जो आपने किया है, इसमें क्या होगा ? मान लो प्रहलादजी गुंजल के भाई पर बिरलाजी आरोप लगाते हैं कि साहब अतिक्रमण कर लिया। प्रहलाद जी गुंजल को उलझाने के लिए इस में बहुत अच्छा रास्ता ढूंढ रहे हैं। यह जो भी चीज है यह लोकतंत्र पर कलंक है। इस सरकार यह कानून कलंक रहेगा। अच्छा होता माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में आप इस प्रकार की स्पष्टवादिता करते कि हम साल भर तक लोकतंत्र का गला घोंट करके जेल के सीख़चों की बजाय हमारे यहां रख देंगे। आप कानून में प्रावधान कर सकते थे यह जो आपका कदम है आपको मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप बार एसोसियेशन को भेजिये, सारे वकील संगठनों को भेजिये। मैंने देकर देखा हर वकील यह कहता है, वकील नहीं जाएगा वहां उसकी पैरवी करने के

(श्री हरिमोहन शर्मा)

लिए जिसको आप पकड़ेंगे, कि नो वकील, गेट आउट। यह कोई बात हुई ? ये लोकतंत्र का हिस्सा है। इस प्रकार का काला कानून बनाने को अगर आप अपनी उपलब्धियां मानें तो मुझे इस मामले में कुछ नहीं कहना है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस काले कानून का आप डटकर विरोध करेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी सारे राजनीतिक परिप्रेक्ष्य को देखते हुए सारी स्थितियों को देखते हुए आप जितने भी इससे संबंधित आदमी हैं आप उसको देखें तो सही। नहीं तो वैसी भूल नहीं हो जाए जैसी अपन ने ज्युडिशियल कस्टडी के नाम पर की थी। हमारी बात को आपने नहीं माना और माननीय राष्ट्रपतिजी के यहां से वो रिजेक्ट होकर आया और फिर अपन शर्मसार हुए और अपन को वो करना पड़ा। इन सब बातों को आपको देखना है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्रीजी विराजमान हैं माननीय मुख्य मंत्रीजी इस राजस्थान का जो परिदृष्य है वो उन भावनाओं के अनुसार है। जहां नैतिक मूल्य ट्रांसपेरेंसी एक ऐसी चीज जो इतिहास में पूर्व के मुख्य मंत्रियों ने दी है, इन सब लोगों ने जो भावना दी है, वो ट्रासपेरेंसी आज की तारीख में वर्तमान सरकार के कार्यकलापों में कुछ देखने को नहीं मिल रही है। आपके सामने मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वो ट्रांसपेरेंसी नाम की चीज नहीं है। आप भले ही महसूस नहीं करें लेकिन जनमानस में ट्रांसपेरेंसी के मामले में इस सरकार की ओर से जो कदम उठाये जा रहे हैं उन पर पूर्ण शंका है और उनको ईमानदारी पर पूरा शक होता जा रहा है। शायद कुछ लोग जो आपके इर्दगिर्द रहते हों वो असलियत को आपको नहीं पहुंचाना चाहते हैं। अपन सेज की बात करें। सेज की बात में आप ऊपर से लेकर नीचे तक देख लें। हमने विरोध किया। सेज का विरोध नहीं है सेज का काम आपका ठीक है। सेज होना चाहिए विकास होना चाहिए राजस्थान का। इस मामले में मतभेद नहीं हैं। लेकिन ट्रांसपेरेंसी के अभाव में जो इसका परिदृष्य नजर आता है वो पूरा ही ऐसा है कि जिसके कारण अगर आपको ट्रांसपेरेंसी लानी थी तो क्यों कर लिया आपने चुपचाप महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा से ? आपको निकालना चाहिए था कि हमारी ये शर्तें हैं राजस्थान की। इस प्रकार का सेज का निर्माण करना चाहते हैं। कौन-कौन से इंडस्ट्रियलिस्ट हैं जो हमारी मदद करना चाहते हैं, कौन-कौनसी भागीदारी करना चाहते हैं। चुपचाप महिन्दा एण्ड महिन्द्रा से बैठ करके बिना पूर्व में कैबिनेट की मीटिंग बुलाये आपने पूर्व में एम.ओ.यू. साइन किया। फिर दबाव पड़ा। आपके मंत्रिमण्डल के सदस्यों ने कुछ आपत्ति उठायी।

(श्री हरिमोहन शर्मा)

आपत्ति उठाने के बाद आपका फिर जो भी केन्द्रीय नेतृत्व है आपके जो भी यहां प्रदेशाध्यक्ष हैं इन्होंने एक वातावरण बनाया ट्रांसपेरेंसी को एक डाउट में लिया। पूरे देश में चर्चा हुई। कलराज मिश्र जैसे जो आपके प्रभारी हैं उन्होंने सबको बुला कर चर्चा करने के बाद और ट्रांसपेरेंसी के बाद आपने उसको कैबिनेट में रखा। अच्छा होता आप पहले उसको कैबिनेट में रख देती। और कैबिनेट में रखा वो भी एक ठीक से जनता में मैसेज नहीं गया। मैसेज इसलिए नहीं गया कि उद्योग मंत्री होने चाहिए थे। आपके कैबिनेट मैमो पर उद्योग मंत्री के दस्तख्त होने चाहिए थे। आपने जे.डी.ए. वालों से ही काम चला लिया। अगर जे.डी.ए. का ही विभाग आप मानते हैं और जे.डी.ए. के हिसाब से ही वो सब काम चल रहा है तो मुझे कुछ नहीं कहना है। तो फिर आपने एम.ओ.यू. जो साइन किया उस पर जे.डी.ए. वाले सेकेट्री के दस्तख्त करा दिये फिर रीको वाले के क्यों कराये ? ये जो चीजें हैं कि मंत्रीजी का नहीं होना, यह सही है कि नरपतसिंहजी के पिताजी का देहावसान हो गया था। यह भी सही है कि घनश्यामजी तिवाड़ी बाहर गये हुए थे। लेकिन यह भी सही है कि जब विवाद और राजनीतिक विश्लेषण और जो राजनीतिक विवाद पैदा हुए उस समय इन दोनों का ही नहीं, यहां के लोकसभा सदस्यों सहित जयपुर के विधायकों तक की भी यही राय थी। अच्छा होता उस ट्रांसपेरेंसी को बनाये रखने के लिए आप इतनी जल्दी में इतनी हड़बड़ी में पांच मंत्रियों के सामने उस बात को नहीं रखतीं, आ जाने देती घनश्यामजी को भी और राजवीजी को भी। तो जो परिदृष्य ट्रांसपेरेंसी के मामले में आया वो एक ऐसा है, इसी प्रकार आप रिडकोर में देख लें 5 करोड़ में आप 15 करोड़ का काम करने जा रहे हैं। कोई मोदी साहब उसके सी.एम.डी. बन गये। कौन से मोदी हैं ? आपकी जो टर्म्स एण्ड कण्डीशन थीं पब्लिकली उसको पब्लिसाइज करते कि हम यह कम्पनी बनाने जा रहे हैं हमारी यह बात है हमारे ये शर्तें हैं। आपने चुपचाप ही पी.डब्ल्यू.डी. मिनिस्टर साहब ने करके और पांच करोड़ में उनको 15 करोड़ का काम दे दिया...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं आपको करेक्ट कर दूं आपके पास जानकारी तो है नहीं 25 करोड़ की इक्विटी है और रिडकोर में 50 प्रतिशत राजस्थान सरकार का है और इसके अन्दर जो ...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : मैं यह नहीं पूछ रहा हूं, मुझको इस बात का

(श्री हरिमोहन शर्मा)

जवाब दें कि आपने पब्लिकली टेण्डर क्यों नहीं इन्वाइट किये ? आपने एक ही कम्पनी को बैठकर कैसे दे दिया कोई घर की दुकान है? घर की दुकान थोड़े है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसी तर्ज पर आपकी भारत सरकार ने एम.ओ.यू. की है। भारत सरकार ने एम.ओ.यू. की है इसी तर्ज पर।

श्री हरिमोहन शर्मा : आप पब्लिकली करते। इन्वाइट करते। आप पब्लिकली करते और पब्लिक में जाकर के कहते कि हमारी ये शर्तें हैं, हम ये विकास का काम करना चाहते हैं। हम यह बात करना चाहते हैं आपने जिस प्रकार महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा को चुपचाप सब काम कर दिया सेज का वैसा का वैसा रिडकोर के माध्यम से, कोई मोदी साहब हैं, न जाने किन के नजदीकी हैं, उन मोदी साहब के भाई भतीजों को सीएमडी भी आपने नियुक्त दिया, यह तरीके हैं। मुख्य मंत्रीजी मैं जानता हूं कि हमारी यह बातें आपको अच्छी लगने वाली नहीं हैं। लेकिन मैं ईमानदारी से कहता हूं कि इन गम्भीर बातों पर आपके दल के जो लोग हैं वह बाहर जाकर खुलेआम हमसे सहमति अभिव्यक्त करते हैं कि हां ट्रांसपेरेंसी नहीं है। ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिये, हां टेण्डर होने चाहिये। इन सब महत्वपूर्ण बातों पर आप गौर करें इससे राजस्थान का हित होगा। आपका हित होगा और आपके दल का हित होगा। इसलिए मेरा विनम्र अनुरोध है और आखिर में जो वर्तमान में परिस्थितियां बन रही हैं, आपको शेर-शायरी और कविता का बहुत शोक है और जो 8 तारीख को आपके जन्म दिन पर आप जो बजट पेश करने जा रही हैं उसमें कुछ न कुछ हमको पहले की तरह सुनने को मिलेगा। लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं जो स्थिति है उस पर :-

''जब तक ढपली हाथ में तुम्हारे, जैसे चाहो खूब बजालो।
कुछ सपना बाकी मत रखना, मन के सब अरमान निकालो।
सावधान होकर यह सुनलो, कल इनका भी आयेगा।
जनता का बदला है तेवर, तुमको सबक सिखायेगा।''

श्री उपाध्यक्ष : श्री धर्मपाल चौधरी।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय ने इस सदन में अपने अभिभाषण के माध्यम से राजस्थान सरकार ने जो अपने दो साल में कार्य किये उनके बारे में राजस्थान की जनता को संदेश दिया। यह अभिभाषण राजस्थान की सरकार ने इस सवा

(श्री धर्मपाल चौधरी)

दो साल में राजस्थान की जनता से जो वादे किये थे उनको पूरा करने के लिये जो-जो हमने कार्य किये उनकी इस अभिभाषण में चर्चा है। सवा दो साल पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी जब हमारी पार्टी की प्रदेशाध्यक्ष थीं पूरे राजस्थान में इस तपती हुई लू में गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में जाकर पूरे राजस्थान का दौरा किया। राजस्थान के उस गांव में रहने वाली जनता की समस्याओं के बारे में जानकारी ली और उसी का परिणाम है जो कांग्रेस 156 सीट पर थी वह 56 पर रह गई और हमारी पार्टी पहली बार पूर्ण बहुमत में आई। इससे पहले तीन बार हमारी सरकार रही लेकिन एक बार जनता पार्टी के रूप में, दूसरी बार जनता दल और भारतीय जनता पार्टी के रूप में और तीसरी बार निर्दलीयों के सहारे हमारी सरकार चली। पहली बार पूर्ण बहुमत में आई और इस पूर्ण बहुमत के पीछे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो परिवर्तन यात्रा की वह कारण रहा। मुख्य मंत्रीजी के पद पर बैठने के बाद जो हमने घोषणा पत्र बनाया था आज जिस घोषणा पत्र को लेकर यहां पर आप चर्चा करते हो उस घोषणा पत्र का 75 प्रतिशत काम हमारी सरकार ने इन दो सालों में पूरा कर दिया। हमारे अभी पोने तीन साल बचे हैं सवा दो साल गुजरे हैं। और इन बचे समय में चाहे गृह कर का मामला हो क्योंकि सरकार का घोषणा पत्र पांच साल का है और उस पांच साल में जो बाकी कार्य हमें करने हैं समय आने पर गृह कर भी समाप्त कर दिया जायेगा। आप लोगों ने भी घोषणा पत्र बनाया था। कितनी घोषणाओं को पूरा किया था। आप लोगों के राज में आने से पहले आपके जितने सीनियर पदाधिकारी थे, नेता थे महामहिम भैरोंसिंहजी शेखावत के राज में पांच पैसे बिजली का दाम बढ़ा था और आप लोगों ने सचिवालय की दीवार फांद दी थी कि राजस्थान के किसान के साथ अन्याय हो गया। राजस्थान का किसान बरबाद हो गया। क्या किया आपने राज में आते ही ? आज बात करते हो गांव के किसान की, आपने बिजली का दुगना दाम कर दिया। दाम बढ़ाया जो बढ़ाया लेकिन उस किसान को 8 घंटे बिजली देने की बात की, आपने दी पांच सालों में। बिजली नहीं देने का उस किसान ने जो आपको करंट लगाया जिस पोजिशन में आप 156 में इधर बैठे थे अब 56 में उधर बैठे हैं। कोई सरकार जब बनती है, अशोक गहलोतजी जब मुख्य मंत्री बने एक ही अलाप खजाना खाली है। कैसे राज को चलाना है, आज जिस तरह से हम अपने घर को चलाते हैं उसमें घर का मुखिया कहां से पैसा लायेगा यह उसकी जिम्मेदारी है। राजकीय पद पर मुख्य मंत्री बैठे हैं, मुख्य मंत्री का काम है कि पैसे की

(श्री धर्मपाल चौधरी)

व्यवस्था कैसे हो, उसको कैसे खर्च किया जायेगा। अशोक गहलोतजी का तो एक ही अलाप, खजाना खाली है। पांच साल निकल गये राज चला गया लेकिन उनका खजाना कभी भरा नहीं। हमारे मुख्य मंत्री ने बैठते ही 100 दिन, 200 दिन, एक साल, दो साल और पांच साल की कार्य योजना बनाई। इस राजस्थान की जिस जनता को हमने विश्वास दिया था चुनाव के समय उसका कार्य किया। इसलिए 100 दिन की योजना को मजाक में लिया, 200 दिन की योजना बनाई तो मजाक में लिया, कहा कि क्या हो जायेगा 100 दिन में। 100 दिन 200 दिन और एक साल और दो साल इसके पीछे विचार था, एक विचारधारा थी कि हम इन-इन योजनाओं को, आज अगर हम किसी चीज के बारे में सोचेंगे ही नहीं तो वह कैसे पूरी होगी।

मुख्य मंत्रीजी का अच्छा वित्तीय प्रबन्धन और दूसरा भगवान में भी आस्था रखती हैं। जब हम देवी-देवताओं की पूजा करते हैं तो वैसे भी समृद्धि होती है। इसी का कारण रहा कि राजस्थान में कुशल वित्तीय प्रबन्धन के कारण से हमने 2003-04 में जहां कांग्रेस के राज में 7 प्रतिशत और 10 प्रतिशत वृद्धि हुई थी, हमारे राज में 15.86 और 16.13 प्रतिशत की राजकीय कोष में वृद्धि हुई। इसका कारण है कुशल प्रबन्धन। समय पर ध्यान रखने की बात है। पंजाब के कैरो मुख्य मंत्रीजी होते थे। उनको कहते थे कि साहब सरकार कैसी चल रही है तो वह इस बात का जवाब देते थे कि साढी सरकार दी गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट वह होती है जो मिनट-मिनट में गौर करती है। वसुन्धराजी की सरकार नहीं है, गवर्नमेंट चल रही है और मुख्य मंत्रीजी मिनट मिनट में हर क्षेत्र पर गौर करती हैं। चाहे राजस्थान में किसान की बात हो, शहर में रहने वाले व्यक्ति की बात हो, हर क्षेत्र में मुख्य मंत्रीजी ने काम किया है और जिसकी वजह से हमारा कुशल प्रबन्धन रहा। चाहे बजटीय घाटे की बात हो उसमें भी कमी आई है। आज राजस्थान में पहली बार मुख्य मंत्रीजी ने नारा दिया हरित, शिक्षित और विकसित राजस्थान। अशोक गहलोतजी ने नारा दिया था पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, एक मास्टर मत लगाओ। पूरे पांच साल में एक मास्टर लगाया नहीं। लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने हरित, शिक्षित और विकसित राजस्थान का सपना देखा। उसमें गांव के खेत में हरियाली होगी और हमारा समाज शिक्षित होगा तो अपने आप राजस्थान की तरक्की होगी। इसके लिये शिक्षा में हर गांव में प्रत्येक एक किलो मीटर में पढ़ने वाले बच्चों के लिये स्कूल हो इसके लिये चाहे जितने भी स्कूल खोलने

(श्री धर्मपाल चौधरी)

पड़े हमारी सरकार ने खोले और उन स्कूलों में 6473 राजीव गांधी पाठशालाओं को हमने क्रमोन्नत किया। 4162 नये स्कूल खोले। 5170 प्राथमिक विद्यालयों को उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया। लगभग 900 प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया। 500 माध्यमिक विद्यालयों को उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत किया। इस तरह इन दो सालों में संख्या है 15 हजार। यही नहीं इसके साथ आपकी सरकार ने पूरे पांच साल में एक मास्टर की भर्ती नहीं की। सिर्फ राजीव गांधी पाठाशालाओं में 1200 रुपये के नाम के पैराटीचर्स लगाये।

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो पुरानी बात हो गई आप तो आज की बात करो।

श्री धर्मपाल चौधरी : पुरानी बात नहीं हुई, आज की ही बात कर रहे हैं। पहले वालो को भी पीटना पड़ता है रोज वहां से आप जो बोलते हो, पहले आपकी बात भी बतानी पड़ेगी। आज आप जिस भ्रष्टाचार की बात कर रहे हो अभी आपकी ही पार्टी के एक केन्द्रीय मंत्री को मंत्रिमण्डल से इस्तीफा देना पड़ा था, भ्रष्टाचार की बात करते हो। (व्यवधान) बडे दुर्भाग्य की बात है इतने सीनियर विधायक हमारे पूजनीय प्रतिपक्ष के नेता बैठे-बैठे बोल रहे हैं तो बाकी का क्या होगा।

श्री उपाध्यक्ष : यह पुरानी बातों का आप से ही सीख रहे हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : अभी भ्रष्टाचार के मामले की बात हो रही थी। भ्रष्टाचार में अभी ताजा ही उदाहरण है, आपके एक केन्द्रीय मंत्री जो राजस्थान के थे उनको इस्तीफा देना पड़ा। इस बात पर भ्रष्टाचार के मामले में, भ्रष्टाचार तो कांग्रेस के राज में...(व्यवधान)

श्री अमराराम धोद : आपके एम.पी. कितने संसद से निकाले वह भी बता दो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसा है, धोद से आने वाले माननीय सदस्य...

श्री संयम लोढ़ा : ऐसा है कि ऊपर तो गोलवोलेकर की फोटो, दीनदयाल उपाध्यायजी की फोटो और नीचे नोट गिने जा रहे थे बैठ-बैठ के। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसा है सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य...

डा. जालम सिंह रावलोत : आप किसी व्यक्ति विशेष पर इस तरह नहीं कह सकते। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : वो ही फोटो लगाकर लूटते हैं।

श्री संयम लोढ़ा : शर्मनाक तो यह है कि जब पार्लियामेंट में कार्यवाही हो रही थी तब आपकी पार्टी ने वहां वाकआउट किया, इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : कोई वाकआउट नहीं किया, हम न पक्षधर हैं और न लूटते हैं ऐसी फोटो लगा लगाकर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री धर्मपाल चौधरी : लूट और खसौट का तो जहां तक सवाल है देश में आजादी के बाद में आपकी सरकार रही उसके कितने घोटाले हैं उनके बारे में तो आप अच्छी तरह जानते हो, यह तो गरीब लोग थे जिन लोगों ने थोड़े-थोड़े पैसों में, आज करोड़ों रुपये से, मंत्री पद से तो हटा दिया उनको हटाओ ना सदस्यता से, नटवर सिंहजी को आज मंत्रिमण्डल पद से हटा दिया और कितने करोड़ रुपये के घोटाले का उनके ऊपर चार्ज लगा...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप काहे को, विषयान्तर्गत मत जाइये। आप अभिभाषण पर आ जाइये।

श्री संयम लोढ़ा : वाल्कर कमेटी की रिपोर्ट असत्य साबित हो गई और नटवर सिंहजी निर्दोष साबित होंगे, यह ध्यान रखना।

श्री हरिमोहन शर्मा : नटवर सिंहजी सदन के सदस्य नहीं हैं, नटवर सिंहजी का नाम नहीं लिया जाना, नटवर सिंहजी सदस्य नहीं हैं सदन के।

श्री नवरतन राजोरिया (फुलेरा) : सोनिया गांधी ने अपने रिश्तेदार को बचाने के लिये सारी कार्यवाही कराई, सीबीआई इसको (व्यवधान) प्रभावित किया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री हरिमोहन शर्मा : उनका अहसानमंद हमेशा ही रहना चाहिये।

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसा है कि अहसानमंद किसका रहना चाहिये किसका नहीं, राजस्थान की जनता के अहसानमंद हैं जिन्होंने यहां पर भेजा है, जिन्होंने हमारी सरकार बनाई है, आपके अहसानमंद नहीं हैं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : आप चिंतित मत होइये सांसद जो

(श्री भंवरलाल शर्मा)

बीजेपी के बर्खास्त हुये, नटवर सिंहजी का मामला है, मैं तो इतना कहना चाहता हूं कि 'कबीरा तेरी झौंपड़ी गलगटिया के पास कृषि सो बोवसी तू क्यों भयो उदास'।

श्री धर्मपाल चौधरी : सरदारशहर से आने वाले माननीय सदस्य, आप तो इधर उधर जाते रहते हो और जाते रहे हो। और माल मलाई भी मिली क्यों अपन चक्कर में पड़ें, आप तो छोड़ो इन बातों को। आप तो कृपा करो, आप तो कृपा करके माफ करें। (व्यवधान) जहां तक भ्रष्टाचार के बारे में बात हो रही थी कि सेज के मामले में सिरोही से आने वाले सदस्य बोल रहे थे, माननीय उधर से यह नूराकुश्ती है उधर से दो-तीन जने ही बोलते हैं। सेज के मामले में बोले, किसी मामले में बोले सरकार पर और सीधा मुख्य मंत्रीजी पर आरोप लगाते हैं, आरोप लगाने से पहले सोचना चाहिये।

श्री संयम लोढ़ा : इस पर मुख्य मंत्री पर कोई आरोप नहीं लगाया है, आप लगा रहे हो आरोप यह कहकर के।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप बैठ जाइये।

श्री संयम लोढ़ा : मुख्य मंत्री पर सेज पर कोई आरोप नहीं लगाया है, मैंने यह कहा है आप रिकार्ड उठाकर चैक कर लीजिए। मुख्य मंत्री की चमचागिरी करने के लिए फालतू का मुख्य मंत्रीजी को मत लपेटो इसके अन्दर, ऐसे मंत्री नहीं बनोगें आप। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसा है कि बात को कहकर, अभी ताजा कहीं थी, हरिमोहनजी हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य बोले थे.... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : मैंने यह कहा है कि जेडीए ने डिसिजन कर लिया, जेडीए ने प्रस्ताव भेज दिया और उसके बाद सरकार का मंत्री हाईकोर्ट में एफेडेविट देता है यह बात मैंने कही है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : सरकार के मंत्री ने कोई हाईकोर्ट में एफेडेविट नहीं दिया।

श्री संयम लोढ़ा : जेडीए चेयनमैन के रूप में आपका एफेडेविट गया है उसमें, क्या बात कर रहे हैं आप। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : जेडीए का फंक्शन मात्र इतना ही था कि रीको को जमीन अलाट करके दे (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : जेडीए ने फैसला कर लिया उसके बाद भी हाईकोर्ट को गुमराह करने का काम किया आपने। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आप बिराजिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा : मैं बिराज जाऊंगा पर मेहरबानी करके आप इस तरह से मुख्य मंत्रीजी का नाम मत लीजिए कि सेज में मुख्य मंत्री पर घोटाले का आरोप लगाया है। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : अभी माननीय हरिमोहनजी, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य, उन्होंने लिया, आपने कहा और कितने लोगों ने इस बात को उठाकर कि सेज के मामले में जो बात उठाई है, सेज के मामले में पहले हमारे जो मंत्री वह वहां पर गये थे तमिलनाडू, वहां पर जाकर उन्होंने दस्तखत किये थे जब...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : मेरा भाषण रिकार्ड पर है मुख्य मंत्रीजी पर कोई भ्रष्टाचार का आरोप मैंने नहीं लगाया। मैंने ट्रांसपेरेंसी की बात की उस पर अब भी कायम हूं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : यह तो ठीक है मुख्य मंत्रीजी पर आरोप नहीं लगाया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य कनक्लूड कीजिए।

श्री रामनारायण चौधरी : उनको समझाइये कि गलत तथ्यों के ऊपर क्यों बहस बढ़ा रहे हैं।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप तो छोड़िये, आपको तो मिड वे बहरोड मंजूर है, मिडवे के पीछे रहते हो, आप काहे को चक्कर में पड़ो।

श्री महीपाल यादव : आप इस भ्रष्टाचार के पचड़े में क्यों फंस रहे हो, क्यों पोल निकलवा रहे हो सारी।

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसा है आप तो पोल छोड़ो आप तो मिडवे में.... (व्यवधान)

श्री महीपाल यादव : यह सेज में जेडीए से नक्शे पास कराने में क्या घपले हुए ? पूछ लो।

श्री धर्मपाल चौधरी : कांग्रेस के राज में जब हम उस प्रतिपक्ष में बैठते थे और आप सत्तापक्ष में बैठते थे आपके समय हमने लालकोठी क्षेत्र में,

(श्री धर्मपाल चौधरी)

जमीन में, हमारी माननीया सदस्य जो हमारी सीनियर लीडर थी कमला बेनीवालजी, उनके खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में स्ट्रक्चर पास हुआ। पृथ्वीराजनगर योजना का क्या किया आपने अपने राज में ? आनंद नर्सरी, प्रताप नर्सरी का क्या किया आपके राज में ? महरचंद एण्ड कम्पनी क्या थी आपके राज में ?

डा. सी.पी. जोशी : यह सब हमारे राज में हुये, ढाई साल आप क्या कर रहे थे ?

श्री धर्मपाल चौधरी : अब कर रहे हैं ना।

डा. सी.पी. जोशी : कमिशन क्यों नहीं किया (व्यवधान) ढाई साल में, हमारे समय में काम हुये सब जो बिलकुल गलत थे आपके कथनानुसार तो ढाई साल में कार्यवाही क्यों नहीं की आपने ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसा है बिराजो अभी करवा देंगे। (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : बिलकुल, क्या तकलीफ है।

श्री संयम लोढ़ा : हमारे राज में (व्यवधान) कोई भी घोटाले हुए, सब पर कार्यवाही करो आप।

डा. सी.पी. जोशी : यह निकाल दो दिमाग में. I am for this, very categorically Simultaneously you have to recollect these things. यह सरकार जो काम कर रही है उन सरकार के कार्यक्रमों के संबंध में भी चिन्ता कर ले। यह सेज का मामला है यह मामला नहीं है, ट्रान्सपेरेंट है कि नहीं। सेज के मामले में दस हजार एकड़ जमीन ली फिर तीन हजार कर ली हमने, दस हजार से सात हजार कम क्यों किये हमने ? जिन चीजों के बारे में न जानकारी, सेज आप कर रहे हैं अच्छा काम कर रहे हैं। We are for this. मैं इसलिए कहना चाहता हूं माननीय सदस्य (व्यवधान) यह इतनी देर से है, जो सदन में नहीं है, उन पर आरोप भी लगाए और जो सदन में है उन पर आरोप भी लगाये, दोहरा मापदण्ड नहीं हो सकता। बिलकुल रिकार्ड पर आना चाहिये। पिछली सरकार ने गलत काम किया कंवीक्शन होना चाहिये कोई तकलीफ नहीं है।

श्री धर्मपाल चौधरी : कर रहे हैं ना, आप बिराजो।

डा. सी.पी. जोशी : लेकिन वन साइडेड काम नहीं हो सकता। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : ऐसा है कि आप बिराजे।

डा. सी.पी. जोशी : ऐसा है, मैं खड़े होकर जिम्मेदारी से कह रहा हूं। केबीनेट क्या होती है केबीनेट के निर्णय क्या होते हैं केबीनेट के निर्णय कैसे होते हैं यह मुख्य मंत्रीजी को मालूम है। केबीनेट क्या निर्णय कर सकती है क्या नहीं कर सकती, यदि नियम और कानून का फाल्ट हुआ तो सज़ा मिलनी चाहिये कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन यह कहकर कि....(व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी पर आरोप लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री पर आरोप नहीं लगा रहे हैं। मुख्य मंत्रीजी की फंक्शनिंग पर क्वेश्चन करने वाले आपकी ही केबीनेट के लोग हैं। हमने आरोप नहीं लगाया कभी भी। सेज में क्या हो रहा है हमें तो मालूम नहीं था, केबीनेट में क्या हो रहा है हमें मालूम नहीं था।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप छोड़िये ना।

डा. सी.पी. जोशी : छोड़ो नहीं, मैं यह इसलिये कहना चाहता हूं जब भी कोई आता है कि ढाई साल में आपने ऐसा किया इसलिए (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, किस चीज पर बहस हो रही है ?

डा. सी.पी. जोशी : सज़ा दो, फांसी दो (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : घोटाले आपके राज में हुये हैं, जांच करा लें....

डा. सी.पी. जोशी : फांसी लगा दो, आपका राज है। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : घोटाला आपके राज में हुआ है। आपने पैरवी की है घोटालों की...(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : कार्यवाही करो ना।

एक माननीय सदस्य : जनता ने लगा दी आपको फांसी।

डा. सी.पी. जोशी : कार्यवाही करो ना क्या तकलीफ है, आपको अधिकार है। हम मुख्य मंत्रीजी के पास भीख मांगने आये, केस विदड्रा करने के लिए...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : काहे पर बहस हो रही है, कौनसे नियमों में बोल रहे हैं ? (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : आप बोले तो नियम बने हैं, हमारे सदस्य बोले

(डा. सी. पी. जोशी)

तो नहीं बोल सकते, महावीरजी खड़े हो गए (व्यवधान) रूल कोट किया आपने, आपने रूल कोट किये थे संयमजी कह रहे थे (व्यवधान) आपने रूल कोट किया। कमलाजी का नाम लिया, कमलाजी मैम्बर है हाउस की ?

श्री संयम लोढ़ा : पूरे राजस्थान की जनता जानती है 90 बी में करने के (व्यवधान) वहां किसके पास पहुंचाया जा रहा है पूरे राजस्थान की जनता जानती है।

डा. सी.पी. जोशी : आपका अधिकार है, आप दूसरी पार्टी को (व्यवधान) यह क्या तरीका है ?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

(समय : 16.29 बजे)

(श्रीमती सुमित्रा सिंह, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री शंकर सिंह राजपुरोहित : इतने गुनाह इकट्ठे हो गये हैं (व्यवधान) आप सुन नहीं पाओगे, हम यह कह रहे हैं आप सुन नहीं पाओगे। किस-किस बात की पैरवी करेंगे आप।

डा. सी.पी. जोशी : यदि हमने भ्रष्टाचार किया है तो सरकार को पूरा अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आसन पांवों पर है। आसन पांवों पर है। कौन बोल रहे थे ?

श्री धर्मपाल चौधरी : मैं बोल रहा था।

श्री अध्यक्ष : कृपया जारी करें।

श्री धर्मपाल चौधरी : आप भ्रष्टाचार की बात पर जब नाम लेते हैं और जो कार्यवाही की आप बात कर रहे हैं ना....

श्री महादेव सिंह खण्डेला : आप किसान हैं, किसान की बात करें। सेज से आपको क्या मतलब है, क्या मतलब है सेज से आपका ।

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं रोकें, खण्डेला से आने वाले माननीय सदस्य। (व्यवधान)।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : नहीं बताते हैं तो आपको एतराज है.. (व्यवधान) पूरे भ्रष्टाचार से डूबे हुए थे।

श्री अध्यक्ष : खण्डेला से आने वाले माननीय सदस्य, बीच में नहीं रोकें।

श्री धर्मपाल चौधरी : सेज से पहले, जब कांग्रेस का राज था तो जमीन का भाव यहां पर क्या था और किसान की जो जमीन थी, 15 प्रतिशत से जो पैसा लेते थे, 15 प्रतिशत जमीन देते थे और मुआवजा कितना देते थे ? अब जो हमने मुआवजा दिया था, कूकस में दिया, और यह मुख्य मंत्रीजी की सोच किसान के प्रति थी तभी तो 25 प्रतिशत दिया। आज 20 प्रतिशत आवासी जमीन मिलेगी, प्रतिशत कामर्शियल जमीन मिलेगी। यदि यह मुख्य मंत्रीजी की सोच नहीं होती किसान के प्रति तो क्यों करतीं ? आज जमीनों का 40-50 लाख रुपये भाव हो गया तो कहां से हो गया ? यह बाहर से लोग अगर पैसा लगाने नहीं आते, यहां पर बिल्डर नहीं आते, यहां पर अंसल और दूसरी कालोनियां बसाने के लिये लोग नहीं आते तो यह जमीन का भाव किसान का नहीं होता। आप तो किसान-विरोधी हो कि किसान को जो समृद्धि मिल रही है, अब यहां का किसान जब जयपुर का पैसा मिलता है तो वह दूसरी जगह जाकर बसता है तो वहां की जमीन का भाव बढ़ गया। आज हमारे अलवर जिले में हरियाणा में रेट बढ़ने की वजह से दाम बढ़ गये। अब जयपुर में मिलने के बाद आगे दाम बढ़ गये। तो किसान विरोधी नहीं, किसान की मदद में ही हमारी मुख्य मंत्रीजी हैं। जो भी पैसा आज किसान को, जितना पैसा मुआवजे के रूप में और जमीन के रूप में मिलेगा, आपके राज में कभी नहीं मिला। किसान की हितैषी हमारी सरकार है।

भ्रष्टाचार के इन मामलों को छोड़कर आज अगर निवेश की जहां तक बात है, आपने जयपुर में बहुत बड़ा फंक्शन किया था, मुख्य मंत्रीजी ने। और वहां भी, विदेश में भी गये थे। कितने लोग आये थे ? लेकिन आज हमारी मुख्य मंत्रीजी की पोजिटिव सोच के कारण से कितना निवेश हो रहा है। तकलीफ आपको यह हो रही है कि राजस्थान में विकास हो रहा है। राजस्थान के लोगों को काम मिलेगा। आपको किसी से कोई मतलब नहीं है। यह बीच में नूरा-कुश्ती है ना कुछ लोग बोलकर कि आपके दो मंत्री बोल पड़े, मंत्रिमण्डल में क्या होता है, मंत्रिमण्डल की बातें गुप्त होती हैं। मंत्रिमण्डल में क्या होना चाहिए, सबकी साझा जिम्मेदारी है। आप भी मंत्री रहे हो। मंत्रिमण्डल में जो चीज आयेगी तो एक जने के कहने से रुक जाएगी क्या ? बाकी की सरकार के कोई फैसले होते हैं, कोई भी अन्दर की बात होती है, उसको बाहर करते हैं, आपके दो मंत्रियों ने कह दिया, हमारे एक मंत्रीजी तो पहले खुद ही कह गये थे (व्यवधान) उनके पिताजी का देहावसान होने की वजह से नहीं आये। आज उन बातों को कहिये। आप राजस्थान की जनता का विकास नहीं चाहते, आप

(श्री धर्मपाल चौधरी)

अनर्गल बातें करके असत्य आरोप लगाकर सदन का समय खराब करना चाहते हो। आप किसान विरोधी हो, आपकी इस रीति-नीति व सोच के कारण ही आप वहां पर बैठे हो। इसलिये माननीय अध्यक्ष महोदय, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण यहां पर पढ़ा, राजस्थान की जनता के विकास का पत्र पढ़ा मैं उसका समर्थन करता हूं, जयहिन्द।

श्री जुबेर खान : मुख्य मंत्रीजी, एक बात तो मानिये कि धर्मपालजी अब मंत्री बनने के लायक हो गये हैं। केबिनेट के बारे में सारी जानकारी हो गयी है, इनको मंत्री बना दीजिएगा।

श्री अध्यक्ष : श्री बी.डी. कल्ला। श्री बी.डी. कल्ला।

श्री महावीर प्रसाद जैन : श्री रामलाल शर्मा का नम्बर है।

श्री अध्यक्ष : अब मैंने नाम पुकार लिया उनका, उनको बोल लेने दीजिए। फिर रामलालजी बोल लेंगे।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ये तो आखिरी वक्ता होंगे?

श्री श्रवण कुमार : अध्यक्ष महोदय, मेरा नम्बर है इनके पहले तो। आपने कैसे पुकार लिया पहले ही। मेरा नाम नहीं है इसके अन्दर ?

श्री अध्यक्ष : जितना समय बचा है, वह एक घण्टा लेंगे।

श्री श्रवण कुमार : नहीं, एक घण्टा लेंगे तो हम नहीं लेंगे एक घण्टा। हम अमरीका से आये हैं क्या।

श्री जुबेर खान : 5 मिनट पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य को।

श्री अध्यक्ष : आप अपने नेता से बात करिये। मुझसे बात करने का आपका कोई अधिकार नहीं है।

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा नाम नहीं है क्या इसके अन्दर ? मेरा नाम तो है ना ? मेरा नाम नहीं है क्या इसके अन्दर ?

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, 5 मिनट दीजिएगा, चाहे बी.डी. कल्लाजी के यहां से कम कर दीजिएगा 5 मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, हमारा समय पड़ा है। समय हमारा पड़ा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने नाम पुकार लिया, मैंने पुकार लिया।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, 5 मिनट मैं कम बोल लूंगा, इनको 5 मिनट दे दीजिए।

श्री अध्यक्ष : नहीं मैंने नाम पुकार लिया, बी.डी. कल्ला।

श्री श्रवण कुमार : माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे पीड़ा है कि किसान के बारे में कोई नहीं बोला, अभी तक और सारे केवल सेज के बारे में बोलते हैं। मुझे इस बात की पीड़ा है। मुझे किसान के बारे में बोलना है।

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

(व्यवस्था-सूचक-घण्टी)

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : x x x

श्री अध्यक्ष : क्या कहा था ? (व्यवधान) अब आपके दो मिनट बचे हैं। अब जो टाइम है, 7 मिनट कल थे, और आज जो समय का विभाजन हुआ है उसमें लोक जन शक्ति पार्टी के दो मिनट हैं और दो मिनट के बजाय 10 मिनट पहले ही आप बोल चुके हैं। माननीय बी.डी. कल्ला।

श्री श्रवण कुमार : x x x

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : x x x

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं किया जाए। (व्यवधान) आसन की तरफ से जिनका नाम पुकारा गया है केवल वे ही बोलेंगे और उन्हीं का अंकित होगा।

श्री सुरेश मीणा : x x x

श्री अध्यक्ष : करौली से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया स्थान ग्रहण कर लें । आप स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) तो बोलने का मौका देंगे ना, बैठें तो सही। आप बैठें। माननीय बी.डी. कल्ला।

श्री श्रवण कुमार : x x x

श्री अध्यक्ष : आपको नहीं बोलना है, जो आसन कहेगा, उन्हें ही बोलना है। आसन जिनका नाम पुकारेगा, उसे बोलना है। कांग्रेस पार्टी का समय खतम हो चुका है और एक घण्टा भी नहीं बचा है इसलिये मैंने बी.डी. कल्ला का नाम पुकार लिया है।

श्री श्रवण कुमार : x x x

श्री अध्यक्ष : अब आप रहने दें, स्थान ग्रहण करें, आप स्थान ग्रहण करें।

श्री रणवीर सिंह गुढ़ा : x x x

श्री अध्यक्ष : मैंने बी.डी. कल्ला का नाम पुकार लिया है। आसन जिनका नाम पुकारता है वे ही अपना भाषण प्रारम्भ करते हैं। चूंकि कांग्रेस

(श्री अध्यक्ष)

पार्टी का समय समाप्त होने जा रहा है, मैंने नाम पुकार लिया, मैं इसमें अमेंडमेंट नहीं करुंगी।

श्री श्रवण कुमार : x x x

(श्री श्रवण कुमार, सदस्य द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, सदन का समय जाया नहीं करें। मैं आपसे अनुरोध कर रही हूं, आप अपना स्थान ग्रहण करें। आप कृपया स्थान ग्रहण करें। बहिर्गमन करना है, बहिर्गमन कर दीजिए, आपकी मर्जी।

श्री ओम बिरला : x x x

श्री रणवीर सिंह गुढा : x x x

श्री अध्यक्ष : श्री बी.डी.कल्ला। माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें। गुढा से आने वाले माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण करें। मैंने बी.डी. कल्ला का नाम पुकार लिया है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मेरा नाम पुकार लिया, मैं बोल लूंगा, लेकिन 5 मिनट का समय मेरे में से इनको दे देते आप।

श्री ओम बिरला : x x x

श्री अध्यक्ष : ये आपके बाद में बोल लेंगे।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अच्छा, मेरे बाद में बोल लेंगे, ठीक है।

श्री अध्यक्ष : यदि आसन को इस तरह से सभी माननीय सदस्य डिक्टेट करने लग जाएंगे और यह कहने लग जाएंगे कि मैं तो बोलूंगा ही तो फिर आसन कैसे अपना दायित्व निभा सकता है। इसलिये मैंने नाम आपका पुकार लिया, अब आप बोलें, प्रारम्भ करें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : माननीय अध्यक्ष महोदय, टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा है और जिसका समर्थन जौहरी बाजार से आने वाले माननीय सदस्य ने किया, उसका मैं पुरजोर विरोध करता हूं। उस विरोध के पीछे कारण, सबसे पहले तो इस अभिभाषण में लिखा है, सौ दिवसीय योजनाएं, 365 दिवसीय योजनाएं, यह सारी की सारी योजनाएं फैल्योर रही हैं। इनके जो लक्ष्य थे वे पूरे प्राप्त नहीं हो सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो घोषणाएं और जो वायदे राजस्थान के लोगों से वर्तमान सरकार ने किये हैं, उन

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

वायदों में यह खुद ही कह रहे हैं कि यह अब तक पूरे नहीं किये। कुछ परियोजनाएं ऐसी होती हैं जिन योजनाओं को राज्य सरकार 5 सालों में पूरा करती है। लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से यह जानना चाहता हूं कि कर्जा माफ करने का, 10 हजार तक के कर्जे माफ करने का वादा सवा दो साल से पूरा क्यों नहीं किया। हाउस टैक्स माफ करने का वादा, यह कोई 5 साल में खर्च करने की बात नहीं है। मान लो यह हजार स्कूल खोलने की बात करते और यह कहते कि हम 5 साल में हजार स्कूल धीरे-धीरे खोलेंगे तो बात समझ में आती। लेकिन हाउस टैक्स माफ कर देंगे, हम 10 हजार का कर्जा माफ कर देंगे, प्रतिवर्ष 50 हजार मकान बनाएंगे।

लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि सवा दो साल में क्या आपने 1 लाख भी मकान बनाये ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि आपने कहा था कि 1 लाख लोगों को हम प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। आज रोजगार की स्थिति यह है कि संगठित और पब्लिक सेक्टर में जब कांग्रेस की सरकार थी इस प्रदेश में 12 लाख 2 हजार लोगों को रोजगार मिलता था और सन 2004-05 की रिपोर्ट्स आपकी यह बताती है कि इनकी संख्या घटकर 11 लाख 75 हजार हो गयी। तो रोजगार तो घट रहा है। युवा लोग आशान्वित हैं कि आप प्रतिवर्ष 1 लाख लोगों को रोजगार देंगे लेकिन रोजगार निरन्तर घटता हुआ चला जा रहा है। डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। ऐसी परिस्थिति में रोजगार के अवसर, अभी मेरे से पूर्व हमारे इधर से, तारानगर से आने वाले मेरे माननीय साथी ठीक कह रहे थे कि अभी आपने हंड्रेड परसेंट कट कर रखा है इण्डस्ट्रियल सेक्टर में। इससे अपने 50 हजार व्यक्ति बेरोजगार हो जाएंगे। आप रोजगार देने की जगह बेरोजगारी बढ़ा रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में जो वादे आपने किये थे उनका क्या हश्र होगा ?

आपने यह भी वादा किया था कि हम 450 करोड़ रुपये की लागत से 'किसान कल्याण कोष' बनाएंगे और आपने इस अभिभाषण में बताया है कि उसके लिए आपने साढ़े नौ करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। मैं यह जानना चाहता हूं कि 250 करोड़ रुपये से आपने प्राकृतिक आपदा कोष के निर्माण की बात कही थी, उसके लिए आपने क्या प्रावधान किया ? सवा दो साल में इसके ऊपर 500 करोड़ रुपये खर्च हो जाने चाहिए थे। लेकिन यह सारे के सारे काम, वादे जैसे किये थे, वे वादे हवा में उड़ गये। इनका ऐसा हश्र हुआ है कि

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

राजस्थान की जनता यह जानने लगी है कि यह सरकार वादे करती है लेकिन उन वादों को निभाती नहीं है। उसके बाद मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इस अभिभाषण में यह जिक्र किया गया है कि यहां पर एक तरीके से ओवर-ड्राफ्ट की स्थिति इन्होंने नहीं आने दी। मैं यह जानना चाहता हूं कि ओवर-ड्राफ्ट की स्थिति इसलिए नहीं आयी कि एक तो आपने 58 से 60 साल की उम्र कर दी। और 58 से 60 साल की जब उम्र की तो 2 साल तक आपको प्रतिवर्ष लगभग 800 करोड़ रुपये रिटायरमेंट पर जो बेनिफिट्स मिलते हैं, वे आपको देने नहीं पड़े। तो 1600 करोड़ रुपये तो आपको यह मिल गये। इसके आलवा जो फाइनेंस कमीशन ने इमोल्यूमेंट्स दिये, उन इमोल्यूमेंट्स का लाभ आपको मिला। और उसके कारण आपके पास पहले की तुलना में, हमारी सरकार ने जो केन्द्रीय सरकार है, उसने ज्यादा पैसा आपको दिया, उसका भी आपको लाभ मिला।

इसके अलावा आपने लगभग 17000 करोड़ रुपये के ऋण ले लिये। जो जी.डी.पी. का और ऋण का जो अनुपात था, हमारे वक्त 45 परसेंट था, अब वह बढ़कर 60 परसेंट हो गया। अब ऋण लेकर घी खा रहे हो आप। इसके अलावा और कोई काम आपने नहीं किया। जहां तक विकास का सवाल है, कांग्रेस के शासन के वक्त जी.डी.पी. 11.4 परसेंट थी। अध्यक्ष महोदय, अभी विकास की दर मात्र 4 परसेंट रह गयी है। यदि इसमें कहीं गलती हो तो मैं पूर्व उप मुख्य मंत्री भाभड़ाजी ने जो कथन कहा था कि विकास की दर राजस्थान की निश्चित रूप से चार परसेंट पर रह गयी है, यह चिन्ता का विषय है। लेकिन इसका जवाब माननीय मुख्य मंत्रीजी जो वित्त मंत्री भी हैं, वे ही दे सकती हैं। मेरे पास इसका जवाब नहीं है। ऐसा उल्लेख उन्होंने भी किया है। तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब आपने कैपिटल आउट-ले बढ़ाया, परिसम्पत्तियों का निर्माण किया तो यह विकास की दर पीछे क्यों चली गयी ? विकास की दर ही किसी भी प्रदेश के बारे में यह बताती है कि वह किस तरीके से प्रदेश का विकास कर रही है या नहीं कर रही है।

मैं आपके सामने उन तथ्यों के बारे में भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि राजस्थान में सवा दो साल में 1 मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं हुआ। 1 नयी यूनिवर्सिटी स्थापित नहीं हुई। 1 नया इंजीनियरिंग कालेज नहीं खुला। एम.बी.ए. इंस्टीट्यूट नहीं बनी। हां, घोषणाएं जरूर हुई हैं लेकिन धरातल में यह चीजें नहीं आयीं तो बड़े-बड़े काम हुए नहीं हैं। सिंचाई की कोई नयी

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

योजना क्रियान्वित नहीं हुई। तो ऐसी परिस्थिति में जो आप कह रहे हैं कि हमने यह कर दिया, यह कर दिया, क्या किया आपने ? कैपिटल आउट-ले का जहां तक सवाल है 5161 करोड़ रुपये का कैपिटल आउट-ले अब तक हमारे सामने दिखायी दिया है। एक्चुअल फिगर्स जब आएंगे, जब आर्थिक समीक्षा की पुस्तक आएगी तो मैं समझता हूं कि उसमें और ज्यादा पता लगेगा कि आपने क्या कैपिटल आउट-ले किया, क्या परिसम्पत्तियों का निर्माण किया। लेकिन मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान में परिसम्पत्तियों का निर्माण नहीं हुआ है बल्कि राजस्थान जो है विकास के मामले में ऋणात्मक ग्रोथ की ओर जा रहा है।

जहां तक आपने स्टाम्प शुल्क 11 से 8 परसेंट करने की बात इस अभिभाषण में कही है। यह बात सही है कि आपने 11 से 8 परसेंट स्टाम्प ड्यूटी की। लेकिन अध्यक्ष महोदय, पिछले दरवाजे से तीन बार डी.एल.सी. की रेट में परिवर्तन कर दिया। उससे रजिस्ट्रेशन की दरें सब जगह बढ़ गयीं। जिन जमीनों की दरें दो हजार रुपये प्रति वर्गमीटर थी, आज तीन हजार, चार हजार, पांच हजार रुपये की दरें कर दी गयीं और उससे रजिस्ट्रेशन का शुल्क बढ़ गया। आपने बिजली के ऊपर 850 करोड़ रुपये का भार गरीब जनता पर बढ़ा दिया। आपने डीजल और पेट्रोल के ऊपर 50 नये पैसे प्रति लीटर सेस लगाया। इसी प्रकार से आपने बिक्री कर के ग्रुपिंग बनाकर लगभग 1200 करोड़ रुपये का भार राजस्थान की गरीब जनता के ऊपर डाल दिया। तो यह सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं कि सरकार ने टैक्स का बर्डन राजस्थान की जनता के ऊपर बढ़ाया। दूसरी और कर्जा लिया। लेकिन इसके बावजूद भी योजना का, जो 60 परसेंट पैसा है वह हमारा सिंचाई और बिजली की योजनाओं पर खर्च होता है। लेकिन मुझे कहते हुए अफसोस है कि इन इन्फ्रास्ट्रक्चर के डवलपमेंट के लिए राजस्थान की सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। अब आप बता रहे हो कि हम राजस्थान में 2012 तक इतनी बिजली पैदा कर देंगे लेकिन आपने सवा दो साल में क्या किया? अभिभाषण तो पिछले वर्ष आपने क्या किया इसका लेखा-जोखा है। आने वाले 2012 में क्या कोई जरूरी है कि आप रहेंगे ? लेकिन 2012 तक का आपने एक तरीके से विश्लेषण करके रख दिया कि हम 2012 तक यह काम करेंगे। इसलिए अभिभाषण में इस तरह की बातें पहले कभी नहीं कही गयीं लेकिन इन्होंने कह दी।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

अब आप योजना के बारे में बहुत कहते हैं। आपकी वार्षिक योजना 8350 करोड़ रुपये की आपने बनायी है। बहुत अच्छी योजना बनाई है लेकिन आप देखिये कि आपने खर्चा क्या किया है? दिसम्बर तक मात्र 54 परसेंट खर्चा आपने किया है। आप अपने उद्बोधन में जब आप बोलें तो बताये कि आप क्या 8350 करोड़ रुपये खर्च कर पाएंगी ? मुझे डाउट है।

अध्यक्ष महोदय, 7000 करोड़ रुपये भी वार्षिक योजना का खर्च नहीं कर पाएंगे। और यह योजना जो है इसका केवल ढोल पीट-पीट कर आपने प्रचार किया, लेकिन वास्तव में योजना के अनुरूप काम नहीं हुआ। और आपने अगली वार्षिक योजना भी जो मंजूर करवायी है, मैं अभी आपको दावे के साथ कहता हूं कि वह योजना भी आप पूरी तौर से क्रियान्वित नहीं कर पाएंगे। जहां तक आपने व्यय जो किये हैं, उसमें वेस्टफुल एक्सपेंडिचर ज्यादा किया है। मुझे आप माफ करेंगे, जब आप डावोस से आयीं, करोड़ों रुपये के विज्ञापन लग गये। होर्डिंग्स लग गये। यह कौनसी परम्परा है ? क्या पहले कभी कोई मुख्य मंत्री या मंत्री विदेश नहीं गया और उसके आने के बाद जिस तरीके से विज्ञापनबाजी हुई ? वह तो हम लोगों ने विरोध किया तो रातोंरात कई विज्ञापन उतर गये। जब आपने अपने शासन के दो वर्ष मनाये, होर्डिंग्स, हां, प्रिंट मीडिया को विज्ञापन दो, समझ में आता है। होर्डिंग्स के ऊपर करोड़ों रुपये ... (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत : आपने बिना विदेश गये विज्ञापन लगाये थे। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बीच में नहीं टोकें, प्रतिपक्ष के नेता.... (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : कोई बात नहीं। वह तो ऐसा है कि आपके मंत्री और मुख्य मंत्री निवास पर मिलते हैं या नहीं मिलते हैं लेकिन आप लोग होर्डिंग्स पर जरूर मिलते हो। यह बात जरूर है। होर्डिंग्स में सब जगह दिखाई देते हैं लेकिन आप अपने बंगलों में लोगों से नहीं मिलते हो, यह आम जनता में कहावत है। ... (व्यवधान) आपका भी लगा हुआ है स्टेशन पर, आप क्यों चिन्ता कर रहे हो? आपका भी, आपको पता है कि नहीं ? आपका होर्डिंग्स लगा हुआ है रेलवे स्टेशन पर।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : कम से कम मेरे को तो छोड़ो आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ...(व्यवधान) आप घर पर आओ, आपको दान-दक्षिणा देंगे।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कह रहा था कि वेस्टफुल एक्सपेंडिचर खूब हुआ है, जम कर हुआ है। इसके साथ-साथ अब आपने अभिभाषण में महामहिम राज्यपाल महोदय के माध्यम से यह फरमाया कि राजस्थान बीमारू राज्य से निकल गया है। बीमारू राज्य के क्या पैरामीटर्स हैं, आप बतायें? पहले बीमारू कैसे था और अब बीमारू कैसे नहीं है? राजस्थान के विकास की दर नेगेटिव जा रही है। बेरोजगारी बढ़ रही है और आप कह रहे हैं कि बीमारू राज्य से राजस्थान निकल गया। केवल ओवरड्राफ्ट तो इसलिए नहीं हुआ कि आपने कोई खर्चा नहीं किया। अकाल पड़ रहा है। लोग भूखे मर रहे हैं। पशुओं के लिये इन्तजाम नहीं हैं लेकिन आप कह रहे हो कि ओवरड्राफ्ट नहीं है। ओवरड्राफ्ट तो खर्चा करोगे तब होगा, विकास करेंगे तब ओवरड्राफ्ट होगा। विकास नहीं करोगे तो खर्चा नहीं होगा।

इसके अलावा मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में मुख्य रूप से हम लोगों को अपना ज्यादा से ज्यादा पैसा इन्फ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करना चाहिये लेकिन राजस्थान में ऐसा नहीं हुआ है। और मुख्य रूप से राजस्थान में फिलूजखर्ची हुई है और फिजूलखर्ची के साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मंत्रियों का ध्यान नहीं है। मुख्य मंत्रीजी, आप कड़ी समीक्षा करें कि आपके प्रभारी मंत्री एक साल में एक बार भी जाने वाले मंत्रियों की संख्या कितनी है अपने जिलों में, मैं समझता हूं बहुत-से ऐसे मंत्री हैं जो साल में एक बार गये या गये ही नहीं और कोई उन जिलों के बारे में भान नहीं है कि जिलों में क्या हो रहा है।

इसके अलावा, आप बीमारू राज्य के बारे में जैसा मैंने आपको बताया, इसके पैरामीटर्स के बारे में बतायें। आज राजस्थान जितना पीछे जा रहा है, जिस तरीके से विकास की गति है, वैसा का वैसा राजस्थान शिक्षा के मामले में भी पीछे जा रहा है। मेरी जानकारी के अनुसार साक्षरता का प्रतिशत...(व्यवधान)..

श्री जोगेश्वर गर्ग : आज का सबसे बड़ा असत्य।

डा. बुलाकीदास कल्ला : शिक्षा के क्षेत्र में जितना रजिस्ट्रेशन और नामांकन होना चाहिये, वह नहीं हुआ। और शिक्षा के क्षेत्र में मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि राजस्थान का साक्षरता का प्रतिशत पिछले सवा साल में लगभग पांच प्रतिशत कम हुआ है। हर क्षेत्र में राजस्थान पीछे जा रहा है तो फिर किस तरीके से राजस्थान आगे बढ़ रहा है? ..(व्यवधान).. ऐसा लग रहा

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

है इनको अपने मुख्य मंत्री पर भरोसा नहीं है कि वे जवाब दे पायेंगे, यह पहले ही जवाब देने लग गये।

श्री महावीर प्रसाद जैन : (सरकारी मुख्य सचेतक) : मुझे लगता है यह ठीक नहीं है। एक घंटे का जो ....(व्यवधान)..

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह तो व्यवधान है, व्यवधान मंत्री हैं। मैं आपसे यह कह रहा था कि शिक्षा के क्षेत्र में राजस्थान पीछे गया है। और इसके साथ-साथ सरकार की आय में बढ़ोतरी बिलकुल नहीं हुई है और आय में बढ़ोतरी नहीं हुई है तो सरकार यह कहे कि हम बीमारू राज्य से आगे निकल गये, कैसे निकल गये ? यह बतायें हमको। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि इन्होंने जो राजस्व घाटा ..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : टोटल टैक्स रेवेन्यू कितना बढ़ाया, यह देख लो जरा। आय में बढ़ोतरी नहीं हुई, आप कह रहे हो शिक्षा में पीछे चला गया।

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह एक नोर्मल बढ़ोतरी है। आपके आंकड़ों की जगलरी है। आप ग्यारहवें वित्त आयोग से पैसा प्राप्त कर रहे हैं और पैसा प्राप्त करके उसको राजस्व घाटा कम होने में दिखा रहे हैं। यह आंकड़ों की जगलरी इकोनोमिक्स के विद्यार्थी जानते हैं। हमने इकोनोमिक्स पढ़ी हुई है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार ने ऐसा कोई विशेष काम किया नहीं। आप उद्योग डवलप करते, आप राजस्थान का शैक्षणिक विकास करते, राजस्थान का इन्फ्रास्ट्रक्चर का डवलपमेंट करते तो आप बीमारू राज्य से आगे निकल सकते थे, लेकिन ऐसा कोई काम आपने नहीं किया।

राजस्थान में आप, बिजली के क्षेत्र में राजस्थान में, जैसा मैंने आपको बताया कांग्रेस के राज में साढ़े 1700 मेगावाट बिजली का उत्पादन हुआ, लेकिन आपने सवा दो साल में बिजली का कोई उत्पादन नहीं किया। आपने कहा था हम किसानों को आठ घंटे बिजली देंगे। आज किसान को मात्र साढ़े तीन और चार घण्टे बिजली मिलती है। विद्यार्थियों को बिजली उपलब्ध नहीं हो रही है परीक्षा के दिनों में। बिजली की स्थिति बहुत खराब है और किसानों के बिल जो पहले कांग्रेस के राज में तीन हजार आते थे, आज इन्होंने पांच हार्स पावर के कनेक्शन 10 हार्स पावर, 15 हार्स पावर, 20 हार्स पावर, 25 हार्स पावर, 30 हार्स पावर में बदलने के कारण उनके बिल 27 हजार रूपये आ रहे हैं। इसके कारण किसान बहुत चिन्तित और दु:खी हैं और किसान इस सरकार

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

को कोस रहे हैं। मैं यह भी आपसे कहना चाहता हूं कि राजस्थान खास तौर से बिजली के अलावा सिंचाई के मामले में भी आपने कहा है कि नर्मदा नदी के लिये 645 करोड़ रूपये की राशि आपने दी। लेकिन आंशिक रूप से उसका पानी जालौर और उसके आस-पास के इलाकों को मिलेगा। क्यों भाई ? गुजरात में आपकी सरकार है। और सरकार आपकी है तो निश्चित रूप से आपको उनसे बात करके पूरा का पूरा पानी जितना पैसा आपने दिया, उसका काम सबसे पहले हो। और नर्मदा का पूरा का पूरा पानी हमारे किसानों को पर्याप्त मात्रा में मिले, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। राजस्थान में इन्टर-स्टेट डिस्प्यूट को यदि आप उठाकर देखें तो राजस्थान सरकार अन्तर्राज्यीय नदी जल विवादों में, विद्युत विवादों में कोई भी सफलता हासिल नहीं कर सकी है। आज हमको पंजाब से पूरा पानी नहीं मिल रहा है। हमको हरियाणा से पूरा पानी यमुना नदी का बिलकुल नहीं दे रहे हैं, आपका गुजरात पूरा पानी नहीं दे रहा है। और तो और मध्य प्रदेश जहां आपकी सरकार है, वहां इन्होंने 151 एनीकट बना रखे हैं और 151 एनीकट में जितना पानी इकट्ठा होता है वह पानी आगे नहीं जाये, उसको रोका जाये। इसके लिये भी आपने कोई व्यवस्था नहीं की है। आपने रावतभाटा एटोमिक पावर प्रोजेक्ट, जिससे 250 मेगावाट बिजली राजस्थान को मिलती थी, वह बिजली हमेशा के लिये मध्य प्रदेश को दे दी। मुझे याद आता है, राजस्थान की एक कहावत है – आप राजस्थान की मुख्य मंत्री हैं या मध्य प्रदेश की मुख्य मंत्री हैं ? आप यह बतायें कि क्या राजस्थान के हितों की रक्षा कर रहे हैं या ....(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी : कल्ला साहब, आप राजस्थान की विधान सभा में बोल रहे हो या मध्य प्रदेश की विधान सभा में ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : राजस्थान में बोल रहा हूं। मैं तो राजस्थान में ही बोल रहा हूं, लेकिन राजस्थान की बिजली ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : बैठी हैं न, दिख रही हैं न आपको राजस्थान में।

डा. बुलाकीदास कल्ला : राजस्थान की बिजली मध्य प्रदेश में दी जायेगी तो निश्चित रूप से हम इसका विरोध करेंगे। ....(व्यवधान)... आपको मेरा भाषण जमेगा कैसे ? पेचिश हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष : बीच में व्यवधान नहीं डालें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : यह पूछ रहे हैं क्या होती है ? पेचिश क्या होती है ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : विपक्ष के नेता महोदय के चैम्बर में आयेंगे तो बता दूंगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अकाल की सदन में आज चर्चा हुई। अकाल के मामले में कहूं, अभी मैं गांवों का दौरा करके आया हूं। इन्होंने 15,778 गांवों को अभावग्रस्त घोषित किया। सबसे पहले तो आपके स्वयं के जिले में झुन्झुनूं में, सवाई माधोपुर में और अन्य स्थानों पर बहुत से खेतों को 49 प्रतिशत फसल दिखाकर इन्होंने गिरदावरी ऐसी दिखाई है कि वहां किसान परेशान हैं। वह अभावग्रस्त घोषित नहीं हुए। उनको अभावग्रस्त घोषित करना चाहिये। इसके अलावा जिन गांवों को अकालग्रस्त घोषित कर दिया वहां फरवरी महीने में सवा दो लाख श्रमिक काम कर रहे थे। और सवा दो लाख में, आपको जानकर ताज्जुब होगा कि मैं उन गांवों में गया 30 मजदूरों से ज्यादा कहीं स्वीकृति नहीं थी। कहीं पांच, कहीं दस, कहीं बीस और कहीं पच्चीस और उनमें भी 35 प्रतिशत काम ऐसे थे जहां पर कोई भी श्रमिक काम नहीं कर रहा था यानि कार्य शुरू नहीं हुए। और जिन कार्यों को शुरू किया गया था वहां पर भी 80 प्रतिशत और कहीं 100 प्रतिशत आदमी काम कर रहे थे। अजमेर जिले की मेरे पास रिपोर्ट है वहां पर 25 हजार मजदूर स्वीकृत किये गये हैं, उनमें से मात्र सात हजार आदमियों को रोजगार मिला है। ऐसी परिस्थिति में मेरी जानकारी के अनुसार फरवरी माह में जो सवा दो लाख श्रमिक सीमा निर्धारित की थी उसमें से मात्र एक लाख अथवा एक लाख पच्चीस हजार श्रमिकों को काम मिला है। पक्के कामों से राजस्थान के लोगों को राहत नहीं मिल सकती।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 2 लाख 23 हजार को काम मिला है, यह रिकार्ड में है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : लेकिन हमारी जानकारी में यह है। आपने कागजों में कर रखा है लेकिन वास्तविकता में इतने लोगों को रोजगार नहीं मिला।

श्री अध्यक्ष : आपकी जानकारी को उन्होंने दुरूस्त कर दिया है, आप मान लो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है, अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्रीजी जब मैं बोल लूं उसके बाद यह करेक्ट कर दें लेकिन जिस तरह से यह व्यवधान डाल रहे हैं, यह उचित नहीं है। संसदीय कार्य मंत्रीजी, जो कानून कायदों को जानते हैं, तो बेकायदे कानून वाले तो आपके बहुत हैं। लेकिन कानून जानने वाला करता है तो अफसोस होता है।

(समय : 17.00 बजे)

श्री अध्यक्ष : माननीय कल्ला साहब, यद्यपि उचित तो नहीं है लेकिन करेक्ट करना भी जरूरी होता है कई बार।

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह तो मैंने ही पढ़ लिया कि 2,23,000 था। मैं इसलिए प्रतिवाद कर रहा हूं कि वास्तव में एक लाख और सवा लाख से ज्यादा लोग नहीं लगे हैं। मौके पर मंजूर किये हुए हैं इन्होंने लेकिन वास्तव में काम करने वाले लोग इतने ही हैं जितने मैं बता रहा हूं।

इसके अलावा गांवों में जो काम खोले गये हैं वह पक्के नैचर के काम खोले गये हैं, जब तक आप सड़क के और कच्चे कार्यों को, तालाब खोदने के कार्यों को नहीं खोलेंगे तब तक गांव के लोगों को मजदूरी पूरी नहीं मिलेगी। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यह कहना चाहता हूं कि आपके पास 430 करोड़ रुपये तो पिछले अकाल के पड़े हुए थे। उसके बाद 311 करोड़ रुपये टी.एफ.सी. के आपके पास वर्ष 2005-06 के हैं, इसका 25 प्रतिशत, यानि कि साढ़े 77 करोड़ रुपये आपका राज्य का हिस्सा पड़ा हुआ है। कुल मिलाकर के 818.5 करोड़ रुपये की राशि आपके पास अकाल के पेटे 2005 और 2006 में पड़ी हुई है। और अभी जो नया बजट आयेगा उसमें भी करीब आपके पास 430 करोड़ से ऊपर की राशि आपको केन्द्र सरकार से फिर मिलने वाली है। तो इतना रुपया होते हुए भी आप अकाल राहत के कार्य क्यों नहीं खोल रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आ रहा है। राहत कार्यों के प्रति सरकार बिलकुल असंवेदनशील है, किसानों के प्रति सरकार की कोई चिन्ता नहीं है। आज राजस्थान में एक भी पशु सेवा शिविर नहीं है। चारा डिपो खुले हुए हैं कोई सैंकड़ों की संख्या में। जबकि कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त कम से कम 8 लाख से ऊपर पशुओं को पशु सेवा शिविरों में डाला गया था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कितने ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : 8 लाख।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : कब ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इतने सेंसस में ही पशु नहीं हैं अपने पूरे राजस्थान में।

डा. बुलाकीदास कल्ला : कैसे नहीं है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पूरे राजस्थान में नहीं है। ...(व्यवधान)...

डा. बुलाकीदास कल्ला : किसने कह दिया ? आपने पशु जनगणना गिनी नहीं है, करोड़ों में है, आपको मालूम नहीं है।

श्री अध्यक्ष : पशु तो करोड़ों में हैं, यह क्या कह रहे हो आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला : यही तो मैं कह रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : इनको पता ही नहीं है कितने पशु हैं, कितने नहीं हैं। आठ लाख आज नहीं हैं क्या पशु ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : साढ़े चार लाख तो आपने ही लगाये थे पिछले अकाल में।

श्री सांवर लाल : राजस्थान में जनसंख्या पशु संख्या बराबर है बराबर।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, ठीक है।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : कल्लाजी, यह तो जब दिये थे जब केन्द्र सरकार ने 32.5 लाख मैट्रिक टन गेहूं आपको उपलब्ध कराया था, अब हमें दो लाख मैट्रिक टन गेहूं मिल रहा है और इस महीने में हमने चार लाख लेबर सैंक्शन कर रखे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मुझे मालूम है सैंक्शन कर रखे हैं, काम कितने कर रहे हैं ? फरवरी में कभी काम शुरू हुआ है ? अगस्त के महीने में काम शुरू हो जाता था इसलिए मैंने कहा था यह सरकार संवेदनशील नहीं है किसानों के प्रति।

श्री अध्यक्ष : अगस्त में गिरदावरी ही नहीं होती है, कहां से हो जायेगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है बाड़मेर और जैसलमेर में जहां पर जून, जुलाई, अगस्त में बरसात नहीं हुई थी, ऐसे जिले में तो काम शुरू करना चाहिए था। आज आदिवासी क्षेत्रों में काम बिलकुल शुरू नहीं किया तो ऐसी स्थिति में रुपया होते हुए भी काम शुरू नहीं करना मैं समझता हूं गैर-जिम्मेदाराना काम है। सरकार को युद्ध स्तर पर पूरे गांवों में काम शुरू करना चाहिए। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया बीच में नहीं टोकें। माननीय सदस्य, बीच में नहीं टोकें, व्यवधान नहीं डालें।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह क्या परेशानी है बीच में, यह गलत तरीका है।

श्री अध्यक्ष : वह बीकानेर के शहर के रहने वाले हैं, उनको पता नहीं गिरदावरी किस वक्त होती है, आप बीच में नहीं टोकें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैडम, मेरे को पता है गिरदावरी किस महीने में होती है लेकिन मैंने कहा कांग्रेस के राज में अगस्त में काम शुरू हो गये थे।

श्री रामनारायण चौधरी : हमारे पी.सी.सी. प्रेसिडेंट को आप बीकानेर तक सीमित नहीं कर सकते, पूरे राजस्थान के हैं, सब जगह गये हैं। आपने अपने भाषण के शुरूआत में कहा है कि मैं सब जगह गया हूं और मेरी जानकारी के आधार पर मैं बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : अच्छा ठीक है, बहुत अच्छा।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, रिकार्ड देख लीजिए, परम्परा देख लीजिए किसी भी माननीय सदस्य को अपनी जानकारी के आधार पर बोलने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है, ठीक है।

श्री रामनारायण चौधरी : और सरकारी आंकड़ों का विरोध कर सकता है, उनका खण्डन कर सकता है। अब सरकार के पास साधन है तो वह अपने रिकार्ड से कह सकते हैं कि यह स्थिति है, तब देखेंगें। अब पहले ही अध्यक्ष महोदय ने फरमा दिया कि करेक्ट कर सकते हैं, मान्यवर, करेक्ट तो जब करें न कि जब यह पेश करेंगे आंकड़े। फिलहाल तो हम अपने ही वह आंकड़े बता रहे हैं यह जब आंकड़े दें जब आप गलत कह देना।

श्री अध्यक्ष : क्यों ? वो कोई भी यदि गलत आंकड़े देते हैं तो सदन का कोई भी माननीय सदस्य करेक्ट कर सकता है, इसमें कोई भी आपको आपत्ति नहीं होनी चाहिए, प्रतिपक्ष के नेता महोदय।

श्री रामनारायण चौधरी : किस आधार पर कह सकता है, वह कह सकता है कि मेरी जानकारी में यह है।

डा. सी.पी. जोशी : अध्यक्ष महोदय, कल्ला साहब बीकानेर के एम.एल.ए. के साथ-साथ राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भी हैं, सारे राजस्थान में ट्यूर किया है, वह बीकानेर के एम.एल.ए. हो सकते हैं, यह गलत है।

श्री अध्यक्ष : ठीक है। चलिये बोलिये, आपको थोड़ा विश्राम मिल गया, बोलिये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैंने यह गिरदावरी के बारे में केवल नहीं मैंने यह कहा था अगस्त में कांग्रेस ने काम शुरू कर दिये थे।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं, ठीक कहा, अच्छा बोले हैं, बोलिये।

श्री अध्यक्ष : कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। अब आपको कर दिया न दुरुस्त प्रतिपक्ष के नेता ने, ठीक है।

श्री सांवर लाल : कांग्रेस ने काम इसलिए शुरू किये कि आपके राज में बरसात हुई नहीं थी।

मोहम्मद माहिर आजाद : अब आप करा लो बरसात।

श्री सांवर लाल : आपको जानकारी नहीं है क्या, माननीय सदस्य, केवल 15 हजार गांवों में अकाल है और अब की बार पीने के पानी और इर्रिगेशन की जो फसल होगी रिकार्डेड है।

श्री अमराराम (धोद) : 15 हजार में क्यों पड़ने दिया? बरसात आप ही बरसाते हो फिर 15 हजार में क्यों नहीं बरसाया आपने? आप तो बरसाते हो पानी, आपके अरदास से ही बरसात है, आपके होम से ही बरसात है तो फिर 15 हजार में क्यों नहीं बरसाया आपने ?

श्री सांवर लाल : यह कम्यूनिस्टों का काम है। मैंने यह नहीं कहा कि मैं या सरकार बरसाती है। समय लगेगा।

डा. किरोड़ी लाल मीणा : अब आपके पाप धुलने में समय लगेगा, एक साथ नहीं धुलेगा।

श्री जुबेर खान : हवाई जहाज को 15000 गांवों में और घुमा देते ताकि वहां भी बरसात हो जाती।

श्री अध्यक्ष : आप बोंलने दें बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य को। ...(व्यवधान) अब आप फिर व्यवधान करने लग गये।

मोहम्मद माहिर आजाद : नेता बोलेंगी जब हम भी पूछेंगे।

श्री अध्यक्ष : नेता से आप बी.डी. कल्ला की तुलना नहीं कर सकते हैं, प्रतिपक्ष के नेता से कर सकते हैं लेकिन बी.डी. कल्ला से कैसे करेंगे आप सदन के नेता की तुलना? यह क्या बात हुई।

श्री प्रद्युम्न सिंह : एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर। यह व्यवस्था हुई है कि अगर आंकड़े यहां पर कोई गलत पेश करता है तो उसको सदन का कोई भी माननीय सदस्य करेक्ट कर सकता है। अभी आपने आसन से व्यवस्था दी है।

श्री अध्यक्ष : जी। खा क्या रहे हैं, पहले यह बताएं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आई एम सोरी। इस सदन के अन्दर आपका नौवां टर्म है, सभापति महोदय।

श्री सांवर लाल : सभापति महोदय नहीं अध्यक्ष महोदय कहिये।

श्री अध्यक्ष : आप मुझे डिमोट क्यों कर रहे हैं, डिमोट क्यों कर रहे हैं? आप मुझे सभापति क्यों कह रहे हैं ?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन यह है कि आपने कहा कि कोई भी करेक्ट कर सकता है। अगर यह है, इसके अन्दर मेरा आपसे निवेदन है कि आपने कहा है कि मुख्य मंत्री को कोई नहीं टोक सकेगा, बाद में प्रश्न कर सकेंगे। बीच में कहीं पर भी आंकड़े गलत आयें तो क्या उनसे कोई प्रश्न करने की आप हमें इजाजत देंगी क्या ?

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता को नहीं, आप बाद में कह सकते हैं क्यों कि यह परम्परा पहले बी.ए.सी. में तय हो चुकी है कि सदन की नेता और प्रतिपक्ष के नेता को कोई बीच में नहीं टोकेगा इसलिए उनको बीच में नहीं टोकिये। बाद में पूछ लें आपको जो पूछना है।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था तो हमेशा से है और हमेशा से थी। लेकिन जब कल्ला साहब सीएलपी लीडर थे तब रोकते थे, तब क्या हो जाता था आपके मापदण्ड अलग-अलग हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : एक मिनट। आपने यह एक ऐसी व्यवस्था दे दी है महामना, कोई भी माननीय सदस्य किसी को भी करेक्ट कर सकता है, ऐसा वाक्य आपने कहा है 'करेक्ट'। संसदीय परम्परा में ऐसा कोई किसी के पास अधिकार नहीं है। हर सदस्य को चुनौती देने का अधिकार है। चुनौती दे सकते हैं, करेक्ट नहीं कर सकता। करेक्ट तो रिकार्ड के आधार पर ही होगा, आप करेंगी करेक्ट क्या है वह तो चुनौती दे सकता है। संसदीय परम्परा में चुनौती है, आप अपने दफ्तर से सलाह कर लेना, चुनौती शब्द निकलेगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, अकाल के बारे में राजस्थान में सब लोगों को मिल कर यह सोचना चाहिए कि अकाल से छुटकारा कैसे मिले। इसके लिए हम सब लोगों को अरावली का जितना भी एरिया है उसको हराभरा करने की आवश्यकता है क्योंकि वृक्ष जहां अधिक होते हैं वहां वर्षा ज्यादा होती है। दुर्भाग्य से राजस्थान में वृक्षों की कटाई इतनी ज्यादा हुई है, उसके कारण वर्षा राजस्थान में नहीं होती है। इसलिए हमको वृक्षारोपण के ऊपर, और अरावली की पर्वतमाला को हराभरा करने की आवश्यकता है ताकि राजस्थान में अकाल से हमेशा के लिए मुक्ति मिल सके।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

राजस्थान के लोगों को केन्द्रीय सरकार ने एक सौगात दी है-'राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना' की।

जिसके लिए हमारे चुनाव घोषणा पत्र में यह वादा किया गया था कि एक करोड़ लोगों को केन्द्र में जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हम एक करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। भारत की संसद ने इसे मंजूर कर दिया और राजस्थान के छह जिलों को जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, सिरोही, करौली और झालावाड़ यह छह जिले चुने गये हैं। इन जिलों के लाखों लोगों को इस योजना का लाभ मिलेगा और आने वाले समय में अन्य जिले भी इससे जुडेंगे। और यह हमारे राजस्थान के लिए आर्थिक समृद्धि का और गांवों की समृद्धि का एक आधार बनेगी और किसान जहां सुकाल भी होता है तो भी किसान सौ दिन तक बेरोजगार रहता है उसको कम से कम रबी और खरीफ की फसल के अलावा सौ दिन का जो रोजगार मिलेगा वह निश्चित रूप से उनकी आर्थिक समृद्धि का एक आधार बनेगा। इसमें यह भी प्रावधान किया गया है कि जिन लोगों को रजिस्ट्रेशन होने के बाद यदि पन्द्रह दिन तक मांगने पर रोजगार नहीं मिलता है तो 25 प्रतिशत बेरोजगारी भत्ता और तीस दिन तक रोजगार उपलब्ध...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य बीच में बात नहीं करें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा इसमें वन थर्ड महिलाओं का आरक्षण है। यह योजना निश्चित रूप से राजस्थान का काया कल्प करेगी। इसके साथ-साथ मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान की सरकार इस योजना को भी राजस्थान राज्य ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना के रूप में परिभाषित कर रही है। मैं इसको उचित नहीं मानता। कभी केन्द्रीय सरकार ने कहा कि आपकी योजना है तो आप ही पैसा खर्च करो तो हजारों लाखों लोग जो इस योजना में काम करने वाले हैं, लाभान्वित होने वाले हैं उनका क्या होगा। इसलिए जिस प्रकार से योजना आयी है, मूल रूप से उसी रूप में उसकी क्रियान्विति होनी चाहिए।

इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय सरकार ने एक लाख चौहत्तर हजार करोड़ रुपए की लागत से भारत निर्माण योजना की शुरुआत की है और उस योजना से न केवल सर्व शिक्षा अभियान बल्कि जल, बिजली, सिंचाई, सड़क, टेली कम्युनिकेशन, इन सब का गांव-गांव में विकास होगा। गांवों में

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

मकानों का निर्माण होगा और राजस्थान का भी इसको बहुत बड़ा लाभ होगा। शिक्षा मंत्रीजी, सर्व शिक्षा अभियान नहीं होता तो आज आप इक्यावन हजार आदमियों को नौकरियां देने की बात करते हैं ना इसमें आपके विभाग की हवा निकल जाती। अब आप कह रहे हो इक्यावन हजार आदमियों को आपने नौकरी दी। यह नौकरी, भारत सरकार को धन्यवाद दीजिए, यह पैसा आपको सर्व शिक्षा अभियान में मिला तब जाकर के आपने यह नौकरियां दीं। लेकिन मैं जानता हूं कि आपने स्टेट बजट से क्या दिया ? पिछले सवा दो साल में मात्र 5437 लोगों को आपने एक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि हमने नौकरी दी, वह किनको, मृत कर्मचारियों के आश्रितों को अथवा शहीदों के आश्रितों को, इसके अलावा आपने कोई नौकरियां स्टेट सैक्टर में नहीं दी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : 1905 सैकिण्ड ग्रेड के लोगों को स्टेट से दी, फर्स्ट ग्रेड की जितनी नियुक्तियां हुई हैं और चार हजार जो भेजे हैं आर. पी. एस. सी. को वह सारे स्टेट के बजट से हैं। यह 39 हजार में से 9 हजार स्टेट के बजट से हैं और यह जो पैसा लाए हैं उसमें नगद 350 करोड़ रुपए सरकार के राजस्थान सरकार का हिस्सा दिया तब जाकर मिले हैं। आपके पास देने को कौड़ी नहीं थी इसलिए नहीं मिला आपको।

श्री महावीर प्रसाद जैन : दिमाग नहीं था, कौड़ियां तो बहुत थीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है केन्द्र सरकार ने कितना रुपया दिया यह भी बता दो ? 1050 करोड़ रुपया केन्द्र सरकार ने दिया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : राजस्थान सरकार ने दिया वह मैंने बता दिया और केन्द्र ने दिया वह आप बता दो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं बता रहा हूं 1050 करोड़ रुपया दिया है आपको तब जाकर के आपको यह सारी चीजें मिली हैं।

श्री वासुदेव देवनानी : वह भी राजस्थान की जनता का टैक्स था, कोई फिरौती में नहीं दिया है..(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : लेकिन माननीय अध्यक्ष महोदय, शिक्षा मंत्रीजी यह बताएं कि आपने सवा दो साल में सवा दो लाख लोगों को रोजगार देना था उसका आंकड़ा बताइये, वह आदमी कहां गये जिनको नौकरी देनी थी ? आपने अपने चुनाव घोषणा पत्र में साफ कहा कि हम प्रतिवर्ष एक लाख लोगों को रोजगार देंगे लेकिन वह रोजगार कहां गया ? इसलिए मैं कहना

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

चाहता हूं कि चुनाव घोषणा पत्र करने से पहले भी सोचना चाहिए आप घोषणा पत्र में क्या लिख रहे हैं, क्या नहीं लिख रहे हैं। इसके बाद आपने डांग क्षेत्र के विकास के लिए पांच करोड़ रुपए का डांग क्षेत्र इतना लम्बा चौड़ा है, एक गांव का विकास भी पांच करोड़ रुपए में नहीं होता है। इसलिए डांग क्षेत्र का विकास आप पांच करोड़ में वह बीरबल की खिचड़ी की तरह कर पायेंगे, बाकी कर नहीं पायेंगे।

जहां तक डेयरियों का सवाल है डेयरी के चुनाव राजस्थान में हुए। अध्यक्ष महोदय, हमारे रामचन्द्रजी चौधरी को हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। और सुप्रीम कोर्ट के डाइरेक्शन के बाद यहां राजस्थान में चुनाव हुए और आज भी आर.सी.डी.एफ. के चुनाव नहीं हो रहे हैं। मैं मांग करना चाहता हूं कि राजस्थान कोआपरेटिव डेयरी फेडरेशन के चुनाव कराए जाएं ताकि किसानों को, जो दुग्धपालक हैं, उनको वहां की सत्ता मिले और वह ढंग से वहां पर काम कर सकें।

श्री सांवर लाल : आपने कब-कब आर.सी.डी.एफ. के चुनाव करवाए, जरा जानकारी दे दीजिए ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : हमने नहीं किया तो आप क्यों नहीं करा रहे हो, हमारे रास्ते चलोगे क्या ?

श्री सांवर लाल : आप राज में आते हो तब तो कुछ नहीं करो और केवल सवाल पूछने का अधिकार लेकर बैठे हो क्या ?

श्री रामनारायण चौधरी : हम तो आपके रास्ते चलेंगे।

एक माननीय सदस्य : हमारे कहने से पूरा चलोगे तो आपका मामला यही होगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा लग रहा है अध्यक्ष महोदय, डेयरियों के चुनाव में सारे कांग्रेस के लोग जीत गये इसलिए चुनाव कराने की मंशा नहीं है ...(व्यवधान)

श्री मदन राठौड़ : ..हमारा व्यक्ति जीतकर आया है कहां कांग्रेस के जीतकर आ गये ? पाली से ग्यारह जगह से ...

मोहम्मद माहिर आजाद : भीलवाड़ा से.. ज्यादातर डेयरियों के अन्दर कांग्रेस जीती है, आप केवल पाली को लिए बैठे रहो यहां, पाली राजस्थान नहीं है..(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह : भरतपुर के बारे में तो + + + मत बोलो, मैं बैठा हूं यहां..(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : यूं ही खुश हो रहे हो फालतू ही, कराओ आर.सी.डी.एफ. के चुनाव..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : ...कौन बनेगा तब पता चलेगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, कम से कम हाउस को तो आप आर्डर में रखो। यह तो आपसे मैं प्रोटक्शन चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष : अब वह आसन का संरक्षण चाह रहे हैं, अब कोई नहीं बीच में बाधा डालेगा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अब मैं आपसे यही कह रहा था कि डेयरी के चुनाव होने चाहिए, कृषि उपज मण्डी समितियों के चुनाव होने चाहिए, कोआपरेटिव बैंक्स के चुनाव होने चाहिए। हमने कोआपरेटिव बैंक के चुनाव समय-समय पर करवाये हैं और इसी प्रकार....(व्यवधान) बराबर कराए हैं।

श्री मदन राठौड़ : कब कराए हैं ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : कई बार कराए हैं कोआपरेटिव सोसायटीज के जितने भी चुनाव हैं..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया व्यवधान नहीं डालें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उन सभी चुनावों को अध्यक्ष महोदय, कराना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : बीच में बाधा नहीं डालें, बोलने दें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : सरकार ने सरसों की खरीद के बारे में यहां पर बड़े, 2400 करोड़ रुपए की सरसों खरीदी। मैं जानना चाहता हूं कि आपने उसमें कितना कांट्रीब्यूट किया ? यह सारा का सारा पैसा केन्द्र का 'तांगा घोड़ा सरकारी और घर की लागे डिच्कारी' केन्द्र सरकार पैसा दे और आप अभिभाषण में कहो कि हमने 2400 करोड़ की सरसों खरीद ली। अब खरीद लो ना ? अब आप नीति देखिए कि कोटा सम्भाग में सरसों की खरीद की जाएगी और बाकी सरसों की खरीद कहीं नहीं होगी, यह क्या, आप पूरे राजस्थान में सरसों खरीदिए। आपकी नीतियां विभेदकारी हैं। अलग-अलग जिलों में अलग-अलग सम्भागों में आपकी नीतियां जो हैं वह ट्रांसपेरेंट नहीं हैं इसलिए नीति को ऐसा होना चाहिए कि पूरे राजस्थान में एक साथ किसानों की सरसों को खरीदा जाना चाहिए। इसके साथ-साथ आपने ...(व्यवधान)

बहुत जगह आ चुकी है, गंगानगर में आ चुकी है।

श्री जुबेर खान : अलवर, भरतपुर, धौलपुर में आ रही है सरसों भारी मात्रा में किसान निकाल रहे हैं वहां तो खुलवा दीजिए।

श्री अमराराम (धोद) : कोटा में कौनसी खरीद ली ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : जहां खरीद केन्द्र शुरू होंगे, किसान के पास सरसों होगी तो दे देंगे। अध्यक्ष महोदय, यहां पर मैं जिक्र करना चाहूंगा ए.डी.बी. प्रोजक्ट का। एशियन डवलपमैंट बैंक प्रोजक्ट जो है राजस्थान में जब आया तो उसमें साठ करोड़ रुपए अस्पतालों के डवलपमैंट के लिए रखे गये थे। आज चिकित्सा, स्वास्थ्य का क्षेत्र इतना नेग्लेक्टेड है उसमें पैसा बहुत कम देने को मिलता है लेकिन छह मेडिकल कालेजेज के लिए जो साठ करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया गया था वह अलग आपने डाइवर्ट कर दिया। हमारे रेलवे फाटकों की समस्या के लिए जो इकसठ करोड़ रुपए की राशि रखी हुई थी दो साल से आज वह लटक रही है लेकिन उसका कहीं पर भी कोई प्रावधान नहीं कर रहे हैं। मुझे लगता है यह पैसा दूसरी जगह सरकार डाइवर्ट कर रही है। आप अपना उद्बबोधन दें तो बताएं कि आप इस ए.डी.बी. प्रोजक्ट को जो मूल रूप में लागू हुआ था उसको उसी रूप में क्रियान्वित कर रहे हैं या उसमें क्या-क्या परितर्वन कर रहे हैं कम से कम सदन को तो बताएं कि ए.डी.बी. प्रोजक्ट में जो हास्पिटल के लिए पैसा रखा गया था और जिन प्रोजेक्ट्स के लिए अलग-अलग सम्भागों में जो राशि रखी गयी थी उसका आप क्या कर रहे हैं ? कच्ची बस्तियों के लिए मूल रूप से प्रोजक्ट बना था।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उस पैसे की ब्याज और पैनल्टी उस समय लगी है इनको पता है कि नहीं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मेरे को सब पता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ब्याज और पैनल्टीज लगी है आपके यहां और काम नहीं हुआ, पैसा पड़ा रहा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप तो ऐसे ही बोल रहे हैं, आपको पता तो है नहीं। 61 करोड़ रुपये और जमीन देने का काम..

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपका भाषण ऐसा पिटा है आज, सारे तो माननीय सदस्य आपके हंस रहे हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : हां ठीक है, बैठो आप। मेरे भाषण की आपको बड़ी चिन्ता है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : आप मेरे मित्र हैं, साथ-साथ एम.एल.ए. बने हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति इन बच्चों को उत्कृष्ट विद्यालयों में जैसे एम.जी.डी. स्कूल, सेंट जेवियर स्कूल, पब्लिक स्कूलों में एडमिशन दिये जाते थे। उनके आवास, भोजन, शिक्षण शुल्क, पैसे की व्यवस्था हमेशा राज्य सरकार करती थी, पिछले दो वर्ष से यहां पर एक भी विद्यार्थी भर्ती नहीं किये जा रहे हैं। यही विद्यार्थी एस.टी.के., एस.सी. के आई.ए.एस., आई.पी.एस. बनते थे लेकिन दो साल से, यह 1100 प्रतिवर्ष भर्ती किये जाते थे, नये बच्चों की भर्ती नहीं की जा रही है तो इससे यह सिद्ध होता है कि राज्य सरकार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। दूसरी ओर शिक्षा विभाग में जो भर्ती हुई उसमें विधवा महिलाओं को जो भर्ती किया गया...(व्यवधान)

श्री हीरालाल : दे रही है सरकार..(व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : यह राज्य के बजट में प्रावधान था। आपकी जानकारी का अभाव है इसलिये मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं...(व्यवधान)

श्री बत्तीलाल : आप असत्य बोल रहे हैं, आंकड़े गलत हैं..(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है मुझे अभी शिक्षा मंत्रीजी ने जवाब दिया है, मेरे पास प्रश्न का उत्तर पड़ा है कि दो साल से एक भी बच्चे की भर्ती नहीं हो रही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप जानकारी कर लें माननीय मुख्य मंत्री महोदया कि 1100 स्कालरशिप किसके समय, पहले 800 थी, 1100 किया गया है। यह जानते हुए कि लोग पब्लिक स्कूल में पढ़ेंगे, कहीं पढ़ेंगे इनके ऊपर खर्च ज्यादा आयेगा। लेकिन उसके बावजूद भी यह निर्णय लिया गया कि जो होनहार बच्चे हैं उनको यह थ्रू ए कम्पीटीशन एडमिशन मिलेगा, उसको आपने रोक दिया, उस पर आप गौर करें। मेरा तो यही आपसे अनुरोध है।

श्री अध्यक्ष : कर लिया गौर, अब आगे चलो। हां, कर लिया गौर, गौर कर लिया।

डा. बुलाकीदास कल्ला : विधवा महिलाओं को भी अध्यापकों की नियुक्ति दी गयी उसमें भी एस.सी. और एस.टी. की विधवाओं को जो आरक्षण दिया जाना चाहिये था, वह नहीं मिला। मेरी जानकारी के अनुसार और संसद में निजी शिक्षण संस्थाओं के लिये जो बिल आया उस बिल में एस.टी., एस.सी. के लोगों को आरक्षण देने की बात की तो मुझे कहते हुए अफसोस है

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसका विरोध किया और किसी भी पार्टी ने विरोध नहीं किया..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया शांत रहें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : इसके अलावा केन्द्र प्रवर्तित जो योजनाएं हैं उन योजनाओं के लिये जो पैसा आया, मुख्य मंत्रीजी जब वित्त मंत्री के रूप में अपना जवाब दें तो यह बतायें कि केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं का कितना पैसा अब तक आपने खर्च कर दिया और कितने में क्या बचत है ? मेरी जानकारी के अनुसार बहुत से विभाग हैं जो 50 से 60 प्रतिशत तक की राशि ही खर्च कर पाये, बाकी राशि खर्च नहीं कर पाये हैं और कई योजनाएं तो ऐसी हैं, आप नोट कर लें चाहे तो। जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्युअल स्कीम, इसमें तो मैं अभी संबंधित केन्द्रीय मंत्रीजी से मिला था। उन्होंने कहा राजस्थान ऐसा राज्य है जिन्होंने इसके लिये अभी तक कोई योजना ही नहीं भेजी है। हमारे पास करोड़ों रुपया पड़ा है, हम राजस्थान को देने के लिये तैयार हैं लेकिन आपकी सरकार की तरफ से कोई योजना इनके पास नहीं आयी है। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात पैसे ले जा चुके हैं इस योजना के लेकिन आपकी सरकार की तरफ से कोई इसमें योजना अभी प्रस्तुत नहीं की।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : कल्ला साहब, यह जवाहर लाल नेहरू अरबन इम्प्रूवमेंट की जो योजना है इसमें भी हमने केन्द्र सरकार को भेज दिया है।

श्री अध्यक्ष : आप तो सरकार से कहें सीधा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : दूसरी आप गलतबयानी यहां कर रहे हैं। बीकानेर रेलवे बाइपास की बात कर रहे हैं। आप खुद सक्षम नहीं हैं, आपकी केन्द्र में सरकार है। रेलवे ने कहा है कि आपकी फिजिबल नहीं है, रेलवे क्रासिंग है। रेलवे क्रासिंग में किसी प्रकार का कोई घटाव नहीं होगा। 24 से 25 बार रेलवे क्रासिंग बन्द होता है, वह उतनी ही बार होगा। इसलिये हम सोच रहे हैं और वहां की जनता भी चाहती है कि वहां एलीवेटेड रोड बन जाए, एक मात्र आप अड़े पड़े हो इसलिये वहां की जनता यह भुगत रही है वरना एलीवेटेड रोड़ आज से दो वर्ष पहले बन चुकी होती।

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है स्वायत्त शासन मंत्रीजी को मालूम ही नहीं है। केन्द्र सरकार ने यह लिखकर दिया है कि यह फिजिबल नहीं है तो आप इसको सदन की मेज पर रख दें, मैं मान जाऊंगा आपकी बात को। मेरे

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

सामने मुख्य मंत्रीजी ने इसी बजट सेशन में जनरल मैनेजर के साथ मीटिंग की थी उसमें फाइनेंस सेक्रेटरी, बड़े-बड़े विभागों के स्वायत्त शासन विभाग के सेक्रेटरी वगैरह प्रिंसीपल सेक्रेटरी वहां मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में यह बात कही थी कि यह तो हमारा काम है, हमारे अफसर हैं आपके मेमोरेंडम पर अंडर स्टैंडिंग कर लेंगे। मुझे लगता है स्वायत्त शासन मंत्रीजी यह पैसा कहीं झालावाड़ या कोटा सम्भाग में ले जाने वाले हैं और आपने जो एक करोड़ रुपया हमने अपने वक्त में जमा कराया था वह भी आप वापस लेने की चिट्ठी लगा चुके हैं। इसलिये मेरे पर आरोप लगाने से पहले अपने गिरेबान में झांककर देखें कि आपकी नीयत क्या है। और आप कृपा करके बीच में नहीं बोलें, जब मैं बोल लूं उसके बाद में अपना जवाब दे दें।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं ए.डी.बी. के मूल प्रोजेक्ट को तोड़ मरोड़कर रख दिया। कच्ची बस्तियों पर एक पैसा खर्च नहीं हुआ। कच्ची बस्तियों का कोई सुधार नहीं किया और कुल मिलाकर बरसों से जो समस्याएं मुंह बायें खड़ी थीं उन समस्याओं के समाधान के लिये सरकार ने कोई प्रयत्न नहीं किया। अब रहा सवाल आपने जवाहर लाल नेहरू अरबन रिन्युअल स्कीम के अन्तर्गत कोई स्कीम भेजी है तो कब भेजी है ? हम निकलवा कर ले आयेंगे। हम ऐसे लोग नहीं हैं जो राज्य के हित में काम नहीं करना चाहते। हम स्वयं केन्द्र के मंत्रियों से मिलकर इसको निकलवा कर लायेंगे। लेकिन आप जरा कापी तो दे दें हमको। आपने कब भेजी केन्द्र सरकार को ?

मैं आपके माध्यम से कुछ ऐसी संस्थाओं का जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनका जिक्र करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में लोकायुक्त का पद कितने समय से खाली है ? और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी उसको भरना चाहती हैं, या नहीं भरना चाहती हैं और भरेंगी तो कब तक ? लोकायुक्त का पद, कोई दूसरा ऐसा राज्य बता दें मुझे जहां लोकायुक्त का पद खाली है। आज राजस्थान का लोकायुक्त नहीं है, आज कोई भी बड़े पद पर बैठा हुआ व्यक्ति भ्रष्टाचार में लिप्त है तो राजस्थान की जनता जाकर किसको शिकायत करे ? लेकिन यह पद खाली पडा हुआ है लम्बे अरसे से खाली पडा हुआ है। कौन जिम्मेदार है इसका ? मैं समझता हूं कि इन प्रश्नों के बारे में पहले भी मैंने विधान सभा में एक प्रश्न उठाया था लेकिन मुझे अफसोस है कि यह सरकार कोई काम नहीं करती इस कारण से लोकायुक्त

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

जैसे महत्वपूर्ण पद को भी यह जान बूझकर नहीं भर रही है ताकि भ्रष्टाचार के मामले नहीं उठाये जाएं।

इसके अलावा राज्य सूचना आयुक्त का पद खाली पडा हुआ है, इसको क्यों नहीं भरा जा रहा है ? इसके अलावा आपके उर्दू अकादमी के अध्यक्ष का पद खाली पड़ा है। मानव अधिकार आयोग में जो दो पद खाली पड़े हैं उनको क्यों नहीं भर रहे हैं ? इन सब पदों को तत्काल भरने की आवश्यकता है।

अभिभाषण में यह भी कहा गया है कि औद्योगिक विकास राजस्थान में बहुत किया है। मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार थी जब राजस्थान में तब 1800 करोड़ का विनियोजन मंजूर हुआ था। मैं जानना चाहता हूं कि उसमें से कितना विनियोजन हुआ और कितना आपके वक्त में वापस चालू किया और आपने सवा दो साल में कौनसा नया विनियोजन किया ? उसके बारे में भी बतायें कि आपके आने के बाद इतना विनियोजन हुआ।

उसके बाद मैं यह जानना चाहता हूं कि आपने उद्योगों के माध्यम से कितने लोगों को रोजगार दिया ?

जहां तक आबकारी नीति का सवाल है राजस्थान में देशी शराब का उत्पादन गंगानगर शुगर मिल के माध्यम से होता था और यह गंगानगर शुगर मिल 20 से लेकर 25 करोड़ का लाभ प्रतिवर्ष मिलता था। इस गंगानगर शुगर मिल के 75 प्रतिशत काम को छीनकर निजी हाथों में दे दिया गया। और खास तौर से आदिवासी इलाकों में केन्द्र सरकार के निर्देश हैं कि जितना भी बन्दोबस्त का काम किया जाये वह पब्लिक सैक्टर की यूनिट से कराया जाये। वहां पर भी आज निजी हाथों में यह काम दे दिया गया। आदिवासियों को पहले की तुलना में दुगुनी दर पर शराब मिलती है।

और तो और, सूखा दिवस पांच थे, वह सूखा दिवस भी कम करके तीन कर दिये गये। और मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि निजी क्षेत्र में देने के पश्चात् सरकार की क्या मंशा है, इसकी पूरी की पूरी जांच करवायी जानी चाहिये और इसमें जो भी गड़बड़ हुई है वह सदन के सामने आनी चाहिये।

मैं इसके साथ-साथ आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे अनुसूचित जाति और जनजाति के भाई हमें सवेरे-सवेरे मिलते हैं कि हमारी जमीनों के ऊपर दीगर लोग कब्जा कर रहे हैं। इसके लिये मुख्य

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

मंत्रीजी, टास्क फोर्स बनायें और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लोगों के खेतों पर कब्जा होता है, मकानों पर कब्जा होता है उसको 15 दिन की अवधि के अन्दर खाली करके आप वापस उसका पजेशन दिलवाएं ताकि उन लोगों को यह भरोसा हो सके कि सरकार में हमारी सुनवाई हो रही है। नहीं तो ऐसा लगता है कि एक तरफ जो भू-माफिया लोग उनकी जमीनों पर कब्जा करते हैं। दूसरी ओर वहां पर जमीनों पर कब्जा होने के बाद सरकार भी परवाह नहीं करती है। जहां तक कानून और व्यवस्था की स्थिति का सवाल है। राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति पिछले सवा दो साल में बिगड़ी है। राज्य के कई जिलों की स्थिति तो यू.पी. और बिहार से बदतर हो गयी है। अपराधों का ग्राफ 7.83 प्रतिशत बढ़ गया है। मैं कुछ आंकड़े आपके सामने रखना चाहूंगा। पचास हजार अपराधी तो ऐसे हैं जो खुले घूम रहे हैं। हर सप्ताह एक डकैती, रोज तीन हत्याएं 1027 हत्याएं एक साल में, 2 लूट रोजाना, 511 लूट एक साल में, 3 बलात्कार 884 बलात्कार एक वर्ष में, 7 बलवा रोज, 2019 एक साल में, 15 नकबजनी एक दिन में और 4579 एक वर्ष में, 51 चोरियां प्रतिदन 15626 एक साल में। महिला अत्याचार, रोज एक दहेज हत्या एक वर्ष 318, हर रोज एक महिला की हत्या 86, महिला उत्पीड़न 17 घटनाएं रोज 5261, छेड़छाड़ के मामले 2223, 6 घंटे के बाद एक महिला पर अत्याचार ऐसी संख्या 1397 और यहां तक कि पाली के माननीय विधायक...(व्यवधान) एक मिनट, आप बाद में बोल लेना। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं प्रार्थना आपसे यह कर रहा हं कि 1999 से पूर्व के जो आंकड़े हैं उनसे इस आंकड़ों की तुलना करके अपने सामने रखकर के फिर बोलें कि क्या स्थिति है।

मोहम्मद माहिर आजाद : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय घनश्यामजी ने कहा था कि राज्य ने जो पैसे दिये हैं सर्व शिक्षा अभियान में वह इन्होंने बता दिये और केन्द्र ने जो दिया वो इन्होंने बता दिये। आपके समय में जो हो रहा है, वह यह बता रहे हैं हमारे टाइम की आप बता देना, इतना कष्ट आप करना न।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : इनको दे रखा है हमने।

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, अब तो यह आंकड़े भी नहीं आयेंगे। गृह मंत्रीजी ने एक सर्कूलर जारी कर दिया कि अपराधों की संख्या घटाओ। अपराधों की संख्या घटाने का मतलब है कि एफ.आई.आर. मत दर्ज

(श्री रामनारायण चौधरी)

करो। एफ.आई.आर. दर्ज नहीं करेंगे तो घट जायेगी। यही हो रहा है थानों के अन्दर कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की जा रही है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, पाली के माननीय विधायक हमारे साथी हैं, उनकी क्वालिस गाड़ी उनके घर के आगे से गुम हो गयी। मैं माननीय गृह मंत्रीजी से जानना चाहूंगा कि वह बरामद हो गयी।

श्री अध्यक्ष : किसके घर के आगे से ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : पाली के विधायक, उनकी क्वालिस गाड़ी गुम हो गयी, क्या वह आपने बरामद कर ली ? विधायकों की चोरियां ही बरामद नहीं होती हैं तो आम आदमी की क्या होती होंगी। एक महिला मेरे पास आयी कि मैं आई.जी. के पास गयी थी और उनको जाकर कहा कि मेरी चेन लूट गयी तो वह कहते हैं कि हमारे परिवार में भी ऐसी घटनाएं हो जाती हैं यह क्या चेन चोरी हो गयी यह तो आम बात हो गयी जैसे। इस चीज की फरियाद को तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। यह स्थिति है राजस्थान में कानून और व्यवस्था की। और तो और, मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस प्रदेश में स्टेट स्पोंर्स्ड टेरेरिजम हो रहा है। गलता पीठ पर गलता के रामोदराचार्यजी महाराज की डैथ के बाद उनके दसवीं के नहान का कार्यक्रम चल रहा था। वहां पर, अखिल शुक्ला और कई लोग वहां पहुंच गये। और जिस तरीके से पुलिस वहां आयी, और तो जगह पुलिस जहां अपराधी होते हैं वहां पहुंचती नहीं हैं। आठ-दस घंटे तक और यहां पर वह तत्काल 5 मिनट में पहुंच गयी। पुलिस ही नहीं पहुंची, पांच सौ आदमियों की टास्क फोर्स पहुंच गयी और वहां पर छावनी बना दिया। यह क्या कोई तरीका है। रामानुज संप्रदाय और रामानंद संपद्राय यह दो अलग-अलग संप्रदाय हैं। रामानुज संप्रदाय जो है उसकी यह गद्दी है वहां पर रामानंदियों को लाकर के बिठा दिया। यह एक स्टेट स्पोंर्स्ड टेरेरिज्म नहीं चलेगा। और जो अधिकारी इसमें लिप्त हैं वह क्या यह समझते हैं कि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो सकती है ? उनके खिलाफ भी कार्यवाही हो सकती है समय आने पर। लेकिन यह स्टेट स्पोंर्स्ड टेरेरिज्म जो फैलाया जा रहा है यह राजस्थान के हित में ठीक नहीं है। और इसमें हाई कोर्ट से स्टे दे रखा है उसके बावजूद भी सरकार की हिम्मत देखिये कि सरकार के अधिकारी खुलेआम वहां पर कब्जा करवा रहे हैं। यह मैं समझता हूं कि राजस्थान के इतिहास में काले अक्षरों में लिखा जायेगा कि सरकार ने इस प्रकार के काम किये हैं कि मंदिर पर कब्जा कराया है..(व्यवधान)

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : बीस अरब रूपये की संपत्ति बेची है उसकी भी जांच करायी जाये । 1993 से लेकर आज तक अरबों रूपये की संपत्ति बेच दी इन लोगों ने।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : हां, भंवरलालजी क्या कह रहे थे।

श्री भंवरलाल शर्मा : मेरे को कल्लाजी से भिड़ाओगे क्या ? ऐसा है दो संप्रदायों के महंतों का मामला है उनके गुणावगुण की चर्चा इस सदन में नहीं हो तो बहुत बढ़िया है।

श्री मोहन लाल गुप्ता : यह क्यों उठा रहे हैं इस मैटर को ? माननीय कल्लाजी, इस मैटर को क्यों उठा रहे हैं (व्यवधान) यह क्या फैमिली ट्रस्ट को अनुमति दे रहे हैं कि वह जमीनों को बेचे ? यह फैमिली ट्रस्ट है।

श्री रामनारायण चौधरी : नहीं कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, आप बिराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी : इसमें कानूनी कार्यवाही होने दें।

श्री मोहन लाल गुप्ता : क्या कल्लाजी इस बात के समर्थक हैं कि फैमिली ट्रस्ट को ही रहने दिया जाये, यह पारिवारिक गद्दी है...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : सरकार को इसमें पार्टी नहीं बनना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : दो परिवारों के झगड़े में आप भी क्यों पड़ रहे हो। (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : यह पारिवारिक गद्दी है, इस पारिवारिक गद्दी की जो संपत्ति है उसको बचाने का हक किसको है (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : दो परिवारों के झगड़े में आप भी क्यों पडें।

श्री कालीचरण सर्राफ : अध्यक्ष महोदय, यह गलता पीठ के बारे में यहां सदन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। गलता पीठ कोई पारिवारिक पीठ नहीं है। वहां रामोदराचार्यजी की डैथ हो गयी और उनके बेटे वहां पर बैठ जायें महंत के रूप में, क्या आप यह चाहते हैं ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप बिराजें।

श्री कालीचरण सर्राफ : नहीं, बिराजें क्या, आप गुमराह कर रहे हैं। आप सदन को गुमराह करने की कोशिश मत कीजिये...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसा है कोर्ट इंटरवीन करके उनको बुलायेगी तब आपको पता चलेगा...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह चलेगा तो चलेगा(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : आप चाहते हैं कि वह पारिवारिक गद्दी बन जाये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप बोले थे तो मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया था...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : आप पारिवारिक ट्रस्ट को बढ़ावा देना चाहते हैं क्या ?

श्री भंवरलाल शर्मा : अध्यक्ष महोदय, यह मामला बीजेपी और कांग्रेस का मामला नहीं है। यह दो संप्रदायों का मामला है। इसको पार्टी से संबंधित मामला नहीं बनायें।

श्री कालीचरण सर्राफ : पार्टी का सवाल ही नहीं है। यह पारिवारिक गद्दी को रिकोगनाइज कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप छोड़े इस बात को।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं तो इतना ही कहना चाहूंगा कि इस मामले में सरकार को पार्टी नहीं बनना चाहिए और जिस संप्रदाय की गद्दी है उसी का वारिस उसमें बनना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : वारिस क्यों बनेगा ?

श्री मोहन लाल गुप्ता : क्या बंशज, क्या कहना चाहते हैं आप वारिस, वंशज।

श्री जुबेर खान : यह कहना चाहते हैं कि जो हाई कोर्ट ने स्टे दे रखा है जब तक हाई कोर्ट कोई फैसला नहीं दे, सरकार उस पर पुलिस भेजकर छावनी नहीं बनायेगी।

श्री कालीचरण सर्राफ : आप फिर सदन को गुमराह कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : आप हाई कोर्ट के आदेश पालना करायें। यह नहीं होगा कि हाई कोर्ट के स्टे होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पुलिस के संरक्षण में वहां कब्जा करके छावनी बनायें। आतंक फैलायें यह बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।

श्री कालीचरण सर्राफ : आप सदन को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री जुबेर खान : आप हाई कोर्ट की अवहेलना कर रहे हैं।

श्री कालीचरण सर्राफ : आप सदन को गुमराह कर रहे हैं (व्यवधान)

श्री जुबेर खान : क्या हाई कोर्ट ने स्टे नहीं दिया हुआ है ? हाई कोर्ट ने जब स्टे दिया हुआ है तो सरकार को रिसीवर नियुक्त करने की क्या आवश्यकता पड़ गयी ? सरकार से जुड़े हुए संगठनों के लोगों के साथ पुलिस को जाने की क्या आवश्यकता पड़ गयी और दसवीं के कार्यक्रम के दिन वहां आतंक फैलाने की क्या आवश्यकता पड़ गयी ? सरकार बाद में भी कुछ कर सकती थी। आप इसको झूठलाइये मत जो सच्चाई है वह सच्चाई है। आप कह दीजिये कि हाई कोर्ट का स्टे है या नहीं है, आप बता दीजिये।

श्री कालीचरण सर्राफ : नहीं है, नहीं है, जुबेर खान जी, आप सदन को गुमराह कर रहे हैं।

श्री जुबेर खान : अध्यक्ष महोदय, आप रिकार्ड में ले आयें, माननीय जौहरी बाजार से आने वाले सदस्य ने कहा है कि हाई कोर्ट का स्टे नहीं है। मेरा यह दावा है कि हाई कोर्ट का यथास्थिति बनाये रखने का आदेश है। आप इसको दिखवा लीजिये।

श्री मोहन लाल गुप्ता : कोई स्टे नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप बिराजें।

प्रो. बीरूसिंह राठौड़ : तब थे, उनकी डैथ हो गयी...(व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता : आप इस बात को बढ़ावा देना चाहते हैं। वंशवादियों को, आपने कहा है, उनके वंश को गद्दी पर बिठाने के पक्ष में हैं क्या आप ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप बिराजिये। ऐसा है कि रामोदराचार्यजी ने अपने जीते हुए ही उनको अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया था ?

श्री ओम बिरला : राजस्थान के पांच करोड़ किसान और जनता की चिन्ता करें।

श्री मोहन लाल गुप्ता : अपने पुत्र का किया और उस पुत्र ने फैमिली ट्रस्ट बनाया तो क्या आप इस बात के समर्थक हैं कि फैमिली ट्रस्ट...(व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : 1996 में वैलिड पाया गया। हाई कोर्ट ने 1996 में उस ट्रस्ट को वैलिड पाया है।

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : कल्ला साहब, यह निर्णय उनके संप्रदाय की वारिस के आधार पर होता है। पारिवारिक नहीं होता है। संप्रदाय के लोगों ने गद्दी पर बैठाया है। वह वंश परम्परा इस संप्रदाय की है। उस हिसाब से कार्य किया है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप श्रीमाली होकर के यह कह रहे हैं कि रामानंदजी को रामानुजजी पर बैठा दिया जाये, यह क्या बात करते हो... (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : फिर आप एक अरब रूपये के राममाधव मंदिर को उस संप्रदाय से अलग दूसरों को देने को कैसे निकाल रहे हो ?

श्री लक्ष्मीनारायण दवे : आपने अपनी तत्कालीन सरकार के काल में कितने मंदिरों को किया है, आप तो बतायें अपना।

श्री मोहन लाल गुप्ता : हमने तो रिसीवर नियुक्त किया है, निर्णय को आने दो...(व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा : एक अरब रूपये की लागत का है वह उसको आप दूसरे ट्रस्ट को ट्रांसफर करना चाहते हो।

श्री कालीचरण सर्राफ : सरकार ने तो केवल रिसीवर नियुक्त किया है जिससे कि वहां कोई वातावरण खराब नहीं हो। तनाव पैदा नहीं हो, आपस में लड़ाई-झगड़े नहीं हो।

श्री महावीर प्रसाद जैन : यहां पर मंदिर-मस्जिद का मसला ना उठाया जाये तो ज्यादा अच्छा है।

श्री कालीचरण सर्राफ : आप यहां पारिवारिक ट्रस्ट बनाने का पक्ष लेकर के गलत लोगों का पक्ष ले रहे हैं।

श्री महावीर प्रसाद जैन : इन विषयों से बचना चाहिये।

श्री अध्यक्ष : बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य, वैसे भी आपको एक घण्टे से अधिक का समय हो गया है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : व्यवधान का समय बहुत रहा अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : एक घण्टे का ही समय था।

डा. बुलाकीदास कल्ला : व्यवधान कितना हुआ वह माइनस होगा।

श्री महावीर प्रसाद जैन (मुख्य सचेतक) : व्यवधान तो आप स्वयं आमंत्रित करते हैं।

श्री अध्यक्ष : सम अप कर दें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में सहरिया क्षेत्र में भूख से मौतों के मामले आए। मैं अभी एक जानकारी देना चाहता हूं और मेरे पास एक यह शपथ पत्र पड़ा है, आप चाहेंगे तो मैं सदन की टेबल पर

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

रखवा दूंगा। सहरिया क्षेत्र के अलावा भी, रकमेश्वर भील, उम्र 46 वर्ष, रेवदा, ग्राम पंचायत, सोडलपुर, पीपलखूंट।

श्री अध्यक्ष : कब का है, पिछले साल का तो नहीं?

डा. बुलाकीदास कल्ला : 19 फरवरी, 2006 का है, मैं सदन की टेबल पर रखता हूं। आप रखवा दीजिए। उसमें शपथपूर्वक उसकी पत्नी ने कहा है कि मेरा पति भूख से मरा है। इस घटना को रोकने के लिए सरकार क्या उपाय कर रही है ? (व्यवधान) मैं जो बात कहता हूं, तथ्य के आधार पर कहता हूं इसलिए मैंने सदन की टेबल पर रखा है।

श्री अध्यक्ष : शपथ पत्र 2006 में दिया होगा, लेकिन मरा कब वह भी तो इसमें होगा?

डा. बुलाकीदास कल्ला : 19 फरवरी का शपथ पत्र है और अभी का है, हाल ही का है।

श्री अध्यक्ष : पिछला भी दे सकते हैं, पिछले साल का भी दे सकते हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : नहीं, इसी साल का है, इसी साल का, आप दिखवा लें।

श्री भवानी सिंह राजावत (संसदीय सचिव) : कल्ला साहब, पीपलखूंट, बांसवाड़ा तो ऐसा एरिया ही नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं कहां कह रहा हूं कि सहरिया है। जैसे सहरिया आदिवासियों की मौत हुई है, पीपलखूंट में भी ऐसा हुआ है, यह कहा है मैंने। आपको पता तो है नहीं और आप जब सहरिया क्षेत्र में गए थे तो आपने भी लोगों को बहुत दबाया।

श्री भवानी सिंह राजावत : सहरिया क्षेत्र में सहरियाओं ने आपको घुसने नहीं दिया था, आपको याद हो तो ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : नहीं, नहीं, मैंने खुद सुना, मुझे एक विधवा ने कहा कि मेरे पास भवानी सिंहजी आए और बहुत दबाव डाला लेकिन हमने उनको यही कहा कि भूख से मरे हैं।

श्री भवानी सिंह राजावत : उसने कहा कि बी.डी. कल्ला साहब और अश्क अली टाक साहब ने आकर हमारे ऊपर दबाव डाला कि यह बोलो कि हम घास खा रहे हैं और भूख से मौत हो रही है, आपने भी यही कहा था।

डा. बुलाकीदास कल्ला : नहीं-नहीं, कभी भी दबाव नहीं डाला था।

श्री अध्यक्ष : बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य, शपथ पत्र तो घाटोल, बांसवाड़ा का है, आप कहां सहरियाओं की बात कर रहे हैं ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : नहीं-नहीं, आप पूरी बात तो सुनो। मैंने यह कहा है कि जैसे सहरिया आदिवासी भूख से मरे थे वैसा ही एक किस्सा और है। यह कहा है मैंने आप पूरी बात को गौर से सुनें। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (शिक्षा मंत्री) : उस औरत ने शपथ पत्र दिया है तो उसने अपने पति को भूख से क्यों मरने दिया, अपनी खुद की रोटी खिला देती ?

श्री मदन राठौड़ (सुमेरपुर) : उसकी पत्नी ने अपने पति को खाना क्यों नहीं दिया? वह खुद कैसे बच गई?

डा. बुलाकीदास कल्ला : वह भी भूख की शिकार है।

श्री मदन राठौड़ : वह तो मरी नहीं और वह मर गया, यह आपने लिखवाया है, आपने षड्यंत्रपूर्वक लिखवाया है यह एफेडेविट।

डा. बुलाकीदास कल्ला : इसकी जांच करवा लो यदि षड्यंत्रपूर्वक लिखवाया है तो, आपके पास सरकार है, आप जांच करवा लो। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत : पत्नी तो शपथ-पत्र दे रही है और पति भूख से मर रहा है ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, सरकार लैण्ड बैंक बना रही है। यह लैण्ड बैंक बनाने की इनको क्या जरूरत है ? लैण्ड बैंक से पहले मास्टर प्लान बना हुआ है, मास्टर प्लान के अनुसार सरकार को इम्प्रूवमेण्ट करने की आवश्यकता है। यह लैण्ड बैंक भ्रष्टाचार बैंक के रूप में साबित होगा और यह लैण्ड बैंक राजस्थान का कोई हित नहीं कर पाएगा, किसानों का अहित करेगा।

आज रतनजोत के नाम पर आप चारागाहों की भूमि को, गोचर भूमि को एक तरीके से पड़त भूमि को रतनजोत की खेती के लिए आबंटित करना चाहते हैं। मैं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि गोचर और जो भी चारागाह की भूमि है वह वर्षों से गांव में पड़ी हुई है और वह गांव की इकोनोमी का आधार है, इकोनोमी को आधार मानते हुए इस जमीन को बचाया जाए ताकि गांव के मवेशी जो आवारा हैं, या जिसके पास जमीन नहीं

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

है और जब खेती होती है तो उन लोगों को, जो खेत में एक तरीके से अपने पशुओं को चरा नहीं सकते, उनके लिए वह उपयोग में आ सके, इस जमीन को हमेशा के लिए रखना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष : पूरा तो शपथ पत्र पढ़कर सुना दो आप कम से कम।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप कह दो, पढ़ कर सुना देता हूं, लाओ।

श्री अध्यक्ष : सुनाओ, सुनाओ, देओ इनको।

डा. बुलाकीदास कल्ला : लाओ, सुना देता हूं। (व्यवधान)

श्री भवानी सिंह राजावत : सदन को गुमराह करने वाले की बात आनी चाहिए सदन में।

श्री अध्यक्ष : बीच में न बोलें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : श्रीमती गुलाबी, पत्नी रतनेश्वर भील, उम्र 45 वर्ष, निवासी रेणदा ग्राम पंचायत सोडलपुर, पंचायत समिति पीपलखूंट, तहसील घाटोल, जिला बांसवाड़ा की होकर शपथ पूर्वक कथन करती हूं।

श्री अध्यक्ष : हां, आगे पढ़ो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं शपथपूर्वक कथन करती हूं कि मेरा विवाह रतनेश्वर, पिता जीवा भील, निवासी रैणदा के संग हुआ है तथा मेरे व रतनेश्वर के पांच संताने पैदा हुई। जिसमें से बड़ी लड़की की शादी करा दी है।

श्री अध्यक्ष : हां, हां, ठीक है। आगे पढ़ो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं शपथपूर्वक बयान करती हूं कि मेरा पति रतनेश्वर जन्म से भक्तिभाव रखता था। भक्तिभाव है।

श्री अध्यक्ष : हां, हां, पढ़ो तो सही।

डा. बुलाकीदास कल्ला : तथा घर पर अनाज खतम हो गया था, थोड़े दिन इधर-उधर से काम चलाया पर बाद में पड़ौसियों ने भी अनाज की मदद करना बन्द कर दिया। जिस कारण मेरे पति अनाज के अभाव में अकाल भूख से दिनांक 8.2.6 को मर गए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आगे पढ़ते जाओ। सुनो सब शान्ति से।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं शपथपूर्वक कथन करती हूं कि मेरे पति को कोई बीमारी नहीं थी तथा वह स्वस्थ व्यक्ति था। मेरा पति भूखों रहकर मर गया। बच्चे शादी ब्याह में जाकर खाते थे।

श्री अध्यक्ष : पढ़िए तो पूरा।

डा. बुलाकीदास कल्ला : कभी दलिया भी स्कूल में जाकर खा लेते थे जिस कारण बच्चे बच गए। मैं मजदूरी करने बाहर गई हुई थी, एक बच्चा अहमदाबाद गया हुआ था जिसे भी सेठजी ने मजदूरी का भुगतान नहीं किया है। एक बच्चा भेड़ चराने वाले ले गए। शेष छोटे-छोटे बच्चे दूर-दूर गांवों में कोई रोटी खाता है, वहां गिड़गिड़ाते हैं जहां कोई रोटी का टुकड़ा कोई दे देता है खा लेते हैं। या शादी-ब्याह गांव में होता है वहां पर चले जाते हैं। वहां पर खाने को कुछ मिल जाता है तथा प्राइमरी स्कूल में पढ़ते हैं। जहां पर स्कूल में खाने को मिल जाता है जिससे जीवित है तथा मेरा पति भूख से मर गया है। यह लिखा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : वह दैवी तो बाहर गई हुई थी, उसे क्या पता कि कैसे मरा, कैसे मरा, वह तो बाहर गई हुई थी। (व्यवधान)

डा. बुलाकीदास कल्ला : इस विवाद में मैं थोड़े (व्यवधान) उसने शपथपूर्वक लिखा है। (व्यवधान) देखिए, उसने साफ लिखा है कि वह भूख से मर गया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : फंस गए कल्ला साहब आप। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (संसदीय सचिव) : कल्लाजी, आज झूठ का पर्दा खुल गया है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : भूख से मरा है, भूख से।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कल्लाजी, आज आप फंस गए।

श्री कनकमल कटारा : डूंगरपुर-बांसवाड़ा की बात कह रहे हैं। ऐसे भूख से कभी आदिवासी मरा भी नहीं है, न मरने वाला है, वह मेहनत करके कमाता है, कभी भीख भी नहीं मांगता, आज दिन तक। कोई सहरिया भूख से नहीं मरा है। मैं खुद वहां जाकर आया हूं, क्या बात करते हैं आप? (व्यवधान)

श्री हरिमोहन शर्मा (हिण्डौली) : माननीय अध्यक्षजी, आपने पढ़वाया तो इन्होंने पढ़ दिया, अब आप बताओ भूख से मरा कि नहीं ? वह एफेडेविट कैसे दे सकता है? आप करें फैसला।

श्री अध्यक्ष : उसकी पत्नी बाहर गई हुई थी, बाहर मजदूरी पर तो वह शपथपूर्वक नहीं कह सकती कि वह कैसे मरा है। भूख से मरा है या बीमारी से मरा है, वह तो बाहर गई हुई थी।

श्री हरिमोहन शर्मा : यह कहा है कि अनाज नहीं है, आप पढ़ो तो सही, आपने जो पढ़ा है उसके हिसाब से साफ है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : उसने कहा है कि वह बीमार नहीं था, भूख से मरा है, उसने कहा है साफ।

श्री कनकमल कटारा : मैं भी उसी क्षेत्र का निवासी हूं। कोई भी आदिवासी भूख से नहीं मरता। ऐसा कोई उदाहरण नहीं है जहां पर इस प्रकार से भूख से कोई आदमी मरा हो।

श्री हरिमोहन शर्मा : आपका इण्टरप्रिटेशन वास्तविकता के बिलकुल विपरीत है।

श्री कनकमल कटारा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आदिवासियों में कोई भीख नहीं मांगता, वह मेहनत करके खाता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया स्थान ग्रहण करें। (व्यवधान) सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य, स्थान ग्रहण कर लें, आप भी स्थान ग्रहण कर लें तो उपयुक्त होगा।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, वह मजदूरी करने के लिए इंग्लैण्ड तो गई नहीं थी, सऊदी अरब तो गई नहीं थी, उस गांव के आसपास कहीं गई तो पता नहीं चलता कि भूख से मरा कि भूख से नहीं करा। आपने पूरा तो पढ़वा लिया, चार जगह यह आ गया कि भूख से मरा है, बीमार नहीं था।

श्री अध्यक्ष : वह बाहर गई हुई थी। (व्यवधान) माननीय सदस्य, अब आप विराजे। वह भीलवाड़ा गई हुई थी मजदूरी करने के लिए, यह अख़बार कह रहा है, मजदूरी करने, अख़बार ने खुद ने भी माना है कि बाहर गई हुई थी।

डा. बुलाकीदास कल्ला : लेकिन उसने यह कहा है कि वह भूख से मरा है।

श्री ओम बिरला : वह माहिर साहब वह आपकी तरह तन्दुरुस्थ था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह बाहर गई हुई थी, उसने कहा है।

श्री प्रद्युम्न सिंह (राजाखेड़ा) : यदि पत्नी को पता नहीं होगा तो किसको पता होगा कि उसका पति कैसे मरा है। किसको पता होगा यदि पत्नी को पता नहीं होगा कि उसका पति कैसे मरा है, दुनिया के दूसरे लोगों को पता होगा। बड़े खेद की बात है कि आसन से इस प्रकार की टिप्पणी की जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : यह कोई खेद की बात नहीं है।

मोहम्मद माहिर आजाद : शपथ पत्र में यह तो मान रहे हो कि वह भीलवाड़ा गई थी और वह तीन जगह कह रही है कि उसका पति भूख से मरा उसको नहीं मान रहे, जो आपको अच्छा लग रहा है उसे तो मान रहे हो और जो खराब लग रहा है उसे नहीं मान रहे हो।

श्री ओम बिरला : भूख से व्यक्ति एक दिन में नहीं मरता। भूख से नहीं, कुपोषण होने के बाद धीरे-धीरे व्यक्ति मरता है।

डा. दिगम्बर सिंह (चिकित्सा मंत्री) : अगर वह तन्दुरुस्थ आदमी था तो एक दिन में नहीं मर सकता था। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आपका भूख से कोई लेना-देना नहीं है बिरलाजी।

श्री हरिमोहन शर्मा : शपथ पत्र में कहा है और शपथ पत्र में वरबेटम यह बात आई है कि वह भूख से मरा है। अब आपको कहना चाहिए कि शपथ पत्र में लिखा है वह ठीक है।

श्री अध्यक्ष : शपथ पत्र में है कि बाहर गई हुई थी भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में नौकरी कर रही थी।

श्री हरिमोहन शर्मा : भूख से मरना लिखा है।

श्री अध्यक्ष : अब उसे क्या पता कि कैसे मरा, उसका पति कैसे मरा।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, पत्नी को पता नहीं होगा तो किसको पता होगा? पत्नी कह रही है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : उसने लिखा है कि वह स्वस्थ है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : लौट कर आई होगी और लोगों ने बताया होगा कि भूख से मरा है, पत्नी को भी पता नहीं होगा तो किसको पता होगा। बड़े खेद की बात है, गलत इण्टरप्रिटेशन किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : राजाखेड़ा से आने वाले माननीय सदस्य, आदमी स्वस्थ है वह एकदम भूख से कैसे मरेगा ?

श्री अध्यक्ष : वह तो छोड़कर चली गई थी।

श्री महावीर प्रसाद जैन : अब आप मुझे बताओ, उसने कहा कि मेरा पति स्वस्थ था।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अध्यक्ष महोदय, अच्छा तो यह होता आप यह कहें

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

कि हम इसकी जांच कराएंगे, अगर ऐसा हुआ है तो ऐसा नहीं होगा। उसकी पत्नी कह रही है भूख से मरा है। बड़े खेद की बात है कि आपको इस प्रकार का इंटरप्रिटेशन नहीं करना चाहिए।

श्री महावीर प्रसाद जैन : ऐसे शपथ पत्र लिखवाकर लाना उचित नहीं है।

श्री कनकमल कटारा : मैं खुद गया था, साथ में मदनजी दिलावर, मंत्री गये और वहां जाकर बोले तो लोगों ने कहा कि कौन कह रहा है घास खा रहे हैं। कौन कहता है, हम उसको मारेंगे। इस तरह से उन्होंने बोला। इससे पहले गेहूं लाकर आपकी पार्टी वाले लोगों ने लाकर रख दिया। इस प्रकार का असत्य भाषण करना ठीक नहीं है। भूख से मरे, यह बिलकुल सरासर गलत है।

श्री हरिमोहन शर्मा : महिला अध्यक्ष और महिला मुख्यमंत्री उस महिला की बात को सच नहीं माने, यह समझ में नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : चलिए, आगे चलिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं लैण्ड बैंक की बात कर रहा था। इनको बनाना चाहिए था बिजली बैंक। आज राजस्थान में मिथेन गैस इतनी है कि 35 हजार मेगावाट बिजली पैदा कर सकते हैं। आज राजस्थान में इतना लिग्नाइट है कि 3500 मेगावाट बिजली पैदा हो सकती है, लेकिन सरकार बना रही है लैण्ड बैंक। प्रोपर्टी डीलर की तरह काम कर रही है सरकार। इसलिए प्रोपर्टी डीलर का काम छोड़कर सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित बैंक बनाना चाहिए ताकि राजस्थान का डवलपमेंट हो राजस्थान में बिजली, सिंचाई की व्यवस्था ज्यादा से ज्यादा बने और हमेशा के लिए अकाल से राजस्थान को मुक्ति मिल सके।

हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत विस्तार से सेज के बारे में बताया। मैं इसके बारे में कुछ तथ्य बताना चाहता हूं। अब तक हिन्दुस्तान में आठ स्पेशल इकोनोमिक जोन बने हैं और उनमें करीब-करीब डेढ़ लाख लोगों को रोजगार मिला है, लेकिन राजस्थान में सेज का जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें यह बताया गया है कि 14 हजार करोड़ का विनियोजन होगा। और यह भी बताया गया है कि इस सेज के मामले में राजस्थान में करीब दो लाख लोखों को रोजगार मिलेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि इसमें ऐसे कौन कौन से उद्योग लगाये जाएंगे जिनमें दो लाख लोगों को रोजगार मिलेगा। आठ सेज जो हिन्दुस्तान भर में बने हैं उनमें तो डेढ़ लाख लोगों को रोजगार मिला

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

है और आप यहां पर जो सेज बनाने जा रहे हैं उसमें आप दो लाख लोगों को रोजगार दे देंगे।

श्री अध्यक्ष : एक लाख।

डा. बुलाकीदास कल्ला : चलो, एक लाख लोगों को रोजगार कैसे दे देंगे ?

श्री हरिमोहन शर्मा : एक लाख लोगों को भी नहीं देंगे। कल ही मुझे जवाब दिया है हम अच्छी संख्या में रोजगार देंगे। संख्या नहीं बतायी।

श्री अध्यक्ष : आप बीच में व्यवधान न करें। आप बीच में व्यवधान न डालें। अपने ही सदस्य को बीच में खुद ही व्यवधान डालते हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगी छह बजे का समय मुख्य मंत्रीजी के जवाब का है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : बीच में व्यवधान करेंगे उसको जोड़ना पड़ेगा आपको।

श्री अमराराम (धोद) : यह हमारी जिम्मेदारी है क्या? यह हमारी ड्यूटी थोड़े ही है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि सेज के मामले में ..

श्री अध्यक्ष : आपकी पार्टी का समय तो समाप्त हो चुका है।

श्री महावीर प्रसाद जैन : समय समाप्त हुए तो बहुत समय हो गया।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, सेज के मामले में ट्रांसपेरेंसी नहीं अपनायी गयी। (व्यवधान) बस खतम कर रहा हूं, आपने छह बजे तक के लिए कहा है, छह बजे तक खतम कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष : दो और लोग बोल लें।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप विराजें। सेज के मामले में ट्रांसपेरेंसी नहीं अपनायी गयी। यह मैं नहीं कह रहा हूं, आपके शिक्षा मंत्रीजी और उद्योग मंत्री ने भी कहा कि सेज के मामले में ट्रांसपेरेंसी नहीं अपनायी गयी। मैं यह जानना चाहता हूं...

श्री अध्यक्ष : Please sum up now.

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं यह जानना चाहता हूं यदि ट्रांसपेरेंसी नहीं अपनायी गयी तो मुख्य मंत्रीजी ने उन मंत्रियों के खिलाफ क्या कार्यवाही की?

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

आज मंत्रिमण्डल में फूट है, मंत्रिमण्डल कैसे काम कर रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है।

श्री अध्यक्ष : आपके तो अच्छा है ना जो फूट है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मुख्य मंत्रीजी के ऊपर यदि यह आरोप है तो मुख्य मंत्रीजी को विचार करना चाहिए कि ट्रांसपेरेंसी का आरोप मंत्री इनके ऊपर लगा रहे हैं। और हम भी कह रहे हैं सेज के मामले में निश्चित रूप से टेण्डर इन्वाइज नहीं किये गये, पर्टीकुलर कम्पनी को क्यों सेज का काम दिया गया ?

श्री अध्यक्ष : अब आप प्लीज।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, मुझे समझ में नहीं आता आप मेरे फ्लो को रोक रहे हैं, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : आप मेरा प्रोटेक्शन तो चाहते हैं, लेकिन कितनी देर तक प्रोटेक्शन दूं, पांच घण्टे तक बोलने दूं आपको? आप एक घण्टा तीन मिनट बोल चुके हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप कृपा कर विराजें।

श्री अध्यक्ष : जब कि कांग्रेस पार्टी का इतना समय नहीं था।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं पांच-छह मिनट में सम-अप कर रहा हूं।

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, आपके फ्लो को तो आपकी पार्टी ने ही रोक लिया, पहले दो पद दिये और अब एक पर ले आये।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, सेज के मामले में हमारे नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने सरकार के लिए जुगाड़ कहा था।

श्री अध्यक्ष : यह तो कह दिया, दूसरा पाइंट लाओ।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं कह रहा हूं कि यह कबाड़ा सरकार है, इन्होंने भ्रष्टाचार किया है, इसकी सीबीआई से जांच होनी चाहिए। पूरा का पूरा सेज का मामला भ्रष्टाचार है। 3500 करोड़ का भ्रष्टाचार हुआ है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए और दूध का दूध और पानी का पानी होकर लोगों के सामने आना चाहिए।

श्री ओम बिरला : एक भी भ्रष्टाचार तो साबित करो सदन के पटल पर। माननीय सदस्य, भ्रष्टाचार की बात करने से पहले उसके प्रमाण से साबित करें। भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचारी तो आप हो।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप बैठिए। 1050 एकड़ जमीन जेडीए दे रहा है डीएलसी रेट पर। यह भ्रष्टाचार नहीं है डीएलसी रेट पर जमीन, जेडीए की जमीन जो 1050 एकड़ है वह जमीन क्यों दी जा रही है और यह काम रीको के माध्यम से क्यों नहीं कराया गया ? कांग्रेस ने भी जो सेज डवलप किये थे..

श्री कालीचरण सर्राफ : जीई केपिटल को 700 रुपये प्रति वर्गगज के हिसाब से आपने जमीन दी। वह तो भ्रष्टाचार नहीं था और हमने डीएलसी रेट पर जमीन दे दी वह भ्रष्टाचार है, कमाल कर रहे हैं आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपकी सरकार है, आप उस पर कार्यवाही क्यों नहीं करते ? आप विराजिए।

श्री कालीचरण सर्राफ : जीई केपिटल को 700 रुपये वर्ग गज पर जेएलएन मार्ग पर जमीन दी, उसमें आपको भ्रष्टाचार की बू नहीं आयी और अब डीएलसी रेट, जो कलक्टर की अध्यक्षता में कमेटी होती है वह डीएलसी रेट तय करती है। उसमें हमने जमीन दे दी तो वह भ्रष्टाचार हो गया ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : डीएलसी की रेट कौन तय करता है यह तो सारा सदन जानता है, लेकिन डीएलसी की रेट पर सेज के नाम पर जो जमीन दी गई है यह घोटाला है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए।

श्री मोहन लाल गुप्ता : अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं आठ राज्यों में जो सेज को जमीन दी है वह किस रेट पर दी है? आप बताएं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप किसानों को अपने दूध की कीमत नहीं देते। किसान को आज दूध की कीमत कांग्रेस राज से कम दी जा रही है। आज किसानों को पशु आहार महंगा दिया जा रहा है। किसानों की कोई परवाह नहीं है। सरकार केवल मात्र बड़े-बड़े लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रही है जो राजस्थान की जनता सहन नहीं करेगी। अभी आप नगाड़े और ढोल बजाकर टैक्स वसूल कर रहे हैं। जब चुनाव आएंगे तो लोग ढोल बजाकर आपका विरोध करेंगे, यह आप कान खोलकर सुन लें। इसलिए मैं कहना चाहता हूं-

"दिल की हर आरजू मिट्टी में मिला देती है,
तंगदस्ती हमें जीने की सज़ा देती है,
जीने देती है, न मरने की रजा देती है,

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

कैसी है यह भाजपा की हुकूमत जो हंस-हंसकर सज़ा देती है।"

आपने सवा दो साल में सज़ा देने के अलावा कोई काम नहीं किया।

श्री अध्यक्ष : शेर से समाप्त कर दिया। अब तो समाप्त कर दिया ?

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आप तो कृपा करो कम से कम।

श्री अध्यक्ष : शेर से समाप्त कर दिया आपने?

डा. बुलाकीदास कल्ला : ऐसे तो सामान्य सदस्य को भी कोई इस तरह से नहीं करता और आप फ्लो तोड़ रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आप कितनी देर बोलेंगे?

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैंने कहा मैं छह बजे खतम कर दूंगा अपना भाषण।

श्री अध्यक्ष : देखिए, 5-5 मिनट दो और पार्टीज को बोलने दीजिए।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैं बहुत जल्दी समाप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : आप एक घंटा 13 मिनट बोल चुके हैं। कांग्रेस पार्टी का समय समाप्त हो चुका है। मैंने 30 मिनट आपको और ज्यादा दे दिये हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (सरदारशहर) : अध्यक्ष महोदय, बार-बार आप कह रहे हैं कांग्रेस का समय समाप्त हो गया है। हम आशा लगाये बैठे हैं समय आ रहा है। हद कर दी आपने।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, आप मुझे समय नहीं दे रहे हैं, नहीं तो मैं बताता राजस्थान में किस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है। कोई नितिन सोमानी के केस को दबाने में लगा हुआ है।

श्री अध्यक्ष : अब तक क्यों नहीं बोल दिया ? भ्रष्टाचार की बात पहले करते ना आप।

डा. बुलाकीदास कल्ला : बोल रहा हूं, कर रहा हूं। भ्रष्टाचार की बात किससे करें ? लोकायुक्त का मामला होता तो लोकायुक्त में इन मामलों को ले जाते तो रोक लग जाती। लोकायुक्त का आफिस ही नहीं है यहां पर। आपको गवर्नमेंट को डाइरेक्शन देना चाहिए गवर्नमेंट लोकायुक्त का पद कब भर रही है ? ऐसे मामलों में जब बात कहते हैं, सत्य बड़ा कटु होता है, अप्रिय होता है, लेकिन उस सत्य के अन्दर अमृत होता है, इसलिए सत्य बात कहने के लिए हम यहां आये हैं और कहेंगे।

(डा. बुलाकीदास कल्ला)

मैं कहना चाहता हूं भ्रष्टाचारियों को संरक्षण सरकार दे रही है। खुले आम हर महकमे में लूट हो रही है। आज स्कूलों की स्थिति देखें तो वहां मास्टर नहीं। हास्पिटल में देखें तो डाक्टर नहीं। डिस्काम कम्पनी की देखें तो वहां पर जेईएन, एईएन नहीं।

श्री अध्यक्ष : Please now sum up.

डा. बुलाकीदास कल्ला : हालत यह है कि जलदाय विभाग के इंजीनियर्स काम नहीं कर रहे हैं, पेयजल की गम्भीर समस्या गांवों में है। इन सब कामों को देखते हुए सरकार ने अभिभाषण जो असत्य का पुलिन्दा है, इस असत्य के पुलिन्दे का मैं विरोध करता हूं। और जो-जो मुद्दे हमने उठाये हैं इन मामलों में, खासतौर से सेज के मामले की सीबीआई से जांच हो, लोकायुक्त की नियुक्ति हो, सूचना का जो राज्य स्तर का आयुक्त है उसकी नियुक्ति हो, मानवाधिकार आयोग के खाली पदों को भरा जाए, और किसानों की बिजली की

(समय : 18.00 बजे)

समस्या का हल किया जाए इन भावनाओं के साथ में जो प्रस्ताव प्रस्तुत किया उसका पुरजोर विरोध करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हमारे भी दो सदस्यों को समय दें।

श्री अध्यक्ष : प्लीज, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : समय हमारा देख लो न, बंटवारा आपने ही किया था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण कर लें।

श्री महावीर प्रसाद जैन : हमारी भी सुनवाई होती है, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : दो-दो मिनट में, फिर माननीय मुख्य मंत्रीजी को, देऊं ?

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, हमको कोई आपत्ति नहीं है लेकिन सदन के नेता की गरिमा में उनका भाषण सुनने के लिए प्रतिपक्ष बैठा रहना चाहता है। हमारे नेता ने, हमारे पी.सी.सी. के प्रेसीडेंट ने अपना वक्तव्य दे दिया और सदन के नेता महोदय ने सुना, हमको इसकी खुशी है और हम उन्हें धन्यवाद देना देते हैं। लेकिन अब आप और बुलाएंगे किसी को और फिर

(श्री रामनारायण चौधरी)

और बुलाएंगे, हमारे से इतना इन्तजार नहीं किया जाएगा। आप कृपा करके इनसे रिक्वेस्ट कर दें, हमारे सदन के नेता की गरिमा को रखने के लिए कुल बुलाते न ?

श्री अध्यक्ष : अब आप बिराजो।

श्री रामनारायण चौधरी : कल बुलाते न इनको ?

श्री महावीर प्रसाद जैन : थोड़ा श्री इन्तजार हमारे लिए भी कर लो।

श्री अध्यक्ष : जालमसिंहजी रावलोत, लेकिन आप तीन मिनट में अपनी बात कर लें।

डा. जालम सिंह रावलोत (शिव) : हां, मैं तीन मिनट में, मैं तो 30 मिनट की तैयारी करके आया था तीन मिनट में कैसे कन्क्लूड करूं ?

श्री अध्यक्ष : नहीं, आप तीन मिनट में बोलें।

डा. जालम सिंह रावलोत : ठीक है, मैं बजट पर बोल लूंगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय द्वारा इस पवित्र सदन में दिये गये अभिभाषण के पक्ष में माननीय एन.एस. गुर्जर द्वारा रखे गये प्रस्ताव के पुरजोर समर्थन के लिए मैं खड़ा हुआ हूं। इस अभिभाषण में स्पष्ट है कि हमारी यशस्वी मुख्यमंत्री के कार्यकाल में राजस्थान ने पिछले दो साल में सभी क्षेत्रों में प्रगति की है, विकास किया है। चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, चाहे सिंचाई का क्षेत्र हो, चाहे पेट्रोलियम और रिफाइनरी का क्षेत्र हो, सब क्षेत्रों में शानदार सफलता मिली है। उसी का परिणाम है कि दो साल की अवधि में राजस्थान में जो चुनाव हुए हैं, लोक सभा के चुनाव, नगरपालिका चुनाव, पिछले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में हमको शानदार सफलता मिली है। अभी कुछ समय पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी की जन सम्पर्क यात्रा में जो लाखों युवाओं, माताओं, बहनों की जो भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी वह इस बात का प्रतीक है कि हमारी यशस्वी मुख्य मंत्री के प्रति राजस्थान के हर वर्ग में, राजस्थान की हर ढाणी और गांव में जबरदस्त लोकप्रियता है, एक ही नाम चल रहा है वसुन्धरा वसुन्धरा। मैं इस पवित्र सदन के माध्यम से उनका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि जिस तरीके से पिछले दो सालों में आप राजस्थान को ऊंचाइयों तक उठाया है। आपके मन में नम्बर एक मुख्य मंत्री बनने की कल्पना नहीं रही है, आपके मन में हमेशा यह बात रही है कि राजस्थान न केवल विकसित राज्य बने बल्कि विकसित राज्यों में भी नम्बर एक पर कैसे आए।

(डा. जालम सिंह रावलोत)

मैं खास कर एक मिनट में बात फ्री करता हूं कि जब बाड़मेर और जैसलमेर जैसे पिछड़े क्षेत्रों में आपने विशेष ध्यान दिया उसके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, खास कर नर्मदा का पानी बाड़मेर जालोर को मिला, बाड़मेर लिफ्ट कैनाल और बालोतरा उण्ड लिफ्ट कैनाल के काम जल्दी पूरे हों, इसके लिए आप हमेशा प्रयत्न करती रही हैं और उनको जबरदस्त गति मिली है। मैं खास कर आपकी इस बात के लिए कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि राजस्थान में पिछले 50 साल से तेल की खोज का काम चल रहा था लेकिन आपके पग फेरे का परिणाम है कि ज्यों ही आपने राजस्थान के मुख्यमंत्री का पद सम्भाला राजस्थान में तेल मिला। और आपने न केवल तेल मिलने तक बात को सीमित रखा केन्द्र से हर हिसाब झगड़ा करके अपनी बात को प्रमुखता से रखकर राजस्थान से और खास कर के बाड़मेर में रिफाइनरी खोलने का निर्णय लिया उसके लिए आभार... (व्यवधान) मैं आधे मिनट में, खास कर एक निवेदन करना चाहता हूं कि पश्चिमी राजस्थान में और खास कर बाड़मेर जैसलमेर के पिछड़े जिलों के लिए सीमावर्ती क्षेत्र के विकास के लिए सीमावर्ती विकास बोर्ड की जो हम लम्बे समय से मांग कर रहे हैं, आपको इस बात की पूरी जानकारी है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप बजट प्रस्तुत करने वाली हैं 8 मार्च को आपके जन्मदिन के दिन राजस्थान के बाड़मेर जैसलमेर के लिए सीमावर्ती विकास बोर्ड का आप गठन करें ताकि यह पिछड़ा हुआ राजस्थान का क्षेत्र अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर जो स्थित है उसका सर्वांगीण विकास हो सके। एक बार पुनः धन्यवाद, आपने समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बहुत-बहुत धन्यवाद। श्री अमराराम धोद।

श्री फतेह सिंह : अध्यक्ष महोदय, हमको भी मौका देना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आपको दूंगी, बिराजो, पांच मिनट में अपनी बात कह दें।

श्री अमराराम (धोद) : श्री अध्यक्ष, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो धन्यवाद प्रस्ताव टोडारायसिंहनगर से आने वाले माननीय सदस्य ने रखा है, जहां सत्ता पक्ष की ओर से बड़ी वाहवाही ली जा रही है कि राजस्थान में दो साल में राजस्थान सरकार ने कोई समस्या नाम की चीज नहीं छोड़ी है। लेकिन यह भी कटु सत्य है कि राजस्थान में पिछले दो साल में भारतीय जनता पार्टी के शासन में पानी मांगने वाले 11 किसानों का खून करने का रिकार्ड भी राजस्थान की सरकार ने बनाया है, जिन्होंने केवल मात्र पानी

(श्री अमराराम (धोद)

मांगा था। चाहे वह रावला-धड़साना हो, चाहे वह सोयला हो, उन्होंने पानी मांगा था और आपके चुनावी वायदे परिवर्तन के वायदों के अनुसार, मांगा था कि आप हमें वोट दो हम आपको पानी देंगे।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ (कुम्भलगढ़) : पानी कभी दिया था क्या ? आप बताइए जितना हमने दिया कभी आज तक मिला था क्या ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में व्यवधान नहीं डालें।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से अमरारामजी से एक निवेदन करूंगा कि आप जो बार-बार गिनवा रहे हैं कि किसानों का खून बहा है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, बीच में व्यवधान नहीं डालें।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : खून किसने बहाया ?

श्री अमराराम (धोद) : आप तो अपना देख लो पहले। अभी जेल में जाकर आए हो। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : मेरी परवाह मत करो आप, चाहे मेरा खून चला जाए, चाहे मेरा शरीर चला जाए, मैं जहां हूं वहीं रहूंगा, चिन्ता मत करो।

श्री अध्यक्ष : गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य, (व्यवधान) आप बीच में व्यवधान करेंगे तो वह पांच मिनट के बजाय सात मिनट लेंगे क्योंकि एक मिनट निकाल दिया आपने उनका। अब आप बीच में नहीं बोलें। कोई माननीय सदस्य व्यवधान नहीं डालें।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि राजस्थान की सरकार, जो वर्तमान सरकार है, चाहे पूर्ववर्ती सरकारें हों, राजस्थान के हित में जो राजस्थान में सबसे कम पानी है, सबसे ज्यादा क्षेत्रफल है उस पानी का उपयोग करने की प्राथमिकता हमारी नहीं रही हैं, हमारी प्राथमिकताएं और ही रही हैं। न हमारे पानी जो हमारा स्थायी जल, चाहे वह पड़ोसी राज्यों से लेने की स्थिति हो, मैं निश्चित रूप से कहना चाहूंगा कि पिछले बजट सत्र में सर्वसम्मति से इस हाउस में प्रस्ताव पास करके सरकार को इस बात के लिए अधिकार दिया था कि पंजाब से हमारे हिस्से का .8 एमएफ पानी लेने के लिए राजस्थान की सरकार जो भी करेगी, राजस्थान के हित के लिए, यह हाउस सम्पूर्ण मिलकर सरकार के साथ है। पंजाब से निश्चित रूप से, पंजाब के

(श्री अमराराम (धोद)

मुख्यमंत्री ने बयान भी दिया लेकिन अफसोस है कि आज तक एक साल बीतने के बाद भी हमारे हिस्से का पानी आज तक राजस्थान की सरकार न पंजाब से ले पाई है न हमारी प्राथमिकताएं हैं। सबसे पहले हमें राजस्थान को विकसित करना है तो राजस्थान के हिस्से का पानी 56 साल की आजादी के बाद हमारी सरकार की, राजस्थान की स्थिति यह रही है कि आज भी हम हमारे सरफेस वाटर का 52 प्रतिशत उपयोग कर पाये हैं। यह हमारी प्राथमिकताएं रही हैं। जहां पीने के पानी को उपयोग में लेना था सिंचाई दूसरा फेज था लेकिन इसकी निगाह नहीं करके हम केवल वोट किस तरह से हमको हासिल हो सकते हैं, किसान की राजस्थान के 75 प्रतिशत जनता की, पेयजल की कृषि की उनकी कोई चिन्ता नहीं है।

दूसरा, अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सरसों जो हिन्दुस्तान का 45 प्रतिशत उत्पादन होता है, और पिछले 10 साल से जिन आर्थिक नीतियों के चलते राजस्थान के किसान का हज़ारों करोड़ रुपये का नुकसान हर साल जो पूरे देश का 45 प्रतिशत सरसों अकेले राजस्थान पैदा करता है और जिससे आयात जो खाद्यान्न तेल आयात होता है उस पर टैक्स नहीं बढ़े। मैं समझता हूं कि पूरे सदन की यह जिम्मेदारी है न सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष बल्कि जिसमें राजस्थान पूरे देश के लिए 45 से 50 प्रतिशत खाद्यान्न तेल के रूप में सरसों और दूसरे सोयाबीन मूंगफली जो पैदा करते हैं और जिस आयात को फ्री करके बाहर से तेल आने से जिस पर टैक्स लगाकर हमारे पूरे राजस्थान के जनप्रतिनिधि अगर हम चाहते हैं कि किसान का हित होगा। राजस्थान की सरकार और केन्द्र सरकार के पैसे से पिछली बार समर्थन मूल्य पर खरीदा गया, इस साल भी खरीदा जाएगा। लेकिन यह समस्या ही हट जाए, हजारों करोड़ का समर्थन मूल्य पर खरीदने का मतलब है कि किसान को लागत मूल्य भी आज की तारीख में नहीं मिले। और वह फसल है जो राजस्थान के हित में सबसे कम पानी में सबसे ज्यादा फसल पैदा हो सकती है। इसलिए मेरा तो आपके माध्यम से निवेदन है कि सरकार न केवल सरकार और प्रतिपक्ष के रूप में सोचे बल्कि राजस्थान में किसान जो कम पानी में ज्यादा पैदावार सरसों के रूप में करता है उसको किसी तरह से हम उचित मूल्य दिलाकर राजस्थान के विकास में भागीदार हो सकते हैं, मैं समझता हूं कि इस काम के लिए सम्पूर्ण सदन मिलकर के भी केन्द्र सरकार पर इस बात का दबाव डालें तो अच्छा हो। दूसरे राज्य अपने राज्य के किसान को बचाने के

(श्री अमराराम (धोद)

लिए, उसको कीमत दिलाने के लिए सब दल मिलकर कर सकते हैं तो मैं समझता हूं कि राजस्थान का किसान भी कर सकता है। लेकिन हालत यह है, हमारे मुख्य मंत्रीजी ने, जब सरसों की फसल जो अगेती फसल थी, वह शत-प्रतिशत नष्ट हो गई, आपने बयान दिया कि गिरदावरी होगी, निश्चित रूप से गिरदावरी हुई। लेकिन केन्द्र सरकार के पास शायद आपने प्रस्ताव भेजा और केन्द्र सरकार ने कह दिया कि शीत लहर से फसल नष्ट होना प्राकृतिक आपदा में नहीं आता और हम उसको नहीं देंगे। आज क्या हालत है, अध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने अगर आप इजाजत दें तो, यह हालत है कि यह जो अगेती फसल थी, एक भी दाना सरकार का कोई भी मंत्री साबुत दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा। उसकी पूरी साल की फसल चौपट हो गई। उसको एक भी नया पैसा अगर हम मदद के रूप में नहीं दे पायें तो जो वायदे हमने परिवर्तन यात्रा के माध्यम से किसान से किये थे कि किसी भी रूप में अगर फसल का नुकसान होगा तो सरकार उसकी मदद करेगी। पूरी भरपाई नहीं कर सकती, कोई सरकार नहीं कर सकती लेकिन उसको मदद के रूप में....

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : तारामीरा है।

श्री अमराराम (धोद) : तारामीरा देखा है क्या आपने ? आप तो अफीम देखो और मजे करो।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : बोया हुआ है।

श्री अमराराम (धोद) : और जो आपके विरोध में राजनीति में आये उन पर हमला कराओ। (व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर : ऐसा है, मेरी चिन्ता मत करो, मेरे खिलाफ तो एफआईआर करवाने में आप भी मौजूद थे, बीजेपी, कांग्रेस, सारे के सारे मौजूद थे इसलिए मेरे को कोई परवाह नहीं है।

श्री अध्यक्ष : यह तो गेहूं या जौ दिखाई दे रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : इनको गेहूं ही दिखाई देंगे अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : मैं कह रही हूं, गेहूं या जौ दिखाई दे रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : तो आप इजाजत दें तो मैं टेबिल पर रख दूं।

श्री अध्यक्ष : क्या है यह ? सरसों है ? इतनी छोटी कैसे है ? ऊपर का हिस्सा है। विराजो आप, बाद में करना परीक्षण।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, बिजली की बातें भी बहुत हो रही हैं लेकिन जब तक राजस्थान में बिजली के मामले में हम आत्म निर्भर नहीं होंगे, न हम खेती का विकास कर सकते हैं, न हम उद्योग का विकास कर सकते हैं। मैंने पहले भाषण सुना है, अभी हमारे वर्तमान शिक्षा मंत्रीजी 1993 से 1998 तक कहते थे कि एक किलोमीटर की चिमनी लगेगी और राजस्थान के बाहर पाकिस्तान में हम बिजली दे देंगे। पांच साल में कांग्रेस के शासन में भी सुने लेकिन जब तक जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जब तक हम उन पर बिजली बनाने के बारे में नहीं सोचेंगे और राजस्थान को बिजली के मामले में आत्म निर्भर नहीं बनायेंगे, आज राजस्थान की सरकार ने जो भी घोषणाएं की थीं, मैं समझता हूं, सब की सब फेल हो गई। 72 घंटे में ट्रांसफार्मर देना, 120 दिन में कनेक्शन देना, तीन साल में तमाम किसानों को अप-टू-डेट तक हम कनेक्शन दे देंगे, क्या हालत है ? 120 दिन की बजाय एक-एक साल से हो रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

आज भी राजस्थान के किसान को जिस तरह विजिलैंस के नाम पर लूटा जा रहा है, मैं समझता हूं पिछले एक महीने में निश्चित रूप से बिजली बढ़ी है। लोग जब सड़कों पर उतरे, निश्चित रूप से 6 घंटे के प्रयास कर रहे हैं। इस बात के लिए तो सरकार को मैं धन्यवाद दूंगा लेकिन एक महीने बिजली नहीं देकर फसल में 25 प्रतिशत का जो नुकसान न केवल इस रबी की फसल में कर दिया बल्कि खरीफ की फसल में बिजली नहीं देकर सैकड़ों करोड़ का राजस्थान के किसान का नुकसान सरकार के वायदे के बाद में हुआ है।

इसलिए अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है, जहां सेज की बात हो रही है, राजस्थान का औद्योगिक विकास हो, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। लेकिन औद्योगिक विकास राजस्थान के किसान की कीमत पर हो, यह कतई राजस्थान का किसान बर्दाश्त नहीं करेगा। जयपुर का जेडीए राजस्थान के अमीर आदमी को 43 लाख रुपये प्रति बीघा के हिसाब से फार्म हाउस के लिए जमीन देगा और किसान से केवल डीएलसी रेट से जमीन लेगा। राजस्थान में विकास करें, सेज लाना है और सेज लाइये, हमें इससे कोई एतराज नहीं है। लेकिन राजस्थान के किसान की कीमत पर अगर विकास होगा तो यह राजस्थान का किसान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो बाजार रेट है...

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद।

श्री अमराराम (धोद) : जब वो 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश करेगा तो एक हजार करोड़ रुपये जो बाजार की कीमत है वो राजस्थान के उस किसान को, जिसकी पीढ़ियों से वह है उसको क्यों नहीं देगा ? जब 10 हजार करोड़ रुपये का निवेश होगा तो 11 हजार करोड़ का निवेश होगा। दूसरे भी बहुत से हैं, ओमेक्स कम्पनी आई है जो बाजार कीमत पर खरीद कर विकास कर रही है।

श्री अध्यक्ष : प्लीज, समाप्त करें।

श्री अमराराम (धोद) : महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा कम्पनी, इसलिए मेरा तो आपके माध्यम से इतना ही निवेदन है कि राजस्थान में जहां शिक्षा की बात कर रहे हैं, शिक्षा में जितने भी स्कूल खुले हैं....

श्री अध्यक्ष : आपने अपनी महत्वपूर्ण बातें कह दी हैं। शिक्षा के बारे में बहुत लोग कह चुके।

श्री अमराराम (धोद) : एक ही मिनट। अध्यक्ष महोदय, वह कहूंगा जो किसी ने नहीं कही। सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष ने वो बात कही है...

श्री अध्यक्ष : समय तो समाप्त हो गया आपका। (व्यवधान) 10 मिनट ले लिये हैं आपने।

श्री अमराराम (धोद) : हमने यह घोटाला किया, आपने यह घोटाला किया है... (व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता : माननीय अध्यक्ष महोदय, सेज में किसान स्वेच्छा से जमीन दे रहे हैं, 25 प्रतिशत मुआवजा मिल रहा है उनको।

श्री अध्यक्ष : 10 मिनट ले लिया है समय आपने।

श्री मोहन लाल गुप्ता : उनको एक करोड़ रुपये बीघा का भाव मिलेगा। आप किसान की बात कर रहे हैं, किसानों का तो हित हो रहा है, किसान तो चाह रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : 50 लाख रुपये आज बीघा के भाव हैं। (व्यवधान) आपकी सरकार में हिम्मत है तो घनश्यामजी की अध्यक्षता में एक सदन की कमेटी बना दीजिये, जांच हो जाएगी। 50 लाख रुपये बीघा का... (व्यवधान) एक करोड़ मिलेगा, आसान हो जाएगा।

श्री मोहन लाल गुप्ता : किसानों का कोई नुकसान नहीं हो रहा है इसमें। जेडीए को अपने आप किसान जमीन दे रहे हैं।

श्री अमराराम (धोद) : 20 बीघा में से डेढ़ बीघा मिलेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौड़ : .... कितनी गिरवी रख दिये अमरीका को आपने ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आपने दुगुना समय ले लिया। कृपया समाप्त करें अब आप।

श्री अमराराम (धोद) : जहां शिक्षा की बड़ी बात की जा रही है, एक मिनट में समाप्त कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष : 10 मिनट तो ले चुके आप।

श्री अमराराम (धोद) : अध्यक्ष महोदय, जहां शिक्षा की बात की जा रही है, मेरा आपके माध्यम से एक तो यह निवेदन है कि जिस तरह से प्रधान मंत्री सड़क योजना में...

श्री अध्यक्ष : अब आप शिक्षा की करते-करते सड़क पर आ गये।

श्री अमराराम (धोद) : मैं तो यह कह रहा हूं कि जिस तरह नीति बनाई है, आज तक जो राजस्थान में जिस तरह स्कूल खोलने का क्रम रहा है वह कोई भी मापदण्ड नहीं रहा, वह राजनीति के आधार पर स्कूलें खोली जाती हैं। एक ग्राम पंचायत में दो-दो सीनियर सैकण्डरी स्कूल, और एक जो पांच हजार की आबादी है वहां मिडल स्कूल नहीं है। तो निश्चित रूप से अगर हम राजनीति केवल स्कूलों के माध्यम से, कर्मचारियों के माध्यम से, और आज मैं कह सकता हूं कि राजस्थान के सैकण्डरी और सीनियर सैकण्डरी जितनी भी ग्रामीण स्कूलें हैं, सबसे बड़ा नुकसान तो जो खाली पद रहते हैं, चाहे वो

(समय-समाप्ति-सूचक-घंटी)

चिकित्सा में हैं, चाहे शिक्षा में हैं, वह राजस्थान के 40 हजार गांवों को भोगना पड़ता है। और ये खाली पद इसलिए रखे जाते हैं कि राजस्थान का किसान और ग्रामीण जो गांव में बसता है....

श्री अध्यक्ष : अब आप कृपया स्थान ग्रहण करें।

श्री अमराराम (धोद) : उसकी चिकित्सा और शिक्षा का फायदा नहीं उठा सके इसलिए कोई भी रिक्त पद रहने का मतलब यह है कि कोई भी क्राइटेरिया के अनुसार नहीं खोलकर...

श्री अध्यक्ष : अब आप कृपया स्थान ग्रहण करें, बात समाप्त करें।

श्री अमराराम (धोद) : मैं समझता हूं कि यह राजस्थान की आम जनता के साथ हित नहीं हो रहा है। इसलिए मैं इस अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का पुरजोर शब्दों में विरोध करता हूं कि राजस्थान की जनता के साथ न्याय किया जाए और अपने वायदों के अनुसार किसान को हक दिया जाए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। श्री फतेह सिंह। पांच मिनट का समय है।

श्री फतेह सिंह (कुशलगढ़) : अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय का अभिभाषण जो यहां पर पेश हुआ है और उसका समर्थन माननीय सदस्य के द्वारा किया गया उस पर वाद-विवाद हो रहा है। मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि राज्यपाल के अभिभाषण के अन्दर जो बातें दर्शायी गई हैं वो एक अगली कड़ी है। और यह भी बातें दर्शायी गई हैं कि पिछली सरकार ने किस तरह से काम किया है, यह सारी बातें इसमें ली गई हैं। इस वाद-विवाद में एक बात उभर करके सामने आई है कि प्रदेश का विकास किस रूप में करना है उसके बनिस्बत यहां पर मैंने यह देखा है कि एक-दूसरे का विरोध करना, इस सरकार ने यह किया, पिछली सरकार ने यह किया, इससे तो कोई समस्या का हल हो नहीं सकता। लेकिन मेरा मानना है कि ऐसी कोई समस्या हो प्रदेश के अन्दर तो पक्ष और विपक्ष मिल-बैठ करके किसी काम की तैयारी करें तो मेरे खयाल से किसी तरह की कोई बात कठिन नहीं है।

अभी सभी माननीय सदस्यों ने सरकार की वाह-वाही की। मैं भी उनको धन्यवाद देना चाहूंगा कि शिक्षा में, गृह विभाग में, मुख्य मंत्रीजी ने या विद्युत मंत्रीजी ने जिस तरह से यहां पर जो काम किये हैं, ढ़ाई साल में या सवा दो साल में, उसकी तो सराहना सब लोग कर ही रहे हैं। लेकिन साथ-साथ कुछ एरिया ऐसा भी है, मेरा यह मानना है कि प्रदेश का कुछ हिस्सा ऐसा भी है जिस इलाके के लिए कोई नहीं बोल रहा है। आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा के बारे में ऊपरी मन से कुछ लोग जरूर कहते हैं, एस.टी., एस.टी. के बारे में कि वहां विकास की कमी है। मैं इस मौके पर यह कहना चाहूंगा कि बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में सिंचाई का अभाव है। मैं इस मौके पर मुख्य मंत्री महोदय से भी यह निवेदन करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा में माही बजाज सागर परियोजना बनी हुई है। माही बांध से गुजरात को पानी दिया जा रहा है और राजस्थान के अन्दर जो अपने हिस्से का पानी मिल रहा है पर अभी नर्बदा

(श्री फतेह सिंह)

योजना का पानी गुजरात को मिलने जा रहा है। अगर उस पानी को रोका जाये और गुजरात को नहीं देकर के राजस्थान के हिस्से का पानी जो बांसवाड़ा जिले का है, आपका नोन कमांड एरिया घाटोल, दानपुर, कुशलगढ़, सज्जनगढ़, गांगनतलाई और बागीडोरा एरिया का नोन कमांड एरिया है, वह पानी गुजरात को नहीं देकर अगर वहां उस इलाके को दिया जाये। लिफ्ट से या सुरंग से, किसी भी तरीके से अगर उस इलाके को दिया जायेगा तो वहां के आदिवासी जो गुजरात में जाते हैं, बीमार होते हैं, मरते हैं और मुसीबत में फंसते हैं, वह उनको लाभ मिलेगा। तो मेरी मांग है सरकार से, समय कम है इसलिए मैं शोर्ट में कहना चाहता हूं। मेरी मांग सरकार से यह है कि बांसवाड़ा में माही बांध का जो पानी है, वह बांसवाड़ा जिले के नोन कमांड एरिया है, मैंने अभी जो आपके सामने बताया है, उन इलाके को दिया जाये, यह मेरी एक मांग है।

दूसरा मेरा निवेदन यह करना था कि इस साल बारिश लगातार होती रही, एक माह बारिश रुक गई। राजस्थान प्रदेश में और जगह बारिश ज्यादा हुआ होगा, कहीं कम हुआ होगा। लेकिन बांसवाड़ा के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि बारिश समय पर हुई, काश्तकारों ने फसलें बोई, फसलें बोने के बाद में एक माह तक लगातार बारिश रुक गई, रुकने के बाद में वह फसलें सूख गई, फिर बारिश आई, बारिश आने के बाद में वह वापस पनपी नहीं। तो वहां पर जो गिरदावरी हुई है, 60 प्रतिशत से 69 प्रतिशत तक के आंकड़े उसकी गिरदावरी में आये हैं और सरकार ने अभी तक बांसवाड़ा जिले को अकाल से घोषित नहीं किया है, वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है। सिर्फ यह बात चालू की गई है कि भारत सरकार की राष्ट्रीय गारन्टी रोजगार योजना के तहत इस जिले को हम काम देंगे। रजिस्ट्रेशन करा लिया गया, जोब कार्ड दे दिया गया, उसके बाद भी वहां के लोगों को अभी तक काम नहीं मिला है। इस सम्बन्ध में मुझे यह कहना है, गारन्टी रोजगार योजना का जो कानून बना है उसमें भारत सरकार राजस्थान सरकार को बजट देगी, पैसा देगी और वह काम देंगे और 100 दिन काम देने का उन्होंने वादा किया है। लेकिन फिलहाल इस मौके पर अकाल पड़ा हुआ है, चारे की कमी आयेगी, अनाज की कमी आयेगी, गरीब लोगों को जो सहायता दी जा रही है, वह भी एक जरूरत पड़ेगी, रोजगार की जरूरत पड़ेगी। और एक परिवार में से एक व्यक्ति को रोजगार देने वाली बात चली रोजगार गारन्टी योजना में तो बाकी लोगों का हाल क्या होगा? मैं इस

(श्री फतेह सिंह)

मौके पर मुख्य मंत्री महोदया, आपसे भी निवेदन करना चाहूंगा, बांसवाड़ा जिले के लोग खेती के ऊपर निर्भर है, किसान मजदूर हैं, बाहर जाकर मजदूरी करते हैं और उससे भी पूरा नहीं पड़ता है। और अकाल जैसी स्थिति में अगर आप अकाल की घोषणा नहीं करेंगे, वहां के लोगों को रोजगार नहीं देंगे, चारा, पानी और खाद्यान्न की व्यवस्था नहीं करेंगे तो वहां के लोग कहां जायेंगे ? यह तो स्थिति बिगड़ेगी और वहां के आदिवासी लोग गुफा-तीर-तलवार और सब तरह के हथियार वे लोग रखते हैं। वे लोग जंगलों में रहने वाले हैं, वे आन्दोलन खड़ा करेंगे तो प्रशासन से वह नहीं सम्भलेगा। इसीलिए समय रहते मेरा आपसे निवेदन करना है कि उस इलाके को भी, आप बांसवाड़ा जिले को भी अकाल घोषित कर, अकाल में मानकर, उस इलाके में राहत कार्य चालू करें और चारा-पानी की व्यवस्था करें, खाद्यान्न की व्यवस्था करें। क्योंकि पिछली बार काम चले थे, वहां के लोगों को काफी गेहूं मिला था, रोजगार मिला था। और इस साल गेहूं की मात्रा भी कम है, गेहूं आ नहीं रहा है, लोग इधर-उधर भटक रहे हैं, महंगे भाव से गेहूं ले रहे हैं तो मेरा यह मानना है कि गेहूं राजस्थान सरकार, भारत सरकार से लेवे या कहीं से भी लेवे, जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की होती है। तो खाद्यान्न की भी व्यवस्था इनकी करें।

दूसरा, मुझे यह कहना है कि शिक्षा का स्तर बढ़ाने के लिए एक साक्षरता अभियान चला, उसके बाद में वातावरण बना, लोगों ने लड़कों के एडमिशन कराये। प्राइमरी स्कूल खुली, मिडल स्कूल खुली, उसके बाद में सीनियर सैकण्डरी स्कूल खुली, सैकण्डरी स्कूल खुली, कालेज और आवास विद्यालय खुला। और इतनी बड़ी भीड़ होने के बाद में भी, मैं कुशलगढ़ का उदाहरण देना चाहूंगा, एक ही पंचायत समिति में, कुशलगढ़ पंचायत समिति में 250 अध्यापकों की कमी है। पूरे बांसवाड़ा जिले में अध्यापकों की इतनी कमी नहीं है जितनी कुशलगढ़ के अन्दर कमी है। इसका कारण क्या हो सकता है ? आपने इतनी सारी पोस्टें भरी, उसके बाद भी कुशलगढ़ क्षेत्र को आपने छोड़ दिया। वहां पर 264 पोस्टें वेकेंट हैं। आपकी प्राइमरी स्कूल में और राजीव गांधी पाठशाला खुली थी वह प्राइमरी में कन्वर्ट हुई। जहां पर डबल मास्टर थे, वहां से एक-एक अध्यापक को राजीव गांधी पाठशाला में लगाया गया। दूसरी राजीव गांधी पाठशाला थी उसमें जो लड़के बी.ए. बी.एड. थे, एस.टी.सी. थे, उन लोगों को आर.पी.एस.सी. में बैठाया, उनका सलेक्शन हो गया, दूसरे जिले में भेज दिया गया। वह राजीव गांधी पाठशाला आज खाली हैं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, कृपया कन्क्लूड करें। समाप्त करें।

श्री फतेह सिंह : वहां के लोगों का यह कहना है कि राजीव गांधी पाठशाला जो चल रही है, उनको बन्द कर दिया जाये या वहां पर किसी अध्यापक को रखा जाये। यह पंचायत समिति स्तर का मामला नहीं है। पंचायत समिति के पास में कोई अध्यापक नहीं है, इसलिए वह स्कूलें खोली जा रही हैं।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें माननीय सदस्य। कृपया आप समाप्त करें।

श्री फतेह सिंह : मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय से, आपने जितने लड़कों का सलेक्शन किया, बांसवाड़ा जिले को छोड़कर आपने अन्य जिलों में भेज दिया और वहां जगह खाली छोड़ दी। इसका कारण क्या हो सकता है? अब भी मैं उम्मीद करूंगा आपसे कि बांसवाड़ा को जितने भी अध्यापक आप दें, आज जो हमारा एरिया खाली पड़ता है, शिक्षा से लोग वंचित हैं, उन स्कूलों में अध्यापकों की पूर्ति करें।

श्री अध्यक्ष : कृपया समाप्त करें माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री फतेह सिंह : दूसरा निवेदन मुझे यह करना था, आपने वहां पर कालेज खोले। कालेज के अन्दर स्टाफ की कमी, सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोली, उसके अन्दर भी स्टाफ की कमी, सैकण्डरी स्कूल क्रमोन्नत की, वहां पर कमी और उसके बाद स्कूल क्रमोन्नत हुई...

श्री अध्यक्ष : मैं नहीं चाहती कि मैं यह आदेश दूं कि अंकित नहीं करें। आप कृपया समाप्त करें अब। अब कृपया समाप्त करें।

श्री फतेह सिंह : मैं तो कभी बोलता नहीं हूं, समय आपने बढ़ाया है। मुझे आपकी आज्ञा से निवेदन करना है कि वहां के कालेज के अन्दर जितने लड़कों ने एडमिशन लिया है, जब लेक्चरर नहीं होंगे उसके बाद में वहां पढ़ाई कौन करायेगा? तो मैं उम्मीद करूंगा, जिस उम्मीद से माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत, जो आज उपराष्ट्रपति हैं, उनकी मेहरबानी से वहां कालेज खुला, बाद में कई कांग्रेसी मुख्य मंत्री वहां जाकर घोषणा करके आये थे और आपके द्वारा ही यह कालेज खोला गया था, उस समय आप मंत्री थीं। और आज जो कालेज जम चुका है, उसके बाद में आज आपके लेक्चरर वहां जाते हैं, उनको आप हटा लेते हैं। पोस्टिंग तो कर देते हैं बाद में हटा लेते हैं तो क्या होगा? यह कालेज हमारा टूटेगा, फिर उस क्षेत्र के आदिवासियों का भविष्य क्या होगा?

श्री अध्यक्ष : अब आप समाप्त करें, अब आप कृपया समाप्त करें।

श्री फतेह सिंह : इसी तरह से मंत्री महोदय, आवास विद्यालय खोला गया, उसके अन्दर भी अध्यापकों की कमी है। सीनियर स्कूल या सैकण्डरी स्कूल आपने खोली हैं, वहां पर अध्यापकों की कमी है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, जो कमी है, मैंने बताई है उन कमियों की पूर्ति आप करें।

श्री अध्यक्ष : श्री सुरेश मीणा। माननीय सदस्य, आप 10 मिनट से अधिक समय ले चुके हैं। कृपया समाप्त करें।

श्री फतेह सिंह : और जो भी व्यवस्था आप कर सकते हैं, उतना करें। मुझे तो अपनी तरफ से जो कहना था, कह दिया है और वहां की जनता की आवाज उभरेगी, विरोध प्रकट होगा तो स्थिति बिगड़ेगी। इसलिए मैंने आपके सामने जो बात कही है, उसके ऊपर आप गौर कर इस व्यवस्था को ठीक करें।

श्री अध्यक्ष : मंत्रीजी गौर करियेगा।

श्री फतेह सिंह : अन्त में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि राज्यपाल महोदय के अभिभाषण का मैं समर्थन करता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : बहुत अच्छा, धन्यवाद। श्री सुरेश मीणा। पांच मिनट।

श्री सुरेश मीणा (करौली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर मुझे जो बोलने का अवसर दिया है, उसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं। मैं नया-नया हूं ना, कोई बात नहीं। अध्यक्ष महोदय, लेकिन मैं चार दिन से राज्यपाल महोदय के अभिभाषण को सुन रहा हूं। इसमें किसान, एस.सी. एस.टी. की महिलाओं के साथ बलात्कार, यह सारा मामला सिमटकर आ रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सरकार को कि सबसे ज्यादा ध्यान राज्य सरकार ने किसानों पर और एस.सी. एस.टी; के लोगों पर दिया है लेकिन मैं एक बात पूछता हूं कि जब से यह विधान सभा चालू हुई है राजस्थान में, तब से एस.सी. एस.टी. की महिलाओं के साथ बलात्कार के अलावा कोई जनरल की महिला के साथ बलात्कार का मामला आया है क्या? मैं पूछता हूं क्या जनरल की महिलाओं के लिए कोर्ट से स्टे ले रखा है क्या? यह बात....(व्यवधान)

श्री भवानी जोशी : यह बिलकुल गलत है। आप किसी सम्प्रदाय को गलत कहें, आप कैसे जनरल की महिला के लिए कह रहे हैं, यह बिलकुल

(श्री भवानी सिंह)

शर्मनाक बात है। आप अपनी बात कह सकते हैं लेकिन जनरल की महिला के बारे में आप ऐसे कहें कि उसने कोर्ट से स्टे ले रखा है, यह बिलकुल गलत है। उसने कोर्ट से स्टे ले रखा है, यह बिलकुल गलत बात है। महिला तो महिला होती है।

श्री सुरेश मीणा : आप बैठिये ना। मैंने किसी महिला के बारे में नहीं कहा है। सामान्य वर्ग की महिला के बारे में कह रहा हूं। ऐसा है अध्यक्ष महोदय, भूख से मरे तो एस.सी. एस.टी. के लोग मरे, बलात्कार हो तो एस.सी. एस.टी. के लोगों के साथ हो, यह बहुत बुरी बात है। चाहे पार्टी कांग्रेस की सरकार हो....

श्रीमती सूर्यकांता व्यास : क्या बात कर रहे हैं, यह क्या बात हुई।

श्री सुरेश मीणा : चाहे बीजेपी की सरकार हो, इन लोगों ने जो एससी एसटी के लोगों का दिमाग इस प्रकार का कर दिया है कि तुम इसी काबिल हो कि तुम भूख से मरोगे, तुम्हारे साथ बलात्कार होंगे, यह तुम्हारे पर राज करेंगे, इस प्रकार का इनके ऊपर इस तरह की व्यवस्था की है। मैं पूछना चाहता हूं, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे बीजेपी की सरकार हो, बजट में कहते हैं...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आप बोलने दीजिये न उनको, जो कुछ बोल रहे हैं।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : मायावतीजी की सरकार में सबसे ज्यादा बलात्कार किन पर हुए थे, बताने की कृपा करेंगे आप ?

श्री अध्यक्ष : हद हो गई।

श्री सुरेश मीणा : जनरल के लोगों पर। जनरल की महिलाओं पर हुए थे वहां सबसे ज्यादा।

श्री सुरेन्द्र सिंह राठौर (गंगानगर) : और आप बहुत खुश हैं ? खुश हैं न ?

श्री सुरेश मीणा : खुश हैं।

श्री अध्यक्ष : गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य, हमें पता लग गया कि आज आप सदन में हो। अब बार-बार न उठें आप। पता लग गया, आप सदन में हैं, अब बार-बार न उठियेगा।

श्री सुरेश मीणा : मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि इस अभिभाषण में जो प्रावधान रखा है कि एससी एसटी के लिए इतना पैसा हम

(श्री सुरेश मीणा)

खर्च करेंगे। लेकिन मैं समझता हूं आज तक, आज ही नहीं, आज तक किसी भी सरकार ने इन लोगों के ऊपर जो खर्चा किया है, वह बिलकुल कुछ नहीं किया है। यदि इस खर्चे को पूरा कर दिया जाता तो आज यह भूख की बात नहीं आती, यह बलात्कार की बात नहीं आती और राजस्थान की विधान सभा में एसटी एससी का मुख्य मंत्री बैठता, यदि यह बात नहीं होती तो। लेकिन इनका दिमाग इस प्रकार का कर दिया है कि आप तो भूख से मरोगे, आपके साथ यह होगा। मैं पूछना चाहूंगा माननीय शिक्षा मंत्रीजी से, माननीय शिक्षा मंत्रीजी, कल पेपर में पढ़ा हमने कि एसटी एससी की महिलाएं नहीं मिलीं तो उसकी जगह हमने जनरल की विधवा महिलाओं को भर लिया, ऐसा क्यों किया ?

श्री घनश्याम तिवाड़ी : नहीं किया। गलत है।

श्री सुरेश मीणा : नहीं, अख़बार में आया है और आपने भरा है। ऐसा अन्याय नहीं होना चाहिए। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, यह अन्याय मत करो, और यदि आपने भर लिये तो फिर कोई बात नहीं।

श्री अध्यक्ष : आप आसन को सम्बोधित करें, उधर नहीं। उधर नहीं देखें, हां। इधर देखकर बात कहिये।

श्री सुरेश मीणा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात यह पूछना चाहता हूं कि हमने बेकलाग का मामला रखा। बेकलाग में कुछ मास्टर बनाकर, पूरे दूसरे डिपार्टमेंट्स में आज तक एक बेकलाग नहीं भरा। बता दें आपने कौन से डिपार्टमेंट में बेकलाग भरा है एसटी एससी का। दूसरी बात पदोन्नति की, किसी भी डिपार्टमेंट में पदोन्नति नहीं दी। ऐसा अन्याय, ऐसा घोर अन्याय नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष : आप आसन को सम्बोधित करिये माननीय सदस्य।

श्री सुरेश मीणा : माननीय गृह मंत्रीजी, आपसे पूछना चाहता हूं अध्यक्षजी के माध्यम से, कि मैंने जब तृतीय सत्र चला था उस समय एक क्वेश्चन पूछा था आपसे कि राजस्थान में एसटी एससी के कितने अधिकारी, कितने थानेदार, कितने डीवाईएसपी लगे हुए हैं तो आपने यह कहा था कि यह कांग्रेस के टाइम का मामला है। लेकिन अब तो दो साल हो गये हैं, अब बता दो कितनों को फील्ड पोस्टिंग दे दी आपने, अब बता दें हमको।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : बहुत लगे हैं भई, सीमा से भी अधिक।

श्री सुरेश मीणा : फील्ड पोस्टिंग कितनी दी है, इसके बारे में पूछना चाहूंगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जो विकास होना चाहिए, वह विकास एसटी एससी का नहीं हो पा रहा है। आज भी वह लोग भूख से मारे जा रहे हैं क्योंकि उनको इसी कदर रखा है कि वह अब भी कमा कर नहीं खा सकते। उनसे कह दिया जाता है कि तुमको सेंटर से पैसा आ जायेगा, तुमको गेहूं आ जायेगा तो कमाने की जरूरत नहीं है, तुम्हारी जमीन हमको दे दो। तो इस प्रकार की व्यवस्था यहां पर की, उस व्यवस्था को बदलना होगा।

आज हमारे बीच में माननीय हमारी मुख्य मंत्रीजी विराजमान हैं और बड़ी खुशी की बात है कि पश्चिमी राजस्थान से पहले सबसे ज्यादा मुख्य मंत्री बनते थे। लेकिन अब की बार हमारी मुख्य मंत्री पूर्वी राजस्थान से हैं, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। और सारा पैसा अब तक जो भी चाहे सेंटर से पैसा आया हो, चाहे राज्य का पैसा हो, वह अधिकतर पश्चिमी राजस्थान में लगा है। इसलिए आप हमारी तरफ की अब की बार मुख्य मंत्री बनी हैं, अब की बार 75 प्रतिशत इधर, 25 प्रतिशत उधर देने की कृपा करें। धन्यवाद, आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : माननीय मुख्य मंत्रीजी।

श्री रणवीर सिंह गुढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने सब को समय दे दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मेरे को चार मिनट का राज्यपाल के अभिभाषण पर...

श्री अध्यक्ष : सदन के नेता जब खड़े होते हैं तो माननीय सदस्य सब बैठ जाते हैं, आप कृपया स्थान ग्रहण कर लें।

श्री रणवीर सिंह गुढा : आपने मेरे को समय क्यों नहीं दिया। मैं पांच मिनट आपसे चाह रहा हूं, मेरे क्षेत्र के बारे में, झुंझुनूं के बारे में, शेखावाटी के बारे में पांच मिनट से ज्यादा नहीं बोलूंगा।

श्री अध्यक्ष : नहीं, पांच मिनट अब नहीं, नाम पुकार चुकी उनका।

श्री रणवीर सिंह गुढा : आपने मेरे को खुद व्यवस्था दी थी कि पांच मिनट का समय दिया जायेगा, आपने केवल मेरे साथ + + + क्यों किया...

श्री अध्यक्ष : आपको मैंने कब कहा। वह दिया तो आपने तब, तब आपने जो कुछ किया, वह कर ही दिया तब वह तो। आपको समय दिया तब आपने कह दिया, अब आपका समय आज नहीं दूंगी।

श्री रणवीर सिंह गुढा : मैं जानना चाहूंगा अध्यक्ष महोदय। सभी ने किया। मैं यहां देख रहा हूं, शुरू से लेकर अभी तक...

श्री अध्यक्ष : आज मुख्य मंत्रीजी बोलेंगी।

श्री रणवीर सिंह गुढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट चाहता हूं, झुंझुनूं के बारे में और मेरे क्षेत्र के बारे में अपनी समस्याओं को इस अभिभाषण के माध्यम से....

श्री अध्यक्ष : अंकित नहीं हो।

श्री रणवीर सिंह गुढा : x x x (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सुबह आपको दिया था, क्या किया आपने।

श्री रणवीर सिंह गुढा : x x x

डा. दिगम्बर सिंह : x x x

श्री सांवर लाल : x x x

श्री रणवीर सिंह गुढा : x x x

श्री अमराराम (धोद) : x x x

श्री रणवीर सिंह गुढा : x x x

श्री अमराराम (धोद) : x x x

श्री रणवीर सिंह गुढा : x x x (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देखिये, ऐसा है कि यदि इस प्रकार सभी धींगामस्ती करने लग जायेंगे तो आसन अपना काम नहीं कर पायेगा।

श्री रणवीर सिंह गुढा : x x x (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : मैंने तो दिया नहीं, आप किसके कहने से बोल रहे हैं?

श्री रणवीर सिंह गुढा : x x x

श्री अध्यक्ष : आप तीन मिनट में अपनी बात समाप्त करेंगे। इस समय समय हुआ है छह बजकर सैंतीस मिनट, सैंतीस मिनट। छह सैंतीस हुए हैं, अब आप, इसमें अड़तीस हो गये।

श्री रणवीर सिंह गुढा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से यही कहना चाहता हूं इस अभिभाषण के संदर्भ में, राजस्थान के अन्दर जो भ्रष्टाचार, मैं यह नहीं कह रहा हूं कि दो साल की देन है। लेकिन शुरू से लेकर आज तक भ्रष्टाचार को रोकने का किसी ने भी कारगर कदम

(श्री रणवीर सिंह गुढा)

नहीं उठाया। दो साल पहले मेरे क्षेत्र में बीडीओ के खिलाफ भ्रष्टाचार का मामला उठा था, उसको ससपैण्ड किया, बाद में वापिस बहाल कर दिया। मैं अनुरोध करना चाहता हूं मुख्य मंत्री से, राजस्थान में जो भी अधिकारी हैं, जिनके ऊपर चार्ज है, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार की जांच चल रही है, मुख्य मंत्री महोदय उन सभी को टर्मिनेट करेंगी, राजस्थान की जनता आपका सम्मान करेगी। राजस्थान की जनता ने यह उम्मीद करी थी कि यह वसुन्धराजी राजस्थान में भ्रष्टाचार को उखाड़ कर फेंक देंगी। मैं कहना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जो लीकर, जो करोड़ों-अरबों रुपये की लीकर सरकार कम्पनियों से खरीद रही है, उसमें जो कमीशन आ रहा है, वह कमीशन कहां जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी कहना चाहता हूं, मैं यह नहीं कह रहा हूं, हिन्दुस्तान के अन्दर सब लोग कहते हैं, अल्पसंख्यकों का क्या हुआ, उनकी सुरक्षा का क्या हुआ, अगर उनकी सुरक्षा का, मैं कांग्रेस के भाइयों से भी कहना चाहता हूं, आज यूपीए की सरकार बैठी है। अगर वह अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का पुख्ता इन्तजाम करना चाहती है तो फोर्सेज के अन्दर, प्रशासन के अन्दर उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाय। जो भाई एसटी एससी की बात कर रहे थे, मैं इतना कहना चाहता हूं कि यह प्रजातंत्र है, इस प्रजातंत्र के अन्दर बातें प्रजातंत्र की हो रही हैं लेकिन रास्ते राजतंत्र की ओर जा रहे हैं। आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आपने महाराजा मानसिंहजी की मूर्ति लगाई, हमारे पूर्वज थे, हम सम्मान करते हैं लेकिन संविधान के नीचे, कानून के नीचे, इस विधान भवन के अन्दर हमको सब को बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर मूर्ति विधान सभा में लगानी चाहिए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि जिस सदन में डा. अम्बेडकर का सम्मान नहीं है उसके मानने वाले करोड़ों अनुयायियों को कभी राजस्थान में सम्मान नहीं मिल सकता। मैं मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध करना चाहता हूं, पिछली बार कांग्रेस की सरकार से हमने आंदोलन किया था, हमने मांग की थी अम्बेडर की मूर्ति लगाने के लिए। और इस मांग पर मैं कांग्रेस छोड़कर के और लोक जनशक्ति पार्टी से जाकर के चुनाव लड़ कर के सामने आया था। कथनी करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। जो लोग एस.सी./एस.टी. या गरीब के ऊपर अत्याचार करते हैं, कुठाराघात करते हैं

(श्री रणवीर सिंह गुढा)

उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही करनी चाहिए। आपसे अनुरोध करता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सब भ्रष्टाचार के खिलाफ आप सरकार की इनसे तुलना मत कीजिये। आप ये मत कीजिये कि आपने क्या किया था। आप ये मत कीजिये कि आपको कर्नाटक ने या विश्व बैंक ने सर्टीफिकेट दे दिया कि आपकी वित्तीय व्यवस्था अच्छी है। हमारे क्षेत्र में हम जा रहे हैं, गिरदावरी रिपोर्ट में झुंझुनूं में पक्षपात हुआ है। झुंझुनूं के होस्पिटल की व्यवस्था खराब है। झुंझुनूं में शेखावाटी विश्वविद्यालय खुलना चाहिए। झुंझुनूं में पानी की व्यवस्था खराब है, पीने के पानी की व्यवस्था खराब है सिंचाई के पानी की व्यवस्था तो दूर की बात है। 80 प्रतिशत हैण्डपम्प मेरे क्षेत्र में खराब पड़े हैं वहां कोई हैण्डपम्पों के पाइप की सप्लाई नहीं हो रही है। ए.इएन., जे.इएन., बी.डी.ओ. विकास के पैसे में पचास परसेंट भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, 30 लाख रुपये का वाटरशैड बनता है आप स्वीकार करते हो खुद तीस लाख में से वाटरशैड में तीस हजार रुपये भी खर्च नहीं किये जा रहे हैं। मुख्य मंत्री अगर भ्रष्टाचार को नहीं रोक पा रही हैं तो ये सरकार की कामयाबी नहीं कही जा सकती। मैं अनुरोध करना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से कि आपसे राजस्थान ईमानदारी की उम्मीद करता है। आपने बोलने का समय दिया बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष : धन्यवाद। माननीय मुख्य मंत्रीजी।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव का पारण

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले मैं महामहिम राज्यपाल महोदय को सदन के माध्यम से आभार व्यक्त करना चाहती हूं कि उन्होंने अपने अभिभाषण में हमारी सरकार का जो हमारी सरकार की योजनाएं थीं, हमारी सरकार की उपलब्धि थी उसका खाका खींच कर सबके सामने यहां रखा। इसके साथ-साथ प्रतिपक्ष के नवनियुक्त नेता आदरणीय रामनारायणजी चौधरी जो इतने अनुभवी हैं और आज प्रतिपक्ष के नेता बने हैं उनको हम सब की ओर से मैं बधाई हार्दिक बधाई देना चाहूंगी। मुझे पूरा विश्वास है कि उनके अनुभव का हम सबको लाभ मिलेगा।

श्री अध्यक्ष : कल तो मिल ही गया था लाभ। कल तो लाभ मिल गया था आज और ले लो आप।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : हम सबको अनुभव का लाभ मिलेगा और उनके बड़े सुलझे हुए विचार...

श्री अध्यक्ष : कल तो लाभ मिल गया था आज और ले लो आप।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : हम सब लाभान्वित होंगे। इसके साथ-साथ मैं जो पहले प्रतिपक्ष के नेता थे श्री बी.डी. कल्लाजी के योगदान की भी सराहना करना चाहूंगी। उसको हम सब याद रखेंगे और साथ-साथ मैं सब माननीय सदस्य जिन्होंने आज के और पिछले चार दिन के डिबेट में भाग लिया था और जिन्होंने बड़े सकारात्मक रचनात्मक सुझाव हम लोगों के सामने रखे थे, उनको सबको मैं धन्यवाद देना चाहती हूं। साथ-साथ मैं मानती हूं कि इस सदन से बहुत सारे बड़े नेता निकल कर गये हैं उनके सुझावों से हम लोग आगे बढ़ पाये हैं। राजस्थान में इन सब लोगों के सोच के मिश्रण की वजह से विकास कर पाये हैं, आगे बढ़ पाये हैं और मैं समझती हूं कि आज इसी तरीके से आज हम लोग जैसे बैठे हैं कई बातें हम लोग दोनों ने यहां रखी हुई हैं और उस भावना के अनुरूप हम राजस्थान को आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं समझती हूं कि इस सहयोग के साथ राजस्थान में दो साल में इतने सारे काम हुए हैं पांच साल के अन्दर हम लोग रिकार्ड बना कर रखेंगे आप सबकी मदद के साथ। बहुत लम्बी बात हमारे महामहिम राज्यपाल महोदया ने आप लोगों के सामने यहां की थी और मैं समझती हूं कि उसका खाका बहुत सारे लोगों ने यहां खींचा है। हमारे माननीय सदस्यों ने राजस्थान की सरकार ने क्या-क्या काम किये हैं हर विभाग में हम लोगों की क्या-क्या उपलब्धि हुई है वो आप लोगों के सामने रखा है। और नेचुरली जो हमारे प्रतिपक्ष के लोग हैं उन्होंने जो-जो बातें अपनी भी रखनी थीं वो यहां हम सबके सामने रखी हैं। मैं इसी से अपनी कहानी बताना चाहूंगी। मैं समझती हूं कि आज का जमाना थोड़ा सा बदल गया है। शासन का तरीका भी थोड़ा सा बदल चुका है। एक जमाना था जब सब चीज सरकार ही करती थी। अब आजकल के जमाने में सरकार तो छोटी होती जा रही है, जनता की संख्या बढ़ती जा रही है उसकी आकांक्षाएं बढ़ती जा रही हैं। और ये समय आ गया है जब एक कोओपरेशन के साथ चाहे उसमें वालेंटरी आर्गेनाइजेशंस हों चाहे उसमें सिविल सोसायटीज हों चाहे उसमें जनता की भागीदारी हो, ये सब लोग मिलकर एक दफा रचनात्मक सहयोग करके सरकार में भागीदार बनें तभी मैं समझती हूं कि हम लोग अपने कार्य को पूरा कर सकेंगे।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सबके विचारों को हमने जानने की कोशिश की है। परिवर्तन यात्रा में सब लोगों से मुलाकात भी हुई, गांवों में जाने का मौका भी मिला, सबके सोच और विचारों को सुनने का मौका मिला। और मैं समझती हूं कि एक माइंड सैट जो मैंने देखा है पिछले साल के अन्दर राजस्थान के अन्दर हम सबको एक माइंड सैट चैंज यानी सोच के अन्दर बदलाव लाने की जरूरत है जो पचास साल से भी आती जा रही है उसमें बहुत सारा फर्क हो गया है। दुनिया के अन्दर जो इतिहास पढ़ते हैं, जो ज्योग्राफी को पढ़ते हैं वो अपने-आप इस बात को समझ जायेंगे कि जो पिछले पचास साल में हम लोग करते थे अगर उसी तरीके से हम लोग आगे चलने लगेंगे तो राजस्थान का क्या हमारे देश का कोई विकास हो नहीं सकता। इसीलिए हर सरकार की पूंजी हम मानते हैं कि उसका ह्युमन रिसोर्स है और उस ह्युमन रिसोर्स को किस तरीके से हम स्वस्थ बनायें, उस ह्युमन रिसोर्स को किस तरीके से हम शिक्षित करें, उसको किस तरीके से तगड़ा करें वो ही हमारी पूंजी है। और मैं समझती हूं कि वो अगर तगड़ी हो जाती है तो कोई भी प्रदेश पीछे नहीं रह सकता और इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने शिक्षा के ऊपर, स्वास्थ्य के ऊपर जोरदार ध्यान देने की कोशिश की है।

अभी कई माननीय सदस्यों ने डिबेट में भाग लेते हुए आपको बताया कि शिक्षा में हम लोगों ने क्या-क्या काम किये हैं। शिक्षा के साथ-साथ हमने यह कहा कि वो ढांचा जो है वो महिलाओं से बनाया जाता है इसलिए अगर शिक्षित करना है और स्वस्थ करना है तो सबसे पहले हमारी महिलाओं को भी वो करना पड़ेगा क्योंकि एक महिला शिक्षित और स्वस्थ हो जाती है तो परिवार को बदल देती है और अन्दर से समाज को बदल देती है। और इसीलिए महिलाओं के लिए हमने बहुत कुछ किया। बालिकाओं के लिए भी उनको प्राथमिकता देते हुए शिक्षा के अन्दर और स्वास्थ्य के अन्दर भी हमने उनको आगे ले जाने की कोशिश की। मैं यहां यह बताना चाहूंगी कि मैं समझती हूं कि हमारी एक बहुत बड़ी उपलब्धि जो शिक्षा के अन्दर हमने हजारों स्कूल खोले हैं और साथ-साथ अभियान चलाकर लाखों बच्चों को स्कूल में वापस जाकर जो ड्राप आउट्स थे उनको वापस लाने की हम लोगों ने जो कोशिश की है वो अपने आप में सराहनीय तो है ही परन्तु इसके साथ-साथ हमने कई हजार बच्चों को मिड-डे मील के साथ जोड़ा। मिड-डे मील चलता

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

रहता था। दोपहर का भोजन सब लोग देते थे, घूघरी खिलाते थे कोई स्वाद उसमें होता नहीं था, बच्चे स्कूल में रहते नहीं थे। तो हम लोगों ने यह तय किया कि हमारे बच्चों को स्कूल में अगर हमको रखना है और स्वस्थ अगर हमको बनाना है तो अच्छा पौष्टिक दोपहर का भोजन हम लोग उनको दें। और इसको ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने गवर्नमेंट आफ इंडिया, राजस्थान की सरकार और उसके साथ-साथ एन.जी.ओज उसके साथ-साथ सैल्फ हैल्प ग्रुप इनको जोड़कर एक नया समीकरण बनाया। अब किन्हीं लोगों ने कहा कि ये तो पूरा भारत सरकार के ऊपर ही चलता है। मैं यह कहना चाहूंगी कि हां भारत सरकार का इसमें डेफीनेटली कुछ है एक रुपया उनका भी है। पिछली सरकार पचास पैसे दिया करती थी हम लोगों ने उसको बढ़ाकर एक रुपया करके उसको मैच कर दिया है। आज दो सौ करोड़ रुपया अगर दिल्ली की सरकार दे रही है तो दो सौ करोड़ रुपये हमारी सरकार भी उसके साथ दे रही है और मैं आपको यह कह सकती हूं कि सब लोग यहां जानते हैं क्योंकि आप लोगों ने भी सरकार चलायी है पिछले पांच साल के अन्दर कितना कष्ट हुआ, कैसे पैसे आप लाये।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महावीर प्रसाद जैन (सरकारी मुख्य सचेतक) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय माननीय मुख्य मंत्रीजी के उत्तर देने तक बढ़ाया जाए। उत्तर और पारित तक। ..(व्यवधान).. हां पास होने तक।

डा. बुलाकीदास कल्ला : इनको पता ही नहीं है कि क्या बोलना है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : क्या सदन की अनुमति है भाषण के उपरांत धन्यवाद प्रस्ताव के पारित होने तक सदन का समय बढ़ा दिया जाए ?

(स्वीकृत)

बढ़ा दिया गया।

धन्यवाद प्रस्ताव का पारण

श्रीमती वसुन्धरा राजे : 2003 में हम लोगों ने सरकार सम्भाली थी। मैं यह कहना चाहती हूं कि यह मिड-डे मिल उस समय तक उसी तरीके से था

(श्री मती वसुन्धरा राजे)

जो आप लोगों ने सरकार चलाई आपको मालूम है कि आप लोगों ने किस तरीके से उसमें पैसे डालकर घूघरी को संचालित करने की कोशिश की। मैं सिर्फ यह कहना चाहती हूं कि कितनी मुश्किल से पैसा आप लोग लाये क्योंकि रोज हम लोग सुनते थे कि सरकार के पास पैसा नहीं है, हम बिलकुल गरीब हैं, हमारा खजाना खाली है। यह एक रात में तो बदल नहीं गया। हम लोग अगर पैसे लेकर आये हैं तो उसी खजाने से लेकर आये हैं जिसको आपने कहा था कि बिलकुल खाली है। और मैं आपको इसलिए कहना चाहती हूं कि हम लोगों ने पैसा लगाकर अपना एक विजन डाक्युमेंट तैयार करके हमने यह तय किया कि किस चीज को पहले रखेंगे और फिर किस चीज को उसके पीछे रखेंगे और इसी तरीके से हमने जो मिड-डे मिल का इन्तजाम किया उस मिड डे मिल में हमने कई लोगों से बात की। सबसे पहले अक्षय पात्र जिसको हमने नवम्बर, 2004 में पायलट प्रोजेक्ट में 600 बच्चों के साथ जयपुर में चालू किया। फरवरी, 17 को जब इनोग्रेशन हुआ तो 8000 बच्चों का और जयपुर में आज 60 हजार बच्चों को भोजन खिला रहे हैं। बारां में 11 हजार बच्चों को 90 गांवों में खाना खिला रहे हैं और मैं समझती हूं कि साल के अन्त तक यह 1 लाख 10 हजार तक इसको पहुचा देंगे और बारां में 20150 बच्चों को खाना खिलायेंगे। इसी तरीके से नाथद्वारा में 15 और 30 मार्च के बीच 3000 बच्चों को पायलट प्रोजेक्ट में लाकर उसको आगे बढाने की ओर हम लोगों का ध्यान है। इसी तरीके से नंदी फाउंडेशन ने उदयपुर में 15 फरवरी को इनाग्रेशन किया 70 हजार बच्चों के बहुत बड़े किचन के साथ वह चित्तौड़गढ और भीलवाडा में 40 हजार बच्चों और 30 हजार बच्चों को खाना खिलाने के मूड में हैं। साथ-साथ कोटड़ा और सलूम्बर के लिये 15 हजार और 40 हजार बच्चों के एम ओ यू को हमने साइन कर लिया है और कुछ ही दिनों में झाड़ोल के लिये 40 हजार बच्चों का एमओयू हम लोग साइन करके दोपहर का गर्म पौष्टिक खाना वहां चालू करेंगे।

इसके साथ इन्होंने एक नई चीज और जोड़ी है हैल्थ कार्ड हर बच्चे के लिये, क्लास 1 से क्लास 12 तक। कामन कोल्ड से लेकर कैंसर तक जिसका दाम खाली 50 पैसे होगा, पर चाइल्ड पर डे और उसमें स्टेट गवर्नमेंट यानि नगर परिषद का 25 पैसा और नंदी फाउंडेशन का 25 पैसा जो कि जनरल डोनेशन से वह लेंगे और मैं समझती हूं कि यह जो स्कीम है वह इतनी अच्छी

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

और सिम्पल स्कीम है यह कहीं भी रेप्लीकेट हो सकती है। और नंदी फाउंडेशन का यह कहना है कि राजस्थान में हम इसको पायलट बना रहे हैं परन्तु यह पूरे देश में, क्योंकि इतनी अच्छी स्कीम है, पूरे देश में कापी कर दी जायेगी और मैं समझती हूं राजस्थान के लिये यह बहुत बड़ी चीज होगी।

एजुकेशन में हम लोगों ने बालिकाओं के लिये जो किया है वह मैं समझती हूं कि घनश्यामजी और हमारे पूरे सदस्यों ने पूरी बात आपके सामने रखी। हमने एजुकेशन में बहुत बड़े काम किये हैं और यह ठीक है कि हम लोगों को एक दूसरे को क्रिटीसाइज करना पड़ेगा ही। क्योंकि मैं समझती हूं घर में बैठे हैं तो उस समय हम भी समझते हैं और आप भी इस बात को समझते हो कि हम लोगों ने काम किये हैं और आगे भी करना चाहते हैं। मैं पूछना चाहती हूं अगर हमारी सरकार ने 40 हजार या 70 हजार या 80 हजार टीचर्स को भर्ती किया तो यह 5 साल में आपकी सरकार भी इस चीज को करती। सर्व शिक्षा अभियान के थ्रू करती, किसी अभियान के थ्रू करती। मैं यह कहती हूं पांच साल के कोई भी भर्ती के बाद आज जब भर्ती चालू हो गई है तो वहां समय लगेगा पूरे स्कूल कवर करने में। पांच साल के खड्डे को हम डेढ़ दो साल में नहीं भर सकते। हम धीरे-धीरे हमारे सीमित साधनों को लगा-लगा कर हर साल कुछ टीचर को जोड़-जोड़ कर यह कोशिश करेंगे कि राजस्थान में हमारे जितने स्कूल हैं उसमें टीचर जाकर बैठ जाये। यह एक साल में नहीं हो सकता। मैं यह सोच ही रही थी क्योंकि पिछले 2-3 दिन से हमारे मैनीफेस्टो को लिये-लिये प्रतिपक्ष के कई सदस्य घूम रहे थे। मुझे लगा कि अभिभाषण पर बहस हो रही है तो अभिभाषण की कापी होगी, बजट का टाइम आयेगा तो बजट की कापी होगी, कोई और कापी होगी परन्तु हमारे मैनीफेस्टो को लेकर जो घूम रहे हैं वह क्या रीजन हो सकता है। कभी तो बार-बार लोगों ने कहा कि आपने अपने वादे पूरे नहीं किये। यह तो मैनीफेस्टो की बात है। मुझे लगता है कि जब कुछ बात बची नहीं है तभी तो मैनीफेस्टो पर आनी है। 243 पाइंट जो हमने उसमें लिखे हैं उसमें से करीबन 141 हम लोगों ने वादे पूरे कर लिये हैं। कुछ 51 इस स्थिति में हैं कि बहुत जल्दी पूरे हो जायेंगे। और मैं समझती हूं कि अगर उसकी तुलना पिछले पांच साल की तुलना से कर दी जायेगी तो बहुत जमीन आसमान का अन्तर मिलेगा। इसलिये मैं समझती हूं कि इसके बारे में अपने को बात भी नहीं करनी चाहिये।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

अभी बीकानेर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि क्या यह बीमारू-बीमारू बोलते रहते हैं। और कहा कि बीमारू से आपने निकाला है यह बात तो नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी कही है, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इस बात को रखा। बीमारू से कैसे निकला है और अभिभाषण में आपने इस बात को कैसे रखा है यह तो समझाओ। मैं तो सिर्फ इतना कह सकती हूं कि वित्तीय प्रबन्धन अच्छा रहा। और इस वित्तीय प्रबन्धन में नवीं पंचवर्षीय योजना जिसका आकार 27650 करोड़ था वह अपने लक्ष्य से 8 हजार 80 करोड़ रुपये कम था। और पिछली सरकार की औसत वार्षिक योजना जो उन्होंने अपने कार्यकाल में बनाई थी वह 4 हजार 600 कुछ थी। अगर हम उसी रास्ते पर चलते तो यह जो दसवीं पंचवर्षीय योजना है उस लक्ष्य को हम पूरा नहीं कर पाते। क्योंकि आप इकोनोमिस्ट हैं आप इस बात को समझ जाओगे कि सबसे बडी वार्षिक योजना हमारे दो साल में हम लोगों ने रखी है और कुल 15147 करोड़ की योजना हम लोगों ने बनाई है। इसका दुगुना आकार बना है और इसकी वजह से हमारे राजस्थान के लोगों को फायदा मिला है।

टोडारायसिंह से आने वाले माननीय सदस्य ने बिलकुल ही ठीक कहा था कि गत दो वर्ष के कार्यकाल में एक दिन का भी ओवर ड्राफ्ट नहीं था। यह हमारी सरकार का कुशल वित्तीय प्रबन्धन है और उसका परिणाम है जिसका सुख राजस्थान भोग रहा है, राजस्थान के लोगों को परेशानी नहीं हो रही है। मैं यह कहना चाहती हूं कि यह हम अपने मुंह से ही नहीं कह रहे हैं यह भूरि भूरि प्रशंसा हम लोगों की भारत सरकार के योजना आयोग ने भी की है। मैं इसके बारे में थोड़ा सा पढ़कर आपको बताना चाहूंगी ताकि आपको मालूम पड़ जायेगा कि बीमारू का शब्द कहां से आया और बाहर कैसे निकला, यहां डिप्टी चेयरमैन प्लानिंग कमिशन ने कहा है कि – ''Rajasthan had registered high growth rates in recent years indicating that the State was moving out of BI-MARU syndrome.''

डा. बुलाकीदास कल्ला : यह 5 परसेंट क्यों हुई इसका जवाब दो आप।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : डिप्टी चेयरमैन हैं वह भी इकोनोमिस्ट हैं। और उन्होंने बड़े पुरजोर शब्दों-शब्दों में यह कहा है, हमारी अच्छी प्रशंसा करते हुए कहा है कि बहुत अच्छे तरीके से हमारा राजस्थान चल रहा है और बीमारू सिंड्रोम से हम लोग निकल चुके हैं। इसी तरीके से डा. सइदा हमीद जो मेम्बर,

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

प्लानिंग कमीशन हैं, और जो इस क्षेत्र को देखती हैं, राजस्थान को देखती हैं उनका यह कहना है कि- ''Rajasthan has a variety of successful models of development with public-private participation.", जिसको हमने निकाला है। और उन्होंने इतनी सलाह दी है कि ''The State should, therefore, encourage more and more NGO participation in the implementation of various government programmes." श्री योगेन्द्रजी जो मेम्बर प्लानिंग कमीशन हैं, उनके बारे में तो आप अच्छी तरह से जानते हो, रूरल डवलपमेंट में वह काफी कुछ काम कर चुके हैं। जाने माने आईएएस आफिसर भी रह चुके हैं। उनका यह कहना है कि ''Rajasthan had achieved commendable progress in respect of rural development, literacy, etc." हमने किसी ऐसे तरीके से अभिभाषण में यह बात नहीं रखी। यह सब चीज सुनने, देखने और पार्टिसिपेट करने के बाद हमने आपके सामने यह बात रखी है।

अब मैं कुछ लोगों ने जो अपनी-अपनी बातें कहीं उनके बारे में थोड़ा कहना चाहूंगी क्योंकि मैं समझती हूं कि उन्हीं चीजों में सब बातें आ जायेंगी। नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने हमको यह कहा था कि राज्य सरकार का कुशल प्रबन्धन नहीं है क्योंकि पिछली सरकार की अवधि में ब्याज के भुगतान में की जा रही राशि में 4771 करोड़ रुपये के विरुद्ध इस सरकार द्वारा बजट पेटे 5203 करोड़ रुपये भुगतान किया जा रहा है। मैं आपको सिर्फ इतना ही बताना चाहूंगी 1999-2000 में ब्याज के रूप में जो भुगतान की राशि थी वह 2825 करोड़ रुपये से बढ़कर 2002-03 में 4300 करोड़ रुपये हो गई थी। वर्तमान सरकार द्वारा ऊंची दर वाले जो भी ऋण थे उसको हमने स्वैप किया और यह स्वैप करके ब्याज की दर कम करके 2003-04 में 68 करोड़, 2004-05 में 226 करोड़, 2005-06 में 398 करोड़ रुपये ब्याज की बचत हम लोगों ने की।

वर्ष 2004-05 के अन्दर 5172 करोड़ रुपये का ब्याज हमने भुगतान किया और 2005-06 के लिये हमने 5319 करोड़ रुपये का प्रावधान किया। वर्ष 2004-05 में जो ब्याज भुगतान वर्ष की तुलना में 8.27 प्रतिशत की वृद्धि और वर्ष 2005-06 में बजट प्रावधान में मात्र 2.81 वृद्धि इंगित की गई है। वर्ष 1999-2000 में 25.96 प्रतिशत और वर्ष 2-3 में 10.89 प्रतिशत वृद्धि की तुलना में मैं समझती हूं कि बहुत कम है। ब्याज की राशि राजस्व प्राप्तियों के रूप में वर्ष 1999-2000 में 28.86 और वर्ष 2002-03 में 32.87 प्रतिशत रही

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

है यह कुल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में ब्याज भुगतान वर्ष 2004-05 में 29.12 प्रतिशत और 2005-06 के बजट प्रावधान के अनुसार 25.9 प्रतिशत किया है, मैं समझती हूं कि यह राशि प्रतिवर्ष बढ़ना स्वाभाविक है परन्तु वृद्धि दर में उल्लेखनीय कमी आई है और सिंह साहब इकनोमिक्स किये हुए हैं इस चीज को अच्छी तरह से समझ लेंगे। मैं समझती हूं कि कुल बजट प्रावधान की तुलना में अनुपूरक मांगों के जरिये कराये गये प्रावधान का प्रतिशत 25 और 2004-05 में मात्र 3.27 था तो बजट अनुमानों में हम लोगों ने सही अनुमान किया और वास्तविक आंकलन करने की हमने कोशिश की, सावधानी बरती इसका रिजल्ट आप लोगों के सामने हैं।

इसी तरीके से आबकारी नीति से यह कहा गया कि गंगानगर शुगर मिल बिलकुल ही बन्द होने जा रही है और मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि जीएसएम को 2004-05 में रिकार्ड प्रोफिट होने वाला है कम से कम 12 करोड़। इसका मतलब यह तो मजाक है आप अगर यह कहें कि आबकारी नीति जीएसएम विरोधी है क्योंकि 25 प्रतिशत हमने रखा तो है उनके लिये, तो उसमें लेना ही पड़ेगा परन्तु 12 करोड़ रुपये which is record, जो बनने वाला है और विपक्ष के नेता यह पता कर लें कि दस, बीस या तीन वर्षों के अन्दर जीएसएम ने यहां तक इसका प्रोफिट इसके आस-पास भी प्राफिट किया हो तो यह हमें बता दें। यह कोई हम लोग छिपा नहीं रहे बातें, आप लोगों के सामने फेयरली रखना चाहते हैं। हां 12 करोड़, मैं कह रही हूं बीस, तीस या चालीस...

डा. बुलाकीदास कल्ला : कितना लाभ होता 75 प्रतिशत का हम, छीना नहीं होता तो कितना होता ?

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मैं तो यह कह रही हूं आपके समय से और हमारे समय में इतना अन्तर है कि हम लोगों ने इसे रेड में से निकालकर आज यह स्थिति बना दी है कि 12 करोड़ का आपको यहां फायदा होने जा रहा है जो अपने आप में एक रिकार्ड है।

आपने फिर भी यह कहा कि कोई भी इन्फ्रास्ट्रक्चर के अन्दर आप लोगों का कोई काम नहीं हुआ है उसके अन्दर आपने बिजली की बात जो बहुत बड़े शब्दों में कही।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपने मोनटेकसिंह अहलूवालियाजी को कोट किया उन्होंने यह कहा कि राजस्थान इन्फ्रास्ट्रक्चर के विकास में लेकिंग कर रहा है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मैं यील्ड नहीं कर रही तो आपको बोलने की जरूरत ही नहीं है। आपको क्लियरली बता रही हूं कि इसमें कोई छिपाने की बात नहीं है। और मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि हम लोगों ने आपकी सरकार जब आफिस डिमिट कर गई थी तो उस समय आपने हमको कोई भी पाइप लाइन में एक भी प्रोजेक्ट बिजली का नहीं छोड़ा था। गिराल एक. 125 और मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि दिसम्बर, 2003 के अन्दर हम लोगों ने विंड से 204 मेगावाट, बायोगैस से 7.5 मेगावाट और सेंटर पावर प्रोजेक्ट पार्टनरशिप में 196.5 माने 405.17 मेगावाट हम लोगों ने प्रोड्यूस किया है, आप मेरे को कहेंगे कि जीरो मेगावाट प्रोड्यूस किया है तो यह बिलकुल ही गलत है।

इसी तरीके से अगर पावर क्राइसिस की बात करेंगे तो पूरे राजस्थान की मुसीबत है वह आज की मुसीबत नहीं है। पचास साल में धीरे-धीरे इस स्थिति में हमारा स्टेट आया है। यह पावर क्राइसिस बहुत सारे कांग्रेस रूल्स स्टेट्स के अन्दर आपको दिखाई देगा। महाराष्ट्र के अन्दर किसानों की क्या हालत है वह आप सबके सामने है। हरियाणा, दिल्ली के अन्दर तो स्थिति हमारे से भी बदतर है। इसका मतलब यह नहीं कि मैं नहीं कहती कि राजस्थान की स्थिति में हम लोगों को सुधार लाने की जरूरत है। मैं समझती हूं उसके अन्दर हम लोग पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। पर कांग्रेस के पांच साल के अन्दर आप लोगों ने अपनी सप्लाई को सिर्फ 5 प्रतिशत बढ़ाया और हम लोगों ने दो साल के अन्दर 35 प्रतिशत से ज्यादा बिजली यहां की जनता को दी है। हमने इतनी सारी बिजली दी है इसकी वजह से इकनोमिक ग्रोथ चाहे किसानों के उसमें हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग और बिजनिस के अन्दर हो वह हुई है। मैं यह बताना चाहूंगी कि हमने 530 करोड़ बिजली साल में खरीदी माने दो साल के अन्दर हम लोगों ने हजार करोड़ बिजली खरीदी और जबकि आप लोगों ने अपने पूरे पांच साल के अन्दर 400 से कम बिजली खरीदी।

हमारा पावर प्लांट जो भी है वह 90 प्रतिशत पीएलएफ जो प्लांट लोड फैक्टर पर चल रहे हैं, कुछ पावर प्रोजेक्ट जो फैल हुये है वह सेन्ट्रल के अन्दर आते हैं जैसे नाफ्थाजाकरी हो या रैप हो या दूसरे आरएपीएस का प्रोजेक्ट हो। या दादरी या रिहांद हो। और इसकी वजह से 2500 लाख यूनिट हम लोगों ने खोया है इसी वजह से हमारी क्राइसिस गहरी हो गई है। और मैं समझती हूं कि कांग्रेस ने अपने पांच साल के अन्दर 1 लाख 11 हजार

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

एग्रीकल्चर कनेक्शन जो निकाले हैं और हम लोगों ने ढाई साल के अन्दर, यह फीगर क्रोस करना है, जून 2006 तक हम लोग इससे बहुत ज्यादा पहुंच जाएंगे। हम लोगों ने 1 लाख 75 हजार जो कनेक्शन 12 साल से पड़े हुए थे उनमें से 80 हजार कनेक्शन दे दिये थे और पांच साल में जो कांग्रेस ने 12 हजार कनेक्शन एससी को दिये वह हमने दो साल के अन्दर 10 हजार कनेक्शन दे दिये।

अब टी एण्ड डी लोसेस के ऊपर थोड़ा सा ध्यान अगर हम दें, जब कांग्रेस ने 1998 में टेकओवर किया था तो उस समय टी एण्ड डी लोस, हमारी सरकार से उन्होंने टेकओवर किया तो उस समय 29.43 प्रतिशत लोसेज थे। हमारी सरकार ने स्वस्थ हालत में आपको यह छोड़ा था। 2003 तक आप उसको 41.50 तक आप ले गये थे उसको, 40.9 पर हम लोग लाये और बहुत बड़ा फीडर रिनोवेशन प्रोग्राम चालू कर दिया है। जैसे 8 हजार फीडर को 5 हजार करोड़ लगाकर हम लोग ठीक कराने की फिराक में है जिसमें से अभी हम लोगों ने शुरूआत बहुत ही, अभी-अभी की है। जिसमें से 390-95 फीडर हम लोगों ने किये हैं। बिफोर फीडर रिनोवेशन प्रोग्राम, इसके टी एण्ड डी लोसेज 62.2 प्रतिशत आफ्टर रिनोवेशन आज 22.8 प्रतिशत हो गये। और हमारी कोशिश यह है कि इसको 15 प्रतिशत तक हम ले आयेंगे। हमारी कोशिश में कोई कमी नहीं है और मैं समझती हूं कि हम लोगों ने जो शुरूआत की है उस शुरूआत को हम मजबूती से आप सबकी मदद से ही क्योंकि अकेले नहीं हो सकता, यह बिजली का काम हम सबका है। आप सरकार में आये और हम कुछ कहे और हम सरकार में आये और आप कुछ कहें स्थिति ऐसी हो जाएगी कि पूरा ग्रिड ही बैठ जाएगा, तो यह नुकसान पूरे राजस्थान का होगा और हम हाउस में बैठे बैठे यह कहते रहेंगे कि चिन्ता करो। अगर किसान की चिन्ता करनी है तो फिर आज से ही हम लोगों को शुरू कर लेना चाहिये। इस चीज पर हम लोगों को ध्यान की जरूरत है।

मैं यह कहना चाहूंगी कि लिग्नाइट के बारे में कल्ला साहब ने कहा कि आपने क्या किया ? अभी तक, मैं यह पूछना चाहती हूं कि कांग्रेस ने क्या किया 50 साल के अन्दर ? जीरो मेगावाट लिग्नाइट से आप लोगों ने लिया है, मैं यह कहना चाहती हूं कि हमारी सरकार के अन्दर बरसिंहसर 250 मेगावाट गिराल से 250 मेगावाट, आईपीपीज के द्वारा 1000 मेगावाट, 1500

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

मेगावाट। तो आप यह सोच लीजिए जीरो मेगावाट की तुलना में 1500 मेगावाट हम लोग करने जा रहे हैं, मैं समझती हूं कि वह मजाक नहीं है। गिराल का प्रोजेक्ट, धौलपुर का प्रोजेक्ट आप लोगों ने पाइप लाइन में डालकर उसके लिये कुड गैस, उसके लिये कुछ भी इन्तजाम नहीं करके वैसे ही छोड़ दिया। उसका पूरा का पूरा, घोषण करना तो बहुत आसान है, मैं समझती हूं कि घोषण को आगे ले जाकर उसको वित्तपोषित करना, गैस का इन्तजाम करना यह इस सरकार ने किया है, अगर वो ही करके आप छोड़ देते तो मैं आपको धन्यवाद देती।

मोहम्मद माहिर आजाद : क्या यह सही नहीं है कि T&D लासेज में झालावाड़ और धौलपुर नम्बर एक और दो पर हैं। सबसे ज्यादा बिजली चोरी झालावाड़ और धौलपुर के अन्दर हो रही है, क्या यह सही नहीं है? (व्यवधान)

श्री जोगाराम पटेल : आपके समय से ही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : नगर से आने वाले माननीय सदस्य, आप तो पुराने हैं। सदन की नेता बोल रही हैं, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य ने अभी यह कहा कि कृषि के लिये आपने अभी तक क्या किया, कि मेनिफेस्टो में आपने बहुत सारी चीजें कीं परन्तु कृषि के लिये कुछ नहीं किया है। तो हम तो यह बताना चाहते हैं कि फसल बीमा के अन्दर हम लोगों ने करीबन 200 करोड़ रुपये बांटे हैं। और मैं समझती हूं कि 14 फसलों को राष्ट्रीय फसल बीमा के अन्दर हम लोगों ने अधिसूचित किया है। यह कोई कम नहीं है। आप लोग तो बोलते रहे, 5 साल तो हमने कृषि बीमा, कृषि बीमा बहुत सुना, परन्तु बीमा हुआ नहीं। और मैं यह कहना चाहती हूं यह हम लोगों ने किया 200 करोड़ रुपये हमने दिये और मैं समझती हूं कि यह जिस तरीके से और बढ़ता जाएगा उसमें हमारा पेमेंट भी होता जाएगा। अमरारामजी ने यह कहा कि क्राप इन्श्योरेंस स्कीम में आपने क्या किया ? तो मैं आपको भी यह सूचित करना चाहूंगी कि सौ करोड़ से अधिक और इसी प्रकार से बीमित सरसों का भी जो नुकसान है तो इसी में अगर मुआवजा हो जाता है तो स्कीम के अनुसार हम लोग उसको देंगे। इसलिये इसमें आपको चिन्तित होने की जरूरत नहीं है। हम लोगों का पूरी तरह से किसानों की ओर हमारा ध्यान है। पानी के बारे में कई लोगों ने बात उठायी है। मैं यह कहना चाहती हूं कि नर्मदा का पानी पूरा हम

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

लोगों को प्राप्त होगा। .5 एम.ए.एफ. हमारा हिस्सा है, वह हम प्राप्त करेंगे। और मैं समझती हूं कि कोई विवाद इसके ऊपर नहीं है। यह पानी हम लोगों को मिलेगा। आगे आने वाले समय के अन्दर जिन्होंने पूछा कि आप लोग क्या बिजली और लाने की कोशिश में हो तो मैंने यह बताया कि गिराल के अन्दर आपकी दूसरी यूनिट भी आएगी, धौलपुर में भी आएगी। दो यूनिट्स आपके छबड़ा के अन्दर भी आएंगी और इससे भी सितम्बर, 2008 तक हम लोगों को बिजली प्राप्त हो जानी चाहिए। अध्यापकों के बारे में कई लोगों ने बातें उठायीं, मैं समझता हूं कि उसके बारे में हमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है क्योंकि उसका जवाब कई तरीके से हम लोगों ने दे दिया है।

भारतीय संविधान के 73वें संशोधन की भावना के बारे में कई लोगों ने बात कही यहां और कहा कि इसके अनुरूप राजस्थान पंचायत अधिनियम, 1994 के प्रावधानों को दरकिनार करके जयपुर विकास प्राधिकरण कैसे जमीन ले रहा है। तो मैं आपको यह बताना चाहूंगी कि भारतीय संविधान के 73वें अमेंडमेंट के द्वारा पंचायतों को अधिकार दिये जाने के जो संवैधानिक प्रावधान हैं वह अनुच्छेद 243(जी) और 11वीं अनुसूची में पंचायत में चारागाह निहित होने अथवा चारागाह भूमि पर पंचायतों का स्वामित्व होने का उल्लेख नहीं है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 50 के अनुसार यह पंचायत को केवल चारागाह भूमि नियंत्रण यानि कण्ट्रोल सम्बन्धी अधिकार का उल्लेख है। और जयपुर विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में गांवों में स्थित राजकीय या चारागाह भूमि जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 54 के अनुसार प्राधिकरण में निहित हो जाती है यानि वेस्टेड हो जाती है। इसका उपयोग प्राधिकरण ने किया है। उसका लैण्ड बैंक स्थापित करने की कोशिश की है।

डा. सी.पी. जोशी : साथ में जो कांस्टीट्यूशन में डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग का पार्ट है वह भी देख लें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : Joshiji, I am not yielding.

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं, आप बाद में पूछ लें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : इस तरीके से कई लोगों ने मेरे को यह कहा कि आपने जो अपनी भूमि दी वह भूमि बहुत ही सस्ते दामों में दी है। तो मैं खाली चैक कर रही थी, मैंने कहा कि देखें तो सही कि क्या किस तरीके से

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

यह हुआ है। तो मैंने यह देखा। क्योंकि किन्हीं-किन्हीं लोगों को या इन्वेस्ट अट्रेक्ट करने के लिये कभी-कभी यह शर्त हो जाती है कि आपको कम दामों में जमीन देने की जरूरत होती है। मैंने देखा कि पिछले 5 सालों के अन्दर क्या हुआ। तो मैंने यह देखा कि जी.ई. कैपिटल, जो आपके समय में आयी थी, उसको 750 रुपये पर स्क्वायर मीटर, इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मारवाड़ी एण्टरप्रिन्योर्स को 1750 रुपये पर स्क्वायर मीटर, ग्रीन फायद हास्पिटल को 1505 रुपये पर स्क्वायर मीटर।

श्री प्रद्युम्न सिंह : इंस्टीट्यूट से आपकी सरकार करार करके गयी थी। काफी जमीन आपकी सरकार के वक्त में दे दी गयी थी।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : प्रद्युम्न सिंहजी, I am not yielding, I will finish this then you say what you want to say.

ग्रीन फायर हास्पिटल 1505 रुपये पर स्क्वायर मीटर, EP रुपये 1260 पर स्क्वायर मीटर। और आप हमसे कहते हो, जल महल का मैं नहीं कह रही हूं कितने में दिया है आप लोगों ने। परन्तु फिर आप हमसे पूछते हो कि कितने दाम में आप क्या दे रहे हो। मैं सोचती हूं कि उससे बहुत ज्यादा हम लोगों ने लेने की कोशिश की।

जब आप लोग सेज की बात करते हो तो मैं यह कहना चाहूंगी कि सेज एक ऐसी चीज है जो चायना के अन्दर अब 60 लगने की वजह से चायना का इण्डस्ट्रियल बेस इतना बूम हो रहा है। और पूरी दुनिया के अन्दर अगर चायना का नाम हो गया है तो उस SEZ की वजह से हुआ है। और आपके चेन्नई के अन्दर बहुत बड़ा SEZ, only for IT and ITC services के लिये वहां बनाया गया है। हरियाणा के अन्दर तो आपकी सरकार है, आपको पूछना चाहिए कि वह कौनसी ट्रांसपरेंट मेथेडेलोजी से वह कर रहे हैं कि रिलांयस को उन्होंने बुलाकर 15 हजार एकड़ किसी तरीके से और 5-7 दिन में देने की बात रखी है। उन लोगों ने कुछ तो सोचा होगा। हम लोगों ने तो बुलाकर और पिछले 6 महीने से उनसे बैठकर बड़े ट्रांसपरेंट रूप से तय कर रहे हैं उनके प्राइसेज। हम इस तरीके से किसी को लैण्ड देने वाले नहीं हैं। और महेन्द्रा एण्ड महेन्द्रा एक ऐसी कम्पनी है जो रतन टाटा के साथ पूरे देश के अन्दर और पूरी दुनिया के अन्दर मानी जाती है। वह कोई भी भ्रष्टाचार में कभी लिप्त हुई नहीं है और उसकी रैपुटेशन है। और अगर बिजनस सर्किल्स में आप

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

चले जाओ तो आपको मालूम पड़ जाएगा। मैं समझती हूं कि अगर कोई यह सोचे कि उनके द्वारा थर्ड पार्टी को हम बेच देंगे तो सरकार इतनी तो नासमझ है नहीं और न इतनी कमजोर है। मैं तो समझती हूं कि दो साल के अन्दर उनको सेज का परमिशन मिलना चाहिए और तीसरे साल के अन्दर अगर वे बसाते नहीं हैं तो जमीन वापस लेना, यह हमारा काम है। और हम इसको क्यों छोड़ेंगे किसी तरह ? परन्तु यह तो अब आप लोग बराबर कहने लग गये हो कि हम सेज के अगेंस्ट में नहीं हैं। हमने तो बहुत सारे किस्से सुने हैं। सेज के अगेंस्ट में अब कोई नहीं है। हो कैसे सकते हैं ? क्योंकि सेज एक ऐसा इंन्स्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से दुनिया के अन्दर प्रोग्रेस हुई है तो राजस्थान के अन्दर विकास नहीं होगा ? और मैं तो कह रही हूं, जब कोई कह रहा है कि 10 हजार करोड़ का इम इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और एक लाख से ऊपर हम नौकरी देने जा रहे हैं तो उसको कौन नकार सकता है। कोई भी स्टेट नहीं नकार सकता है। आपके बार्डर पर हरियाणा लगा हुआ है उन्होंने किस आधार पर और किस ट्रांसपरेंसी के साथ रिलायंस को लाये। और रिलायंस और महेन्द्रा के अन्दर आप तुलना भी कर सकते हैं। मैं समझती हूं कि ऐसी कोई बात आप लोगों छिपी हुई नहीं है। मैं समझती हूं कि इसके ऊपर सबको ध्यान देने की जरूरत नहीं है। और इसलिये जब अमरारामजी यह बात उठाते हैं कि बेचारे किसानों की तरफ हमारा ध्यान बिलकुल नहीं गया तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि किसान जितने आपके हैं उतने हमारे भी हैं। और इसलिये हम लोगों ने, जब डी.एल.सी. रेट पर बात चली तो हम लोगों ने जो पूरे देश के अन्दर रेट्स नहीं हैं वह हमने किसानों को दी है। 20 प्रतिशत आवासीय रेट डवलप्ड और 5 प्रतिशत कामर्शियल रेट मैं आपको चैलेंज करती हूं कि कोई और स्टेट है जिसने किसानों को इतना पैसा दिया है या इतना मुआवजा दिया है? It is a one of the best packages. मैं समझती हूं इस देश के अन्दर इसको कोई चैलेंज करे। (व्यवधान) टाइम तो लगेगा, मैं मानती हूं इस चीज को क्योंकि कभी-कभी इस बात का दुःख होता है जब ये बातें उठती हैं और उसके पीछे कोई तथ्य नहीं हैं। इस तरीके से, क्योंकि बिजनस आ रहा है क्योंकि अब हम लोगों को नयी कालोनियां बसानी हैं, इस वजह से यह तय किया गया कि मास्टर प्लान के अन्दर हम एक लैण्ड बैंक का इन्तजाम करेंगे, उस लैड बैंक के अन्दर हम जमीन अलग-अलग कर देंगे कोई होटल हो जाएगा, कोई इन्वेस्टमेंट के लिये हो जाएगा, यह सब हम तैयार रखें ताकि कोई

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

एण्टरप्रिन्योर हमारे पास आता है तो ढूंढने फिरने में हम 6 महीने नहीं निकालें। और इस वजह से हम लोगों ने पहली दफा 56363 बीघा का एक लैण्ड बैंक तैयार कर दिया ताकि कोई भी डवलपमेंट प्रोजेक्ट हमारे सामने आये तो रेडी अवेलेबिलिटी आफ लैण्ड होगी और जल्दी से जल्दी हम उस प्रोजेक्ट को पुट-अप कर सकेंगे। मैं समझती हूं कि हम लोगों ने दूसरी म्युनिसिपैलेटिज और अरबन डवलपमेंट आथोरिट्ज को भी हमने डाइरेक्ट कर दिया है कि आप लोग भी लैण्ड बैंक्स बनाएं और पूरी तरह से कम्प्लांयस जो मास्टर प्लान का है, वह हम लोकल बोडीज के अन्दर एंश्योर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसी तरीके से आर.यू.आई.डी.पी. की बात भी आप लोगों के सामने आयी थी। मैं यह कहना चाहूंगी इसके अन्दर कोई प्रावधान चिकित्सा क्षेत्र के अन्दर नहीं है और इस परियोजना के अन्दर 46.57 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था और इसके विपरीत हमने लगभग 46 करोड़ रुपये के कार्य चालू करा दिये हैं।

कच्ची बस्ती के विकास के लिए 24.11 करोड़ रुपये के प्रावधानों के विरुद्ध हमने 33.3 करोड़ रुपये के कार्य पूरे कर दिये हैं, जिनमें से 132 कच्ची बस्तियां लाभान्वित हुई हैं। और मैं समझती हूं कि कोई भी एस.एम.एस. हास्पिटल में चला जाए और याद करे दो साल पहले उस एस.एम.एस. हास्पिटल की हालत क्या थी? डाक्टर साहब, आप लोग सब यहां पर बैठे हुए हैं और अपने दिल के ऊपर हाथ रखकर अगर आप यह कह सकते हो कि उसकी स्थिति पिछले पांच साल से बेहतर नहीं है तो मैं समझती हूं कि कुछ गलती हो गयी परन्तु आज... (व्यवधान) आप प्लीज।

श्री जुबेर खान : आधा केबिनेट सो रहा है, अधिकारी सो रहे हैं, व्यवस्था करिये कि नींद नहीं लें। मैं सही कह रहा हूं कि अधिकारी और मंत्री आधे, नींद खेंच रहे हैं।... (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे : जितनी सफाई आज एस.एम.एस. हास्पिटल के अन्दर है, हम लोगों ने ओ.पी.डी. को वहां से निकालने, वहां से बाहर करने की कोशिश की है। हम लोगों ने एक कोशिश की है कि ब्लड वगैरह का जो इन्तजाम है, पैथोलाजिकल एग्जामिनेशंस को हम दो बिल्डिंग्स देकर बाहर उसका इन्तजाम करने की कोशिश में हैं। और जो आपके कार्टेज वार्ड हैं उनको बिल्ट अप करने की कोशिश है ताकि जो आपरेशन थियेटर की कमी हो रही

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

थी वह आपरेशन थियेटर बने। कई नयी चीज उस एम.एम.एस. हास्पिटल में बनी है और उसका लाभ राजस्थान के पूरे निवासियों को जाएगा और उसके साथ-साथ जो हरियाणा से, जो यू.पी. से और दूर-दूर से लोग आते हैं, उनको भी उसका फायदा मिलेगा। मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा काम हम लोगों ने, राजस्थान की सरकार ने किया है।

अब यह बीकानेर रेल बाई पास। बीकानेर रेल बाई पास के लिए भाई साहब मैं क्या कर सकती हूं ? मैं इतना ही बताऊं आपको कि पहले तो 60 करोड़ रुपये का वह काम था और अब बढ़कर वह 100 करोड़ रुपये का हो गया है। और हमने एक एम.ओ.यू. को अनुमोदित करके 2004 के अन्दर रेल मंत्रालय, भारत सरकार को भेज दिया था और यह अभी तक निर्णय उनसे अपेक्षित है। रेलवे विभाग द्वारा इसकी उपयोगिता के ऊपर अब शंका प्रगट हो गयी है और वे कहते हैं कि यह अनुपयोगी है। वे कहते हैं कि फिजिबल नहीं है। और समस्या के तात्कालिक समाधान के लिए के.ई.एम. रोड के ऊपर वह एलिवेटेड रोड, मंत्री महोदय जिसके बारे में आपको बता रहे थे, वह बात सही है। वह कहे कि एक एलिवेटेड रोड और गजनेर रोड पर आर.ओ.बी. बनाकर और इसकी निविदाएं, तैयार कर दिया जाए। जनता से सुझाव लिया जाए। जनता से बात की जाए और एक पब्लिक प्लेस में इसका माडल बनाकर रख दिया जाए। और जिन-जिन से बात की है, अधिकांश जनता इसका समर्थन कर रही है। तो मैं समझती हूं कि वापस जाकर उनसे बात करके जो जनता चाहती है, वह अपन करें और इसको जल्दी कर लें। ... (व्यवधान)

अब हमारे भाई साहब, हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने यह कहा कि मेरे विधान सभा में, अब देखो तो कितनी कैसी बात की ? कुल 6 हैण्डपम्प ही लगाये गये हैं। तो थोड़ा सा और देख लेते भाई साहब, थोड़ा सा दौर कर लेते तो उसमें मालमू पड़ जाता कि नैनवा विधान सभा क्षेत्र में ... (व्यवधान) सारी-सारी, आपके नहीं, मैं नैनवां से आने वाले, आपके लिए तो मैं थोड़े ही कहती, रामनारायणजी से कहती हूं। नैनवां विधान सभा क्षेत्र के अन्दर 2005-06 के अन्दर कुल 276 हैण्डपम्प स्वीकृत हुए हैं जिनमें से 242 हैण्डपम्प निर्मित किये जाकर शुरू कर दिये गये हैं। इसके अतिरिक्त ग्रीष्म संवर्द्धन पानी के लिए ... (व्यवधान) 2006 के अन्तर्गत प्रथम फेज में स्वीकृत प्रस्तावों के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नैनवां के अन्दर 19 हैण्डपम्प और लगाये गये हैं।

श्री रामनारायण मीणा (नैनवां) : एक मिनट साहब, मैं माफी चाहता हूं कि यह माडा के हैं। यह माडा के हैं। मैंने माडा के लिए कहा है।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : और कुल 63 हैण्डपम्प लगाये जाने हैं जो आगामी दो माह में लग जाएंगे। ... (व्यवधान)

श्री महावीर प्रसाद जैन : आपने पचास साल में लगाये हैं क्या ? ... (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे : हमारे जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य सेज के बारे में बोलें। तो मैंने तो सेज के बारे में आपको समझा दिया है। और मैं यह बताना चाहती हूं कि यहां पर कोई ऐसी बात नहीं होगी जिससे राजस्थान को लाभ नहीं होगा।

आपने चिन्ता की कि बीसलपुर परियोजना का क्या होगा? वह चिन्ता हम सबको है, आपको अकेले को नहीं है। और मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि यह बहुत बड़ी योजना 1100 करोड़ रुपये की है। और इसका ट्रांसमिशन भाग, जिसके लिए 556 करोड़ रुपये, उसका ट्रांसफर भाग, जिसके अन्दर 463 करोड़ रुपये का काम चालू हो चुका है। और इस प्रकरण में जून, 2005 से 8 फरवरी, 2006 तक स्थगन आदेश के अन्दर यह कोर्ट में रहा और अब ए.डी.बी. की स्वीकृति प्राप्त होने के बाद तीस माह में यह कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। और अगर अच्छी तरह से अभी चालू हो गया तो मैं समझती हूं कि बहुत जल्दी यहां जयपुर के अन्दर पानी मिल जाएगा।

आपको बहुत चिन्ता हो गयी कि यह कर्बला क्षेत्र के अन्दर हज हाउस और सांगानेर में दूसरे हज हाउस के नक्शों का क्या हुआ ? हमें भी बहुत चिन्ता थी तो जब सब लोग आये, हमें बात करने के लिए तो उन्होंने कहा कि बड़ी मुश्किल से पांच साल में रोने-पीटने के बाद हम लोगों को हज हाउस के लिए एक ऐसी जमीन दी, एक बीघा और वह भी बड़ी मुश्किल से तो उन्होंने कहा कि हमें तो जरूरत है। और क्योंकि मैं हज में मंत्री रह चुकी हूं और मैं जानती हूं कि हज का कितना बड़ा आपरेशन होता है। इसलिए हमने तो यह तय कर लिया कि सांगानेर के अन्दर पांच बीघा भूमि वह 20.12.2005 को एक रुपये के टोकन पर हमने दे दी। और इसीलिए मुझे कभी-कभी हंसी आती है, जब लोग कहते हैं, क्योंकि हम लोगों ने किसी भी जाति के ऊपर या किसी भी मजहब के ऊपर कोई बीच में दीवार किसी की नहीं बनायी है। हमारी

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

कोशिश यह है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को सुरक्षित राजस्थान के अन्दर विकसित करें और अब इस भूमि के और जो हज हाउस हैं, वे नक्शे तैयार हो गये हैं। जनवरी, 2006 के अन्दर प्रस्तुत भी हो गये थे और अब वे पास भी हो गये हैं और बहुत जल्दी ही इसका काम भी चालू हो जाएगा। और मैं समझती हूं कि वह हज हाउस, मैं तो यह चाहती हूं कि हमारे समय, तीन साल के अन्दर एक बहुत बड़ा भव्य मकान, हमारे यहां पर हज हाउस बन जाएगा तो वह आपको याद दिलायेगा कि जो ... (व्यवधान) नहीं, आपको याद यह दिलाएगा कि जो आप नहीं कर सके थे इतने सालों में वह पांच साल में, यानि दो साल की अल्प अवधि के अन्दर हम लोगों ने कर भी दिया है। और पांच साल की सरकार के अन्दर उसको खड़ा करके आपके सामने मान्युमेंट बनाकर छोड़ेंगे। ... (व्यवधान)

अब आपको फिर चिन्ता हुई वह रिंग रोड वाली तो फिर आपने कहा कि हमारे पूरे किसान हैं, उनका क्या होगा? हम भी उन किसानों के लिए चिन्तित हैं। और आपको यह कहना चाहती हूं कि पूर्व में अवाप्त की गयी जमीन के अवाप्ति क्षेत्रफल में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया गया है। वह जो क्षेत्रफल है वह क्षेत्रफल रहेगा। जिस तरीके से उसका डिजायनिंग था, वह डिजायनिंग रहेगा और मैं चाहती हूं कि बहुत जल्दी बन जाए ताकि उसका फायदा सब लोगों को हो।

प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्दर आप बहुत चिन्तित हुए और आपने कहा कि हमारे बारे में भी कोई सोचे। मैं आपको बताना चाहती हूं कि क्यों नहीं सोचे? हमने तो 200 के 200 में सोच की है क्योंकि अगर 918 गांव, 918 किलोमीटर और 3043 गांव... (व्यवधान) नहीं-नहीं, 3918 गांव, 3043 गांव पांच साल में अगर जुड़े, और हमने अगर 3936 किलोमीटर, और 9470 गांव हमने अभी जोड़ दिये तो मैं समझती हूं कि कितना बड़ा काम हो गया है। तो आपका भी क्षेत्र इससे वंचित नहीं रहेगा। इतना फास्ट काम चल रहा है कि हर के क्षेत्र के अन्दर इसका असर आपको देखने को मिलेगा इसलिए माननीय सदस्य, आपको चिन्ता करने की जरूरत नहीं है। यह स्टेट्स के अन्दर पहला नम्बर राजस्थान के पी.डब्ल्यू.डी. को मिला है। यह इण्डिया टू डे के अन्दर भी आया है और इसका मुझे गर्व है।... (व्यवधान) नहीं, मैंने कहा था 9470 किलोमीटर और 3936 किलोमीटर, that's the other way round.

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

अब हमारे तारानगर से जो माननीय सदस्य आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि गरीबों को घरौंदा योजना के तहत घर उपलब्ध कराने का जिक्र आपने किया था और अब तक इसमें एक भी मकान आबंटित नहीं हुआ है। तो वैसे तो हमने कई स्कीम्स बनायी हैं। उसके अन्दर एक टाइम बाउण्ड पीरियड के अन्दर हम लोग काम करने जा रहे हैं पर घरौंदा के बारे में थोड़ा सा बता दूं कि यह 2004-05 में प्रारम्भ की गयी थी। इसके तहत 3480 मकानों का निर्माण किये जाने का लक्ष्य है। वर्ष 2004-05 में 418 मकान और 2005-06 में 2623 मकानों का कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है और जिनमें से 1948 मकानों का निर्माण पूर्ण कर लिया गया है और 1743 मकान लाटरी के द्वारा, उनका आबंटन किया जाएगा। लाटरी में सफल आवेदकों में से 770 आवेदकों को आबंटन-पत्र जारी किये जा चुके हैं और इनमें से 13 व्यक्तियों को पैसा जमा कराने के उपरान्त कब्जा भी दे दिया है और 31 मार्च, 2006 तक 480 मकानों का कब्जा दिया जाना सम्भावित है तो यह काम किया।

मैं तो यह कहना चाहती हूं कि पूरे पचास साल के अन्दर जो काम नहीं हुए हैं और आप हमसे यह चाहते हैं कि दो साल के अन्दर एक जादू की छड़ी चलाकर और दो साल के अन्दर उतना काम कर दें, जो पचास साल के अन्दर नहीं हुआ है। वह हमारी कोशिश है, हम कर रहे हैं। फिर एक बात आपने उठायी। मैं समझती हूं कि मेरा बहुत रेस्पैक्ट है आपके लिए क्योंकि मैं समझती हूं कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। बहुत अच्छा बोलते हैं सब कुछ इस हाउस के अन्दर। परन्तु आप जब कभी-कभी यह क्वेश्चन उठाते हैं तो दुःख होता है। ...

आपने बीमारू क्षेत्र के साथ-साथ यह भी कहा कि मुख्य मंत्री आवास पर अनाप-शनाप खर्च करके सुनामी रिलीफ के पैसे से हैलीकाप्टर खरीदा। किस-किस लेवल पर गये, इस लेवल पर मैं तो समझती हूं किसी को भी नहीं जाना चाहिये। क्योंकि मैं बता दूं सुनामी पीड़ितों के लिये एकत्रित की गयी राशि इनकी सहायता के लिये है और हम राजस्थान सरकार उस पैसे से हैलीकाप्टर नहीं खरीदेगी। इस लेवल तक हम लोग कोई भी नहीं जायेंगे। मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि उसके लिये करीबन 19.59 करोड़ रुपये अलग से कलेक्ट किये हैं और कांचीपुरम्, विल्लूपुरम और कुडलूर के पुनर्वास के लिये हमने आपदा प्रबन्धन और सहायता विभाग से आवास विकास संस्थान लिमिटेड द्वारा इसका काम चालू किया है। मैं बताना चाहती हूं कि मैं खुद गयी

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

थी, आई थिंक सितम्बर के महीने में, मुझे एग्जेक्टली ध्यान नहीं है, पर सितम्बर के महीने में वहां गयी थी। उसके बाद जोरदार मानसून हुई है, वहां पोंगल भी आया था, छुट्टियां भी थीं। उनके अधिकारियों के साथ हमारे अधिकारी बात करके तीन करोड़ खर्च किये हैं और उनको यह कह दिया है कि जल्दी से जल्दी जितने पास करना है, पास करके बहुत सुन्दर और शानदार बिल्डिंग्स वहां बनेंगी। और आप कभी वहां जाओगे, उसको देखकर आप खुद खुश हो जाओगे और फिर कभी यह बात नहीं कहोगे।

जहां तक सी.एम. हाउस के ऊपर खर्चा किया है या सचिवालय के ऊपर खर्च किया है मैं अपने घर तो ले नहीं जा रही हूं। मैं समझती हूं सी.एम. हाउस के अन्दर कोई आता है और उसको देखता है तो वह यह तो कहेगा न राजस्थान सरकार कंगाल नहीं है और हमारी इज्जत बनी रहेगी। इसलिये मैं आपको यही कहना चाहती हूं कि अब वह जमाना गया जब हम भीख के कटोरे लेकर किसी के सामने खड़े हों। हम सबको स्वाभिमान के साथ और इज्जत के साथ सिर ऊंचा करके कहना है कि राजस्थान का वासी किसी के सामने गिड़गिड़ायेगा नहीं। कोई भी हमारे सचिवालय में आयेगा तो वह यह नहीं कहेगा कि कहां आ गये, और यह तो भिखारी है इनको पैसा नहीं देना हमें। और अगर हम पैसा दे देंगे तो यह वापस कर सकेंगे ? यह हमें जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं एक ऐसी जगह हो जो लोग आयें वहां वह रेस्पैक्टफुली आये और इज्जत के साथ वह जाये। और कहे कि हां, यह राजस्थान की सरकार है और इसको हमने बनाकर रखा है।

दूसरी बात फिर बहुत सारे लोगों ने कहा आई.जी.एन.पी.के अन्दर और पानी के अन्दर आप हमारी बात नहीं रखते हो और लड़ते नहीं हो। तो मैं कहना चाहूंगी कि अन्तरराज्यीय जल विवादों के ऊपर हम लोगों ने पुरजोर अपनी आवाज उठायी है। और हमने यह कोशिश की है कि रावी-व्यास के पानी का जो मसला है वह जल्दी से हल हो जाये। उसका पानी हम लोगों को जल्दी से जल्दी मिले। आप सब इस चीज से वाकिफ हो कि पंजाब सरकार ने जल के सभी अनुबन्धों को निस्तारित किये जाने की अधिसूचना जारी कर दिये जाने के कारण राजस्थान की पहल पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने माननीय उच्चतम न्यायालय को रेफरेंस किया था और रेफरेंस में जल्दी सुनवाई हो उसके लिये हम बहुत प्रयासरत हैं। इसके बारे में मैं खुद माननीय

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

सदस्यों और सांसदों के साथ प्रधान मंत्री से जाकर मिली। उनसे हमने निवेदन किया कि बहुत जल्दी हमारी सुनवाई करें। और विशिष्ट बैंच का वहां गठन करवाया जाये। और कार्यवाही आज के दिन भी भारत सरकार के स्तर पर लम्बित है। दिनांक 25-10-2005 को शिमला के अन्दर माननीय गृह मंत्री भारत सरकार की अध्यक्षता में हुए नोर्दर्न जोनल काउंसलिंग की मीटिंग में उन्होंने यह मुद्दा पुरजोर ढंग से वहां उठाया था। जहां तक यमुना जल के 1994 के समझौते की क्रियान्विति का संबंध है, मैं इतना कहना चाहूंगी कि राजस्थान को आबंटित 1.119 बीसीएम पानी के उपयोग के लिये हरियाणा सरकार से हमने बार-बार निवेदन किया है। उसके पश्चात् भी एम.ओ.यू. पर वह किसी न किसी बहाने से दस्तख्त नहीं कर रहे हैं। हरियाणा सरकार आंशिक रूप से 1994 में हुए समझौते पर अपर यमुना रीवर कमेटी के समक्ष विवाद कर रही है जिसे हम पुरजोर ढंग से राज्य के हितों की रक्षा के लिये अपना पक्ष रख रहे हैं।

मध्य प्रदेश ने गांधी सागर कैचमेंट में 2003 से पहले, यानि किसकी सरकार थी 151 एनीकट, जिनकी कुल भराव क्षमता 85 एम.ए.एफ. है, वह बनाये हैं। इसके बारे में मध्य प्रदेश राजस्थान कंट्रोल कमेटी स्थाई समिति की बैठक दिनांक 28-5-2005 को हुई जिसमें हमने निर्णय किया कि गांधी सागर बांध की यील्ड स्टेडी केन्द्रीय जल आयोग से कराई जाये। और मध्य प्रदेश ने हम सबको यह भी आश्वस्त किया कि गांधी सागर के कैचमेंट एरिये में अब कोई नया एनीकट नहीं बनायेंगे तो हमारे पांच साल के अन्दर हम उसको सुरक्षित रखेंगे। केन्द्रीय जल आयोग को यील्ड स्टेडी हेतु दोनों राज्यों ने अपनी अपनी हिस्सा राशि भेज दी है। इसलिये जब आप कहते हो इसके लिये हम लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे थे, मैं आपको कहना चाहूंगी कि उसमें हमने कोई कमी नहीं छोड़ी है। अब माननीय सदस्य बहादुर सिंहजी ने कहा कि यह हमको फसल बीमा का लाभ नहीं मिल रहा है। इसका कुछ करो। वह कहते हैं तहसील को यूनिट मानकर मुआवजे का भुगतान करो। मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगी कि यह केन्द्रीय सरकार की योजना है और हमको दिशा-निर्देश के अनुरूप ही तहसील को यूनिट मानकर फसल कटाई प्रयोगों के आधार पर औसत उत्पादन की गणना करना होगा। यह स्कीम उनके द्वारा हम लोगों को दी गई है। इसमें चेंजेज राजस्थान की सरकार द्वारा नहीं हो सकते। पर मैं

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

विश्वास करती हूं कि कोई प्राब्लम होगी तो इस बात को हम ऊपर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे।

दीगोद क्षेत्र से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि किसानों के लिये बहुत सारी घोषणाएं हुई हैं, फायदे की बात आप लोगों ने की है परन्तु कोई फायदा नहीं दिया है। लम्बा काम है, इसमें हम लोगों ने कितना तो पानी का काम करवाया, कितना आबियाना माफ किया, कितनी नहरों को ठीक किया, कितने फव्वारे हमने दिये, कितने डी.ए.पी. और फर्टिलाइजर पहुंचाया, कितने नये सोयल कंजर्वेशन के यूनिट्स खोले, बहुत सारी चीजें हमने की हैं। उन्न्त बीज की उपलब्धि करवाई, कितने क्विंटल बीज हमने दिलवाये, वह सब आपके सामने है। वह सब लोगों ने गिनवा दिये इसलिये मैं बार-बार उसको नहीं कहूंगी। पानी की कमी के कारण काश्तकारों ने सरसों की खेती को अपनाया है, यह आपने कहा है। मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि पिछले साल रिकार्ड उत्पाद हुआ और यह रिकार्ड उत्पाद कैसे हुआ ? आप कह रहे हो कि पानी नहीं मिलता। पानी नहीं मिलता तो हवा से तो नहीं हुआ, अच्छा पानी हुआ, अच्छी बरसात हुई। इसलिये 14 लाख मीट्रिक टन तक प्रिक्योरमेंट हुआ। मैं आपको यह भी कहना चाहती हूं कि जिन-जिन लोगों ने हमारे सामने यह बात कही कि गोदाम भरे हुए हैं, उसका क्या होगा ? मैं आपको बताना चाहती हूं कि 10 लाख मीट्रिक टन रखने तक गोदाम हमने खाली करवा दिये हैं। नई फसल आयेगी तो उसके अन्दर जमा करने के लिये हमारे पास पर्याप्त जगह है और नेफेड वगैरह से हम लोगों ने बात कर ली है। वह लगातार इस सामान को निकालते जायेंगे तो मैं समझती हूं कि हम लोगों को उसकी कोई कमी नहीं आयेगी, उसकी कोई प्राब्लम नहीं आयेगी। आपको उसकी चिन्ता नहीं करनी।

काली सिंध और परवन नदी का पानी व्यर्थ बहना, क्योंकि वह हाड़ौती क्षेत्र के हैं इसलिये उनको चिन्ता है। इसलिये में समझती हूं उनकी चिन्ता और पीड़ा को। मैं कहना चाहूंगी काली सिंध और सहायक नदी में अब तक तीन मध्यम और 35 लघु सिंचाई परियोजनाओं द्वारा 36 हजार हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा हमने उपलब्ध करवाई है। 11 लघु सिंचाई परियोजनाओं में 3 मध्यम और एक वृहद् सिंचाई परियोजना प्रक्रियाधीन है। और इससे लगभग 14,200 हैक्टेयर भूमि में सिंचाई सुविधा हो सकेगी। इसी तरीके से सब माननीय सदस्यों ने अपने बहुत ही अमूल्य सुझाव हमारे सामने रखे।

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि चुनाव घोषणा पत्र में घोषणा की थी प्रतिवर्ष एक लाख लोगों को रोजगार देंगे तो क्या हुआ ? देखिये, जब हम लोग वायदे करते हैं तो उनको पूरा करने की कोशिश करते हैं। और इसीलिये मैं बताना चाहूंगी कि राजकीय विभागों के अन्दर हम लोगों ने सब मिलाकर अध्यापक, सहयोगिनी, साथिन, पटवारी वगैरह लेकर 78,300 पद हम लोगों ने नौकरियां दीं। उद्योग के अन्दर पिछले दो सालों के अन्दर 2 लाख 38,754 हमने नौकरियां दीं। अगर आप इसकी गिनती कर लेते हैं तो दो साल के अन्दर मैं आपको यह कह सकती हूं कि 3,13,074 नौकरियां दीं। जो मेरी जानकारी में हैं, दी हैं। इस तरीके से महिला स्वयं सहायता समूह तो 4300 ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : सहयोगिनी नौकरी है क्या ? 700 रूपये देते हैं आप। आप नौकरी मानते हो तो बहुत बढ़िया है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : सहयोगिनी नौकरी नहीं है, अगर यह नौकरी नहीं है तो पांच साल में यही कर देते न ? अगर यह नौकरी नहीं है तो यह दिलवा देते। मैं समझती हूं कि यह प्राब्लम नहीं होती। परन्तु इसमें पैसा तो खर्च होता है और हम लोगों ने इन सबको इकट्ठा करके तीन लाख रोजगार उत्पन्न करवाये, यह रोजगार है। इसको रोजगार में आप गिनोगे।

और इसी तरीके से रोजगार सृजन जो हुए हैं उसमें 433.23 लाख मानव दिवस, काम के बदले अनाज, सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अन्दर रोजगार सृजन वानिकी कार्य के अन्दर 313 लाख मानव दिवस और स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना के अन्दर 57,908 स्वरोजगार। यह हुए हैं।

तो मैं यह समझती हूं कि बहुत सारा हुआ है, यह शुरूआत है। जी, अभी और होगा, चिन्ता मत करो आप।

माननीय सदस्य ने यह भी कहा कि वार्षिक योजनान्तर्गत पर्याप्त व्यय ही नहीं किया गया है तो आकार बढ़ाने का क्या फायदा ? और गत वर्ष के बजट में विभिन्न मदों में व्यय का प्रावधान किया गया था, उनमें वास्तविक रूप से किया गया व्यय 20 से 60 प्रतिशत तक ही रहा है। तो मैं आपको बताना चाहूंगी कि 2003-04 वार्षिक योजना 5504, उसको हमने 6044 करोड़ तक व्यय किया और वह 145 प्रतिशत तक था और यही वार्षिक योजना 2004-05 में 6797 करोड़ की थी जिसके विरुद्ध 6590 करोड़ रुपये

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हमने व्यय किये जो लगभग उसका 97 प्रतिशत था। और अभी मैं आपको कहना चाहती हूं कि 54 प्रतिशत और जनवरी के अन्दर 66 प्रतिशत। और मैं आपको यह कह सकती हूं कि जब तक हमारा 31 मार्च का समय आ जायेगा तब तक बहुत अच्छी तरह से खर्चा हम लोग करके आपको बता देंगे।

इसी तरीके से आपने यह कहा है कि राज्य सरकार ने 15,778 गांव अकालग्रस्त घोषित किये हैं। तो मैं आपको बताना चाहती हूं कि यह अकालग्रस्त घोषित किये, अब अकाल नहीं भी है फिर भी हम इस कोशिश में हैं कि ज्यादा से ज्यादा नौकरियां प्रोवाइड करें। अकालग्रस्त जहां-जहां 15 हजार गांवों के अन्दर हम लोगों को कमी महसूस हुई है तो वहां हम लोग देने की कोशिश कर रहे हैं, भगवान की दया से मैं समझती हूं कि बरसात अच्छी रही है और नुकसान जहां-जहां हुआ है, चाहे ओलावृष्टि हुई तो पहली दफा राजस्थान की हिस्ट्री में हमने ओलावृष्टि तक को मुआवजा दिया जो किसी और सरकार ने अभी तक नहीं दिया था।

श्री महावीर प्रसाद जैन : कभी दिया है आपने ओलावृष्टि में? कभी गये हो वहां ओलावृष्टि में ? (व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (मुख्य मंत्री) : इसी तरीके से चारे की समस्या की जिलों के अन्दर जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, अजमेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, सिरोही, जालौर, अनुदानित दरों पर चारा वितरण करने के लिए 346 चारा डिपो हम लोगों ने स्वीकृत कर दिये हैं, उनमें से मुझे लगता है कि करीब 60-70 तो चालू आलरेडी हो चुके हैं, दूसरे भी चालू अभी जल्दी हो जायेंगे और चारा परिवहन अनुदान दरें दूरी के अनुसार 50 रुपये से 60 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित की गयी है। सो, यह सब काम हैं। यह माहिर साहब का था।

सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, श्री संयम लोढ़ा ने भी यह बात की कि वृद्धा अवस्था पेन्शन का बजट 96 करोड़ से बढ़ा कर 200 करोड़ कर दिया जाए, तो मैं बताना चाहूंगी कि 13,924 लाख रुपये के प्रावधान के विरुद्ध 12,570 लाख रुपये व्यय करके 6 लाख व्यक्ति और वर्ष 2005-06 में 13,515 लाख रुपये के प्रावधान के विरुद्ध 10,673 लाख रुपये व्यय करके 6 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित किया है।

विधवा की पुत्रियों के विवाह पर 10 हजार रुपये और आपने यह कहा कि सिरोही जिले के अन्दर 1600 फार्म लम्बित हैं जिन्हें नौ माह से लम्बित हैं।

श्री संयम लोढ़ा : आपको सारी सूचनाएं गलत दी गयी हैं, पूरे राजस्थान के 1600 फार्म बाकी हैं। सुनिये आप, आपको गलत इन्फोर्मेशन दी गयी है...(व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे : जो तथ्य आपके सामने था...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य, आप बाद में बोल लेना, बीच में नहीं बोलेंगे।

श्री संयम लोढ़ा : अध्यक्ष महोदय, सिरोही जिले का जिक्र नहीं किया, पूरे स्टेट की बात हो रही थी।

श्री अध्यक्ष : बीच में नहीं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : सूट नहीं करे तो फिर कैसे...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : क्या कोई बिच्छू काट रहा है क्या...(व्यवधान) क्या हो गया?

श्रीमती वसुन्धरा राजे : फिर आपने भी एक नयी बात निकाली, आपने यह कहा कि राजस्थान का मुख्यमंत्री है। सब लोग जानते हैं कि राजस्थान सबसे बड़ा प्रदेश है इस देश का। और सब लोग जानते हैं कि आज की दुनिया के अन्दर कम्यूनिकेशन एक ऐसी चीज है जिसको अपने को जल्दी से जल्दी उसको इस्तेमाल करने की कोशिश होनी चाहिए। आपने यह कहा कि 200 से ज्यादा हवाई यात्राएं की हैं मुख्यमंत्री ने दो साल के अन्दर वह भूल गये कि अशोक गहलोत साहब ने 900 से ज्यादा यात्राएं कीं अपने पांच साल के अन्दर। तो जहां तक उसकी गिनती करा लो आपको मालूम पड़ जायेगा। हमने तो इस बात को उठाया इसलिए नहीं क्योंकि मैं समझती हूं कि हरेक मुख्यमंत्री को करनी चाहिए ताकि वह जल्दी से जल्दी अपने क्षेत्र के अन्दर पहुंच सके।

श्री महावीर प्रसाद जैन : और उन्होंने काम भी कुछ नहीं किया, खजाना खाली है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : काम करना जरूरी है, जायेंगे। हिण्डौली से आने वाले माननीय सदस्य ने बहुत सारी बातें मेरे सामने कहीं, मुझे उनका कागज मिल जाए, उन्होंने सेज की बात की, उन्होंने रिडकोर की बात की, प्लानिंग कमीशन की बात की, बीमारू वाली बात भी उन्होंने की। तो वह तो मैंने उनको बता दी। सेज की भी बात मैंने उनको बता दी। और उनको ला एण्ड आर्डर पर बहुत चिन्ता हुई। तो पहले तो मैं रिडकोर का ले लूं, बता दूं

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

आपको कि रिडकोर के बारे में क्या कहा गया है। क्योंकि राजस्थान के अन्दर हम लोगों ने कुछ अच्छा ही किया होगा इसलिए हम लोगों को यह टिप्पणी हुई है। यह एक बहुत जानीमानी और अच्छी मैग्जीन है, उसका नाम है इंडियन इन्फ्रास्ट्रक्चर, उसमें रोड एण्ड ब्रिजेज के बारे में उन्होंने लिखा है, राजस्थान मेगा हाई-वे प्रोजेक्ट और यह कहते हैं :-

"New Development Model. Traveling on Rajasthan Roads would soon become a delightful experience. The agent of change is the Rajasthan Mega Highway Project which aims to improve and maintain important road corridors within the state. The project will set new benchmarks in many respects. For, one, it is the biggest private sector road project undertaken by the State. If successfully implemented it would mark the credibility of the new privatization model that has been employed." और आखिर में वो यह कहते हैं :-

"Project benefits. The North-South Project Roads would shorten the distance by 80 to 100 Kms. Compared to the competing National Highway stretches leading to savings in both vehicle operating costs and time. Thus it is expected that traffic will be diverted away from the National Highways to the Project Corridors leading to the economic development of the adjoining villages. इसके बाद वो कहते हैं :-

"…moreover entrusting the roads to RIDCOR on a long term basis has obviated the needs for the state Government to spend on maintenance and upkeep and this step would lead to savings of Rs. 30 billion." Not million. "The savings could be utilized by the State Government for maintenance and upkeep of other roads and infrastructure facilities that may not be amenable to investment on a commercial basis. The project will significantly enhance the tourist potential of the State as better connectivity would open up hitherto inaccessible spots. RIDCOR also proposes to take up community development and environmental protection measures as part of the project and it has earmarked 200 million for this purpose. Prior to this project about 25 private road projects involving small investments have been completed in Rajasthan. The success of a project of such magnitude will certainly help in building the case for public-private partnership projects in India."

श्री विष्णु मोदी : मैडम, टेल दैम कि बिलियन, एक बिलियन में कितने रुपये होते हैं Five thousand crore rupees for one billion.

डा. सी.पी. जोशी : मैडम, यह इश्यू नहीं है. Why he is intervening ?

श्रीमती वसुन्धरा राजे : Let me finish. I have told him also.

आपको मैं कह रही हूं प्लीज। इसी तरीके से माइकल कारटर, जो कंट्री डाइरेक्टर फोर इंडिया हैं वर्ल्ड बैंक के, उन्होंने 8 जुलाई, 2005 को चीफ सेक्रेटरी को चिट्ठी लिखते हुए कहा राजस्थान में :-

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

"It is gratifying to learn about the performance of the banks projects in Rajasthan as reflected in the disbursement ratio for 2005 of 21% and the fact that there are no project at risk in the State's current portfolio. We are particularly impressed with the Rajasthan's performance in the rural roads project with all contacts for Tranche-I already awarded and on-going and all the procurement action for Tranche-II well underway. By the end of Tranche-III we believe all habitations of 19 districts having a population of 750 and above will be connected." यह भी आपका प्रश्न था, इसका भी जवाब हो गया.

"This is a significant achievement for which your team deserves credit. The physical works are proceeding exceedingly well under the Rajasthan Water Sector Projects. After initial teething problems the two education projects i.e. Rajasthan DPEP-I and II are progressing satisfactorily. On Rajasthan power, commendable progress has been achieved on the implementation of the Electricity Act and in the reduction of transmission and distribution losses."

और यह सोनियाजी के बिलकुल इनर सर्कल का एक बहुत अभिन्न अंग Visiting Professor at the G.B. Pant Social Science Institute of Ahemdabad, National Food for Work Programme in Times of India 2nd July 2005 mentions:

"The only place where the program emerged in a positive light was Rajasthan. Muster-rolls were authentic, contractors have been kept out, wages were quite close to the legal minimum, laborers had a favorable view of the assets created under the programme, and this shows that the programme can work but only if basic safeguards are in place starting with strong provisions for transparency and accountability."

यह जो कह रहे हैं वह हम नहीं कह रहे हैं, यह तो ऐसे लोग हैं जिनको बहुत सारे लोग देश के अन्दर भी और विदेश में भी अच्छी तरह से मानते हैं।

इसी तरीके से इण्डिया टुडे ने जो प्रकाशित किया था लेख ग्राम सड़क परिवर्तन का मार्ग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्दर उन्होंने कहा राजस्थान की जैसलमेर से 80 किलोमीटर दक्षिण में स्थित 300 की आबादी वाले छोटे से गांव राहू का पार के प्राइमरी स्कूल के बच्चे अभी एक साल पहले तक हफ्ते में दो दिन ही स्कूल जाया करते थे। इसकी वजह यह भी थी कि स्कूल में कोई स्थानीय शिक्षक नहीं था। बाहर के शिक्षक को गांव पहुंचने में तीन दिन लगते थे। जिसमें एक दिन ऊंट पर बैठकर सम गांव तक पहुंचना पड़ता था और घर लौटने में भी उसे दो दिन लगते थे। मगर मार्च, 2004 में जिसमें समधरणा मार्ग यह मार्च, 2004, अपन ने 8 दिसम्बर को टेक ओवर

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

किया है और मार्च, 2004 के अन्दर वह कहते हैं कि 21 किलोमीटर लम्बी सड़क बन जाने से स्कूल टाइम टेबल का हुलिया बदल गया है। अब शिक्षक हफ्ते में छह दिन पढ़ाता है जबकि उच्च प्राथमिक शिक्षा के लिए छात्र पढ़ने के लिए दूर डाबरी गांव जाते हैं। इसके साथ-साथ उन्होंने यह भी कहा कि राजस्थान राज्य प्रगति में प्रथम, इसमें इनका यह कहना है कि रोड्स के ऊपर उन्होंने एक समीक्षा दी है। और उसके अन्दर राजस्थान ने 11,120 किलोमीटर उन्होंने बनाया और 78.5 प्रतिशत लक्ष्य की प्राप्ति करके सब स्टेट्स के अन्दर इसमें दस स्टेट्स का नाम दिया है। जो उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, आन्ध्रा, कर्नाटक, उड़ीसा वगैरहा सबसे नम्बर एक के ऊपर आया है।

इसी तरीके से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्दर एन्युअल रिपोर्ट आयी जिसमें यह कहा है कि- ''Rajasthan is the leading state in the country. This year the Department will connect so many more and the World Bank has conveyed the appreciation to Rajasthan for its procurement of the tranches.

यह सब मैं इसलिए आपको बता रही हूं क्योंकि यहां जब अपन बात करते हैं ..(व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : सुदर्शनजी का बाकी रह गया और आडवाणीजी का बाकी रह गया वह भी कोट कर देना चाहिए। दो बाकी रह गये सर्टीफिकेट। एक तो सुदर्शनजी का बाकी रह गया जहां आप जाकर आए मुख्य मंत्रीजी, और एक आडवाणीजी का बाकी रह गया, वह भी बता दें। बाकी सब ठीक रहे।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : जोशीजी, आपने जब बात की तो हमने तो कुछ नहीं बोला, मैं समझती हूं कि थोड़ा सा पेशेंस रखकर सुनने में कोई प्राब्लम नहीं है। उसके बाद आपको जो कहना है आप कहें (व्यवधान)

डा. सी.पी. जोशी : I am supporting you. You have given so many examples. Why you are leaving the certificates of K. Sudershan and Advaniji? These two certificates are required. That's all. Everything is fine perfectly al-right

श्री महावीर प्रसाद जैन : आडवाणीजी ने तो सर्टिफिकेट देकर भेजा है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : मैं आपको यह कहना चाहती हूं कि पर्यटन के अन्दर भी राजस्थान ने बहुत अच्छा कार्य किया है और मैं इसको स्पेशली आपके सामने लाना चाहूंगी। जहां पांच वर्ष के अन्दर राज्य आयोजना में

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

लगभग 33 करोड़ रुपये व्यय होते थे उसको दो वर्ष के अन्दर 43 करोड़ रुपये व्यय किया है और जो संख्या देशी और विदेशी पर्यटकों की होती थी उसमें नया रिकार्ड स्थापित किया है। 2005 में 11.31 लाख विदेशी पर्यटक राजस्थान में आए और राजस्थान के इतिहास में यह सबसे ज्यादा नम्बर है। वर्ष 2002 के विदेशी पर्यटक आगमन की संख्या से तीन गुना अधिक है। और इसी तरह से देशी पर्यटक जो हैं उन्होंने भी एक रिकार्ड बनाया। 2005 में 188 लाख देशी पर्यटक राजस्थान आए और अब तक सर्वाधिक है। और वर्ष 2002 के देशी पर्यटक आगमन की संख्या से जो लगभग दो गुना है यह मैं सबके सामने बताना चाहती हूं।

मैं यह भी कहना चाहूंगी कि जयपुर एयरपोर्ट को अन्तरराष्ट्रीय एयरपोर्ट घोषित कर दिया है। उदयपुर हवाई अड्डे को अन्तरराष्ट्रीय स्तर का बनाने के लिए हम पूरा सहयोग दे रहे हैं। हमने अभी जमीन अवाप्ति करके नया काम वहां चालू कर दिया है और निजी हवाई सेवाओं के अन्दर भी वृद्धि हो गयी है। हमारे जो छोटे-छोटे एयर स्ट्रिप्स थे उनके लिए भी हम लोगों ने पैसा अलग कर दिया है परन्तु हमारी निजी हवाई सेवाओं से बातचीत चल रही है। हो सकता है कि यह छोटे एयर स्ट्रिप्स पर जाने का काम चालू कर दें ताकि यह हवाई सेवा सब लोगों को माने ज्यादा से ज्यादा डिस्ट्रिक्स के अन्दर भी लोगों को फायदा हो।

आमेर बोर्ड बनाकर हम लोगों ने आमेर का विकास चालू कर दिया है। बहुत सारे लोग उस आमेर विकास के अन्दर हैं। मीनाक्षी जैन के द्वारा उसका काम हम लोगों ने चालू कर दिया है। और मैं मानती हूं कि इसका एक लाइट एण्ड साउंड प्रोग्राम हम दीपावली या दीपावली के बाद तक तैयार कर देंगे। सबसे अच्छी बात यह हुई है कि राजस्थान के समस्त संग्रहालय जो हैं, उनके अन्दर हम लोगों ने विकास चालू किया है। और यह तो ऐसे ही पड़े रहते थे और पहली दफा इसके अन्दर पांच हजार वस्तुओं से ज्यादा का डिजिटाइजेशन करा दिया है और लगभग चार हजार पाण्डुलिपियों की माइक्रो फिल्मिंग पूरी हो गयी है। और डाक्यूमेंटेशन जो है, ओवर थ्री एण्ड हाफ लाख आब्जेक्ट था, वह हमने पूरा कर दिया है। और यह पहली दफा देश के अन्दर हुआ है और राजस्थान के अन्दर हम लोगों ने किया है। यह अपने आप में मायने रखता है।

अब हमारा यह फेवरेट, जो मैं नाथद्वारा से आने वाले माननीय सदस्य के साथ शेयर करती हूं। इसमें मैं जानती हूं कि हम और वह एक हैं क्योंकि

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

नाथद्वारा के अन्दर नाथद्वारा मंदिर मण्डल के द्वारा मन्दिर विस्तार लाल बाग़ सौन्दर्यीकरण, गोवर्द्धन परिक्रमा, ऐसे काम हम लोगों ने चालू कर दिए हैं और अभी तक करीब तीस करोड़ रुपये का काम हम लोगों ने चालू कर दिया है। निजी सम्पत्तियों का अधिग्रहण भी हम लोग धीरे-धीरे करके उसको वाइडनिंग जो उसकी ब्यूटीफिकेशन हम करना चाहते हैं, ठीक है वह बालाजी जैसी तर्ज के ऊपर तो नहीं होगा, परन्तु हमने सपना देखा है कि उस तर्ज तक हम उसको ले जाने की कोशिश करेंगे। एक रिलीजियस टूरिज्म के हिसाब से एक बहुत बड़ा तर्ज है और मैं समझती हूं कि यह अगर सफल हो जाता है तो हमारे बहुत ऐसे हैं केलादेवी है, खाटू श्यामजी हैं बहुत जगह ऐसी हैं जो इसके अन्दर भी आ सकेंगी और जिनके अन्दर हम लोग यह इम्प्रूवमेंट कर सकेंगे। इसलिए मैंने कहा कि नाथद्वारा के अन्दर मैं पहले आप लोगों को इसके बारे में बताऊं, यह बहुत जरूरी और बहुत यूजफुल काम हम लोगों ने कर दिया।

डा. सी.पी. जोशी : बहुत अच्छा हो रहा है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे : अब आखिर में हिण्डोली से आने वाले माननीय सदस्य बहुत चिन्तित हो रहे थे कि ला एण्ड आर्डर का क्या करने वाले हैं। ला एण्ड आर्डर के अन्दर कुछ नहीं हुआ है। ला एण्ड आर्डर आप तो चाहते हो कि बिलकुल जीरो बन जाए हम भी चाहते हैं कि जीरो बन जाए परन्तु यह तो फिजिकली और ह्यूमनली इम्पासिबल है कि कोई भी स्टेट के अन्दर ला एण्ड आर्डर सिचुएशन बिलकुल जीरो बन जाए। हमारी कोशिश यह है और इसीलिए हमारे गृह मंत्रीजी, हमारा पूरा पुलिस विभाग इसमें लगा हुआ है। और मैं देख रही हूं कि उन्होंने किस तरीके से कई ऐसे सेंसेटिव केसेज को हैंडल किया है जो मैं समझती हूं कि उनकी पीठ हम सभी लोगों को थपथपानी चाहिए। क्योंकि रोज अगर हम यही कहें अच्छा काम करने के बावजूद भी कि तुम तो वैसे ही काम करते हो और प्रोत्साहन उनको नहीं मिले, मैं समझती हूं कि एनरजाइज करने के लिए यह जरूरी है कि हम लोग इस चीज को रिकगनाइज करें और उन लोगों की पीठ थपथपा कर उनको बोलें कि आपने बहुत अच्छा काम यह किया है और आगे करें और प्रोत्साहित करें। और मैं आपको यह बताना चाहती हूं कि राजस्थान के अन्दर 2.7 क्राइम रेट की तुलना में महाराष्ट्रा में 6.8, बिहार में 10.09, केरला में 22.11, कर्नाटक में 11.04 और हिमाचल प्रदेश में क्राइम रेट 11.07 प्रति लाख जनसंख्या है। अगर हमारी आप उससे तुलना कर लें तो आप देख लेंगे कि हम अच्छी पोजिशन में

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

हैं। मैं यह नहीं कहती और मैं समझती हूं गृह मंत्री या कोई नहीं कहेगा कि इसमें इम्प्रूवमैंट करने के लिए जगह नहीं है। हम तो करने की कोशिश करते रहेंगे परन्तु यह भी हम रिकगनाइज करें कि अच्छा काम हुआ है। इण्डिया टुडे ने 15 अगस्त, 2005 पत्रिका के अन्दर और मैं भी वहां उस कार्यक्रम में थी, यह कहा कि केरला और तमिलनाडु के बाद तीसरे नम्बर के ऊपर राजस्थान स्टेट है। मैं समझती हूं कि बहुत बड़ी बात है और हम लोगों को उनको सराहना चाहिए।

इसके साथ-साथ कुछ ऐसे केसेज हैं जिनका मैं उदाहरण आपके सामने रखना चाहूंगी बैंक कर्मी की हत्या करा बाइस लाख लूट के प्रकरण का पर्दाफाश, जिला जयपुर शहर दक्षिण जयपुर के अन्दर किया गया है और इसमें अनुसंधान सी.आई.डी(सी.बी) को एस.ओ.जी टीम द्वारा किया जा रहा है। इनके द्वारा मुलजिमान राधेश्याम और यह तो बहुत ही फास्ट पकड़ा गया था। और इसी तरीके से एक बहुत बड़ा केस जो यह वन्य जीव अपराध अब आप स्वयं जानते हो कि शेर का वेनेशिंग टाइगर्स सरिस्का के अन्दर टाइगर नहीं हैं, रणथम्भौर के अन्दर टाइगर कम हो गए हैं यह राजस्थान के लिए बहुत ही गम्भीर मामला है। हम लोग बहुत इससे दुखी हुए हैं परन्तु यह एक रात का या दो साल का काम नहीं है। यह काम धीरे-धीरे पूरे सरिस्का के सब बांध चले गये इसका मतलब यह तो कई दिनों से चलता आ रहा है और इसी तरीके से रणथम्भौर के अन्दर काम हुए उसके ऊपर और हम लोगों ने उस समय प्रधान मंत्री जब आए उनके सामने हमने यह कहा कि अभी बहुत सालों से फोरेस्ट डिपार्टमेंट के अन्दर भर्ती ही नहीं हुई है, कितने जो लोग हैं जिनको घूमना पड़ रहा है उनकी उम्र बहुत हो गयी है तो वह घूम नहीं पा रहे हैं। जिनकी बंदूकों को अपग्रेड हम लोगों ने नहीं किया है। जिनकी जीपें, गाड़ी फोरेस्ट के अन्दर उसकी अपग्रेडेशन नहीं हुई है। उसके लिए फुल हम लोगों को पैसे की जरूरत होगी तो अगर इनको हम लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है तो इसमें पैसे की जरूरत होगी। और प्रधानमंत्रीजी से हमने बात करके सौ करोड़ रुपया उनसे मांगा कि केवलादेव के अन्दर सरिस्का के अन्दर और रणथम्भौर के अन्दर आप हमारी मदद इसमें कर दीजिए। बात तो बहुत हुई परन्तु उसके बाद एक पैसा हम लोगों ने देखा नहीं। हमारी तरफ तो एक पैसा नहीं आया और सरकार की ओर से हमने कहा कि बस और कुछ नहीं तो जब सी.बी.आई. की इतनी बड़ी जांच यहां करा ली तो सी.बी.आई. को ही इस्तेमाल करके उन

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

अपराधियों को पकड़ लेते जिन्होंने यह बदमाशियां करी हैं। और मैं कहना चाहती हूं और मैं सराहना चाहती हूं राजस्थान की पुलिस की, जिसने एस.ओ.जी और कोटा ग्रामीण की पुलिस ने जाकर मध्य प्रदेश के अन्दर

(समय : 20.00 बजे)

उनको पकड़ा। तिब्बत तक उनको पकड़ कर और पूरे देश के अन्दर अन्तरराष्ट्रीय गिरोह को पकड़ कर सबके सामने रखा। यह राजस्थान की पुलिस ने करके दिया। यह जाल तस्करों का पूरे देश के अन्दर फैला हुआ था। शेर और तेंदुए की खाल की तस्करी हो रही थी और इसको राजस्थान की पुलिस ने पकड़ा। और जबकि इतनी बात हमको दिल्ली की सरकार से सुननी पड़ती थी, यह राजस्थान ने करके दिखाया।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध, 36 घंटे के अन्दर-अन्दर जो 12 मई, 2005 को जोधपुर शहर के अन्दर जर्मन महिला के साथ बलात्कार प्रकरण हुआ था, 36 घंटे के अन्दर-अन्दर न्यायालय के अन्दर चालान भी प्रस्तुत कर दिया और 15 दिन के अन्दर अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सज़ा भी सुना दी। तो यह कैसे भूल रहे हैं लोग ? इसके साथ-साथ 12 जून, 2005 को कानोता थाने के अन्दर एक बच्ची के साथ जो बलात्कार हुआ था, 7 दिन में न्यायालय में चालान प्रस्तुत करके उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुना दी। इसी तरीके से 24.11.2005 को विधायकपुरी थाने के अन्दर जो विदेशी महिला के साथ छेड़छाड़ के मामले में बात हुई थी उसके अन्दर तुरन्त ही चालान न्यायालय में पेश कर दिया और छह माह के कारावास की सज़ा उनको सुना दी। इसी तरीके से 26.12 को जालूपुरा इलाके में अमेरिकन महिला के साथ अपहरण जो छेड़छाड़ की थी, उन दो प्रमुख अभियुक्तों को सात-सात वर्ष की सज़ा सुना दी गयी है। 17.1. को नवलगढ़ में जो कुछ हुआ उसके दूसरे दिन ही अभियुक्त को एक वर्ष की सज़ा करवा दी गयी।

जहां नशीले पदार्थों की बात थी, राजस्थान पुलिस ने 8.5 किलो ब्राउन शुगर, 40 किलो स्मेक, 30 किलो हेरोइन, 934 किलो अफीम, 2395 किलो गांजा जब्त करके अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही की है।

आतंकवादी का जो प्रकरण है 26 दिसम्बर, 2005 का, इसके बारे में आप सब लोग जानते हो जब कश्मीरी आतंकवादी शब्बीर अहमद को उन्होंने गिरफ्तार करके 3 ए.के. राइफल उनसे लिये। साम्प्रदायिक घटना के अन्दर वर्ष

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

2004-2005 में कोई साम्प्रदायिक दंगा नहीं हुआ। साम्प्रदायिक घटनाएं गत दो वर्ष में केवल चार बार हुई हैं और वर्ष 2002 में इनकी संख्या 62 थी, वर्ष 2004 में यह 15 और वर्ष 2005 में 19 घटनाएं हुई हैं। ला एण्ड आर्डर की रैंकिंग के अन्दर राजस्थान इज नम्बर थ्री। मैं समझती हूं कि यह जवाब मैं माननीय हरिमोहनजी को देना चाहती थी और हरिमोहनजी, मैं यह समझती हूं आप यहां बैठे हुए हो, मैं कहती हूं कि कोई भी नाबालिग बच्ची के साथ इस तरीके का व्यवहार करे उसको तो जेल क्या उसको तो जिन्दा मार कर टांग देना चाहिये।

मैं समझती हूं आप जो भी यहां बैठे हुए हैं आप लोगों के अन्दर भी यह फीलिंग होनी चाहिये। मैं समझती हूं कि जब क्राइम के बारे में आप इतनी बात कह रहे हो तो जब क्राइम प्रोटक्शन के लिये हम लोग कोई एक्ट या बिल लाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको यह कहना चाहिये। इसके ऊपर सार्थक बहस करके हम वह स्थिति बनायें कि कोई भी आदमी इस तरीके का व्यवहार करके, चोरी-चपाटी या बदमाशी करके फारिग या फ्री नहीं जा सकता। इसके लिये हम और आपको मिलकर बात करनी चाहिये। मैं आपको आज सब लोग जो यहां बैठे हुए हैं, यह पार्टी विशेष की वजह से नहीं, या किसी जाति की नहीं, या किसी मजहब की बात नहीं करती हूं। यह सदन हमारा बहुत ही सम्माननीय सदन है, हम लोग सब इसमें, राजस्थान के सब लोगों ने सबको वोट दे देकर इस सदन के अन्दर भेजा है। मैं समझती हूं कि एक नया चेप्टर हम लोगों को खोलने की जरूरत है। हम लोगों ने लड़ाइयां एक दूसरे की लड़ी हैं। जब तक हम फील्ड में हैं अपन लड़ाई लड़ेंगे परन्तु जब हाउस में आ जाते हैं तो आपकी भी उतनी ही जिम्मेदारी है जितनी हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिये मेरा आप सबसे यही कहना है कि एक नया चेप्टर खोलें, सहयोग का चेप्टर। हम लोग मिलकर आज राजस्थान के विकास के लिये हम लोग जुटें। मैं समझती हूं कि लड़ाई-झगड़े के साथ नहीं परन्तु बातचीत के साथ, डायलाग के साथ मिल बैठकर और जो समस्या है, आपकी भी समस्या है, हमारी भी समस्या है, उनको बैठकर सुलझाने की हम लोग कोशिश करें। दिल्ली की सरकार के साथ हमारी समस्याएं हैं, हम और आप दोनों मिलकर, जाकर उनको हटाने की, उनको खतम करने की कोशिश करें। मैं सब लोगों को कहना चाहूंगी कि आपके आखिरी में कल्ला साहब ने जो शायरी पढ़ी उसमें तो बड़ा

(श्रीमती वसुन्धरा राजे)

आक्रामक स्वर उन्होंने अपनाया। आक्रामक स्वर उन्होंने अपनाया है और मैं यह कहना चाहती हूं उसके जवाब में कि-

उड़ान वालों उड़ान पर वक्त भारी है।

परों की अब नहीं हौंसलों की बारी है।

समन्वित राजस्थान के विकास के लिये,

यह सिर्फ मेरी नहीं, हम सबकी जिम्मेदारी है।

इसलिये सिर्फ मैं तो इतना ही कहना चाहूंगी यह गौरवशाली प्रदेश अत्यन्त ही विकसित हो, अत्यन्त ही समृद्धशाली बने, यह हम सबका सपना है। इस सपने को पूरा करने के लिये हम सब लोग विकास की गंगा बहाने के लिये हम लोग सब मिल बैठकर आगे बढ़ाने की इसको कोशिश करें।

मैं सबको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आज इस सार्थक डिबेट के अन्दर आप सब लोगों ने भाग लिया। मैं धन्यवाद प्रस्ताव पारित करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करती हूं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, एक दो प्रश्न हैं। एक तो मैं यह जानना चाहता हूं कि राजस्थान की वर्तमान में ग्रोथ रेट क्या है ? और आपने दो वर्ष में कितना...

श्री अध्यक्ष : यह बतायेंगे बजट में। जब बजट भाषण का जवाब देंगी तब ग्रोथ रेट भी बता देंगी आपको।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आपने कहा था कि बीच में नहीं बोलें, बाद में प्रश्न कर सकते हैं और यह परम्परा है...

श्री अध्यक्ष : कभी परम्परा नहीं रही है। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रश्न पूछने की परम्परा नहीं है।

डा. बुलाकीदास कल्ला : कैसे नहीं रही है ? यह बहुत गलत बात है। अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गलत परम्परा डाल रहे हैं आप। भैरोंसिंहजी जी यहां पर आधे घंटे तक प्रश्न करते थे। क्या बात करते हैं आप ?

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह बजट की बात है और बजट के समय तब पूछना आप। पहले आप बजट तो...

डा. बुलाकीदास कल्ला : अध्यक्ष महोदय, पहले मेरे को प्रश्न पूछने दीजिये। आप पहले प्रोटेक्ट मत करिये इस सरकार को।

श्री अध्यक्ष : जी.डी.पी. के बारे में आप तब ही पूछियेगा। क्या मतलब हुआ ? जी.डी.पी. की बात बजट के समय बोलना।

डा. बुलाकीदास कल्ला : आप पहले मेरे को प्रश्न पूछने दीजिये। सेज के मामले में आपने बिना रीको जो थी वह नोडल एजेंसी थी। लेकिन आपने बिना यह इण्डस्ट्री डिपार्टमेंट के केबीनेट मीमो लाये, कैसे आपने उनको किस आधार पर महिन्द्रा एण्ड महिन्द्रा कम्पनी को किस आधार पर आपने सेज का मामला दिया ? और दूसरा प्रश्न मैं यह करना चाहता हूं...

श्री सांवर लाल : अध्यक्ष महोदय, सारी बातें खुलासा हो गयी हैं, अब पास कराइये धन्यवाद प्रस्ताव।

श्री अध्यक्ष : अब आप स्थान ग्रहण करें प्लीज।

डा. बुलाकीदास कल्ला : टोटल आउट ले क्या है जिससे पता लग जायेगा कि आप क्या करना चाहते हैं..

श्री अध्यक्ष : Resume your seat please.

श्री सांवर लाल : सारी बातें खुलासा कर दी गयी हैं।

डा. बुलाकीदास कल्ला : मैंने यह भी कहा था कि..(व्यवधान) आपकी नीयत थी क्या करेंगे आप...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : स्थान ग्रहण करें। कृपया स्थान ग्रहण करें माननीय सदस्य।

(डा. बुलाकीदास कल्ला, माननीय सदस्य द्वारा सदन से बहिर्गमन)

प्रश्न यह है कि डा. एन.एस. गुर्जर, सदस्य, विधान सभा द्वारा राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव को स्वीकार किया जाए ?

(स्वीकृत)

राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव स्वीकार किया गया।

सदन की बैठक बुधवार, दिनांक 08 मार्च, 2006 के प्रातः 12.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 20.08 बजे दिनांक 08 मार्च, 2006 के 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

परिशिष्ट-1

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

हिण्डौली में औसत से कम वर्षा होने से उत्पन्न स्थिति

मान्यवर,

इस वर्ष हिण्डौली विधान सभा क्षेत्र में औसत से काफी कम वर्षा हुई है। सारे लघु एवं मध्यम सिंचाई परियोजनाऐं खाली हैं। लगातार वर्षा की कमी के कारण अण्डरग्राउण्ड वाटर कम होता जा रहा है इसके फलस्वरूप काफी वर्षों पूर्व लगाये गये हैण्डपम्प स्थाई रूप से खराब हो चुके हैं और उन स्थाई हैण्डपम्पों के खराब होने के पश्चात् उनके स्थान पर नये हैण्डपम्प नहीं लग रहे हैं।

अधिकांश पाठशालाओं में हैण्डपम्प (राजीव गांधी सतत शिक्षा अभियान के तहत चल रही पाठशालाओं में तथा प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में हैण्डपम्पों के अभाव में बालकों को घर से पानी लेकर आना पड़ता है। अतः नीतिगत निर्णय लेकर प्रत्येक विद्यालय में हैण्डपम्प लगाने का सरकार को निर्णय लेना चाहिए।

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में इस वर्ष नये हैण्डपम्पों की स्वीकृति लगातार निवेदन करने के बाद भी नहीं हो पा रही है इस कारण काफी परेशानी हो रही है।

स्वजल धारा योजना के अन्तर्गत 2 वर्ष गुजर जाने के बाद भी बूंदी जिले में उपयोगिता प्रमाण-पत्र के अभाव में दूसरी किस्त नहीं मिल पा रही है। इस कारण केन्द्र सरकार से प्राप्त धनराशि प्राप्त नहीं हो पा रही है। राज्य सरकार को इस योजना का मानीटरिंग करना चाहिए ताकि केन्द्र से उपयुक्त धनराशि प्राप्त हो सके। इसी प्रकार हिण्डौली एवं अन्य गांवों के लिए पेयजल स्कीम बनना चाहिए। स्वीकृत ठीकरदा की स्कीम पूरी नहीं हुई है। इस समय हिण्डौली के कनिष्ठ अभियन्ता की जगह खाली है। हैण्डपम्प ठीक करने के अभियान के लिये पाइप आदि उपलब्ध नहीं है।

अतः सरकार से मांग है कि उक्त समस्याओं के समाधान हेतु कारगर कदम उठाने का कष्ट करें।

हरिमोहन शर्मा

(हिण्डौली)

मेड़ता नगरपालिका के अधिशासी अधिकारी व अध्यक्ष द्वारा प्रजातंत्र पर किये जा रहे कुठाराघात के सम्बन्ध में

महोदय,

मेड़ता का निर्वाचित बोर्ड है उसमें चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रस्तावित ऐजेण्डे को बोर्ड की बैठक में सम्मिलित करने का नियम एवं प्रावधान है उसके लिए नगरपालिका के कुल 30 पाषर्दों में से 12 पार्षदों ने दिनांक 21-12-2005 को उप नियम बनाने के सम्बन्ध में वित्त सम्बन्धी चर्चा के सम्बन्ध में व विकास कार्यों की चर्चा के लिए विशेष बैठक का अनुरोध किया गया था। इसके सम्बन्ध में दिनांक 4-2-2006 को श्रीमान निदेशक स्थानीय निकाय, जयपुर ने अधिशासी अधिकारी नगरपालिका, मेड़ता को निर्देश भी दिया था उसकी अनुपालना अधिशासी अधिकारी ने नहीं की बल्कि दिनांक 14-2-2006 को साधारण बैठक इनके पार्षदों के आवेदन का हवाला देते हुए बुलाई उसमें उनके द्वारा उल्लिखित ऐजेण्डा नं.-1 राजस्थान नगरपालिका अधिनियम-1959 की धारा 88 खण्ड अ के अन्तर्गत समिति गठन हेतु नियम उपनियम बाइलाज 2006 बनाने बाबत् था नहीं रखा। जिस पर नगरपालिका के 17 पार्षदों ने उन्हें निदेशालय स्थानीय निकाय में शिकायत की जिस पर सहायक विधि परामर्श स्थानीय निकाय ने अधिशासी अधिकारी नगरपालिका को दिनांक 20-2-2006 को निर्देशित किया कि दिनांक 27-2-2006 की बैठक में इस ऐजेण्डे को सम्मिलित किया जावे। पूर्व में क्यों नहीं किया गया उसका स्पष्टीकरण भी मांगा गया परन्तु उसकी अनुपालना भी नहीं की गई तब आहूत बैठक दिनांक 27-2-2006 को नगरपालिका पार्षदों ने मीटिंग के दौरान इसकी मांग की परन्तु कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं देकर अध्यक्ष नगरपालिका मीटिंग से उठकर चली गयी तथा वहां पर असमंजस्य की स्थिति पैदा हो गई तब से लगातार पार्षदगण उपस्थित 29 पार्षदों में से 17 निर्वाचित पार्षद व 3 मनोनीत पार्षद कुल 20 पार्षद धरने पर बैठे हैं। इस सम्बन्ध में जिला कलक्टर, नागौर व निदेशक स्थानीय निकाय, जयपुर सभी को अवगत करा दिया गया है परन्तु अभी तक उसका समाधान नहीं हुआ है। प्रजातन्त्र में निर्वाचित पार्षदजनों की बात को अध्यक्ष नगरपालिका अल्पमत के आधार पर भी न मानकर अपने पद का दुरूपयोग कर रहे हैं तथा अधिशासी अधिकारी ने लगातार निदेशालय के आदेशों की कूट रचानापूर्वक अवहेलना की है।

श्रीमान अधिशासी अधिकारी ने जानबूझ कर 27-2-2006 को बैठक के

दिन आकस्मिक अवकाश आवेदन भेज दिया जिसकी उपस्थिति रजिस्टर में सी.एल. अंकित है। मीटिंग में भी अधिशासी अधिकारी के कार्य के लिए राजस्व निरीक्षक प्रोसेडिंग लिखने के लिये बैठाया गया वो भी अध्यक्ष के साथ ही उठकर चले गये। दिनांक 28-2-2006 के दोपहर 2.30 बजे तक किसी प्रकार की प्रोसेडिंग नहीं लिखी गई थी जिसकी जांच उपखण्ड अधिकारी, मेड़ता ने की परन्तु उसके बाद प्रोसेडिंग रजिस्टर में इस आशय की प्रोसेडिंग लिख दी कि हो-हल्ला के कारण बैठक निरस्त कर दी गई, लिखकर श्रीमान राजस्व निरीक्षक ने हस्ताक्षर कर दिये। इस प्रकार की कार्यवाही पूर्व में भी इस नगरपालिका में दो मीटिंगों में अध्यक्ष नगरपालिका व अधिशासी अधिकारी ने मिलीभगत करके एकाधिकार रखने के लिए करते रहे जिससे वहां पर प्रजातन्त्र के अधिकारों का हनन हो रहा है।

इस विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित कर अनुरोध है कि निदेशालय के आदेशों की अवहेलना करने वाले अधिशासी अधिकारी व राजस्व निरीक्षक के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे तथा अध्यक्ष नगरपालिका द्वारा पद दुरूपयोग के सम्बन्ध में इन्हें अयोग्य घोषित करने की कार्यवाही की जावे तथा 27-2-2006 से संचालित बैठक की अधूरी कार्यवाही को सम्पूर्ण करवाकर धरना उठवाया जावें।

हरीशचन्द्र कुमावत
(नावां)

पाली रंगाई-छपाई के कारखानों से निकले प्रदूषित जल से जमीन खराब होने बाबत

महोदय जी,

मैं इस विशेष उल्लेख के जरिये माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्रीजी की जानकारी में लाना चाहूंगा कि पाली का कपड़े की रंगाई-छपाई के उद्योग में काफी नाम है पिछले कुछ वर्षो में ये उद्योग बहुत तेजी से पनपा है। पाली में बनने वाली साड़ी, लूंगी, ब्लाऊज पीस पूरे भारत में ही नहीं बिकता ब्लकि बहुत बड़ी मात्रा में यह कपड़ा निर्यात भी किया जाता है। पाली के विकास का मुख्य आधार यह उद्योग है इस उद्योग के कारण हजारों लोगों को रोजगार के अवसर भी मिले हैं औद्योगिक प्रगति के साथ-साथ औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले प्रदूषित पानी के कारण रोहर क्षेत्र के कई गांवों में प्रदूषण की समस्या ने

विकराल रूप धारण कर लिया है हालांकि प्रदूषित पानी को उपचारित करने हेतु पाली में तीन ट्रीटमेन्ट प्लान्ट को चलाने हेतु जो राशि ट्रस्ट द्वारा निर्धारित की गई है वो भी देते हैं फिर भी ट्रस्ट द्वारा ट्रीटमेन्ट प्लान्टस के सफल संचालन नहीं करने से बड़ी मात्रा में प्रदूषित पानी बिना ट्रीट किये सीधा नदी में छोड़ दिया जाता है जिसके कारण 50-60 कि. मीटर आगे तक के उन गांवों की जमीनें जो नदी के आसपास है पूरी तरह खराब हो गई हैं जिन खेतों में 15-20 वर्ष पूर्व अच्छी फसल होती थी प्रदूषित पानी के कारण आज वहां घास भी नहीं उगती इस क्षेत्र के काश्तकार पिछले कई वर्षों से लगातार जल प्रदूषण की समस्या के समाधान हेतु अपनी आवाज प्रशासन एवं सरकार तक पहुंचा रहे है उनके द्वारा कई बार धरने भी दिये गये प्रदर्शन भी किया गया परन्तु जल प्रदूषण की समस्या के रोकथाम हेतु कोई प्रभावी कदम ना तो ट्रस्ट द्वारा उठाया गया ना ही सरकार द्वारा इस क्षेत्र के किसान अपनी उपजाऊ जमीन के बंजर हो जाने के कारण काफी आक्रोश में है वे ट्रीटमेन्ट के प्लान्ट के सफल संचालन करने, प्रदूषित पानी ट्रीट नहीं हो सकने की स्थिति में फैक्टरियां बन्द करने एवं जल प्रदूषण के कारण उनकी जमीने खराब होने पर उसका समुचित मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं।

मैं माननीय वन एवं पर्यावरण मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इण्डस्ट्रीज द्वारा ट्रीटमेन्ट प्लान्ट के संचालन हेतु निर्धारित राशि दी जा रही है। ट्रस्ट प्लान्ट को चलाने में असफल रहा जिसके चलते प्रदूषित पानी सीधा नदी में छोड़ा गया जिसके कारण हजारों बीघा उपजाऊ भूमि बंजर हो गई जिसके लिये ट्रस्ट जिम्मेदार है जिन किसानों की भूमि पूरी तरह खराब हो गई ट्रस्ट द्वारा उस भूमि का समुचित मुआवजा दिलवाया जाये। ट्रस्ट के पास पर्याप्त राशि है सरकार सर्वे करवाये कि किन-किन काश्तकारों की भूमि खराब हो गई है उसके कारण किसानों का कितना नुकसान हुआ है फिर मुआवजा राशि निर्धारित कर ट्रस्ट को बाध्य किया जाये कि वो उन किसानों को मुआवजा राशि दे एवं जो-जो जमीनें जल प्रदूषण के कारण बंजर हो गई उन्हें कैसे ठीक किया जा सकता है इसका सर्वे भी ट्रस्ट अपने खर्चे पर करवाये ताकि जिन किसानों की भूमि जल प्रदूषण के कारण खराब हो गई उनके साथ न्याय किया जा सके।

ज्ञानचन्द पारख

(पाली)

पीपल्दा क्षेत्र में रोड मरम्मत एवं पुलियाओं के निर्माण करवाने बाबत

महोदय,

निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में स्थित उनियारा, इन्द्रगढ़, ढीपरी रोड़ (राज्य मार्ग संख्या 19), इन्द्रगढ़ जिला (बूंदी से (ढीपरी) जिला कोटा) तक सड़क काफी क्षतिग्रस्त है। तथा इस मार्ग पर जगह-जगह 10 नाले पड़ते हैं, जिन पर कोई पुलिया निर्मित नहीं है। इस कारण से थोड़ी सी बरसात होते ही नांलों में पानी आने से मार्ग अवरूद्ध हो जाता है। इन नालों पर वाहन उतारने पर दुर्घटनाग्रस्त हो जाते हैं। अभी हाल में ही प्रथम वर्षा के दौरान एक बस के ग्राम चाणदा के बाद नाले में गिर जाने से दो व्यक्तियों की मृत्यु तथा 30 यात्री घायल हो गये।

अन्त में अनुरोध करता हूं कि सरकार उक्त क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत एवं नालों पर पुलिया बनाने की उचित कार्यवाही करके अनुग्रहित करें।

धन्यवाद।

प्रभूलाल वर्मा,
(पीपल्दा)

बानसूर से गुजर रहे स्टेट हाइवे नम्बर 52 पर अतिक्रमण

महोदय,

कस्बा बानसूर जिला अलवर में सड़क सीमा में एमडीआर 25 (कोटपूतली बानसूर अलवर रोड) तथा एसएच 52 (स्टेट हाइवे 52) आलनपुर बानसूर नारायणपुर रोड के दोनों तरफ भू-माफिया लोगों ने रातों रात दुकानें बनाकर पी.डब्ल्यू.डी. की सीमा में अतिक्रमण कर करोड़ों रुपये की जमीन पर कब्जा जमा लिया है। साथ ही अवैध खोखों की जो कि लगभग 300-400 की संख्या में थे, उनको स्थानीय प्रशासन ने कानूनी तरीके से नोटिस देकर हटा दिया गया है।

दिनांक 23-9-1988 को "अवांड भूमि अवाप्ति सड़क बानसूर से नारायणपुर" किया गया था, उस समय 1988 में 92,706.80 पै. भूमि अवाप्ति अधिकारी सार्वजनिक निर्माण विभाग वृत्त पंचम जयपुर द्वारा जारी किया गया था। उस वक्त अवार्ड जारी हुआ तो उस समय नक्शे में सड़क चौड़ाई 80 रखी गयी थी। जो कि वर्तमान में सड़क के दोनों तरफ अवैध रूप से पी.डब्ल्यू.डी. की सीमा में अतिक्रमियों व भू-माफियाओं लोगों ने सड़क सीमा को बिलकुल

सकड़ा दिया है जिससे घंटो-घंटो जाम लगा हुआ रहता है। तथा यातायात व्यवस्था अवरूद्ध होने से बढ़ती दुर्घटनाओं के कारण आम जन बेहद दुखी है। बीमार महिलाएं तथा गर्भवती महिलाओं को अस्पताल पहुंचने से पूर्व ही प्रसव पीड़ा के कारण रास्ते में जाम में ही प्रसव पीड़ा के कारण रास्ते में जाम में ही प्रसव होते पाया गया है। अतः पीडब्ल्यूडी विभाग की करोड़ों की जमीन पर अवैध कब्जे कर लिये गये हैं।

माननीय मुख्य मंत्रीजी की अध्यक्षता में दिनांक 30-5-2005 को आयोजित कानून एवं व्यवस्था से सम्बन्धित बैठक के दूसरे सत्र में जिलाधीशों एवं जिला पुलिस अधीक्षकों को यह निर्देश दिये थे कि राजकीय भूमि पर अतिक्रमणों को तुरन्त हटाया जाये। शहरों एवं कस्बों में बढ़ती आबादी के कारण यातायात व्यवस्था अवरूद्ध न हो तथा इस पर पी.डब्ल्यू.डी. सीमा में सड़कों के दोनों तरफ किये गये अतिक्रमणों को तुरन्त हटाया जावे।

माननीय मुख्य मंत्रीजी के निर्देशों के बाद जिलाधीश महोदय के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन ने शान्तिपूर्ण व कानूनी तरीके से कार्यवाही कर अवैध खोखों को हटाया गया तथा पीडब्ल्यूडी विभाग के एईएन, एक्सईएन और एसई के सहयोग से पक्की अवैध निर्मित दुकानों को जो कि पी.डब्ल्यू.डी. विभाग की सीमा में अतिक्रमण कर बनाई गई थी को हटाने हेतु चिन्हित किया गया। जब से स्थानीय प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने हेतु जब से चिन्हित किया है तब से अतिक्रमी लाखों रुपये लेकर जयपुर में यह कहते हुए घूम रहे हैं कि एस.डी.ओ. का स्थानान्तरण करायेंगे तथा कार्यवाही रूकवायेंगे में वे कामयाब हो गये हैं तथा अखबारों में हजारों रुपयों का विज्ञापन देकर खुशी जाहिर की है कि एस.डी.ओ. का स्थानान्तरण हो गया है व अतिक्रमण रूक गया इससे सरकार की क्या मंशा जाहिर होती है।

शहर में इस प्रकार सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा अतिक्रमण हटाने में सहयोग नहीं करने का आदेश माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री के निजी सचिव के आदेश क्रमांक दिनांक 23-2-2006 के अनुसरण में मा. मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग ने दिनांक 26-2-2006 रविवार को आदेश प्रसारित कर अतिक्रमण हटाना रोक दिया और वहां के परगना अधिकारी को हटा दिया। वहां इस प्रकार की गम्भीर चर्चा है कि यह मामला वहां कुछ लोगों द्वारा आर्थिक सहयोग करने का कारण हुआ है।

परन्तु अतिक्रमणियों के अनुरोध पर पीडब्ल्यूडी विभाग की करोड़ों की

भूमि पर अतिक्रमण कर सड़क मार्ग के दोनों ओर अतिक्रमण कर रातों-रात कब्जा कर दुकानें खड़ी कर दी गई उनको जब पी.डब्ल्यू.डी. विभाग के अधिकारियों ने चिन्हित कर नोटिस प्रदत्त किया तो माननीय सार्वजनिक निर्माण मंत्री के निजी सचिव के आदेश द्वारा रोका जाना स्पष्ट अन्याय को दर्शाता है।

इसी प्रकार फरवरी, 2005 से स्वीकृति हुई सी.आर.एफ. योजना में बानसूर में आलनपुर से बानसूर नारायणपुर रोड़ का स्वीकृत 171 लाख रुपया ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। नाही सड़क बनाने का कार्य शुरू हुआ है और नाही अतिक्रमण की कार्यवाही पूरी होने दी।

अत: मेरा माननीय मुख्य मंत्रीजी से अनुरोध है कि अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही को शीघ्र पूरा करावें, रोके नहीं, तथा सीआरएफ के तहत 23 फरवरी, 2005 को स्वीकृत सड़कों के सुधारीकरण की स्वीकृत राशि का कार्य शीघ्र प्रारम्भ करने के आदेश जारी करें।

अत: जनहित में किये निर्णयों को जारी रखें ताकि जनता का विश्वास बना रहे अगर जनता का विश्वास खतम हो गया तो क्षेत्र में अराजक तत्वों व अतिक्रमणियों के होसले बुलन्द होते देर नहीं लगेगी। साथ ही कानून व्यवस्था ठप्प होने का खतरा उत्पन्न हो जाएगा। बानसूर में वर्तमान में 99.99 प्रतिशत जनता इस अतिक्रमण को हटाने की कार्यवाही का समर्थन कर रही है। अत: कस्बा बानसूर में सड़क के दोनों ओर करोड़ों की पीडब्ल्यूडी की सम्पत्ति पर से अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही नहीं रोके साथ ही क्षतिग्रस्त पानी भराव क्षेत्र की सड़क को जो कि सीआरएफ में स्वीकृत है सी.सी. रोड़ बनाने के आदेश शीघ्र जारी करें।

महीपाल सिंह यादव,
(बानसूर)

राजसमंद के राजकीय चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने बाबत

महोदय,

मेरे विधान सभा क्षेत्र राजसमंद के जिला आर.के. चिकित्सालय को 200 बैड का किया जाय एवं सभी डाक्टरों के रिक्त पदों को अविलम्ब भरा जाय रेलमगरा को चिकित्सालय में डाक्टरों के रिक्त पदों को भरा जाय।

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र ग्रामीण

बाहुल्य क्षेत्र है गांवों से गरीब लोग असाध्य बीमारी के कारण महंगा इलाज नहीं करा पाते हैं डाक्टरों के रिक्त पदों के कारण उदयपुर जाना पड़ता है इतना खर्चा करना गरीब लोगों के वश की बात नहीं है। अतः श्रीमान से निवेदन है कि राजसमंद जिला चिकित्सालय को 200 शैय्याओं का करने एवं सभी रिक्त पदों को अविलम्ब भरा जाय। तहसील रेलमगरा के चिकित्सालय में सम्पूर्ण व्यवस्था एवं रिक्त पदों को भरा जाय।

कुआरिया में मदर हैल्थ चाइल्ड सेन्टर खोला जाय और केलवा मार्बल बाहुल्य क्षेत्र है कई दुर्घटना होती हैं वहां चिकित्सालय में हड्डी विशेषज्ञ का पद सृजित किया जाय और राजसमंद नगर के पुराने चिकित्सालय में सीटी डिस्पेन्सरी का स्थाइकरण किया जाय ताकि नगर के सभी लोगों को छोटी बीमारियों का इलाज नगर के चिकित्सालय में व्यवस्थित रूप से हो जाय।

राजसमंद में एक मेडिकल कालेज एवं नर्सिंग कालेज की स्थापना कर इसे आर.के. जिला चिकित्सालय से जोड़ा जाय। राजसमंद जिला चिकित्सालय में हड्डी एवं जोड़ सम्बन्धित अति विशेष चिकित्सा सुविधाऐं (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) राजनगर में प्रसूति गृह की स्थापना की जाय।

बंशी लाल खटीक,
(राजसमंद)

दानपुर में पुलिया निर्माण हेतु

महोदय,

दानपुर विधान सभा क्षेत्र में धोडी तेजपुर खजुरी, तिलगार मागंरवा, मकनपुरा, दनासरी आदि पंचायतों में जाने के लिए वर्तमान में बांसवाड़ा से 55 कि.मी. की दूरी तय करनी पड़ती है। तथा इस पुलिया के बनने से इन पंचायतों की दूरी 30 कि.मी. ही रहती है। इस नदी के दोनों तरफ डामर रोड है। अतः इस समस्या को ध्यान में रखते हुये पुलिया बनाकर लाभान्वित करने की कृपा करें।

अर्जुन सिंह,
(दानपुर)

धौलपुर शहर में ड्रेनेज स्कीम की क्रियान्विति के सम्बन्ध में

महोदय,

नगरपालिका मण्डल धौलपुर द्वारा वर्ष,, 1954 से ही ड्रेनेज स्कीम

तैयार कराने हेतु सहायक अभियन्ता, धौलपुर को पत्र लिखा गया था। इसके पश्चात् अधीक्षण अभियन्ता पब्लिक हैल्थ राजस्थान जयपुर को सर्वे स्कीम तैयार करने हेतु 1955 में व समय-समय पर बार-बार लिखा गया।

इसके पश्चात् अधिशासी अभियन्ता सर्वे एण्ड ड्रेनेज डिवीजन हैल्थ जयपुर ने अपने पत्र क्रमांक : 2902 दिनांक 30 जनवरी, 1973 के द्वारा धौलपुर शहर की ड्रेनेज स्कीम की सर्वे फीस 3000/- रुपया की मांग की गई। नगरपालिका धौलपुर ने उक्त राशि निर्देशानुसार चीफ इंजीनियर पी.एच.ई.डी. प्लानिंग बीच-2, सिविल लाइन जयपुर को जरिये चैक नं. 90960 दिनांक 21-2-1974 से भिजवा दिये।

इसके बाद बार-बार लिखने एवं व्यक्तिगत सम्पर्क करने के बावजूद भी ड्रेनेज योजना बनाने का कार्य अभी तक भी लम्बित पड़ा है। अधिशासी अभियन्ता सीवरेज एण्ड ड्रेनेज खण्ड जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर ने अपने पत्रांक 2579 दिनांक 19-11-1990 के द्वारा धौलपुर नगर की सीवरेज ड्रेनेज योजना तैयार कराने हेतु पुनः 74000/- का तकमीना बनाकर प्रशासक नगरपालिका धौलपुर भेजकर उक्त राशि चैक नं. 622464 दिनांक मई, 1991 को अधिशासी अभियन्ता सिवरेज जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग को भेज दी गई।

पुनः धौलपुर शहर के गन्दे पानी के निकास हेतु सर्वे कार्य पूर्ण कराये जाने बाबत जिला कलक्टर धौलपुर की अध्यक्षता में दिनांक 31 जुलाई, 1999 को नगरपालिका ने पीडब्ल्यूडी एवं पीएचईडी आदि विभागों से विचार-विमर्श हुआ जिसमें यह तय किया गया कि धौलपुर शहर के समस्त गन्दे पानी की अन्तिम निकासी चम्बल के भड़कों में की जा सकती है। इस कार्य हेतु धौलपुर शहर के लिए ड्रेनेज योजना के सर्वे एवं डिजाइन का कार्य फर्म मैसर्स अजीत सर्वे एण्ड कंसल्ट्रैट जयपुर द्वारा किये जाने पर कुल व्यय 1,34,625 रुपये व्यय होने की पीएचईडी धौलपुर ने जिला कलक्टर धौलपुर केा दिनांक 21-2-2006 से अवगत कराया कि नगरपालिका धौलपुर ने 74000/- दिनांक 7-5-1991 को सर्वे डिजाइन बीसलपुर परियोजना खण्ड जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर को पूर्व में ही जमा करवा दिये गये थे।

अतः माननीय मंत्री (स्वायत्त शासन) महोदय ने विनम्र निवेदन है कि उक्त कार्य का शीर्घातिशीघ्र करवाने की कृपा करें ताकि धौलपुर शहर में काफी लम्बे समय से व्याप्त गन्दे पानी की समस्या का समाधान हो सके। जिससे आम जनता को राहत महसूस हो।

बनवारी लाल शर्मा,

(धौलपुर)

बल्लभनगर में यातायात सुविधाओं का अभाव

महोदय,

मैं बल्लभनगर विधान सभा क्षेत्र में यातायात सुविधाओं की कमी के सन्दर्भ में सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं :-

बल्लभनगर तहसील मुख्यालय पर पूरी तरह से यातायात साधनों का अभाव है यहां से किसी भी ओर जाने के लिये समुचित व्यवस्था नहीं है। जिला मुख्यालय से जोड़ने के लिये मात्र एक बस चलाई जा रही है जो अपर्याप्त है। तहसील में पड़ने वाले कानो एवं भीण्डर नगरपालिका क्षेत्र पूरी तरह से मुख्यालय से कटे हुये है और इन क्षेत्रों के बीच एक भी बस संचालन नहीं है। दोनों नगरों को चित्तौड़गढ़ से जोड़ने वाली बस भी जो पहले चलती थी वह निरस्त कर दी गई है जिससे चित्तौड़गढ़ व जयपुर से इन नगरों का सम्पर्क पूरी तरह से कट गया है।

कानोड से भीण्डर कीरकी चौकी भोपाल सागर, कपासन कारोई व भीलवाड़ा होकर जयपुर आने वाली बस भी काफी समय से बन्द पड़ी है। मेरा राज्य सरकार से अनुरोध है कि तहसील मुख्यालय को यातायात सुविधाओं को जोड़ने के लिये :

(1) उदयपुर से चित्तौड़गढ़ चलने वाली कुछ गाड़ियों को भटेवर की जगह बल्लभनगर नवानिया रूणडेडा मेणार बंगका होकर चलाया गया।

(2) उदयपुर से भीण्डर कानोड, बड़ी सादड़ी, धरियावद की ओर जाने वाली गाड़ियों को वाया बल्लभनगर होकर चलाया जाय व साथ ही

(3) कानोड-चित्तौड़गढ़ बस पुनः चालू कराई जाय।

(4) कानोड से मुम्बई चलने वाली बस पुनः चालू कराई जाय।

(5) जयपुर से भी कानोड और भीण्डर नगर को जोड़ने के लिये कोई बस चलाई जाय।

महोदय,

राज्य सरकार ने जयपुर से करीब-करीब सभी सम्भाग मुख्यालयों को वोल्बो बस से जोड़ दिया है मात्र उदयपुर को छोड़कर मेरा अनुरोध है कि उदयपुर के लिये भी वोल्बो बस शीघ्र शुरू की जाय।

रणधीर सिंह भीण्डर,

(बल्लभनगर)

शिवगंज नगरपालिका द्वारा सीमा क्षेत्र (पेराफेरी) में भूमि रूपान्तरण की राशि बंडगांव, केसरपुरा ग्राम पंचायतों को उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में

महोदय,

शिवगंज नगरपालिका द्वारा सीमा क्षेत्र (पेराफेरी) में ग्राम पंचायत बड़गांव व केसरपुरा के क्षेत्र को भूमि का रूपान्तरण किया जा रह है लेकिन पंचायत क्षेत्र की भूमि का शुल्क पंचायत को नहीं दिया जा रहा है। गत कई वर्षों से यह स्थिति बनी हुई है। बडगांव व केसरपुरा ग्राम पंचायतों द्वारा कई पत्र भेजे गये लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यह जानकारी दी जाए की शिवगंज नगरपालिका द्वारा बडगांव व केसरपुरा क्षेत्र की किस किसकी कितनी भूमि का कब-कब रूपान्तरण किया गया एवं कितनी राशि वसूल की गई। वसूल की गई राशि में से ग्राम पंचायत बडगावं व केसरपुरा का कितना हिस्सा दिया जाना है। यह राशि कब तक उक्त पंचायतों को दे दी जायेंगी। अतः प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत माननीय स्वायत्त शासन मंत्री से इस सम्बन्ध में कार्यवाही का निवेदन है।

संयम लोढ़ा,
(सिरोही)

खारची में पेयजल व अकाल की विकट स्थिति पर राहत कार्य आरम्भ करने के सम्बन्ध में

महोदय,

विधान सभा खारची में इस वर्ष की गिरदावरी रिपोर्ट के आधार पर 75% तक फसल खराब होने व औसत से कम वर्षा होना बताया गया है।

कम वर्षा होने से क्षेत्र के लगभग सभी बांध, तालाब, एनीकटों में पर्याप्त पानी आता ही नहीं, जो आया वो हब तक पूर्ण रूप से सुख चुका हैं नतिजा फरवरी माह में ही क्षेत्र में पेयजल की समस्या उत्पन्न हो चुकी हैं गांवों में पेयजल परिवहन द्वारा उपलब्ध कराने की स्थिति हो चुकी है। क्षेत्र के 95% गांव जल प्रदाय योजना से वंचित है गांवों में मात्र हैण्डपम्पों से जलापूर्ति होती हैं अथवा आस-पास के कुओं से पानी लाया जाता है। लगातार पड़ रहे अकाल से तथा अत्यधिक जल दोहन से हैण्डपम्पों में भी भू-जल का स्तर

चिन्ताजनक स्थिति में पहुंच चुका है। आने वाले समय में पेयजल की भयावह स्थिति पैदा हो सकती है। अतः समय पर खारची क्षेत्र की लम्बित जल प्रदाय योजनाओं को स्वीकृत किया जावें। पेयजल की लम्बित योजनाएं :-

(1) फुलाद बांस व रेणीया बांध पेयजल योजना

(2) गांधी, सुमेर, गुडा आसकरण पेयजल योजना

(3) गुडा अखेराज पेयजल योजना

(4) पनोता पेयजल योजना

तथा पेयजल की नयी योजना का लाभ भी निम्न गांवों में की जायें। गुडा, देवगन, गुडा जेतावरान, सांसरी व आवापुरा में आवश्यकतानुसार नये हैण्डपम्प स्वीकृत किये जाये ताकि ग्रामीण जनता को पीने का पानी की समस्या से राहत मिल सके।

गिरदारी रिपोर्ट के आधार पर क्षेत्र को इस वर्ष अकालग्रस्त घोषित किया गया है क्षेत्र में लगभग 90% खेतीहर मजदूर हैं जो मात्र खेती पर ही आश्रित है सम्पूर्ण क्षेत्र में अकाल होने से उनके पास आज किसी तरह का रोजगार नहीं है। राहत कार्य आरम्भ नहीं होने से रोजी रोटी की समस्या पैदा हो चुकी है। बाजार में गेहूं के भाव आसमान को छू रहे हैं। गेहूं 12/- रुपये से 14/- रुपये = किलों बिक रहा है बिना मजदूरी के पेट पालना मुश्किल होती जा रही है। लोगों को पलायन करने पर मजबूर होना पड़ रहा है। अगर समय पर सम्पूर्ण क्षेत्र में पर्याप्त अकाल राहत कार्य शुरू नहीं किये गये तो रोजगार के अभाव में गांव के गांव पलायन करने पर विवश हो जायेंगे व कुशल मजदूर और कारीगर को सामग्री मद से माना है जो सर्वथा न्याय संगत नहीं है। तुरन्त प्रभाव से इनको श्रम मद से माना जावे।

क्षेत्र के 41 गांव मंगरा क्षेत्र में आते हैं जिनके पास रोजगार के नाम पर मात्र भेड़-बकरी पालन करना तथा लकड़ी बेच कर गुजर-बसर करते हैं जिनके रोजगार व पीने के पानी की भंयकर समस्या है। अतः मगरा क्षेत्र विकास योजना के तहत विकास के कार्य स्वीकृत किये जावें।

खुशवीर सिंह,

(खारची)

गोगुन्दा की सड़कों की मरम्मत के सम्बन्ध में

महोदय,

विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा के अन्तर्गत बाहुल्य आदिवासी अंचल की पंचायत मुख्यालय सड़क पदराडा से चित्रावास व काछवा से पाटिया, मोरबल तथा मादा से छाली की सड़के कृषि विपणन बोर्ड द्वारा कृषि उपज मण्डी से स्वीकृत कराने के बाद पक्की की गई परन्तु अभी उपरोक्त सड़कों की स्थिति बड़ी खराब हैं। गाड़ियों को एवं स्थानीय वासियों को आने-जाने की भंयकर समस्या बनी हुई है। निरन्तर सड़कें क्षतिग्रस्त होने से व पुलिया व काजवे टूटने से समस्या हो गयी है। अतः कृषि विवपणन मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर उपरोक्त सड़कों को तत्काल मरम्मत कराये जाने की कार्यवाही करावें। क्योंकि उदयपुर कृषि उपज मण्डी से उपरोक्त सड़कों की मरम्मत कराने का प्रस्ताव राजस्थान सरकार के पास भेज रखा है। दूसरे पहरे में मैं निवेदन करना चाहता हूं और सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी को ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि :

1. सड़क विसमा बालातरा से मोरिया सड़क प.स. गोगुन्दा
2. सड़क कड़ेच से कोयलवाव-प.स. गोगुन्दा
3. सड़क तेजा का वास से भीमाणा प.स. कोटड़ा
4. तीलखा (सामोल) से स्वरूपगंज
5. छिपाला सड़क से राजसमन्द ऐरिया
6. धणावल (पलासमा) से आतरी बारां

उपर्युक्त सड़कों को पक्की कर जोड़ने से एक जिले से दूसरे जिले में आने जाने की सहूलियत होगी एवं कम समय में आना जाना सम्भव हो पायेगा। अतः सार्वजनिक निर्माण मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर इन सड़कों को पक्की कराये जाने का आदेश प्रदान करावें।

धन्यवाद।

मांगीलाल गरासिया

(गोगुन्दा)